

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं०-1



विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं०
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-1: सामान्य		
कार्यपालिक सारांश		1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	3
बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2	4
मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत	1.3	5
पाँच वर्ष से अधिक बकाये का कुल राजस्व के बकाये के सन्दर्भ में विश्लेषण	1.4	5
संवीक्षा/कर निर्धारण के बकाये	1.5	6
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग का प्रत्युत्तर	1.6	6
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.7	7
आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर विभागों का प्रत्युत्तर	1.8	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण – सारांशीकृत स्थिति	1.9	9
राज्य आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण	1.10	9
लेखापरीक्षा योजना	1.11	10
लेखापरीक्षा का प्रभाव	1.12	11
अध्याय-II: बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
कार्यपालिक सारांश		13
कर प्रशासन	2.1	15
प्राप्तियों का रुझान	2.2	15
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	2.3	16
प्रति व्यापारी बिक्री, व्यापार आदि की लागत	2.4	16
कर निर्धारण हेतु बकाए मामले	2.5	16
संग्रह की लागत	2.6	17
लेखा परीक्षा के प्रभाव	2.7	17
वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली (एक समीक्षा)	2.8	19
लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.9	46
कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.10	46
क्रय कर का अनारोपण	2.11	54
अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण	2.12	55
प्रवेश कर का अनारोपण	2.13	61
के०बि०क० में गलत करमुक्ति/छूट	2.14	61
राज्य विकास कर का अनारोपण	2.15	64
अपूर्ण सूचना होने पर भी वाद को डीम्ड घोषित किया जाना	2.16	66
ब्याज का प्रभारित न किया जाना	2.17	67
कर की दर की गलत अनुमन्यता	2.18	70

टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना	2.19	71
कर की वापसी के द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ	2.20	72
गलत/मिथ्या आईटीसी0 के दावे के मामले	2.21	74
जमा की पुष्टि न होना	2.22	77
केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति	2.23	80
आदेश के बावजूद इनपुर टैक्स क्रेडिट का सत्यापन न किया जाना	2.24	81
कपड़े की बिक्री पर कर का प्रावधान न होना	2.25	82
अध्याय-III: राज्य आबकारी		
कार्यपालिक सारांश		83
कर प्रशासन	3.1	85
प्राप्तियों का रुझान	3.2	85
राजस्व बकाये का विश्लेषण	3.3	85
संग्रह की लागत	3.4	86
आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.5	86
लेखा परीक्षा के प्रभाव	3.6	86
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3.7	89
नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव	3.8	89
अर्थदण्ड का अनारोपण	3.9	107
अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण परिहार्य व्यय	3.10	108
अध्याय-IV : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कार्यपालिक सारांश		109
कर प्रशासन	4.1	111
प्राप्तियों का रुझान	4.2	111
राजस्व बकाये का विश्लेषण	4.3	111
संग्रह की लागत	4.4	112
आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.5	112
लेखा परीक्षा के प्रभाव	4.6	112
मोटर यान अधिनियम/विभागीय आदेशों का अनुपालन न किया जाना	4.7	114
निजी/कृषि कार्य हेतु पंजीकृत वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग	4.8	116
टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण	4.9	118
वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण राजस्व की वसूली न होना	4.10	119
स्कूल वाहनों पर परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना	4.11	120
दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होने का प्रभाव	4.12	121
अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण	4.13	122
परमिट के नियम और शर्तों के उल्लंघन के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण	4.14	123

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं०
जब्त वाहनों से न/कम वसूली किया जाना	4.15	124
बकाये की वसूली हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण क्रियाविधि का अभाव	4.16	125
तीन माह से अधिक समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना	4.17	126
अध्याय-V : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
कार्यपालिक सारांश		127
कर प्रशासन	5.1	129
प्राप्तियों का रुझान	5.2	129
आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण	5.3	131
लेखा परीक्षा के प्रभाव	5.4	131
विकसित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण	5.5	133
स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.6	134
तथ्यों को छिपाने से सम्पत्ति का अवमूल्यांकन	5.7	136
भूमि प्रयोग के अनियमित परिवर्तन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.8	137
भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत किये गये मूल्यांकन में अनियमिततायें	5.9	138
भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.10	140
30 वर्षों से अधिक अवधि के निष्पादित पट्टे	5.11	141
विकासकर्ता अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क का आरोपण	5.12	142
अलाभकारी व्यय	5.13	148
अध्याय-VI: अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ		
कार्यपालिक सारांश		140
लेखापरीक्षा का प्रभाव	6.1	151
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	6.2	151
अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना	6.3	152
रख-रखाव प्रभार जमा न किया जाना	6.4	153
ईट भट्टा मालिकों से रायल्टी व ब्याज का न वसूल किया जाना	6.5	153
ईट मिट्टी का निकाला जाना	6.6	155
अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण	6.7	157
रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	6.8	158
अनधिकृत उत्खनन	6.9	159
अधिनियम/नियमों के साथ शासनादेशों का अनुरूप न होना	6.10	161
शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना	6.11	162
परिशिष्टियाँ		167-201

प्राक्कथन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व क्षेत्र की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा परिणामों का प्रस्तुतीकरण है जिसमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस तथा अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2012-13 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखा परीक्षा सम्पादित की गई है।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में "वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली" विषयक एक समीक्षा सहित 49 प्रस्तर सम्मिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क ब्याज एवं शास्त्र के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित ₹ 427.93 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 103.91 करोड़ धनराशि की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 2.05 करोड़ की वसूली कर ली गई है कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2011-12 के ₹ 1,30,869.70 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2012-13 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,45,903.99 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 58,098.36 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 71,068.34 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 74,835.65 करोड़ (वाणिज्य संघीय करों में राज्य का भाग ₹ 57,497.86 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 17,337.79 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत ही उगाह सकी।

(प्रस्तर 1.1)

दिसम्बर 2012 तक निर्गत किये गये 10,808 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,305.36 करोड़ की धनराशि के 30,694 प्रस्तर जून 2013 के अन्त तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.6.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों के 1,285 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 6,373 मामलों से सम्बन्धित ₹ 2,045.28 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण एवं अन्य कमियों के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 496 मामलों में ₹ 3.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के मामले स्वीकार किये जिनमें से 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ की वसूली की गई।

(प्रस्तर 1.12.3)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली" की समीक्षा एवं विभाग की हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2009 में प्रारम्भ हुये कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त भी नीतियों, नियामों व प्रक्रियाओं को अभी भी विकसित किया जा रहा है, बदलाव प्रबन्धन नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं और आपदा पूरक एवं सतत व्यवसाय योजना नहीं है।

(प्रस्तर 2.8.7.1, 2.8.7.2)

- करयोग्य माल को लेकर राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों के बारे में कोई तंत्र न होने से जब्ती के मामलों में सन्निहित माल के मूल्य में 14,632 मामलों के ₹ 557.67 करोड़ से 30 मामलों के ₹ 1.53 करोड़ तक की गिरावट हुई।

(प्रस्तर 2.8.7.5)

(प्रस्ताव 3.8.7.1)

भारत में निहित विदेशी मद्रिरा एवं देशी मद्रिरा के अधिकतम खूदरा मूल्य के निर्धारण में एक रूपता न होने से सरकार को अतिरिक्त अनुज्ञा शृंखला के रूप में ₹ 481.20 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

III. राज्य आषकाशी

(प्रस्ताव 2.21)

• इनापुट टैक्स कूडिट के गालत/शुद्धे दावों की खोज न करने से ₹ 14.99 करोड़ के इनापुट टैक्स कूडिट के उकमण, अशुद्धे के अनाशीपण एवं खाल का मामला बना।

(प्रस्ताव 2.17.2.1)

• प्रदेश कर के विलम्ब से राजकोष में जमा पर ₹ 26.71 करोड़ का खाल अपमार्शित था।

(प्रस्ताव 2.10)

• कर की गालत दर दर लगाये जाने, कम दर लगाने, माल के श्रुतिपूर्व वर्गीकरण एवं कर के अनाशीपण के फलस्वरूप ₹ 16.92 करोड़ के कर का अनाशीपण/कम आशीपण हुआ।

(प्रस्ताव 2.8.8.5)

• पंजीकृत व्यापारियों के जल्दी मामलों की निगरानी की कमी से ₹ 39.64 करोड़ की प्रतियोगिता की कम वसूली हुई।

(प्रस्ताव 2.8.8.4)

• अधिनियम का उल्लंघन करके जारी किये गये परिपत्र के परिणामस्वरूप ₹ 32.37 करोड़ की प्रतियोगिता की कम वसूली हुई।

(प्रस्ताव 2.8.8.1)

• सचल दल इकाइयों के एक वर्ष में 23 दिनों से 287 दिनों तक कार्य न करने के परिणामस्वरूप माल के अनधिकृत आवागमन को खोजा नहीं जा सका।

(प्रस्ताव 2.8.8, 2.8.8.2)

• विभाग की सचल दल इकाइयों में अपर्याप्त जनशक्ति, निष्क्रिय नियंत्रण कक्षाएँ एवं उपकरणों की अनुपलब्धता आदि ने प्रवर्तन शाला की सचल दल इकाइयों के कुशल कार्य संचालन में योगदान किया।

(प्रस्ताव 2.8.7.6)

• फार्म 38 (आयात के लिये घोषणा पत्र) के आन लाने लाने लॉडिंग से राजस्व हानि के जोखिम को बढ़ावा मिला।

छीजन की त्रुटिपूर्ण अनुमन्यता के परिणामस्वरूप देशी मदिरा के थोक विक्रेताओं की ₹ 111.57 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

(प्रस्तर 3.8.7.2)

विभाग द्वारा नियमों का पालन करने में विफल रहने से सरकार को बेसिक अनुज्ञा शुल्क व प्रतिभूति जमा के रूप में ₹ 53.68 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.8.8.1)

मार्च में न्यूनतम प्रतिभूति मात्रा के कम उठान के फलस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.8.8..3)

शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन से ₹ 736.49 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.8.10)

नियमों के उल्लंघन पर प्रतिभूति जमा को जब्त न किये जाने से ₹ 47.74 करोड़ का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

(प्रस्तर 3.8.12)

IV. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अप्रैल 2011 से अगस्त 2012 तक की अवधि में कम सीटिंग क्षमता ग्रहण किये जाने के कारण छः सभागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में 723 वाहनों पर ₹ 16.75 लाख कम कर आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 4.9)

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में 12 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से सम्बन्धित 3,706 वाहन अधिक भार ढो रहे थे, पर ₹ 2.97 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.13)

मई 2011 से अक्टूबर 2012 तक की अवधि में तीन माह से अधिक समर्पित 753 वाहनों के सम्बन्ध में 11 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में ₹ 87.55 लाख का कर/अतिरिक्त कर वसूल नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.17)

V. स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

विकास क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 11.87 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 5.5)

सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 5.6 से 5.10 तक)

VI. अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

मनोरंजन कर विभाग में चार कार्यालयों के 122 मामलों में ₹ 5.47 लाख के लाइसेन्स फीस की वसूली नहीं हुई और दो कार्यालयों के 13 मामलों में ₹ 5.53 लाख के अनुरक्षण प्रभार को जमा नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.3 एवं 6.4)

22 जिला खनन कार्यालयों में 1,655 ईट भट्ठा स्वामियों से वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक ₹ 10.22 करोड़ की रायल्टी ब्याज की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 6.5)

अप्रैल 2009 से फरवरी 2013 तक की अवधि में 13 जिला खनन कार्यालयों के 1,400 ईट भट्ठा स्वामियों से ईट के लिये मिट्टी की अवैध निकासी के लिए ₹ 30.75 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.6.1)

जुलाई 2003 से मार्च 2012 के दौरान जिला खनन अधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में खनिजों के अनधिकृत उत्खनन पर उत्खनित खनिज के मूल्य ₹ 7.08 करोड़ और ₹ एक लाख के अर्थदण्ड को नहीं वसूला गया।

(प्रस्तर 6.9.1)

अप्रैल 2003 एवं मई 2013 की अवधि के दौरान दो जिला खनन कार्यालयों में बिना खनन योजना के नवीनीकरण कराये खनिज की खुदाई करने के फलस्वरूप ₹ 18.82 करोड़ के खनिज मूल्य की वसूली नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 6.9.2)

बाट एवं माप विभाग मे तीन मामलों में अर्थदण्ड के अतिरिक्त ₹ 8.50 लाख की फीस/अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 6.11)

कार्यालयिक सांख्यिकी

<p>हमने इस अध्याय में क्या मुख्यता से किया</p>	<p>इस अध्याय में हमने राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उन्मुख, बजट अनुमानों एवं वार्षिक प्राप्तियों में अन्तर्गत, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की प्रत्यक्षता, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों पर सरकार/विभागों द्वारा कार्यावाही करने की प्रक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदन में लम्बित प्रत्येक की स्थिति, राज्य आबकारी विभाग की विभिन्न लेखापरीक्षाओं में सरकार की गैर संतुष्टियाँ, जो कि विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई थी एवं लेखापरीक्षा के प्रभाव को प्रस्तुत किया है।</p>
<p>राज्य सरकार की प्राप्तियों का उन्मुख</p>	<p>उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करत राजस्व, विभागीय संधीय कर एवं शुल्कों का उन्मुख एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व ₹ 71,068.34 करोड़ था जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। शेष 51 प्रतिशत प्राप्तियों की राशि ₹ 74,835.65 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुई।</p>
<p>निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रेषणों का अनुपालन न होना</p>	<p>दिसम्बर 2012 तक जारी 10,808 निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित 30,694 प्रत्येक विनम विहित राशि ₹ 6,305.36 करोड़ थी जून 2013 तक अनुपालन के अभाव में लम्बित थी। निरीक्षण प्रतिवेदन के निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर विभाग/परीक्षा से प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक था परन्तु मार्च 2013 तक निर्गत 1,147 निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जून 2013)। उत्तरों के प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लम्बित संख्या इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि कार्यालय/विभाग/परीक्षा ने निरीक्षण प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण त्रुटियों, त्रुटि और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कोई कार्यावाही आरंभ नहीं की।</p>
<p>विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई धनराशि की बृद्धि कम वर्सली</p>	<p>वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में धारण/विभागों ने ₹ 1,437.76 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेषणों की स्वीकार किया जिसमें से केवल ₹ 36.19 करोड़ (2.52 प्रतिशत) की वर्सली दिसम्बर 2013 तक की गई थी।</p>

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वर्ष 2012-13 में हमने पाया कि केवल तीन विभागों¹ द्वारा 61 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें की गईं जिसमें ₹ 1.46 करोड़ धनराशि के 300 प्रस्तर तय किये गये, जबकि अन्य विभागों द्वारा विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिये कोई पहल नहीं की गई।

यह संस्तुति की जाती है कि शासन सामयिक रूप से सभी विभागों की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करे ताकि लम्बित प्रस्तरों का शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण किया जा सके।

हमारा निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 2,045.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के लेखापरीक्षा प्रेक्षण निर्गत किये गये। शासन/विभागों द्वारा ₹ 3.35 करोड़ के 496 मामले स्वीकार किये गये व 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ वसूले गये।

पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये बकाया राजस्व राशि कुल लम्बित राशि का 60.70 प्रतिशत था। सरकार बकाये की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने का प्रयास करे।

सरकार लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रत्युत्तर में प्रभावी प्रक्रिया लागू करने के लिए शीघ्र एवं उपयुक्त कदम उठाये एवं उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों/आलेख प्रस्तरों के उत्तर तय समय सीमा पर नहीं भेजे और समयबद्ध तरीके से राजस्व बकाये की वसूली के लिये कार्यवाही नहीं की।

विभाग कम से कम स्वीकृत मामलों में निहित धनराशि की वसूली के लिये समुचित कदम उठाये।

¹ वार्षिक्य कर, स्टाम्प एवं निवन्धन तथा राज्य आबकारी विभाग।

अध्याय-1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुसूची आँकड़े सारणी क्रमांक 1.1 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
	• कर राजस्व	28,658.97	33,877.60	41,355.00	52,613.43	58,098.36
	• करेतर राजस्व	6,766.55	13,601.09	11,176.21	10,145.30	12,969.98
	योग	35,425.52	47,478.69	52,531.21	62,758.73	71,068.34
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	30,905.72	31,796.67	43,218.90	50,350.95	57,497.86 ²
	• सहायक अनुदान	11,499.49	17,145.59	15,433.65	17,760.02	17,337.79
	योग	42,405.21	48,942.26	58,652.55	68,110.97	74,835.65
3.	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 + 2)	77,830.73	96,420.95	1,11,183.76	1,30,869.70	1,45,903.99
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	46	49	47	48	49

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,45,903.99 करोड़) का, विगत वर्ष के 48 प्रतिशत के विरुद्ध 49 प्रतिशत था। 2012-13 की प्राप्तियों का शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

1.1.2 सारणी क्रमांक 1.2 वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

सारणी क्रमांक 1.2

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 पर 2012-13 में वृद्धि अथवा कमी (-)	2011-12 पर वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर (0040)	17,482.05	20,825.18	24,836.52	33,107.34	34,870.16	1,762.82	05.32
2.	राज्य आबकारी (0039)	4,720.01	5,666.06	6,723.49	8,139.20	9,782.49	1,643.29	20.19
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क (0030)	4,138.27	4,562.23	5,974.66	7,694.40	8,742.17	1,047.77	13.62
4.	वाहनों पर कर (0041)	1,124.66	1,403.50	1,816.89	2,375.86	2,992.92	617.06	25.97
5.	माल एवं यात्रियों पर कर (0042)	266.49	271.05	241.69	4.81	1.04	(-) 3.77	(-) 78.38
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क (0043)	216.72	272.16	357.00	458.20	484.91	26.71	05.83
7.	भू-राजस्व (0029)	549.28	663.14	1,134.16	490.68	804.64	313.96	63.98
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (0045)	140.58	193.34	245.15	312.46	385.08	72.62	23.24
9.	होटल प्राप्तियाँ (0023)	20.91	20.94	25.44	30.46	34.95	4.49	14.74
	योग	28,658.97	33,877.60	41,355.00	52,613.41	58,098.36	5,484.95	10.43

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

² विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या-11, देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में वृद्धि लेखा शीर्षक 'अ- कर राजस्व' के अन्तर्गत-0020- निगम कर, 0021- निगम कर से निम्न आय पर कर, 0028- आय और व्यय पर अन्य कर, 0032- घन पर कर, 0037-सीमाकर, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क-राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.1.3 सारणी क्रमांक 1.3 वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

सारणी क्रमांक 1.3

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 पर 2012-13 में वृद्धि अथवा कमी (-)	2011-12 पर वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	विविध सामान्य सेवायें (0075)	1,698.79	8,075.13	5,120.67	4,035.23	4,494.11	458.88	11.37
2.	ब्याज प्राप्ति (0049)	963.87	603.66	689.32	789.22	1,186.41	397.19	50.33
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन (0406)	271.92	271.29	280.34	285.88	332.08	46.20	16.16
4.	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (0853)	427.31	604.97	653.39	593.28	722.13	128.85	21.72
5.	सहकारिता (0425)	26.46	16.39	9.38	9.78	11.99	2.21	22.60
6.	विद्युत्	2,499.74	3,203.40	3,711.37	3,484.40	5,535.76	2,051.36	58.87
7.	अन्य ³	878.46	826.25	711.74	947.51	687.50	(-)260.01	(-) 27.44
	योग	6,766.55	13,601.09	11,176.21	10,145.30	12,969.98	2,824.68	27.84

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता

वर्ष 2012-13 के लिये कर एवं करेतर राजस्व के मुख्य शीर्षों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता को सारणी क्रमांक 1.4 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 1.4

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य अथवा कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
क. कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर (0040)	38,492.18	34,870.16	(-) 3,622.02	(-)9.41
2.	राज्य आबकारी (0039)	10,068.28	9,782.49	(-) 285.79	(-) 2.84
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क (0030)	9,308.00	8,742.17	(-) 565.83	(-) 6.08
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,093.90	2,993.96	(-) 99.94	(-) 3.23
5.	विद्युत् पर कर एवं शुल्क (0043)	411.00	484.91	73.91	17.98
6.	भू-राजस्व (0029)	299.96	804.64	504.68	168.25
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (0045)	348.34	385.08	36.74	10.55
8.	होटल प्राप्ति (0023)	35.38	34.95	(-) 0.43	(-) 0.12
ख. करेतर राजस्व					
9.	विविध सामान्य सेवायें (0075)	3,264.23	4,494.11	1,229.88	37.68
10.	ब्याज प्राप्ति (0049)	924.36	1,186.42	262.06	28.35
11.	वानिकी एवं वन्य जीवन (0406)	353.93	332.08	(-) 21.85	(-) 6.17
12.	अलौह उत्खनन एवं धातुकर्म उद्योग (0853)	954.00	722.13	(-) 231.87	(-) 24.31
13.	सहकारिता (0425)	11.25	11.99	0.74	06.58

³ विविध में निम्नलिखित प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं: मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, अन्य प्रशासनिक सेवायें, पुलिस, फसल पालन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, सड़क एवं सेतु, लोक निर्माण आदि।

⁴ अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं: अन्य वित्तीय सेवायें, लाभांश एवं लाभ, लोक सेवा आयोग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं जल-मल निकासी, आवास, शहरी विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क, श्रम एवं रोजगार आदि।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता का विस्तार (-) 24.31 प्रतिशत एवं 168.25 प्रतिशत रहा।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत

मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में वर्ष 2012-13 के दौरान उनके संग्रह पर किये गये व्यय एवं सकल व्यय के सापेक्ष ऐसे व्यय की प्रतिशतता एवं वर्ष 2011-12 में संग्रह पर हुये व्यय की अखिल भारतीय प्रतिशतता का औसत सारणी क्रमांक 1.5 में उल्लिखित है:

सारणी क्रमांक 1.5

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता	2011-12 का अखिल भारतीय संग्रह की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,870.16	430.31	1.23	0.83
राज्य आबकारी	9,782.49	116.88	1.19	2.98
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	8,742.17	237.57	2.72	1.89
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	2,993.96	95.45	3.19	2.96

उपरोक्त सारणी यह इंगित करती है कि राजस्व शीर्ष "बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क एवं वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर" के अन्तर्गत संग्रह पर हुये व्यय की प्रतिशतता गत वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी। विभागों को इस मामले को देखने और संग्रह की अधिक लागत को कम करने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता है। हम "राज्य आबकारी" राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत गत वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से न्यून होने पर सराहना करते हैं।

1.4 पाँच वर्ष से अधिक बकाये का कुल राजस्व के बकाये के सन्दर्भ में विश्लेषण

विभागों⁵ द्वारा प्रतिवेदित कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों के बकाये की 31 मार्च 2013 तक की स्थिति ₹ 23,573.67 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 14,310.37 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक के थे, सारणी क्रमांक 1.6 में दर्शित है:

सारणी क्रमांक 1.6

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक के बकाये	31 मार्च 2013 तक पाँच वर्ष से अधिक पुराने बकाये
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,850.53	14,256.01
2.	राज्य आबकारी	54.06	48.51
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	586.67	उपलब्ध नहीं
4.	वाहनों पर कर	53.83	उपलब्ध नहीं
5.	मनोरंजन कर	28.58	5.85
	योग	23,573.67	14,310.37

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग एवं परिवहन विभाग के पास पाँच वर्षों से अधिक पुराने बकाये का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया सकल बकाये का 60.70 प्रतिशत था।

⁵ वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग

सारणी क्रमांक 1.11

विभाग का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	तय किये गये प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि जिनसे सम्बन्धित प्रस्तर तय किये गये
वाणिज्य कर	32	262	0.88	1995-96 से 2012-13 तक
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	24	06	0.02	2010-11
राज्य आबकारी	05	32	0.56	1996-97 से 1998-99 से 2002-03 एवं 2009-10 से 2012-13 तक
योग	61	300	1.46	

राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के प्रयासों की हम सराहना करते हैं।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के अतिरिक्त, नीचे दर्शाये गये विवरणानुसार मौके पर की गई वार्ता तथा विभागों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 11.12 करोड़ के 552 प्रस्तर निस्तारित किये गये जिनका ब्यौरा सारणी क्रमांक 1.12 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 1.12

विभाग का नाम	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	426	4.79
स्टाम्प एवं निबन्धन	30	0.24
राज्य आबकारी	73	5.32
परिवहन	05	0.13
भू-राजस्व	07	0.44
भू-तत्व एवं खनिकर्म	02	0.19
मनोरंजन कर	09	0.01
योग	552	11.12

अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के शीघ्र निस्तारण के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियाँ नियमित रूप से मिलें और निस्तारण के लिये लम्बित सभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.8 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर सभी विभागों को छः सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने के लिये वित्त विभाग ने निर्देश निर्गत किये थे। आलेख प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिये अनुरोध करते हुए महालेखाकार के माध्यम से हमने अर्द्ध शासकीय पत्र भेजे। विभाग से उत्तर न प्राप्त होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्तरों के अन्त में निश्चित रूप से दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में सम्मिलित 55 आलेख प्रस्तरों एवं एक समीक्षा (48 प्रस्तरों में समेकित एवं एक समीक्षा) को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से जुलाई 2013 में अग्रसारित किया गया था। सम्बन्धित विभागों के सचिवों ने समीक्षा एवं 53 आलेख प्रस्तरों के उत्तर भेजे, जबकि वाणिज्य कर विभाग के 2 आलेख प्रस्तरों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण – सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तारों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों, विभाग द्वारा स्वतः कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। पूर्व में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत, वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 169 प्रस्तारों/समीक्षाओं में से 87 आलेख प्रस्तारों/समीक्षाओं पर कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणी नवम्बर 2013 तक हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2007 के पश्चात् अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण सारणी क्रमांक 1.13 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.13

प्रतिवेदन का वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तारों/समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तारों/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं	प्रस्तारों/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं
2007-08	17 फरवरी 2009	16	14	2
2008-09	28 जनवरी 2010	13	9	4
2008-09 (राज्य आबकारी विभाग पर स्टैण्ड अलोन प्रतिवेदन)	5 अगस्त 2011	29	29	0
2009-10	08 अगस्त 2011	20	13	07
2010-11	30 मई 2012	35	17	18
2011-12	16 सितम्बर 2013	56	0	56
योग		169	82	87

कृत कार्यवाही की टिप्पणी/प्रतिवेदन भेजे जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान हैं कि इन्हें लोक लेखा समिति की बैठकों के छः माह के अन्दर सूचित किया जाना चाहिये। किन्तु, विभागों द्वारा अभी तक संसूचित नहीं किया गया है।

1.10 राज्य आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में, एक विभाग से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी समीक्षाओं तथा प्रस्तारों में उठाये गये मुख्य बिन्दुओं पर शासन/विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तारों 1.10.1 से 1.10.2 में राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित विगत छः वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामले एवं वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1.10.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले छः वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तारों और मार्च 2013 तक की उनकी स्थिति का विवरण सारणी क्रमांक 1.14 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.18

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेषणों की संख्या	निहित राजस्व की धनराशि	स्वीकृत धनराशि	की गई वसूली (31.12.2013 तक)
1.	वाणिज्य कर	2,578	11,022	2,084.95	17.93	2.48
2.	राज्य आबकारी	1,169	2,315	335.17	2.65	2.65
3.	परिवहन	347	2,034	694.75	10.13	10.13
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन	1,336	3,174	174.47	0.54	0.46
5.	भूतत्व एवं खनिकर्म	62	367	474.49	0	0
	योग	5,492	18,912	3,763.83	31.25	15.72

1.12.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क तथा कर एवं करेतर प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,285 इकाइयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में ₹ 2,045.28 करोड़ के अवनिर्धारण/ कर के कम आरोपण एवं अन्य कमियों के 6,373 मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 496 मामलों में ₹ 3.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये एवं 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ वसूल किये।

यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में "वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली" पर एक समीक्षा को मिलाकर 49 प्रस्तर हैं जो कर, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण, से सम्बन्धित हैं जिनमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 427.93 करोड़ है। शासन/विभागों ने ₹ 103.91 करोड़ की धनराशि की आपत्तियाँ स्वीकार की हैं, जिसमें से ₹ 2.05 करोड़ वसूल किये गये। शेष मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)। इन्हे मामलों की चर्चा अनुवर्ती अध्याय-II से VI में की गई है।

कार्यपालिका सारांश

इस अध्याय में हमने क्या मुख्यता से किया है

इस अध्याय में हमने "वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली" पर एक समीक्षा एवं \$149.94 करोड़ के निदर्शी मामले दर्शाये गये हैं। यह हमारे अभिलेखों की नमूना जाँच में पाए गए प्रेषणों से लिए गए हैं व वैट के कम आयेपण प्रवेश कर का कम/अनायेपण अर्थदण्ड के अनायेपण, धोखा प्रपत्तों पर अनियमितता के कारण कम करआयेपण एवं कर की दर के इतिर्पूर्व आयेपण से सम्बन्धित है।

कर संग्रहण में वृद्धि/कमी

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदियार् में ₹ 1762.82 करोड़ की वृद्धि (5.32 प्रतिशत) हुई विभाग की वार्षिक प्रदियार् बजट अनुमानों के विरुद्ध ₹ 3622.52 करोड़ (9.4 प्रतिशत) कम थी।

प्रवर्तन शाखा की कमजोर कार्य प्रणाली

विभाग की प्रवर्तन शाखा (प्र0शा0) में सचल दल (510द0) इकाइयों और विशेष अनुसंधान शाखा (वि0अनु0शा0) शामिल हैं। हमने प्र0शा0 की कार्यप्रणाली में अनेक कमियाँ देखीं, जो कि "वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली" की समीक्षा में चित्रित हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों 2012-13 के अनुपालन की स्थिति

हमने वर्ष 2012-13 के दौरान 616 वाणिज्य कर कार्यलिपियों में 1,17,213 मामलों में से 54,141 मामलों के कर निर्धारण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं गलत कर की दर और इतिर्पूर्व वर्गीकरण के कारण का अनायेपण/कम आयेपण, प्रवेश कर का अनायेपण/कम आयेपण इतिर्पूर्व कर मुक्ति आदि विभाग के ₹ 778.39 करोड़ के 3589 मामले पाये। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के ₹ 2.94 करोड़ के 438 मामले स्वीकार किए। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 316 मामलों में ₹ 89.26 लाख की वसुली की।

हमारा निष्कर्ष

विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली की सुधारण की आवश्यकता है जिससे हमारे द्वारा पायी गई कमियाँ एवं प्रणालीगत कमजोरियाँ से भविष्य में बचा जा सके।

हमारे द्वारा इंगित कर के अनायेपण/कम आयेपण, धोखा प्रपत्तों पर इतिर्पूर्व आयेपण आदि के मामलों पर, विशेषकर उन मामलों में, जिनमें हमारे प्रेषण की स्वीकार किया गया है की वसुली देवे तब तक कार्यवाही के पदल की भी आवश्यकता है।

अध्याय-II बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

व्यापार कर (व्या0क0) राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है (दिसम्बर 2007 के पश्चात इसे वाणिज्य कर के रूप में जाना गया) जो कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व (₹ 58,098.36 करोड़) के 60 प्रतिशत (₹ 34,870.16 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। वाणिज्य कर का आरोपण 31 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (उ0प्र0व्या0क0 अधि0) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम 2008 (उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम) 1 जनवरी 2008 से प्रभावी, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्रवेश कर का आरोपण उत्तर प्रदेश माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के प्रावधानों और तत्पश्चात बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के आरोपण का विनियमन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (के0बि0क0 अधि0) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) उत्तर प्रदेश में निहित है, जिनका मुख्यालय लखनऊ में है। उनकी सहायता 104 एडीशनल कमिश्नरों, 157 ज्वाण्ट कमिश्नरों, ज्वा0क0 494 डिप्टी कमिश्नरों (डि0क0) 964 असिस्टेन्ट कमिश्नरों एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारियों (वा0क0अ0) द्वारा की जाती है।

2.2 प्राप्तियों का रुझान

विगत वर्षों 2008-09 से 2012-13 की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ ही उसी अवधि में व्यापार कर/वैट की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण सारणी क्रमांक 2.1 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य (+) कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक व्या0क0/मू0सं0क0 का प्रतिशत
2008-09	19,705.00	17,482.05	(-) 2,222.95	(-) 11.28	28,658.97	61.00
2009-10	20,741.27	20,825.18	(+) 83.91	0.40	33,877.60	61.47
2010-11	26,978.34	24,836.52	(-) 2,141.82	(-) 7.94	41,355.00	60.06
2011-12	32,000.00	33,107.34	(+) 1,107.34	3.46	52,613.43	62.93
2012-13	38,492.18	34,870.16	(-) 3,622.02	(-) 9.41	58,098.36	60.02

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे।

2012-13 में बिक्री, व्यापार आदि से संग्रह में गत वर्ष की तुलना में 5.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर का विस्तार (-) 11.28 प्रतिशत एवं 3.46 के मध्य रहा।

विभाग ने बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता के विशिष्ट कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार बजट अनुमानों को यथार्थ बनाने का प्रयत्न करे जिससे अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता कम हो सकें।

2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को ₹ 22,850.53 करोड़ का राजस्व बकाया था, जिसमें से ₹ 14,256.01 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था। वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के लंबित राजस्व बकाए का विवरण सारणी क्रमांक 2.2 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का आरम्भिक रहतिया	बकाया का अंतिम रहतिया
2008-09	11,081.94	15,389.85
2009-10	15,389.85	16,453.30
2010-11	16,453.30	16,665.41
2011-12	16,665.41	18,960.28
2012-13	18,960.28	22,850.53

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

31 मार्च 2013 को बकाया ₹ 22,850.53 करोड़ के बारे में विभाग ने बताया कि ₹ 1,730.04 करोड़ के भू राजस्व के बकाए की वसूली के लिए प्रमाणित माँग पत्र निर्गत किए गए, ₹ 4,566.12 करोड़ न्यायालय एवं शासन द्वारा स्थगित किए गए थे, ₹ 489.86 करोड़ की बकाया की वसूली सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी विभागों से थी। ₹ 1,166.26 करोड़ की वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों से सम्बन्धित थे, राज्य के ट्रान्सपोर्टर्स पर ₹ 51.78 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र थे, ₹ 1579.44 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित है। ₹ 13,267.03 करोड़ के शेष बकाए के मामले में की गई विनिर्दिष्ट कार्रवाई के बारे में विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।

2.4 प्रति व्यापारी बिक्री, व्यापार आदि पर कर की लागत

प्रति व्यापारी वैट पर वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान आयी लागत का विवरण सारणी क्रमांक 2.3 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.3

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रति व्यापारी लागत (₹ में)
2010-11	5,94,695	24,836.52	391.45	6,582.37
2011-12	6,42,645	33,107.34	440.89	6,860.55
2012-13	7,08,636	34,870.16	416.18	5,872.97

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

2.5 कर निर्धारण हेतु बकाए मामले

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 3 के अनुसार कर निर्धारण के लिए समय सीमा कर अवधि समाप्त होने के बाद से तीन वर्ष की अवधि तक है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, अतिरिक्त मामले जो कि वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त हुए, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण सारणी क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक रहतिया	कर निर्धारण हेतु प्राप्त मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले	कालम 4 के सापेक्ष कॉलम 6 का प्रतिशत
2008-09	9,38,667	5,33,358	14,72,025	9,50,313	5,21,712	35.44
2009-10	5,21,712	1,83,378	7,05,090	6,92,704	12,386	1.76
2010-11	12,386	5,44,458	5,56,844	5,50,802	6,042	1.09
2011-12	6,042	6,54,378	6,60,420	4,76,368	1,84,052	27.87
2012-13	1,84,052	4,58,225	6,42,277	4,95,505	1,46,772	22.85

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कर निर्धारण हेतु बकाये मामलों का प्रतिशत 1.09 से 35.44 के मध्य है।

विभाग द्वारा बकाए मामलों का कर निर्धारण निर्धारित समय में किया जाना चाहिए।

2.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर से सकल संग्रह, संग्रह पर किए गए व्यय और ऐसे व्यय की सकल संग्रह पर प्रतिशतता सकल संग्रह पर किए गए व्यय के सुसंगत पिछले वर्ष की सुसंगत अखिल भारतीय प्रतिशतता को सारणी क्रमांक 2.5 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर संग्रह की लागत की प्रतिशतता	पिछले वर्ष की अखिल भारतीय प्रतिशतता
2008-09	17,482.05	272.54	1.56	0.83
2009-10	20,825.18	358.43	1.72	0.88
2010-11	24,836.52	406.65	1.64	0.96
2011-12	33,107.34	440.89	1.33	0.75
2012-13	34,870.16	430.31	1.23	0.83

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से अधिक है।

हम शासन से संग्रह लागत कम करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने की संस्तुति करते हैं।

2.7 लेखा परीक्षा के प्रभाव

2.7.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007-08 से 2011-12) के अनुपालन की स्थिति:

हमने वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में प्रतिवेदनों के माध्यम से कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, कर का कम आरोपण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, टर्नओवर का छिपाव, कर की गलत दर का लागू किया जाना, गणना की त्रुटि आदि के ₹ 1,560.51 करोड़ के 10,987 मामलों को इंगित किया। इनमें से विभाग/शासन ने 1,843 मामलों में ₹ 17.93 करोड़ की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था तथा अब तक 732 मामलों में ₹ 2.48 करोड़ की वसूली हो चुकी थी। विवरण सारणी क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत घनराशि		स्वीकार की गई घनराशि		वसूल की गई घनराशि	
		मामलों की संख्या	घनराशि	मामलों की संख्या	घनराशि	मामलों की संख्या	घनराशि
2007-08	489	1,210	1,191.14	124	0.51	114	0.46
2008-09	591	1,967	64.65	202	5.60	128	0.68
2009-10	685	2,711	77.32	559	7.13	112	0.36
2010-11	892	2,648	94.73	436	1.63	148	0.53
2011-12	615	2,451	132.67	522	3.06	230	0.45
योग	3,272	10,987	1,560.51	1,843	17.93	732	2.48

2.7.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13):

वर्ष 2012-13 के दौरान 616 वाणिज्य कर कार्यालयों के कर निर्धारण और अन्य अभिलेखों के 1,17,213 मामलों में से 54,141 मामलों की नमूना जाँच में कर का अनारोपण/कम आरोपण और अन्य अनियमताओं के ₹ 778.39 करोड़ के 3,589

मामले पाए गए, जो निम्नखिलित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं और जिन्हें सारणी क्रमांक 2.7 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.7

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली (एक समीक्षा)	1	73.20
2.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण कम आरोपण	711	75.47
3.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	334	54.67
4.	अनियमित कर मुक्ति का दिया जाना	326	18.45
5.	माल की दर का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	301	8.50
6.	माल का गलत वर्गीकरण	4	0.08
7.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएँ	56	3.21
8.	गणना की त्रुटि	14	16.96
9.	टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना	11	0.09
10.	अन्य अनियमितताएँ	1,831	527.76
	योग	3,589	778.39

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 438 मामलों में ₹ 2.94 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 8,000 का एक मामला वर्ष 2012-13 में इंगित किया गया था तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 316 मामलों में ₹ 89.26 लाख की वसूली की।

“वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली” पर एक समीक्षा एवं कुछ निदर्शी मामले जिनमें कि ₹ 149.94 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है, अनुवर्ती प्रस्तारों में वर्णित हैं।

2.8 वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली

प्रमुख अंश

- वर्ष 2009 से कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ करने के बावजूद नीतियाँ, नियम एवं कार्यविधियाँ अभी तक विकसित की जा रही हैं। परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रण के साधन अपर्याप्त हैं तथा आपदा प्रबन्धन (डिसास्टर मैनेजमेन्ट) एवं सतत कार्य-योजना का अभाव है।
- प्रान्त से होकर गुजरने वाले कर योग्य माल के पारगमन सम्बन्धी जाँच/सूचना तकनीक के अभाव के फलस्वरूप अधिग्रहण के मामलों की संख्या क्रमशः 14632 से घटकर 30 तथा आच्छादित धनराशि ₹ 557.67 करोड़ से घटकर ₹ 1.53 करोड़ रह गयी।
- फार्म-38 (आयात हेतु घोषणा पत्र) को संव्यवहार का विवरण भरे बिना आनलाइन डाउनलोड करने के प्रावधान से राजस्व क्षति का जोखिम बना। **(प्रस्तर 2.8.7.5)**
- अपर्याप्त जनशक्ति, असंचालित नियन्त्रण कक्ष एवं उपकरणों की अनुपलब्धता प्रवर्तन शाखा में सचल दल इकाईयों के दुर्बल संचालन का कारण रही। **(प्रस्तर 2.8.7.6)**
- सचल दल इकाईयाँ वर्ष में 23 दिनों से 287 दिनों तक असंचालित रहें जिसके परिणामस्वरूप माल के अनधिकृत परिवहन की जाँच नहीं की जा सकी। **(प्रस्तर 2.8.8, 2.8.8.2)**
- अधिनियम का उल्लंघन करके परिपत्र निर्गत किये जाने के परिणाम स्वरूप ₹ 32.37 करोड़ की जमानत राशि कम वसूल हुई। **(प्रस्तर 2.8.8.1)**
- पंजीकृत व्यापारियों से सम्बन्धित अभिग्रहण के मामलों की निगरानी की कमी के फलस्वरूप ₹ 39.64 करोड़ की जमानत राशि कम वसूल हुई। **(प्रस्तर 2.8.8.4)**
- पंजीकृत व्यापारियों से सम्बन्धित अभिग्रहण के मामलों की निगरानी की कमी के फलस्वरूप ₹ 39.64 करोड़ की जमानत राशि कम वसूल हुई। **(प्रस्तर 2.8.8.5)**

2.8.1 प्रस्तावना

वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की शक्तियाँ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-13 ए, 28, 28 'ए', 28 'बी' सपठित व्यापार कर नियमावली के नियम 83 और नियम 87 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (20प्र0 वैट) 2008 की धारा 45 से 52 तक तथा सपठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 52 से 59 तक में दिये गये प्रावधानों से संचालित होती हैं। चेक पोस्ट (अगस्त 2008 से अगस्त-2009 के मध्य समाप्त), सचल दल (स0द0) इकाई एवं विशेष अनुसंधान शाखा (वि0अनु0शा0) प्रवर्तन शाखा के अंग हैं जो कि करापवंचन को रोकने के लिए कार्य करती हैं।

प्रदेश की सीमाओं से लगे महत्वपूर्ण स्थानों पर 83 जाँच चौकियाँ माल के प्रान्त बाहर से परिवहन की जाँच के लिए उत्तरदायी थीं। सचल दलों की तैनाती माल के परिवहन के दौरान करापवंचन को रोकने के लिए की गयी है।

छियालीस वि0अनु0शा0 इकाईयों की स्थापना करापवंचन के मामलों की जाँच हेतु की गयी थी। यह वि0अनु0शा0 इकाईयाँ अपने क्षेत्र में कर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण वस्तुओं

- प्रवर्तन शाखा में जनशक्ति का उपयोग।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।
- प्रवर्तन शाखा में कम्प्यूटरीकरण का प्रभाव।
- प्रभावकारिता।
- करप्रवर्तन योजना में वि0अनु0शा10 एवं संवल दल इकाईयों की दक्षता एवं प्रे।
- समय-समय पर निर्मित परिपत्रों का अनुपालन अनुकूल ढंग से किया गया था।
- अधिनियम के प्राधान्यों, विज्ञापितियों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा समीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण की गई थी कि क्या :

2.8.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

(आइ0टी0), एक अक्षिकमि0 (आइ0टी0) एवं सहस्रक कर्मा सहस्रक प्रदान करते हैं। मुख्यतः स्तर पर पर 10 कमी0 (आइ0टी0) के अधीन है जिन्हें एक डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा10) की प्रतिवेदित करती है। विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी (आइ0टी0) शाखा के अधीन कार्यरत है। संवल दल इकाईयों सम्बन्धित विभाग के 10 कमी0 उन्हें सहस्रक प्रदान करते हैं। कुल 144 संवल दल इकाईयों अक्षिकमि0 (संवल दल) होते हैं तथा अक्षिकमि0 (अक्षिकमि0) एवं वार्षिक कर अक्षिकमि0 (व0क0अ0) करते हैं। विभाग स्तर पर डिप्टी कमिश्नर (वि0कमि0) (वि0अनु0शा10) इकाई के प्रभाषी (वि0अनु0शा10) द्वारा की जाती है। उद्देश्य सहस्रक प्रदान प्रवर्तन शाखा की गतिविधियों का नियंत्रण/निगरानी एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा10) एवं उद्देश्य कमिश्नर (स0द0) इनके सहस्रक है। फील्ड में जोन स्तर पर कमिश्नर, वार्षिक कर द्वारा की जाती है। उद्देश्य कमिश्नर (व010 कमी0) में विभाजित है। मुख्यतः स्तर पर प्रवर्तन शाखा की कार्यवाही की निगरानी एडिशनल उद्देश्य से विभाग की 20 जोनों में विभाजित किया गया है। पुनः ये जोन 45 संभागों में विभाजित हैं। प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्यों के कुशल निष्पादन के से नियंत्रण एवं निर्देशन का दायित्व, कमिश्नर-वार्षिक कर, में निहित है जिसका मनोरजन कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। वार्षिक कर विभाग का सम्पूर्ण रूप शासन स्तर पर नीति निर्धारण, निगरानी एवं नियंत्रण प्रमुख संविद, वार्षिक कर एवं

2.8.2 सांगठनात्मक ढांचा

कमियां उजागर हुईं। अधिनियम, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों में जिसमें बेट प्रणाली के पश्चात्, जिसमें जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात् एवं बेट इमने "वार्षिक कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली" पर एक समीक्षा की संकाईयों की संख्या 55 से बढ़ाकर 150 कर दी गयी।
 रोकथाम हेतु संवल दल इकाईयों ही एक मात्र साधन है। जून 2008 में संवलदल अभिलेखों के प्रान्त के अन्दर एवं प्रान्त बाहर से माल के संचालन से करप्रवर्तन की समाप्त कर दी गयी। जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात् माल के बिना उचित द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान दी बरगी में सभी 83 जांच चौकियां उत्तर प्रदेश में बेट अधिनियम दिनांक 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया। शासन स्थलों/गाँवों की जांच करना है।
 आवश्यकतानुसार गोपनीय सर्वेक्षण एवं व्यापारियों/दैनिकियों के व्यापार उत्तरदायी है। विशेष अनुसंधान शाखाओं का कार्य करप्रवर्तन की रोकथाम हेतु न्यायालयों के निर्णयों की माल ब्याख्या, कर का भुगतान न किया जाना आदि के लिये प्रणाली जैसे- अनियमित प्रान्तीय एवं अन्तर्प्रान्तीय बिक्री, स्टाक ट्रान्सफर, माननीय के सख्त में सूचना एकत्र करने, व्यापारियों द्वारा कर अपवर्तन हेतु अपनायी गयी कार्य

2.8.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

समीक्षा के विषय हेतु लेखा परीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से व्युत्पन्न किये गये:

- उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 एवं उनके अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ
- वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी प्रवर्तन मैनुअल
- शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत विज्ञप्तियाँ एवं परिपत्र।

2.8.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

हमने अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के मध्य समीक्षा सम्पादित की एवं वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि आच्छादित की। लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र विभाग की प्रवर्तन शाखा के अभिलेखों की जांच तक सीमित था। हमने कमिश्नर वाणिज्य कर, 35 सचल दल⁴ इकाइयों एवं 14 जोनों⁵ से सम्बन्धित 19 डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0)⁶ कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की।

जिन जोनों में उक्त सचल दल इकाइयां कार्यरत थीं, उनसे सम्बन्धित डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) का चयन भी लेखापरीक्षा हेतु किया गया। इसके अतिरिक्त 17 सचल दल इकाइयों⁷ एवं 3 वि0अनु0शा0 जोनों⁸ से हमने वर्ष 2008-09 से 2011-12 अवधि की सूचनाएं एकत्र कीं। नवम्बर 2012 में विभाग के साथ प्रारम्भिक विचार गोष्ठी आयोजित की गयी थी जिसमें विभाग को लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्य पद्धति से भिन्न कराया गया। समीक्षा के परिणाम विभाग एवं शासन को जुलाई 2013 में अग्रेषित किये गये थे। समापन विचारगोष्ठी सितम्बर 2013 में आयोजित की गयी जिसमें एडीशनल कमिश्नर ने विभाग का तथा सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर ने शासन का प्रतिनिधित्व किया। विभाग/शासन के प्रत्युत्तरों को सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित कर लिया गया है।

2.8.6 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाओं तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए हम वाणिज्य कर विभाग का आभार प्रकट करते हैं।

लेखापरीक्षा के परिणाम

2.8.7 सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

विभाग द्वारा पारगमन घोषणापत्रों (टी.डी.एफ.)⁹ एवं फार्म-38¹⁰ के क्रमशः व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा आनलाइन डाउनलोड करने की पद्धति (जुलाई 2009 एवं सितम्बर 2009) आरम्भ की गयी।

⁴ असि0कमि0 (स0द0-2) आगरा, असि0कमि0(स0द0 1 एवं 2) बरेली, असि0कमि0 (स0दल) बुलन्दशहर, असि0कमि0 (स0द0 1,4,5 एवं 6) गौतमबुद्धनगर, असि0कमि0, (स0द0 1,2,3 एवं 4) गाजियाबाद, असि0कमि0(स0द0 2 एवं 3) गोरखपुर, असि0कमि0 (स0द0 1 एवं 2) झांसी, असि0कमि0 (स0द0 1,2 एवं 3) कानपुर, असि0कमि0 (स0द0 1), लखनऊ, असि0कमि0(स0द0 1 एवं 4) मथुरा, असि0कमि0 (स0द0 2,4, एवं 5) मेरठ, असि0कमि0 (स0द0 2,3 एवं 5) मुरादाबाद, असि0कमि0 (स0द0 1,3 एवं 4) सहारनपुर असि0कमि0 (स0द0) मुगलसराय स्थित वाराणसी असि0कमि0 स0द0 चंदौली स्थित वाराणसी, असि0कमि0 (स0द0-2) नौबतपुर-चंदौली स्थित वाराणसी, असि0कमि0 (स0द0-4) वाराणसी।

⁵ आगरा, अलीगढ़, बरेली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी कानपुर-1 एवं 2, लखनऊ-1 मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी-1

⁶ डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी आगरा, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी बरेली, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी गोरखपुर, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग- झांसी, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए, सी एवं डी कानपुर, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग- मथुरा, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी मेरठ, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी मुरादाबाद, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी सहारनपुर, डि0कमि0(वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी वाराणसी।

⁷ असि0कमि0(स0द0) 1,3,4,5,6,7 एवं 8 आगरा, असि0कमि0(स0द0) 9,10,11 एवं 12 कानपुर, असि0कमि0(स0द0) 2,3,4, एवं 5 लखनऊ, असि0कमि0(स0द0) 2 एवं 3 मथुरा।

⁸ गाजियाबाद-2, लखनऊ-2, वाराणसी-2।

⁹ टी.डी.एफ.ऐसे वाहन के ड्राइवर अथवा स्वामी द्वारा वाहन में लदे माल का विवरण भरकर साथ रखे जाने वाला अभिलेख है जो प्रान्त बाहर से उत्तर प्रदेश में होते हुए अन्य प्रान्त को जाना हो। यह इस बात के प्रमाणस्वरूप होता है कि वाहन में लदा माल उ.प्र. में बिक्री के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। आनलाइन डाउनलोडिंग परिपत्र सं. चेक पोस्ट/528/वाणिज्य कर दिनांक 27 जुलाई 2009 से आरम्भ हुई।

¹⁰ फार्म-38 एक आयात घोषणा पत्र है जो कि पंजीकृत व्यापारियों द्वारा बिक्री हेतु प्रान्त बाहर से माल मंगते समय वाहन के साथ लेकर चलना होता है। आनलाइन डाउनलोडिंग परिपत्र सं. चेक पोस्ट- फार्म-38 व्यवस्था/0910045/वाणिज्य कर, दिनांक 28 अगस्त, 2009 द्वारा सितम्बर 2009 में आरम्भ की गयी।

तथा आई.टी.कॉलेज की विद्यमानता एवं पर्याप्तता की जांच हेतु किया गया।
 कराये जा सकें। इनका विवरण आई.टी.सप्ट सिस्टम की एवं प्रभावकारिता
 द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2010 से 16 दिसम्बर 2012 अवधि तक के ही आंकड़े उपलब्ध
 एनालिसिस) की सहायता से टी.डी.एफ. के डाटाबेक का विवरण किया गया। विभाग
 द्वारा कम्प्यूटर पर आडिटिंग टूल आडिटिंग (इन्स्टीट्यूट जटा परकसट्रूक्चरन एण्ड
 आंकड़ों की शुद्धता, पूर्णता एवं समकता (इन्स्टीट्यूट) की जांच के उद्देश्य से लेखापरीक्षा
 एम.आई.एस. हेतु मुख्यालय पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

हे, टी.डी.एफ. का रखा गया जटा विवरणनीय है तथा केंद्रीकृत जटा का प्रभावकारी
 नीति विद्यमान है, प्रणाली की आवश्यकता अनुसार विविधियां (एस.आर.एस.) अमिनिस्ट्रि
 प्रौद्योगिकी का शैल एवं
 विभाग में संचालन
 लिए किया कि क्या
 यह सुनिश्चित करने के
 प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
 के डाटाबेक की संचालन
 डाउनलोड टी.डी.एफ.
 निर्गत/

हमने
 आदेशक है।
 प्रौद्योगिकी नीति का होना
 अमिनिस्ट्रि संचालन
 के लिए एक संचालन एवं
 अनुपालन सुनिश्चित करने
 एवं समयबद्धता का
 संचालन प्रौद्योगिकी होने
 कार्य योजना के संचालन
 विरोधी निर्णयों से बचने,
 अंशगत एवं परस्पर

सर्वर से जुड़े हैं।
 की (64 के.बी.पी.एस.) लीजल लाइन द्वारा केंद्रीय
 प्रिया नैतक है तथा वे कम्प्यूटर कार्यालय में वाइड
 विभागीय कार्यालयों का अपना स्वयं का लोकल
 डाटाबेस मैनजमेंट सिस्टम से युक्त था। सभी
 बैंक एंड में आरकेल आर.डी.पी.एम. (रिलेशनल
 साफ्टवेयर फ्रंट एंड में जाबा सर्वर वर्गों से युक्त एवं
 विकसित किया गया। एन.आई.पी. द्वारा विकसित
 आनलाइन ड्यू/डाउनलोडिंग हेतु साफ्टवेयर
 बहरी/ट्रान्जिट विवरणन फर्म (टी.डी.एफ.) के
 प्रदेश होते हुए अन्य प्रान्त को माल ले जाने के लिए
 एन.आई.पी. लखनऊ द्वारा प्रान्त बाहर से उत्तर
 सक्षमता के उद्देश्य से बेहतर निर्णय लेने के लिये
 तब (एम.आई.एस.) उपलब्ध करने एवं सूचकीय
 वहलर राजस्व संवर्ण के लिए सुदृढ़ प्रबन्धन संचालन
 ललित निर्णय लेने, कयापवर्धन वोकन एवं परिणामतः

2.8.7.1 टी.डी.एफ. डाटाबेक की संचालन प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा निष्पादित की। हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं :
 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था, हमने टी.डी.एफ. सिस्टम की संचालन प्रौद्योगिकी
 क्योंकि जाँच चौकियों के कार्यों का भाग विभाग के कम्प्यूटराइज्ड आनलाइन सिस्टम
 आपदा प्रबन्धन योजना।

स्थिति में भी सिस्टम का 24x365 दिवस निरंतर संचालन सुनिश्चित करने हेतु
 (ii) लक्ष्य अवधि तक विद्यमान आर्पित बाधा, बाढ़, भूकम्प, वायुस हमला आदि की

उपस्था।
 सॉफ्टवेयर विकास जैसे-मानकीकरण एवं गणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) की
 (i) एल्कीकेशन के प्रयोग हेतु तैयार होने पर किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच एवं

सीमा के अनुसार निम्नलिखित कार्य दिसम्बर 2010 तक पूर्ण किये जाने थे :
 सरकार द्वारा पत्र दिनांक जून, 2010 द्वारा समयावधि में निश्चित की गयी थी तथा
 कन्ड (एन.आई.पी.) के सहयोग से आरम्भ किया गया। उक्त को पूर्ण करने हेतु भारत
 करने के लिए कम्प्यूटरीकरण का कार्य निम्न मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राष्ट्रीय संचालन
 वेब अधिनियम के अनुसार (1 जनवरी, 2008 से प्रभावी) संचालन प्रौद्योगिकी को प्रारम्भ

हमने पाया कि विभाग द्वारा आई.टी.सिस्टम के कार्यान्वयन, सुरक्षा, परिवर्तन प्रबन्धन-नियन्त्रण (यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी उत्पाद के सम्बन्ध में परिवर्तन नियंत्रित एवं समन्वित रूप में लागू किये जाते हैं), बैकअप डाटा का भण्डारण, आपदा निवारण एवं सतत कार्य योजना हेतु नीतियां निर्धारित नहीं की गयी थी। इन बिन्दुओं की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया (सितम्बर, 2013) कि विभाग की आई.टी.पद्धति के आलोक में नीतियां एवं कार्यात्मक ढांचा (फ्रेमवर्क) विकसित किये जा रहे हैं।

उत्तर से पुष्टि होती है कि नीतियां, नियम एवं कार्यविधि विकसित नहीं थे और अभी तक विकास की अवस्था में हैं।

2.8.7.2 आपदा प्रबन्धन एवं सतत कार्य योजना

हमने देखा कि आपदा के तत्काल बाद की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा दर्शाते हुए (ताकि आँकड़ों के प्रसंस्करण (प्रसैसिंग) की कार्यवाही तत्काल पुनः आरम्भ की जा सके), कोई आपदा निवारण एवं सतत कार्य योजना ही नहीं थी। डाटाबेस बैकअप का रखरखाव एन.आई.सी. द्वारा वृद्धि के (इन्क्रीमेंटल) आधार पर किया जाता है जबकि प्राकृतिक अथवा तकनीकी आपदा की स्थिति में डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण डाटाबेस का बैक-अप विभागीय भवन से इतर किसी अन्यत्र स्थान पर भी रखा जाना चाहिये। मुख्य संरूपण (कनफिगरेशन) उपकरणों जैसे-हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कार्मिक एवं अन्य सम्पत्तियां जो आपदा की स्थिति में आई.टी.कार्यों की निरन्तरता हेतु आवश्यक थे, की पहचान करके उन्हें अभिलेखीय रूप में नहीं रखा गया था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2013) कि डाटा बैकअप योजना भवन स्थित एन.आई.सी. के स्टेट डाटा केन्द्र में टेप-ड्राइव एवं हार्डडिस्क में रखा जा रहा है। आपदा-प्रबन्धन योजना एवं कार्यविधि विकसित किये जा रहे हैं।

उक्त से यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण किये जाने वाले आपदा प्रबन्धन योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

हम संस्तुति करते हैं कि आपदा प्रबन्धन एवं सतत कार्य योजना को स्थापित किया जाय।

2.8.7.3 इनपुट एवं वैलीडेशन नियन्त्रण

इनपुट नियन्त्रणों को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सिस्टम में फीड किये गये डाटा पूर्ण, विशुद्ध एवं निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं। यह आँकड़ों की संगतता के मुद्दे को भी इंगित करता है। सिस्टम का डिजाइन एवं संचालन फीडेड डाटा से विशिष्ट आँकड़ों को अलग करने हेतु पर्याप्त होना चाहिये। इनपुट नियन्त्रण एवं निष्कपटता (वैलीडेशन) जांच में कमी की स्थिति में ट्रांजिट पास के निर्गमन में त्रुटियां होने एवं सम्बन्धित डाटा भण्डार नकली आँकड़ों पर आधारित होने की संभावना रहती है।

डाटाबेस की शुद्धता, पूर्णता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डाटा एन्ट्री के दौरान सभी सभावित एप्लीकेशन कन्ट्रोल लागू किये गये हों। यह नियन्त्रण सुनिश्चित करते हैं कि प्रसैसिंग हेतु प्राप्त डाटा विशुद्ध, पूर्ण, वैध, सही तथा अधिकृत है एवं डाटा हस्तान्तरण बिना फील्ड्स के दोहराव के उचित प्रकार से किया गया है तथा सिस्टम में डाटा एन्ट्री के समय सभी फील्ड सही प्रकार से भर दिये गये हैं।

सिस्टम की संरचना एवं संचालन इनपुट से आँकड़ों को पकड़ने हेतु पर्याप्त होना चाहिए। इनपुट एवं नियन्त्रण जांच में वैलीडेशन जांच में कमी की स्थिति में ट्रांजिट पास के निर्गमन तथा सम्बन्धित डाटाबैक में त्रुटियां होने की संभावना रहती है।

हमने दिनांक 11 फरवरी 2010 से 16 दिसम्बर 2012 के दौरान

निकाले/डाउनलोड किये

₹ 98,11,54,740.90 करोड़ धनराशि से

आच्छादित 1,04,62,126 ट्रांजिट पासों की जांच की और पाया कि डाउनलोडेड ट्रांजिट पासों की संख्या फरवरी 2010 की 4,726 की संख्या के सापेक्ष बढ़कर मार्च 2012 में 4,10,189 हो गयी।

टी.डी.एफ. के डाटाबैंक की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 6,50,971 मामलों में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रविष्टियां जैसे- माल का विवरण, वजन एवं इकाई, स्वामी का नाम, प्रस्थान का प्रान्त, गन्तव्य प्रान्त आदि रिक्त थीं। पुनः अनेक मामलों में माल का मूल्य, बिल्टी नम्बर, बिल नम्बर, आदि में 'शून्य' अंकित किया गया था। विवरण सारणी क्रमांक 2.8 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.8

क्र.सं.	फील्ड	फील्ड विवरण खाली/शून्य	मामलों की संख्या
1	चेसिस नम्बर	खाली	6662
2	प्रस्थान का प्रान्त		5748
3	माल का विवरण		32490
4	गन्तव्य प्रान्त		35976
5	इंजिन नम्बर		6661
6	स्वामी		6023
7	माल की मात्रा एवं संख्या		36006
8	ट्रान्सपोर्टर का नाम		18997
9	माल का मूल्य	शून्य	70878
10	बिल्टी नम्बर		371154
11	बिलों की संख्या		60376

हमारे द्वारा डाटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि आगे फील्ड्स में असत्य/अवास्तविक आंकड़े भरे गये थे जैसा कि सारणी क्रमांक 2.9 में अंकित है।

सारणी क्रमांक 2.9

क्र.सं.	फील्ड	फील्ड का विवरण	मामलों की संख्या
1	प्रवेश एवं निकास का दिनांक	सही प्रारूप ¹² में उपलब्ध नहीं	19,400
2	निकास का दिनांक	प्रवेश के दिनांक से भी पहले ¹³ की भरी हुई	35
3	निकास का दिनांक	निकास का दिनांक प्रवेश के दिनांक से चार दिन से भी कम के थे	38,60,760
4	वाहन संख्या एवं ट्रान्सपोर्टर	एक ही दिन में एक ही वाहन के लिए कई टी.डी.एफ. डाउनलोड करना	7,93,593

समापन गोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) विभाग ने बताया कि वेबसाइट सीक्योरिटी आडिट के बाद गलत दिनांक फार्मेट के सम्बन्ध में साफ्टवेयर में संशोधन एवं त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। विभाग ने आगे बताया कि एक्सेल टेबिल फार्मेट में डाटा कन्वर्जन के फलस्वरूप डाटा की तिथि में बदलाव हो सकता है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परिणाम "आईडीया"¹⁴ द्वारा निकाले गये हैं और फील्ड में कोई कन्वर्जन नहीं है क्योंकि "आईडीया" साफ्टवेयर बिना किसी डाटा कन्वर्जन के डाटाबैंक का विश्लेषण करता है।

चार दिन से कम अवधि के लिए तथा एक दिवस में एक ही वाहन के लिए कई ट्रांजिट पास डाउनलोड किये जाने के सम्बन्ध में विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर वाहन पांच से छः घण्टे में पुनः माल को लादकर आ सकते हैं। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि उक्त क्रमांक 3 एवं 4 पर दिये गये मामलों में गन्तव्य स्थान 390 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था जहां से एक अथवा दो दिवस में वापसी यात्रा सम्भव नहीं थी।

¹² प्रदेश में प्रवेश एवं प्रदेश से निकास का दिनांक डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई के प्रारूप में अर्थात् 02/11/2012 होना चाहिये।

¹³ कोई भी वाहन प्रदेश में प्रवेश से पूर्व नहीं निकल सकता जैसे- प्रवेश तिथि 17.04.2010 जबकि निकास तिथि 11.04.2010 अतः प्रवेश का दिनांक निकास से पूर्व ही होना चाहिए।

¹⁴ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रीय आडिट टूल।

2.8.7.4 ऑनलाइन टी.डी.एफ. सिस्टम की दुर्बलताएँ

व्यापार कर अधिनियम की धारा 28 एवं वाणिज्य कर अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में माल के अनियमित आयात एवं उसको लेखों में दर्ज न करने, कर के अपवचन को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाली सीमाओं पर महत्वपूर्ण स्थानों पर जाँच चौकियाँ स्थापित की गयी थीं। जाँच-चौकियाँ निम्न के लिए उत्तरदायी थीं:

- आयात घोषणा पत्रों (फार्म-38) की जांच एवं पृष्ठांकित करके, कर योग्य माल के अनधिकृत प्रवेश को रोकना।
- प्रान्त बाहर से माल लेकर उत्तर प्रदेश में होते हुए अन्य प्रान्त को माल लेकर जाने वाले ट्रान्सपोर्टर/वाहन स्वामियों को ट्रान्जिट पास (बहती) जारी करना।
- निकास जांच चौकी पर ट्रान्जिट पास खारिज करना।

1 जनवरी 2008 से उ0प्र0 वेट अधिनियम लागू किया गया। उस समय पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थानों पर 83 जाँच चौकियाँ कार्यरत थीं। 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान सभी जाँच चौकियाँ दो चरणों- 46 जाँच चौकियाँ¹⁵ जून 2008 में तथा 37 जाँच चौकियाँ¹⁶ जुलाई 2009 में समाप्त कर दी गयीं।

व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर द्वारा ट्रान्जिट डिक्लरेशन फार्म (टी.डी.एफ.) एवं आयात क्रमशः वैकल्पिक व्यवस्था क्रमशः 19 बिन्दुओं पर वाछित सूचना भरने सहित टी.डी.एफ. आनलाइन जारी प्रदेश से होकर निकलने के लिए मान्य था और यह माना जाया कि इस अवधि के बाहर निकल जायेगा। 46 जाँच चौकियों की समाप्ति एवं आनलाइन टी.डी.एफ. डाउनलोड करने की पद्धति लागू करने के मध्य 12 माह का अन्तराल था। इस अन्तराल की अवधि के दौरान उन क्षेत्रों के मार्ग जिनमें जांच चौकियाँ समाप्त कर दी गयी थीं, किसी टी.डी.एफ. से आच्छादित नहीं थे।

हमने देखा कि स0द0इकाई/जोन/मुख्यालय स्तर पर डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ.के विश्लेषण/अनुश्रवण हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी थी। पुनः ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लागू नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य प्रान्त के गन्तव्य हेतु आया माल वास्तव में प्रदेश से बाहर चला गया है। हमने यह भी पाया कि यद्यपि टी.डी.एफ. चार दिन के लिए मान्य है किन्तु इस तथ्य के बावजूद कि प्रवेश एवं निकास के स्थानों के मध्य की दूरी के

घोषणापत्र (फार्म-38) के आनलाइन डाउनलोडिंग की वैकल्पिक व्यवस्था क्रमशः जुलाई¹⁷ 2009 एवं सितम्बर¹⁸ 2009 में प्रारम्भ की गयी। नयी पद्धति में 19 बिन्दुओं पर सूचना¹⁹ वाहन इंचार्ज/ट्रान्सपोर्टर द्वारा आनलाइन भरनी होती है। वाछित सूचना भरने के पश्चात 14 अंकों की स्वउत्पादित आई.डी.संख्या सहित टी.डी.एफ. आनलाइन जारी होता है। इस टी.डी.एफ. की प्रति लेकर वाहन इंचार्ज प्रदेश से होकर निकलने के लिए अनुमत्य था। टी.डी.एफ. प्रवेश की तिथि से चार दिनों के लिए मान्य था और यह माना जाता था कि इस अवधि के अन्दर वाहन उत्तर प्रदेश के बाहर निकल जायेगा। 46 जाँच चौकियों की समाप्ति एवं आनलाइन टी.डी.एफ. डाउनलोड करने की पद्धति लागू करने के मध्य 12 माह का अन्तराल था। इस अन्तराल की अवधि के दौरान उन क्षेत्रों के मार्ग जिनमें जांच चौकियाँ समाप्त कर दी गयी थीं, किसी टी.डी.एफ. से आच्छादित नहीं थे।

15 अछनेरा, अम्बपुर, अम्बावाय, भगवन्पुरा, बांगरा, बिन्वमगंज, बादशाहीबाग, भोपुरा, भोयापुर, बखली, बानिया, देवरी मारवाणीपुर, डूंगरवाला, दुमवाडी, डी-एल बीराह, गोवर्धन, हथिनीकुण्ड, इन्दुपुरी, झुपा, ग्राम खुन्वा, कहरौरा, कोडली बाग, कुलेशपुर, कुआगाव, महाराजपुर, मकनपुर, महरीना, मोरख, मसवारी चौराहा, माधवटाण्डा, नगलाबीच (नन्दगांव), नरमन नगला, नरेनी चौराहा, पनवाडी, रेना नगर, रायपुरी, रामपुर बुजुर्ग, साहिबाबाद (कडकड़ पुल), समर, सौंद्य शमसाबाद, सीतापुर, सुआंवाला (धुगपुरी), टी.पी.नगर, टीलकोठी, विप्रावली।

16 अमरिया, आमटाडा, ओडमोड, बारा, बमनी, गायवाला, भरौली, मुराहडी ग्राम, बडकाला, बडनी, चौखटा, झमण्ड गंज, फतेहपुर सीकरी, गौरीकन्टा, गौरीपुर, हरौनगर, आई.डी.नोएडा, केरना, कौडिया, कौरलगांव, कोडावन, लोनी, मझोला, मसौरा, मोहननगर (मोहननगर एक्स्टेंशन सहित), मुगरी, नीबतपुर, रक्सा, रूपईरिया, सेंग, शाहजहांपुर, श्रीनगर, सोनीकी, लमकुइरगंज, वाकूरदाग, उररी, विजयनगर।

17 परिपत्र सं.- बैंक पोस्ट/528/वाणिज्य कर दिनांक 27 जुलाई 2009।

18 परिपत्र सं.- चौक पोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था/0910045/वाणिज्य कर दिनांक 28 अगस्त 2009।

19 (i) वाहन के प्रस्थान का स्थान (ii) गन्तव्य का स्थान (iii) वाहन नम्बर (iv) डेस्टिंस नम्बर (v) इजिन नम्बर (vi) ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता (vii) वर्तमान पता जैसे कि वाहन की इश्योरेंस पालिसी में दिया गया हो (viii) वाहन स्वामी का नाम व पता (ix) प्रदेश के अन्दर मार्ग का विवरण (x) प्रदेश में प्रवेश का सम्भावित दिनांक (xi) प्रदेश से निकास का सम्भावित दिनांक (xii) विक्टियों की कुल संख्या (xiii) बिलों की कुल संख्या (xv) ननों की कुल संख्या (xv) माल का मूल्य (शब्दों में) (xvi) माल का मूल्य (शब्दों में) (xvii) माल का विवरण (xviii) माल का वजन (xix) प्रिंटिंग (स्वर का आई.पी.एड्रेस)।

दृष्टिगत (जहां एक ही दिन में कई फेरे संभव न हों) एक ही दिन में एक ही वाहन हेतु कई ट्रांजिट पासों का निर्गमन रोकने हेतु सिस्टम में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं था।

राजस्व हित के दृष्टिगत ट्रांजिट पासों (टी.डी.एफ.) का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हमने वर्ष 2010 से 2012 के मध्य डाउनलोड किये गये 1,04,62,126 ट्रांजिट पासों में से 99,000 के आंकड़ों की नमूना जाँच एवं विश्लेषण किया और पाया कि:

- 3,605 व्यापारियों ने अपना माल सड़क मार्ग से एक प्रान्त से अन्य प्रान्त को वाया उत्तर प्रदेश 44,318 टी.डी.एफ. के द्वारा प्रेषित किया। यह हमारे द्वारा विश्लेषण किये गये 99,000 टी.डी.एफ. का 44.77 प्रतिशत थे। उक्त में एक ही वाहन के द्वारा समान प्रेषण के लिए उत्तर प्रदेश में समान मार्ग एवं उन्हीं प्रवेश तथा निकास मार्गों से होते हुए डाउनलोड की जाने वाली टी.डी.एफ. की संख्या पाँच से 569 तक थी। जबकि एक प्रान्त से अन्य प्रान्त में क्रेता को माल सुपुर्द करने तक पूर्ण यात्रा हेतु मात्र एक ट्रांजिट पास ही आवश्यक होता है। हमने देखा कि इस तथ्य के बावजूद कि यह घटनाक्रम वर्ष 2010 से 2012-13 तक निरन्तर जारी था तथा 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 (मई 2012 तक) के दौरान क्रमशः 425,486 एवं 36 ट्रांजिट पास डाउनलोड किये गये, किन्तु विभाग द्वारा इस विसंगति की जाँच नहीं की गयी।
- 3,605 व्यापारियों में से 27 व्यापारियों ने ₹ 133.60 करोड़ मूल्य के माल का प्रेषण एक प्रान्त से अन्य प्रान्त को 911 ट्रांजिट पास डाउनलोड करते हुए घोषित किया। हमने देखा कि इनमें से प्रत्येक वाहन द्वारा प्रथम टी.डी.एफ. दूसरी टी.डी.एफ. में दर्शायी गयी प्रवेश तिथि से एक या दो दिन पहले डाउनलोड की गयी थी। यह भी देखा गया कि यात्रा प्रारम्भ एवं गन्तव्य²⁰ स्थान के मध्य दूरी इतनी अधिक थी कि जाने एवं वापसी की दूरी एक अथवा दो दिन में तय नहीं की जा सकती है। स्पष्टतः एक या दो दिन बाद डाउनलोड की गयी द्वितीय टी.डी.एफ. का भौतिक रूप से उचित उपयोग सम्भव नहीं है।
पाँच व्यापारियों ने अपने माल के परिवहन हेतु 15 वाहनों के लिए बहुसंख्या में टी.डी.एफ. डाउनलोड की। यह टी.डी.एफ. एक ही दिनांक को समान वाहन के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों से माल का लदान करके भिन्न प्रान्तों के अलग-अलग प्रवेश एवं निकास के स्थानों से होते हुए जाने के लिए डाउनलोड की गयी थीं। जबकि एक वाहन किसी प्रान्त में एक स्थान से किसी अन्य प्रान्त में विशिष्ट स्थान पर सुपुर्दगी हेतु उत्तर प्रदेश में एक ही प्रवेश एवं निकास के स्थान से होते हुए, प्रस्थान के लिए ही लोड किया जा सकता है।
- यह भी उजागर हुआ कि दो ट्रान्सपोर्टर्स ने एक ही वाहन हेतु समान प्रवेश एवं निकास की तिथियों के लिए बहुसंख्या में ट्रांजिट पास (टी.डी.एफ.) डाउनलोड किये। यह क्रिया 12 ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा अपनायी गयी।
- हमने यह भी देखा कि विभाग की आई.टी.शाखा द्वारा राजस्व के हित में उक्त को दूढ़ निकालने एवं सचल दलों तथा वि०अनु०शाखाओं को, विश्लेषण एवं वांछित कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।
- हमने विभाग की सूचना प्रबन्धन तंत्र वेबसाइट के प्रतिसत्यापन में पाया कि टी.डी.एफ. का डाटा वेबसाइट पर आटोमैटिकली अपडेट न होकर दिन में मैन्यूअली दो बार²¹ अपलोड किया जाता था। केवल दिन में दो बार टी.डी.एफ. के डाटा की अपलोडिंग के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्रों जैसे— आगरा, बुलन्दशहर,

²⁰ उदाहरणतः— अहमदाबाद (गुजरात) से विराट नगर (नेपाल), अलरसा (गुजरात) से धूलिया (प०बंगाल), भिवांडी (महाराष्ट्र) से काठमाण्डू (नेपाल), इन्दौर (म०प्र०) से दलसिंह सराय (बिहार), लुधियाना (पंजाब) से कटक (उड़ीसा), परवानू (हि०प्र०) से पटना (बिहार), पटना (बिहार) से पुणे (महाराष्ट्र) एवं सतना (म०प्र०) से गिरीडीह (झारखण्ड)।

²¹ 07.54 पूर्वाह्न एवं 01.54 अपराह्न।

हमने "प्रान्त से होकर गजरने वाले प्रेषण वास्तव में प्रान्त से निकल गये हैं", हेतु विमानीय तन्त्र में विकसित प्रणाली की अनुपलब्धता के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि मात्र छः जौनी 2007-08 से 2008-09 के मध्य निकास यौकिया पर बरती खरिज न कराने के 14632 मामले थे जिनसे आच्छादित माल का मूल्य ₹ 4448.60 करोड़ था। उ0प्र0व्यापार कर एवं वेट अधिनियम के प्रावधानानुसार उक्त मामलों में ₹ 557.67 करोड़ कर आर्योपित किया गया। 2008-09 (जुलाई 08 से आगे) से 2011-12 के मध्य अक्षय / डी.डी.एफ. से अनाच्छादित पकड़े गये मामलों की संख्या घटकर मात्र 30 रहे गयी जिसमें आच्छादित माल एवं कर प्रभाव क्रमशः ₹ 1.53 करोड़ एवं ₹ 1.04 करोड़ था जो कि सारणी क्रमांक 2.10 में दर्शाया गया है।

विज्ञापित संख्या-कॉन्सि-2-1980/XI दिनांक 27 अगस्त 2009 द्वारा

विज्ञापित संख्या-कॉन्सि-2-241/XI दिनांक 4 फरवरी 2010 द्वारा

दिया गया।

21/2009 दिनांक 27 अगस्त 2009 द्वारा समाप्त कर प्रावधान विज्ञापित संख्या 1230(2)/79-V-1-09-1 को करने की शक्ति प्राप्त थी जिन्हें वह उचित समझे। यह को ऐसे स्थानों पर जांच यौकी अथवा बैरियर स्थापित उ0प्र0 वेट अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत शासन जाये।

या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो कमिश्नर के सामान्य गजरता है जो अपने साथ ऐसे अभिलेख रखेगा तथा इंटरव्यू या वाहन का इंजाल जब उत्तर प्रदेश से होकर लाकर, अन्य प्रान्त में गन्तव्य को ले जाने के लिए की उपधारा (1) में सन्दर्भित माल को एक प्रान्त से 52 तथा नियम 58 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 50 उ0प्र0व्यापार कर नियम 87 तथा उ0प्र0वेट की धारा 28बी एवं उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 28बी एवं

अभाव

2.8.7.5 प्रान्त से कर योग्य माल के ट्रांजिटिंग हेतु उचित आस्थापन प्रणाली का

जाने का जोखिम बना रहता है। कर्पावधान के उद्देश्य से प्रदेश में प्रवेश किये हुए वाहन के माल खाली कर वापस जांच में आ जावे अन्यथा डी.डी.एफ. का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के पूर्व ही सत्यापन की पद्धति भी तभी कारण है जबकि वाहन संचालकों द्वारा की जा रही वाहनों से प्रतिस्व्यापित ही कराया गया। पुनः एस.एम.एस. द्वारा डी.डी.एफ. के निकल जाने की संभावना से बचने के लिये, संचालक द्वारा पकड़े गये गये मामलों की जांच एवं विश्लेषण नहीं किया गया और न वाहनों के बिना जांच किये हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा हमारे द्वारा इंतजाल किये गए डी एस.एम.एस. के माध्यम से भी डी.डी.एफ. का सत्यापन किया जा सकता है। वरुवार विमानीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा स्थल डी.डी.एफ. की रिपोर्ट वाहनवार, प्रान्तवार, दिनांकवार, प्रवेश एवं निकास बिन्दुवार तथा द्वारा उन्हें रोलबैक एवं सकलित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। लाउन्लीड की गयी पर उपलब्ध है तथा विमानीय अधिकारियों को आवृत्तित गजर आई.डी. एवं पासवर्ड के समस्त आनलाइन एप्लीकेशंस से संबंधित सूचना प्रबन्धन रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट समाप्त गीठी के दौरान (दिसम्बर 2013) विभाग ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित फील्ड की प्रवर्तन इंकाइरियां द्वारा भी स्वीकार किये गये।

ऐसे वाहनों की जांच कर उन्हे पकड़ने में असमर्थता फलित होती है। यह तथ्य वाहनों के माल खाली कर वापस निकल जाने का जोखिम तथा प्रवर्तन शाखा द्वारा गजियाबाद, झांसी, मथुरा आदि की संचालक दल इंकाइरियां के प्राधिकार क्षेत्र से

सारणी क्रमांक 2.10

(₹ लाख में)

खारिज न करायी गयी टी.डी.एफ.							
जाँच चौकियों की समाप्ति के पूर्व अवधि: 2007-08 से 2008-09				सचल दल इकाईयों द्वारा पकड़े गये मामले जुलाई 2008 से 2011-12			
क्र०सं०	जोन	खारिज न करायी गयी बहतियों की संख्या	कुल धनराशि	कर की राशि जो जमा नहीं की गयी	अवैध/बिना टी.डी.एफ. के मामले	कुल धनराशि	कर की राशि जो जमा नहीं की गयी
1	आगरा	शून्य	शून्य	0.43	शून्य	शून्य	शून्य
2	अलीगढ़	11,003	3,932.53	1,730.31	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3	झांसी	575	3,321.13	985.37	18	93.31	79.65
4	कानपुर-II	शून्य	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	सहारनपुर	3,049	4,37,564.09	53,050.7	12	60.07	24.02
6	वाराणसी-I	05	41.77	0	0	0	0
	योग	14,632	4,44,859.52	55,766.81	30	153.38	103.67

नोट : अनुपलब्ध = उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त से यह स्पष्ट है कि सचल दल इकाईयों, जाँच चौकियों का पूर्ण विकल्प नहीं थी। यह प्रान्त में माल की अवैध अनलोडिंग के मामलों को रोकने में उतनी प्रभावी नहीं हो पायीं।

जाँच चौकियों द्वारा 2007-08 से 2008-09 तक मैनुअली जारी की गयी बहतियों एवं 2009-10 से 2011-12 के बीच डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. के आंकड़े सारणी क्रमांक 2.11 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.11

वर्ष	जारी बहतियों/ टी.डी.एफ. का माध्यम	जारी बहतियों/ टी.डी.एफ. की संख्या	वृद्धि/कमी	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2006-07	मैनुअली	17,99,323	-	-
2007-08	मैनुअली	20,10,480	2,11,517	11.76
2008-09	मैनुअली	19,74,896	(-) 35,944	(-) 01.79
2009-10 (सितम्बर 2009 से मार्च 2010)	आनलाइन	21,68,181	1,93,285	09.79*
2010-11	आनलाइन	37,19,217	17,44,321	88.32
2011-12	आनलाइन	42,90,260	5,71,043	15.35

नोट: अप्रैल 2009 से अगस्त 2009 की अवधि में मैनुअली जारी बहतियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

* यह वृद्धि मात्र सात माह की अवधि में थी।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 से 2008-09 के दौरान जब मैनुअली बहती निर्गत की जाती थी तो वृद्धि 11.76 प्रतिशत थी। यहां तक कि 1.79 प्रतिशत की कमी आयी। आनलाइन टी.डी.एफ. जारी की पद्धति आरम्भ करने पर (दिनांक 01 सितम्बर 2009 से) मात्र छः माह की अवधि में 9.79 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। यहां तक कि वर्ष 2010-11 में इसमें 88.32 प्रतिशत का उछाल आया। जबकि फार्म²³ 38 की डाउनलोडिंग में कोई विशेष वृद्धि नहीं देखी गयी जो कि सारणी क्रमांक 2.12 से स्पष्ट है:

सारणी क्रमांक 2.12

(संख्या लाख में)

वर्ष	फार्म 31/38 की संख्या (उपे/मैनुअली निर्गत)	वर्ष	फार्म 38 की संख्या मैनुअली निर्गत एवं व्यापारियों द्वारा डाउनलोडेड
2006-07	7.50	2009-10	48.31
2007-08	43.80	2010-11	18.48
2008-09	34.05	2011-12	37.65
योग	85.35	योग	104.44

टी.डी.एफ.की संख्या में असामान्य वृद्धि पड़ोसी राज्यों में व्यापारियों की संख्या में हुई वृद्धि से भी समर्थित नहीं है। हमने आगे पाया कि व्यापार कर अधिनियम²⁴ के अन्तर्गत जारी मैनुअल के प्रावधानानुसार बहतियों की संख्या में असामान्य वृद्धि/कमी के

²³ आयात हेतु घोषणापत्र- फार्म-31 एवं फार्म-38 क्रमशः उ०प्र०व्यापार कर अधिनियम की धारा 28 ए (1), उ०प्र०व्यापार कर नियम 1948 के नियम 83 (4)(ए) (i) एवं उ०प्र०वैट अधिनियम की धारा 50 तथा उ०प्र०वैट नियम 2008 के नियम 54 (3) में यथापरिभाषित फार्म जिसमें प्रान्त में आयातित, कर योग्य माल का नाम, मूल्य, परिमाण आदि घोषित किया जाता है।

²⁴ उ०प्र०व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर, व्यापार कर के प्राधिकार से जारी "व्यापार कर सहायता केन्द्र/सचल दल मैनुअल" के अध्याय 2 के उप प्रस्तर 11 (1) 3 के अनुसार।

विश्लेषण हेतु डिप्टी कमिश्नर (जांच चौकी) उत्तरदायी थे, किन्तु वेट के अन्तर्गत निर्गत मैनुअल में ऐसा कोई समतुल्य प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने अन्य प्रान्तों में टी.डी.एफ. के डाटा की जांच की पद्धति का अध्ययन किया और पाया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखण्ड और असम राज्यों में जांच-चौकियां अभी भी अस्तित्व में हैं। बिहार में, जहां जांच चौकियां नहीं थीं, यह पद्धति जून 2011 से प्रारम्भ की गयी है। कर्नाटक में टी.डी.एफ. के सत्यापन की विशिष्ट पद्धति 1 जुलाई 2011 से प्रारम्भ की गयी है।

समापन विचारगोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) शासन ने स्वीकार किया कि टी.डी.एफ. पद्धति में खामियां करपवंचन का कारण रहीं और बताया कि टी.डी.एफ. की आड़ में सुनियोजित ढंग से किये जा रहे करपवंचन को रोकने के लिए विभाग द्वारा 03 सितम्बर²⁵ 2013 को नयी व्यवस्था लागू की गयी है।

हम यह संस्तुति करते हैं कि विभाग प्रान्त में नियत प्रावधानों का स्वेच्छिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश एवं निकास के स्थानों पर व्यापारियों की सुविधा के लिए सूचनाओं के संग्रहण हेतु तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक प्रान्त से अन्य प्रान्त में गन्तव्य हेतु वाहन पर लादा गया माल वास्तव में उत्तर प्रदेश से निकल गया है तथा कर अपवंचन पर रोक लगेगी।

2.8.7.6 संव्यवहार का विवरण आनलाइन भरे बिना फार्म-38 (आयात हेतु घोषणापत्र) डाउनलोड किया जाना।

उ0प्र0वेट अधिनियम की धारा 50 तथा उ0प्र0वेट नियमवली 2008 के नियम 54(1) के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी जो प्रान्त बाहर से प्रदेश के अन्दर ऐसी मात्रा, माप अथवा मूल्य का कर योग्य माल जैसा कि इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाये, लाने/आयात करने का इच्छुक हो तो यथाविहित रीति से कर-निर्धारण अधिकारी से निर्धारित आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) प्राप्त करेगा अथवा यथाविहित रीति से विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करेगा।

06 जुलाई 2009 की बैठक में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि फार्म डाउनलोडिंग के पूर्व संव्यवहार का विवरण आनलाइन भरना व्यापारी के लिये अनिवार्य होगा।

फार्म-38 आनलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा 01 सितम्बर 2009 से प्रारम्भ की गयी। तदनुसार अर्ह व्यापारी डाउनलोडिंग का दिनांक एवं फर्म का विवरण भरकर आनलाइन फार्म-38 डाउनलोड कर सकता है। फार्म-38 को डाउनलोडिंग की दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रयोग किया जा सकता है। फार्म-38 के प्रयोग का विवरण उपभोग किये जाने के सात दिन के अन्दर आनलाइन देना होगा।

हमने देखा कि शासन²⁶ द्वारा लिए गये निर्णयानुसार संव्यवहार का विवरण जैसे-वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता भरना अनिवार्य था, तो भी कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा जारी परिपत्र²⁷ में यह कहा गया कि व्यापारी केवल स्वयं का विवरण जैसे-डाउनलोडिंग का दिनांक, निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम तथा स्वयं व्यापारी का नाम एवं पता भरकर फार्म-38 डाउनलोड किया जा सकता है। व्यापारी को शेष संव्यवहार का विवरण जैसे- वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता फार्म-38 के प्रयोग की

²⁵ परिपत्र सं0- सचल दल-टैजिट पास-2013-14/1341/1314041 दिनांक 3.09.2013।

²⁶ बैठक दिनांक 06 जुलाई 2009।

²⁷ परिपत्र सं0- चेक पोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था/0910045/वाणिज्य कर दिनांक 28 अगस्त 2009।

सूचना उसे तीन माह के भीतर प्रयोग करने के सात दिन के अन्दर आनलाइन उपभोक्ता (यूटीलाईजेशन) प्रपत्र भरते समय देने की सुविधा प्रदान की गयी। इस प्रकार संव्यवहार का विवरण विभाग को प्रतिसत्यापन हेतु फार्म-38 डाउनलोडिंग के तीन माह एवं सात दिन के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा। कमिश्नर, वाणिज्य कर का अगस्त, 2009 का परिपत्र, शासन द्वारा जुलाई 2009 में लिए गये निर्णय से भिन्न था। अनिवार्य प्रविष्टियों जैसे- वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता न भरने के फलस्वरूप तीन माह सात दिन की अवधि में एक ही फार्म का कई बार प्रिन्ट लेकर प्रयोग करने का जोखिम उत्पन्न हो गया।

जब जाँच चौकियाँ अस्तित्व में थीं तो फार्म-38 जांच चौकी पर प्रान्त में प्रवेश के समय पृष्ठांकित किया जाता था। यह पृष्ठांकन उसी फार्म के दुबारा प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाता था। डाउनलोड किये जाने वाले फार्म-38 की अनिवार्य प्रविष्टियों को न भरने सम्बन्धी नियन्त्रण की यह कमी स्पष्टतः लेखाओं से बाहर माल को प्रान्त में विक्रय हेतु लाने तथा अन्ततोगत्वा विभाग/शासन को राजस्व क्षति का जोखिम उत्पन्न करती है।

डाउनलोड किये गये फार्मों के प्रयोग की सूचना प्रयोग के सात दिन के अन्दर आनलाइन देनी थी। हमने यह भी पाया कि डाउनलोड किये गये फार्मों में से 15.33 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के उपभोग की सूचना दी ही नहीं गयी थी। विवरण सारणी क्रमांक 2.13 में दिये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.13

वर्ष	डाउनलोड किये गये फार्म-38 की कुल संख्या	प्रस्तुत उपभोग	अन्तर
2009-10	46,533	शून्य	46,533
2010-11	18,48,298	15,60,832	2,87,466
2011-12	37,64,719	31,87,381	5,77,338
2012-13	44,96,865	36,41,038	8,55,827

विभाग ने उत्तर में बताया (मई 2013) कि सिस्टम लागू करने के पूर्व कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के सिस्टम का अध्ययन किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि गुजरात तथा कर्नाटक की प्रणाली भिन्न है एवं परिवहन किये जा रहे माल के संव्यवहार का पूर्ण विवरण उसके परिवहन के पूर्व भरा जाना अनिवार्य है साथ ही उसका सत्यापन जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। क्योंकि प्रान्त में जाँच चौकियाँ विद्यमान नहीं हैं, फार्म-38 के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कड़े एप्लीकेशन नियन्त्रण की आवश्यकता है।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग शासन द्वारा जुलाई 2009 में फार्म-38 की डाउनलोडिंग पर लिए गये निर्णय के अनुक्रम में संव्यवहार के विवरण को अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान बनाने पर विचार कर सकता है।

2.8.7.7 बार-बार पकड़े जाने वाले अपराधियों की पहचान एवं अपंजीकृत व्यापारियों को पकड़ना

उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सपठित धारा-3 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी जिसका वार्षिक कर योग्य व्यापारावर्त ₹ पांच लाख है, कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा तथा विहित प्रारूप एवं रीति से, निर्धारित पंजीयन प्रभारी द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 54 (1)(7) के प्रावधानान्तर्गत यदि पंजीयन हेतु दायी व्यापारी बिना पंजीयन प्राप्त किये व्यापार करता है तो व्यापार की गयी अवधि में ₹ 100 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड के भुगतान का दायी होगा।

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के कर प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार ने पत्र संख्या- एफ नं0

एस-31013/2/2010-एस.ओ./ (एस.टी.), दिनांक 24 जून 2010 द्वारा मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए ₹ 58.40 करोड़ लागत की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि यह सुनिश्चित कर लिया

जाये कि महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में वाणिज्य कर विभाग द्वारा आवश्यक साफ्टवेयरों का निर्माण नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्कारपोरेट (निक्सी)के सहयोग से कराया गया।

हमने विभाग की कम्प्यूटरीकरण कार्यवाही का अध्ययन किया और पाया कि विभाग की प्रवर्तन शाखा के कार्यों से सम्बन्धित कोई भी विशिष्ट माड्यूल²⁸ विकसित नहीं किया गया था। हमने 25 सचल दल इकाइयों के अभिलेखों की जांच की और देखा कि 151 अपजीकृत व्यापारी जो कि ₹ पांच लाख से अधिक मूल्य का कसयोग्य माल ले जाते हुए पकड़े गये थे, का विवरण वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में सचल दल इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख पंजी²⁹ -5 में दर्ज था। यद्यपि वांछित जमानत/अर्थदण्ड/कर ₹ 6.54 करोड़ की उनसे वसूली की गयी थी किन्तु ऐसी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वही व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर एक वर्ष के दौरान एक या अधिक बार पकड़े गये थे। हमने यह भी पाया कि 1946 मामलों³⁰ में से 123 मामले ऐसे थे जिनमें वाहन एक से अधिक बार पकड़े गये थे, उनसे आच्छादित माल का मूल्य ₹ 4.35 करोड़ था तथा ₹ 1.41 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया गया था किन्तु बार-बार अपराध करने वालों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु सूचना संकलित करने की कोई युक्ति विद्यमान नहीं थी। यदि साफ्टवेयर में ऐसा कोई माड्यूल विकसित किया गया होता तो विभाग को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी जा सकती थी।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग ऐसे प्रवर्तन साफ्टवेयर माड्यूल के निर्माण पर विचार कर सकता है जिससे ₹ पांच लाख एवं अधिक के प्रेषण पर करापवंचन करते हुए पकड़े जाने वाले व्यापारियों की पहचान की जा सके तथा उसमें बार बार अपराध करने वाले व्यापारियों की पहचान तथा आंकड़े रखने का भी प्रावधान हो। इस प्रकार के व्यापारियों के पंजीयन एवं न्यूनतम अर्थदण्ड के प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए।

2.8.8 सचल दल इकाइयों की कार्यप्रणाली

उत्तर प्रदेश के अन्दर एवं उत्तर प्रदेश से होते हुए निर्धारित प्रपत्रों³¹/सूचना से अनाच्छादित एवं अपंजीकृत से सम्बन्धित माल के परिवहन के दौरान करापवंचन को रोकने के लिए सचल दल इकाइयों की स्थापना की गयी है। असिस्टेन्ट कमिश्नर (स0द0) अपनी सचल दल इकाइयों के प्रभारी होते हैं। उनका मुख्य उत्तरदायित्व उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 45, 46, 47, 48, 50, 51 एवं 52 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाहनों के द्वारा परिवहन किये जा रहे तथा ट्रान्सपोर्टों के गोदामों में रखे हुए माल की जांच करना है। उनका अन्य उत्तरदायित्व बिलों का संकलन (संवेदनशील वस्तुओं एवं प्रमुख निर्माताओं के बिक्री के बिलों के संकलन को प्राथमिकता देते हुए) करना है। उनका कार्य प्रान्त के अन्दर फर्जी प्रपत्रों के आधार पर माल के परिवहन, रेल एवं सड़क मार्ग से आयातित माल के सन्दर्भ में हो रहे करापवंचन पर प्रभावी ढंग से जांच कार्यवाही कर अंकुश लगाना है। सचल दल इकाइयों का कार्य निर्धारित प्रपत्रों से अनाच्छादित माल का अभिग्रहण, परिवहन किये जा रहे कर योग्य माल के मूल्य का आंकलन एवं माल अवमुक्त किये जाने के पूर्व निर्धारित अर्थदण्ड का आरोपण/जमानत राशि³² की वसूली करना है।

हमने कमिश्नर, वाणिज्य कर के अभिलेखों³³ की नमूना जांच की और पाया कि जून 2008 से पूर्व जब 83 जांच चौकियां अस्तित्व में थीं, मानकों के अनुसार 267 असिस्टेन्ट

28 माड्यूल-टी.डी.एफ. माड्यूल, ई-पेमेंट माड्यूल, ई-रिटर्न माड्यूल, ई-पंजीयन माड्यूल, ई-फार्म माड्यूल (फार्म-38 आदि के लिए), आनलाइन एम.आई.एस.माड्यूल एवं आनलाइन जी.आर.सी. (कीवॉल रीड्रैवल सेल) माड्यूल।

29 पंजी-5-एक रजिस्टर जिसमें वाहन संख्या, ट्रान्सपोर्टर का नाम व पता, वस्तु का नाम, माल का अनुमानित मूल्य तथा आरोपित अर्थदण्ड/जमानत का विवरण दर्ज किया जाता है।

30 जहां पकड़े गये माल का मूल्य ₹ दो लाख से अधिक था।

31 इनवायस/बालान की प्रति, टी.डी.एफ./फार्म-31/फार्म-38, व्यापारी का नाम, माल का मूल्य, वजन, माप अथवा संख्या आदि।

32 उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 48 (6) के अन्तर्गत निर्धारित।

33 प्रवर्तन मैनुअल एवं विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन।

34 उ0प्र0शासन के आदेश संख्या-विज्ञापित संख्या-क0नि0-4-1080/11-2008-400 (65)/91 दिनांक 10 जून 2008 एवं क0नि0-4-1459/11-2009-400 (137)/2001 टी.सी.-5 दिनांक 30 जुलाई 2009 द्वारा जांच चौकियां समाप्त की गयीं।

कमिश्नर तथा 422 वाणिज्य कर अधिकारी जांच चौकियों³⁵ पर तैनात किये जाने थे। जांच-चौकियों की समाप्ति के पश्चात प्रवर्तन कार्यों को सृष्ट करने के लिए सचल दल इकाइयों की संख्या 55 से बढ़ाकर 150 करते हुए 95 नयी सचल इकाइयां स्वीकृत³⁶ की गयीं। वर्ष 2012-13 के दौरान 144 सचल दल इकाइयां (मुख्यालय पर दो इकाइयां नियन्त्रण कक्ष हेतु सहित) संचालित थीं। एक सचल दल इकाई हेतु स्वीकृत जनशक्ति:- एक असि0कमि0, दो वा0क0अधि0 एवं अन्य (चालक, लिपिक आदि) पांच है।

हमने देखा कि जांच चौकियों की समाप्ति के पूर्व तथा बाद में प्रवर्तन कार्यों हेतु स्वीकृत कार्मिकों की संख्या में अन्तर है। यह दर्शाता है कि मुख्य प्रवर्तन शाखा हेतु कार्मिकों का नियोजन अनुकूलतम नहीं था। समाप्त की गयी जांच चौकियों³⁷ के शेष अधिकारी/कर्मचारी प्रवर्तन कार्यों पर नहीं लगाये गये थे। विवरण सारणी क्रमांक 2.14 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.14

विवरण	जांच चौकियों की समाप्ति के पूर्व स्वीकृत जनशक्ति			जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात सचल दल इकाइयों हेतु स्वीकृत जनशक्ति	अन्तर
	जांच चौकियों हेतु	सचल दल इकाइयों हेतु	योग		
असि0कमि0	267	55	322	150	172
वा0कर अधि0	422	110	532	300	232
अन्य	559	275	834	750	84

जांच चौकियों तथा सचल दल इकाइयों द्वारा पकड़े गये वाहनों की संख्या तथा अर्थदण्ड/जमानत के रूप में वसूले गये राजस्व का विवरण सारणी क्रमांक 2.15 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.15

(₹ लाख में)

वर्ष	जांच चौकियों			सचल दल इकाइयों			वर्ष के दौरान पकड़े गये वाहनों की सं०		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
	जांच चौकियों की सं०	पकड़े गये वाहनों की सं०	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	सचल दल इकाइयों की सं०	पकड़े गये वाहनों की सं०	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	संख्या	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	
2007-08	83	5,84,282	14,988.01	55	20,817	6,480.79	6,05,109	21,468.80	(+) 8.35
2008-09 (अप्रैल 08 से जुलाई 08)	83	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध		अनुपलब्ध
2008-09 (अगस्त 08 से मार्च 09)	37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3,242.39	अनुपलब्ध	3,242.39	अनुपलब्ध
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य	136	15,990	6,859.15	15,990	6,859.15	(-) 68.05
2010-11	शून्य	शून्य	शून्य	136	21,693	9,079.67	21,693	9,079.67	(-) 57.70
2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	136	21,446	11,294.50	21,446	11,294.50	(-) 47.39

* वर्ष 2008-09 के लिए जो आंकड़े विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये।
अनुपलब्ध = विभाग के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं।

उक्त से दृष्टव्य है कि :

- वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान सचल दल इकाइयों की संख्या में वर्ष 2007-08 की तुलना में 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वास्तव में राजस्व वसूली में 47.39 से 68.05 प्रतिशत की कमी आयी।
- वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान (सचल दल इकाइयों की संख्या में वृद्धि के बावजूद) पकड़े गये वाहनों की संख्या लगभग समान रही। यह इंगित करता है कि सचल दल इकाइयां जांच-चौकियों का पूर्ण विकल्प नहीं थीं।

समापन गोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) शासन ने बताया कि जांच-चौकियों के समय एक निरन्तर जांच की व्यवस्था थी, अतः अधिक जनशक्ति लगायी गयी थी। जांच-चौकियों की समाप्ति के उपरान्त सचल दल प्रणाली में आकस्मिक जांच की व्यवस्था है अतः कार्मिक आवश्यकतानुसार लगाये गये।

³⁵ बिक्री कर जांच चौकी/सचल दल मैनुअल के अध्याय (3)(3) में निर्धारित मानकों के अनुसार जांच चौकियों पर कार्मिक तैनात किये जाते थे।

³⁶ विज्ञापित संख्या-क0मि0-4-1080/11-2008-400(35)/91 दिनांक 10 जून 2008 द्वारा।

³⁷ जांच चौकियों की संख्या 83, असिस्टेन्ट कमिश्नर 267 एवं वाणिज्य कर अधिकारी 422।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि आकस्मिक जांच प्रणाली में भी कार्मिकों की पाली (शिफ्ट) में तैनाती आवश्यक होती है जिससे कि आकस्मिकता बनी रहे। सचल दल इकाईयों की स्वीकृत जनशक्ति एक पाली के आधार पर निर्धारित की गयी है। इस प्रकार सचल दल इकाईयां चौबीस घण्टे में केवल एक पाली के दौरान कार्य करती हैं जो कि जांच चौकियों की अपर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था का द्योतक है।

2.8.8.1 सचल दल इकाईयों की संचालनात्मक कमियां

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत सचल दल इकाईयां प्रदेश के अन्दर समुचित प्रपत्रों से अनाच्छादित माल के परिवहन की जांच हेतु उत्तरदायी हैं। सचल दल के कार्य व उत्तरदायित्व विभाग के प्रवर्तन मैनुअल में उल्लिखित किये गये हैं। सचल दलों की स्थापना वैध प्रपत्रों आदि से अनाच्छादित माल के परिवहन के दौरान किये जा रहे करापवंचन को रोकने तथा माल के अभिग्रहण के लिये की गयी है। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 2(1)(xiii) में विशिष्टतया यह उल्लिखित है कि जोन में सचल दल इस तरह लगाये जायें कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी प्रवर्तन कार्य बाधित न हो।

के दिनों की संख्या 78 दिनों से 343 दिनों के मध्य थी। विवरण परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।

इस प्रकार बिना व्यवधान के सचल दलों के संचालन द्वारा राजस्व के क्षरण को रोकने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि 24 घण्टे सड़क जांच सम्भव नहीं थी, क्योंकि वाहन/माल के अभिग्रहण के पश्चात, सचल दलों को भौतिक सत्यापन, कारण बताओ नोटिस निर्गत करना तथा जमानत धनराशि जमा कराना जैसी औपचारिकतायें भी पूर्ण करनी पड़ती हैं। इसलिए सचल दलों द्वारा सभी मार्गों पर सतत निगरानी सम्भव नहीं थी। साथ ही विभागीय उत्तर में लेखा परीक्षा द्वारा सूचित आँकड़े काल्पनिक कहे गये।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विभागीय उत्तर प्रवर्तन मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। जहां तक आकड़ों की सत्यता का प्रश्न है, यह सम्बन्धित सचल दल इकाईयों को आर्बिट्रि वाहनों की लागबुक में दर्ज विवरण पर आधारित हैं।

प्रान्त में माल के अनियमित आयात/परिवहन द्वारा करापवंचन को रोकने में सचल दलों की प्रभावकारिता की जांच के उद्देश्य से हमने 35 सचल दल इकाईयों³⁸ के अभिलेखों³⁹ की नमूना जांच किया और पाया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सचल दल इकाईयां-प्रवर्तन मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं थीं। सचल दल इकाईयों के संचालन

³⁸ सचल दल इकाई 2,4,5,7 और 8 आगरा, सचल इकाई 1 और 2 बरेली, सचल दल इकाई बुलन्दशहर, सचल दल इकाई प्रथम बन्दौली, स0द0इकाई-4 गीतगुडनगर नगर, स0द0 इकाई-1,2,3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0इकाई 1 एवं 2 झांसी, स0द0इकाई 1,2,3,8 एवं 12 कानपुर, स0द0इकाई 1 एवं 5 लखनऊ, स0द0इकाई-4 मथुरा, स0द0इकाई 2,4 एवं 5 मेरठ, स0द0इकाई 3 एवं 6 मुंदादाबाद, स0द0इकाई 1,5 एवं 6 नोयडा, स0द0इकाई 1 एवं 4 सहारनपुर और स0द0इकाई-4 वाराणसी।

³⁹ सचल दलों को आर्बिट्रि वाहन की लाग बुक।

40 आर्या, गणितशास्त्र, निरखण, कानपुर-1 एवं II, वायापरी
 41 आर्या व निरखण
 42 अरबी, अरबी, निरखण, कानपुर एवं वायापरी
 43 आर्या, अरबी, निरखण, कानपुर एवं वायापरी
 44 गणितशास्त्र, कानपुर-1 एवं II, वायापरी
 45 अरबी, निरखण, कानपुर, कानपुर और
 46 निरखण, कानपुर एवं वायापरी
 47 अरबी, कानपुर, कानपुर, कानपुर एवं वायापरी

2.8.8.2 अस्थित निरखण कक्ष एवं उपकरणों की अनुपलब्धता

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के मध्य 11 जनों की 35 सवाल दल इकाइयों की समीक्षा के दौरान हमने पाया कि 40 में निरखण कक्ष स्थापित थे लेकिन इनमें से दो जनों में संघालित नहीं थे क्योंकि निरखण कक्ष में कोई कार्मिक तैनात नहीं था। साथ ही निरखण कक्ष में टी.डी.एफ. के विशेषण व व्यापारियों के दिन व पते जांच हेतु इंटरनेट की कनेक्शन भी नहीं था। हमने पाया कि पूरे निरखण कक्ष स्थापित नहीं थे। फरवरी-मार्च 2011-12 के मध्य साल में जहाँ निरखण कक्ष स्थापित/संघालित नहीं था, में पकड़े गये 21,999 मामलों की तुलना में उन चार जनों द्वारा जहाँ निरखण कक्ष स्थापित था, समान अवधि में पकड़े गये 20,187 मामलों से परिलक्षित होता है। इस प्रकार उन जनों की दक्षता बढ़तर थी जहाँ निरखण कक्ष स्थापित किये गये थे।

हमने आगे यह भी देखा कि सवाल दल अधिकारियों का इंटरनेट सुविधा से सुसज्जित कोई उपकरण⁴⁵ उपलब्ध नहीं करया गया जिससे वे वाहन में लदे माल के, व्यापारी के पते व दिन आदि की जांच कर पाते। ऐसे उपकरणों की अनुपलब्धता व निरखण कक्ष के अस्थित होने की दशा में जोड़ चौकी के दौरान वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के विवरण के मिलान अथवा प्रतिस्थापन हेतु सवाल दल अधिकारियों के समक्ष कोई विकल्प नहीं था। विज्ञापित सड0 क0नि0-2-241/X1-9(295)/07-यू0पी0एक्ट-5-2008-उ0प्र0संघालित कर, नियमावली-08-आदेश-(55)-2010 दिनांक 4 फरवरी 2010 द्वारा नियम 55(2) के प्रावधानों को समाप्त किये जाने के पश्चात् सवाल दल प्रभावी की वाहन में लदे माल की प्रमाणिकता की जांच हेतु वाहन के स्थानित सम्बन्धी प्रयोग प्रकीर्ण कायल है।

प्रवर्तन मंत्रालय के अध्याय-10 के पैरा 1 व अध्याय-4 के पैरा 2 के अन्तर्गत अधिसूचित कम्प्लेक्स (सवाल दल) दैनिक रूप से डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. की सैमन्य इंटरनेट से प्राप्त करके इनके वाहनों की जांच हेतु उत्तरदायी है। ज्वाइंट कम्प्लेक्स (वि0अनु0शा0) नियोजन व अनुभवण के लिये उत्तरदायी है।

प्रवर्तन मंत्रालय के अध्याय-4 के पैरा 2 (सी) 3 (I) के प्रावधानान्तर्गत एक प्रभावी सूचनात्मक के द्वारा प्रवर्तन कार्यों के अनुभवण हेतु जौनल स्तर पर निरखण कक्ष की स्थापना का उत्तरदायित्व ज्वाइंट कम्प्लेक्स (वि0अनु0शा0) का है।

सवाल दल इकाइयों की समीक्षा के दौरान हमने पाया कि 40 में निरखण कक्ष स्थापित थे लेकिन इनमें से दो जनों में संघालित नहीं थे क्योंकि निरखण कक्ष में कोई कार्मिक तैनात नहीं था। साथ ही निरखण कक्ष में टी.डी.एफ. के विशेषण व व्यापारियों के दिन व पते जांच हेतु इंटरनेट की कनेक्शन भी नहीं था। हमने पाया कि पूरे निरखण कक्ष स्थापित नहीं थे। फरवरी-मार्च 2011-12 के मध्य साल में जहाँ निरखण कक्ष स्थापित/संघालित नहीं था, में पकड़े गये 21,999 मामलों की तुलना में उन चार जनों द्वारा जहाँ निरखण कक्ष स्थापित था, समान अवधि में पकड़े गये 20,187 मामलों से परिलक्षित होता है। इस प्रकार उन जनों की दक्षता बढ़तर थी जहाँ निरखण कक्ष स्थापित किये गये थे।

हमने आगे यह भी देखा कि सवाल दल अधिकारियों का इंटरनेट सुविधा से सुसज्जित कोई उपकरण⁴⁵ उपलब्ध नहीं करया गया जिससे वे वाहन में लदे माल के, व्यापारी के पते व दिन आदि की जांच कर पाते। ऐसे उपकरणों की अनुपलब्धता व निरखण कक्ष के अस्थित होने की दशा में जोड़ चौकी के दौरान वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के विवरण के मिलान अथवा प्रतिस्थापन हेतु सवाल दल अधिकारियों के समक्ष कोई विकल्प नहीं था। विज्ञापित सड0 क0नि0-2-241/X1-9(295)/07-यू0पी0एक्ट-5-2008-उ0प्र0संघालित कर, नियमावली-08-आदेश-(55)-2010 दिनांक 4 फरवरी 2010 द्वारा नियम 55(2) के प्रावधानों को समाप्त किये जाने के पश्चात् सवाल दल प्रभावी की वाहन में लदे माल की प्रमाणिकता की जांच हेतु वाहन के स्थानित सम्बन्धी प्रयोग प्रकीर्ण कायल है।

सवाल दल अधिकारियों का केवल पंजीकृत व्यापारियों के दिन के सत्यापन और वाहन की सूविधा उपलब्ध नहीं करयी गयी।

उपलब्ध थी किन्तु देखा कि विभागीय अधिकारियों को उक्त हेतु कोई सी.यू.जी.⁴⁷ की टी.डी.एफ. के विवरण की जांच हेतु पूरा पूरा एस.एम.एस.⁴⁶ की सुविधा उपलब्ध नहीं करयी गयी।

समापन विचार गीली के दौरान शासन ने बताया (सितम्बर, 2013) कि विभागीय अधिकारियों को उपकरण उपलब्ध नहीं थे तथा उन्हें उपकरण उपलब्ध करने विशेषक प्रस्ताव विद्यमान था। आगे यह कहा कि मुख्यालय व जौनल स्तर पर सुविधागत निरखण प्रकीर्ण कायल है।

तैयार किया गया था।
समापन विचार गोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि सभी सम्बन्धित कॉम्प्लेक्सों को कमियाँ को दूर करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रधान मंत्रीअल के प्रावधानों के अनुसार एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-II अपने जौन में सवल दल इकाइयों हेतु मासिक इयूटी वार्ट तैयार करने व उसको क्रियान्वित करवाने के लिये उल्लेखित है। बौद्ध उल्लेखित कार्यों के अन्तर्गत कार्यालय 42 सवल दल इकाइयों के अभिलेखा⁴⁸ की जाँच में हमने देखा कि छ: जौनों⁴⁹ में जिनमें उक्त 42 में से 15 सवल दल इकाइया कार्यालय थी, कोई इयूटी वार्ट तैयार नहीं किया गया। आठ जौनों⁵⁰ में जिनमें उक्त 42 में से 21 सवल दल इकाइया कार्यालय थी, इयूटी वार्ट

प्रवर्तन मंत्रालय के अध्याय-10 के पैरा 2 (1) के अनुसार नगर में वाहनों के प्रवेश मार्गों को विन्दीकृत करके आवश्यकतानुसार (दो या दो से अधिक प्रवेश मार्गों से सम्बन्धित क्षेत्र को आच्छादित करते हुए) बीट बनाये जायें। बीट की संख्या सवल दल इकाइयों के अनुक्रम रखी जायें। प्रत्येक बीट में एक सवल दल इकाई अपने अधिकार क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों पर रोड इकाई का कार्य करेगी। इकाइयों में इयूटी सांसाहिक रूप से परिवर्तित की जायें। प्रत्येक बीट की लिक इकाई नामित कर दी जायें जो कि बीट इकाई के संचालित न रहने की स्थिति में अपनी बीट एवं लिक इकाई की बीट में वाहन बेकिंग कर सकें। सवल दल इकाइयों के प्रथम अवकाश के दिवस इस प्रकार नियत किये जायें कि सभी इकाइयों को सप्ताह में एक दिन अवकाश मिल जायें और सांठजनिक अवकाशों में भी प्रवर्तन कार्य बाधित न हो। ऐलवे स्टेशन व इवाइ अइल⁵¹ के आस-पास भी सवल दल इकाइयों द्वारा गहन जाँच की जायें। ऐल में ज्वाकमि⁵² (वि0अन0इग10) सवल दल इकाइयों के प्रभावी अधिकारी होंगे।

2.8.8.3 सवल दल इकाइयों की तैनाती में अनुश्रवण की कमी

2.8.8.4 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में परिपत्र का निर्गमन

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 (7) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त प्रभारी अधिकारी सचल दल, यदि यह समझता है कि माल को अभिग्रहीत करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को अभिग्रहण के तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक लिखित आदेश तामील करायेगा जिसमें ऐसी धनराशि संसूचित होगी, जो ऐसी धनराशि से अनधिक होगी जो संभावित रूप से आरोपित की जाने वाली शास्ति को आच्छादित करने के लिये पर्याप्त हो। उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों में शास्ति की धनराशि माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत है। कमिश्नर वाणिज्य कर ने परिपत्र संख्या चे0 पो0-25 क-परिपत्र/2008/0809100 दिनांक 3 फरवरी 2009 द्वारा निर्धारित किया कि पंजीकृत व्यापारियों द्वारा बिना वैध प्रपत्रों के, प्रदेश के अन्दर या प्रदेश के बाहर से माल को परिवहित करते पाये जाने से सम्बन्धित अभिग्रहण के मामलों में वसूल की जाने वाली जमानत धनराशि क्रमशः देय कर के दो गुना अथवा तीन गुना अथवा माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत जो दोनो में कम हो, होगी। यह आदेश परिपत्र संख्या चे0पो0-25क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र/2009-2010/0910060 दिनांक 5 नवम्बर 2009 द्वारा वापस ले लिया गया।

हमने 21 सचल दल इकाइयों⁵¹ के अभिलेखों की जाँच किया एवं 13 अन्य सचल दल इकाइयों⁵² से सूचनाएं एकत्रित किया और पाया कि फरवरी 2009 से नवम्बर 2009 के मध्य पंजीकृत व्यापारियों के 3031 मामलों में ₹ 128.97 करोड़ का माल इन सचल दल इकाइयों द्वारा अभिग्रहीत किया गया। इन मामलों में ₹ 19.22 करोड़ की जमानत राशि जमा करायी गयी जो कि देय कर का दो गुना या तीन गुना थी। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 40 प्रतिशत आगणित जमानत धनराशि ₹ 51.59 करोड़ आरोपणीय थी। इस प्रकार कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 (7) के

प्रावधानों का उल्लंघन करके परिपत्र निर्गत करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.37 करोड़ कम जमानत राशि मात्र इन 34 सचल दल इकाइयों द्वारा वसूल की गयी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि परिपत्र धारा 48 (7) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं था।

उत्तर अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि प्रावधान ऐसी धनराशि, जो शास्ति को आच्छादित करने हेतु पर्याप्त हो, के जमा हेतु निर्दिष्ट करता है, तथा ऐसे मामलों में धारा 54 (1) के अन्तर्गत शास्ति की धनराशि चालीस प्रतिशत निर्धारित है।

⁵¹ स0द0 इकाई-2, आगरा, स0द0 इकाई 1 एवं 2 बरेली, स0द0 इकाई-2,3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0 इकाई-4, गौतमबुद्ध नगर, स0द0 इकाई-2, गोरखपुर, स0द0 इकाई 1 एवं 2 झांसी, स0द0 इकाई-1,2 एवं 3 कानपुर, स0द0 इकाई-1, लखनऊ, स0द0 इकाई 1 एवं 4 मथुरा, स0द0 इकाई-6 मुरादाबाद, स0द0 इकाई 3 एवं 4 सहारनपुर, स0द0 इकाई मुगलसराय एवं नौबतपुर स्थित वाराणसी।

⁵² स0द0 इकाई 1,3,4,5,6,7 एवं 8 आगरा, स0द0 इकाई 9 एवं 11 कानपुर, स0द0 इकाई-3 एवं 4 लखनऊ, स0द0 इकाई 2 एवं 3 मथुरा।

2.8.8.5 पंजीकृत व्यापारियों के अभिग्रहण के मामलों का अनुश्रवण

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी सचल दल द्वारा यदि यह पाया जाता है कि माल को अभिग्रहीत करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को एक लिखित आदेश तामील करायेगा जिसमें अभिग्रहण के तथ्यों का उल्लेख होगा और ऐसी धनराशि संसूचित होगी जो ऐसी धनराशि से अनधिक होगी जो संभावित रूप में आरोपित की जाने वाली शास्ति को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो अर्थात् माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत। धारा 48 (5) के अन्तर्गत जमानत राशि जमा होने के पश्चात माल अवमुक्त किया जाता है। पंजीकृत व्यापारियों के मामले सम्बन्धित खण्डों में अग्रेतर परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

इन मामलों का अनुश्रवण ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा किया जाता है।

बारह जोनों⁵³ के अभिलेखों⁵⁴ की नमूना जाँच में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य सचल दल इकाइयों ने 41,081 वाहन पकड़े जिनमें ₹ 404.25 करोड़ का माल बिना निर्धारित प्रपत्रों के परिवहित किया जा रहा था और अपंजीकृत व्यापारियों के 41,081 मामलों में ₹ 176.62 करोड़ शास्ति आरोपित की गयी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य पंजीकृत व्यापारियों के 26,510 मामले कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को भेजे गये।

विवरण सारणी क्रमांक 2.16 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.16

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिग्रहीत वाहनों की संख्या		योग	माल का मूल्य		योग	आरोपित शास्ति (अपंजीकृत)	खण्ड में क0नि0 प्राधिकारी को प्रेषित मामले	खण्ड में वसूली गयी शास्ति
	पंजीकृत	अपंजीकृत		पंजीकृत	अपंजीकृत				
2007-08	3014	5662	8676	52.57	35.32	87.89	16.86	3014	0.17
2008-09	6975	5563	12538	152.97	50.87	203.84	21.38	6975	1.90
2009-10	7504	8463	15967	218.75	79.81	298.56	33.79	7504	2.06
2010-11	4466	10725	15191	134.94	109.26	244.20	46.96	4466	1.70
2011-12	4551	10668	15219	133.63	128.99	262.62	57.63	4551	1.88
योग	26510	41081	67591	692.86	404.25	1097.11	176.62	26510	7.71

श्रोत: सम्प्रेक्षा के दौरान एकत्रित सूचनायें

* विभाग के पास मात्र तीन जोन की सूचना (आगरा, अलीगढ़ और कानपुर-II) ही उपलब्ध थी।

17 सचल दल इकाइयों⁵⁵ के मामलों में हमने देखा कि अभिग्रहीत किये गये 17,151 वाहनों⁵⁶ में से 2,566 वाहन पंजीकृत व्यापारियों के थे जिनमें कुल ₹ 190.96 करोड़ मूल्य का माल लाया जा रहा था। प्रावधानों के अनुरूप ₹ 76.35 करोड़ शास्ति के रूप में वसूले जाने थे जबकि मात्र ₹ 36.71 करोड़ वसूले गये। इस प्रकार, जमानत के रूप में ₹ 39.64 करोड़ कम वसूल किया गया।

हमने यह भी देखा कि न तो सचल दल इकाइयों या उनके पर्यवेक्षीय अधिकारियों ने कर, निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर की गयी कार्यवाही अर्थात् सचल दल इकाइयों द्वारा रोड चेकिंग के दौरान पकड़े गये व्यापारियों पर आरोपित व वसूल की गयी कर की राशि की निगरानी हेतु कोई अभिलेख नहीं तैयार किया और न ही पंजीकृत व्यापारियों के अभिग्रहण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यापारियों पर आरोपित कर व उसकी वसूली की आवधिक प्रगति रिपोर्ट भेजने हेतु कोई कार्यप्रणाली विकसित की।

⁵³ आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर-I एवं II, लखनऊ- I एवं II, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी-I

⁵⁴ पंजी-5।

⁵⁵ स0द0इकाई 1 एवं 2, बरेली, स0द0इकाई- 4 गौतमबुद्ध नगर, स0द0इकाई-2,3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0इकाई-3, गोरखपुर, स0द0इकाई 1 एवं 2 झांसी, स0द0इकाई-3 कानपुर, स0द0इकाई- 1, लखनऊ, स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, स0द0इकाई 3 एवं 4 सहारनपुर, स0द0इकाई-मुगलसराय एवं नौबतपुर-2 चन्दौली स्थित वाराणसी।

⁵⁶ वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य (परिपत्र संख्या चोप0-25क-परिपत्र/2008/0809100 के अन्तर्गत सम्मिलित अवधि, फरवरी 2009 से नवम्बर 2009 तक अभिग्रहणों को छोड़कर)

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने बताया (सितम्बर 2013) कि सचल दल इकाइयों द्वारा पकड़े गये प्रकरणों को अपलोड करने हेतु एक साफ्टवेयर बनाया गया है तथा कर निर्धारण प्राधिकारियों को अगस्त 2013 में परिपत्र⁵⁷ के द्वारा संसूचित किया गया है। यद्यपि विभाग ने विवरणों के आनलाइन इन्द्राज हेतु कार्यवाही की है लेकिन कम जमानत राशि वसूले जाने के हमारी प्रेक्षा का समुचित उत्तर नहीं दिया।

2.8.8.6 अभिग्रहीत माल की गैर नीलामी

उ0प्र0मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 48 (9) के प्रावधानान्तर्गत यदि अभिग्रहीत माल पर निर्धारित कर या आरोपित शास्ति की धनराशि को जमा न किया गया हो, वहाँ यथास्थिति माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी निर्धारित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल बिकवायेगा। यद्यपि ऐसे माल के अभिग्रहण के पश्चात नीलामी हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

हमने 25 सचल दल इकाइयों के पंजी-5 की नमूना जाँच किया और पांच सचल दल इकाइयों में पाया कि इन इकाइयों के अधिकारियों ने वर्ष 1998-99 से 2010-11 के मध्य बिना उचित प्रपत्रों के माल का परिवहन करते हुये वाहनों को पकड़ा। व्यापारियों द्वारा उस पर आरोपित जमानत/शास्ति की धनराशि जमा न करने के कारण माल का अभिग्रहण किया गया। चूँकि व्यापारी दीर्घ अवधि तक प्रस्तुत नहीं हुए अतः विभाग ₹ 1.02 करोड़ मूल्य के माल का इकलौता मालिक हो गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.17 में दिये गये हैं।

सारणी क्रमांक 2 17

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	मामलों की संख्या	माल का विवरण	माल का मूल्य
1	स0द0इकाई-4 गाजियाबाद	2005-06 से 2009-10	3	दवा, सिले हुए पश्चान, परचून, प्लास्टिक दाना	8.28
2	स0द0इकाई-1 कानपुर	2009-10 से 2010-11	4	चमड़ा, दवा,विभिन्न माल आदि	1.37
3	स0द0इकाई-2 कानपुर	1998-99 से 2010-11	5	दवा,सुपाड़ी,गुटका	56.13
4	स0द0इकाई-3 कानपुर	1999-2000 से 2001-02	12	गुटका,तम्बाकू,दवा,चूड़ी,मिक्सर ग्राइन्डर, होजरी	7.09
5	स0द0 इकाई-1 लखनऊ	2001-02 से 2009-10	30	गुटका,दवा,लोहा,इस्पात इत्यादि	28.73
योग			54		101.60

हमने देखा कि अभिग्रहीत माल की नीलामी नहीं की गयी और माल गोदाम में पड़ा था जबकि अधिकांश माल नाशवान प्रकृति के थे जैसे-दवा, चमड़ा, सुपाड़ी, गुटखा इत्यादि। विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण अभिग्रहीत माल के मूल्य की वसूली नहीं की जा सकी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि जोनल एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को अभिग्रहीत माल के निस्तारण के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

हम अनुशांसा करते हैं कि राजस्व हित में विभाग अभिग्रहीत माल के निस्तारण हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे।

2.8.8.7 कर का अनारोपण

कमिश्नर वाणिज्य कर के परिपत्र संख्या: सचल दल/ अर्थदण्ड/ क0नि0/ ट्रांजिटपास/ 10-11/ 101104/ वाणिज्य कर दिनांक 20 सितम्बर 2010 के अनुसार, यदि सचल दल इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा टी.डी.एफ. के मामले अभिग्रहीत किये जाते हैं, तो वह शास्ति आरोपित करने के साथ ही कर आरोपित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारियों के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

हमने 35 सचल दल इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि 12 सचल दल इकाइयों⁵⁸ में बिना वैध पारगमन पत्र/ टी.डी.एफ. के 68

⁵⁷ संख्या-आई.टी.-बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन-2013-14 / 642 दिनांक 30.08.2013

⁵⁸ स0द0इकाई 2, आगरा, स0द0इकाई-2 एवं 3, गोरखपुर, स0द0इकाई 2 झांसी, स0द0इकाई-3 कानपुर, स0द0इकाई- 2 एवं 5, मेरठ स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, स0द0इकाई 3 एवं 4 सहारनपुर, स0द0इकाई- नीबतपुर-2 स्थित वाराणसी।

2.8.9 विशेष अनुसंधान शाखा की कार्यप्रणाली

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-4 के पैरा 2 (सी) के प्रावधानान्तर्गत ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) सर्वेक्षित व्यापारियों के प्रतिवेदनों को सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजने तथा प्रेषित प्रतिवेदनों के आधार पर स्थायी/अस्थायी कर निर्धारण की स्थिति की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-9 के अनुसार वि0अनु0शा0 इकाइयों को 12 स्तम्भीय रजिस्टर जिसमें कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित किये गये प्रतिवेदन का विवरण सर्वेक्षण के पूर्ण विवरण एवं उसके आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों का सम्पूर्ण विवरण अंकित हो, तैयार करना होता है। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-5 के पैरा 1 ए (vi एवं vii) के अनुसार डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) और असि0 कमिश्नर (वि0अनु0शा0) अपने द्वारा प्रेषित गोपनीय प्रतिवेदन से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा करेंगे। वे कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर लम्बित वि0अनु0शा0 वादों का त्रैमासिक रूप से मिलान करेंगे। वाणिज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) छोटे व्यापारियों से सम्बन्धित परिवारों की जाँच असि0 कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के सहयोग से करेंगे तथा डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) से अनुमोदित कराने के पश्चात जाँच प्रतिवेदन सम्बन्धित खण्डाधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

वि0अनु0शा0 इकाइयां अपने रेंज/जोन के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टरों के भवनों/गोदामों में सर्वेक्षण, जांच व अभिग्रहण की कार्यवाही करती हैं। अभिग्रहीत दस्तावेजों के साथ प्रतिकूल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों को कर-निर्धारण एवं वसूली हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

प्रान्त में विशेष अनुसंधान शाखाओं द्वारा की गयी कार्यवाही के परिणाम सारणी संख्या 2.18 में दिये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.18

वर्ष	इकाइयों की संख्या	प्रतिकूल सर्वेक्षणों की संख्या	अभिग्रहीत अभिलेखों की संख्या	क0नि0प्रा0 को प्रेषित प्रतिवेदनों ⁶⁷ की संख्या	प्रेषित प्रतिवेदनों में सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	क0नि0प्रा0 को प्रेषित प्रतिवेदनों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में)	गत वर्ष की तुलना में धनराशि में वृद्धि (प्रतिशत में)
2007-08	39	5,024	2,316	6,994	7,547.48	14.36	73.49
2008-09	46	6,133	2,638	8,170	7,916.57	16.81	04.89
2009-10	46	7,031	3,180	8,244	9,008.05	00.91	13.79
2010-11	46	4,625	2,421	7,357	11,513.00	(-) 10.76	27.81
2011-12	46	4,513	2,505	6,979	13,015.00	(-) 05.14	13.04
योग		27,326	13,060	37,744	49,000.10	32.08	133.02

स्रोत : विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन

सारणी क्रमांक 2.18 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मध्य प्रतिकूल सर्वेक्षणों में ग्यारह से पांच प्रतिशत की कमी आयी है तथा कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों में 10.76 से 5.14 प्रतिशत की कमी आयी है। कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों में समाहित धनराशि वर्ष 2008-09 में ₹ 7,916.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 13,015 करोड़ हो गयी। रजिस्टर⁶⁸ में वांछित विवरण अंकित न होने के कारण विभाग इन मामलों में वास्तविक वसूली की स्थिति बताने में असमर्थ रहा।

⁶⁷ कुल प्रेषित प्रतिवेदन प्रतिकूल सर्वेक्षण रिपोर्ट को शामिल करते हुये।

⁶⁸ क0नि0प्रा0कारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों का 12 स्तम्भीय रजिस्टर।

हमने नमूना जांच में देखा कि 11 वि०अनु०शा० जोनों⁶⁹ में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) ने 20,257 सर्वेक्षण किये जिनमें ₹ 24,698.07 करोड़ अपवंचित टर्नओवर कर निर्धारण प्राधिकारियों को संसूचित किया गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.19 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.19

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जोनों की संख्या	सर्वेक्षणों की संख्या	कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों की संख्या	अनुमानित अपवंचित टर्नओवर की सन्निहित धनराशि
2007-08	11	4,590	3,960	5,853.96
2008-09	11	4,845	4,268	4,378.36
2009-10	11	4,655	4,525	4,655.62
2010-11	11	3,188	3,278	4,481.95
2011-12	11	2,979	3,012	5,328.18
योग		20,257	19,043	24,698.07

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कर और उसकी वसूली का विवरण जो कि डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) द्वारा रखा जाना चाहिए, मात्र मुरादाबाद जोन के डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०)⁷⁰ द्वारा रखा गया तथा मुरादाबाद जोन के 2,395 मामलों में अपवंचित टर्नओवर पर आरोपित कर⁷¹ की वसूली⁷² 22 से 25 प्रतिशत तक रही।

हम मात्र पांच जोन⁷³ के 21 व्यापारियों के कर निर्धारण आदेशों की जांच कर सके जिन्हें वि०अनु०शा० अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रतिकूल सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, अन्तिम रूप दिया गया था और पाया कि :

- तीन व्यापारियों⁷⁴ के वर्ष 2007-08 से 2009-10 के वाद जिनमें ₹ 1.34 करोड़ का कर सन्निहित था, उ०प्र०मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 32 व उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण हेतु लम्बित थे।
- नौ व्यापारियों⁷⁵ के वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के वादों में, जिनमें ₹ 115.27 करोड़ का अपवंचित टर्नओवर और ₹ 6.18 करोड़ का कर सन्निहित था, प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कर घटाकर ₹ 8.04 लाख कर दिया गया। सभी मामले अपील में लम्बित थे।
- दो मामलों⁷⁶ में व्यापारियों ने निर्धारित कर ₹ 1.5 लाख जमा कर दिया और एक मामले⁷⁷ में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कोई अपवंचन नहीं पाया। चौथे मामले⁷⁸ में ₹ 8000 की आई.टी.सी. उत्क्रमित की गयी।
- वर्ष 2009-10 के एक मामले⁷⁹ में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अप्रैल 2012 में ₹ 88.30 लाख कर निर्धारित किया गया।
- शेष तीन मामलों⁸⁰ में जो वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित थे तथा जिनमें ₹ 1.50 करोड़ का कर सन्निहित था, में जून 2011 से सितम्बर 2012 के मध्य वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये।

इन इक्कीस मामलों में हमने पाया कि वि०अनु०शा द्वारा संसूचित करापवंचन कर निर्धारण/अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर पोषणीय नहीं रहा।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2013) कि वि०अनु०शा इकाइयों को कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर की गयी कार्यवाही का विवरण

⁶⁹ आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर-I एवं II, लखनऊ-I, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी-I

⁷⁰ जोन मुरादाबाद के डि०क०, वि०अनु०शा०-ए, वि०अनु०शा०-बी एवं वि०अनु०शा०-विजैनौर।

⁷¹ निर्धारित कर ₹ 171.71 करोड़।

⁷² वसूली ₹ 41.19 करोड़।

⁷³ आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ एवं नोएडा।

⁷⁴ बंसल इस्पात गाजियाबाद, चेतना स्टील्स गाजियाबाद और गाजियाबाद आयरन एण्ड स्टील कम्पनी गाजियाबाद।

⁷⁵ गेल इण्डिया लि० आगरा, गणेश इण्टरप्राइजेज आगरा, गिरीराज किशोर आगरा, बालाजी फूड प्राइवेट मथुरा, समय फूड प्रा०लि० नोएडा, मैनी स्टील वर्क्स नोएडा, नमिता अग्रवाल आगरा, नीलकण्ठ स्वीट्स लखनऊ, कृष्णा इलेक्ट्रिक एवं हार्डवेयर नोएडा।

⁷⁶ स्वदेशी मैनुफैक्चरिंग (प्रा०)लि० नोएडा एवं वैली हेल्थ प्राइवेट्स (प्रा०)लि० नोएडा।

⁷⁷ बाबूलाल एण्ड सन्स मथुरा।

⁷⁸ खण्डेलवाल स्टील्स सेंटर गाजियाबाद।

⁷⁹ एस०जी०स्टील्स गाजियाबाद।

⁸⁰ राजगंगा डेवलपर्स लखनऊ, सुरेश चन्द्र रिषी कुमार मथुरा, ताज स्टील वर्क्स नोएडा।

पाँच जौन⁸⁹ में उपलब्ध थे। इन पाँच जौनों में से केवल तीन जौनों⁹⁰ में निर्माता इकाइयों में किये गये सर्वेक्षण व अभिग्रहण के ही विवरण उपलब्ध थे। इस प्रकार पर्यवेक्षी व निगरानी नियंत्रण में निदेशन का अभाव था तथा उद्देश्यपूर्ण नहीं रहा। शेष नौ जौनों⁹¹ से सूचनायें/आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) तथा कहा कि मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत⁹² कर दिये गये हैं।

2.8.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को तर्कपूर्ण प्रभाव के साथ व्यवस्थित रूप से लागू करने में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सामान्यतः परिभाषित है कि यह सभी नियंत्रणों पर नियन्त्रण है। आन्तरिक नियन्त्रण तुरन्त एवं प्रभावी सेवाओं तथा करपवंचन एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध उचित सुरक्षा के लिए वित्तीय और प्रबन्धन की विश्वसनीय सूचना प्रणाली के सृजन करने में भी मदद करता है।

हमने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के मध्य आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित सचल दल इकाइयों के संबंध में सूचनायें कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर से एकत्र किया और पाया कि क्रमशः 129, 136, और 134 सचल दल इकाइयाँ आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित की गयीं। पुनः कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभिलेखों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इन इकाइयों द्वारा जमा का मात्र कोषागार से सत्यापन किया गया और अन्य कोई अभिलेख नहीं जाँचे गये थे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सचल दल इकाइयों को विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित नहीं किया जाता है। वि0अनु0शा0 इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी। चूँकि प्रवर्तन शाखा वाणिज्य कर विभाग का अभिन्न अंग है अतः इसके सभी पक्षों को आन्तरिक लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को भविष्य में सचल दल इकाइयों के समस्त अभिलेखों जैसे डिटेंशन मेमो, कारण बताओ नोटिस, अभिग्रहण आदेश, गोदाम पंजी, पंजी-5, भौतिक सत्यापन रजिस्टर, मामलों की पत्रावलियाँ, नगद जमानत जमा करने का रजिस्टर, रोकड़ बही आदि की जाँच हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

2.8.12 निष्कर्ष

समीक्षा में उजागर हुआ कि टी.डी.एफ. एवं फार्म 38 के निर्गत करने एवं खारिज/जमा में कमियाँ थीं। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि टी.डी.एफ. के आनलाइन प्रणाली में निवेश एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली में खामियाँ थीं। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा तथा प्रवर्तन शाखा के मध्य समन्वय का अभाव है तथा प्रवर्तन शाखा को डाटा एन्ट्री के आँकड़े समय से प्राप्त नहीं हो रहे थे। बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टरों को ढूँढ़ निकालने हेतु कोई माड्यूल विद्यमान नहीं है। विद्यमान सचल दल इकाइयों में संचालनात्मक खामियाँ थीं, नियंत्रण कक्ष असंचालित थे तथा सचल दल अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में उपलब्ध सूचनाओं से प्रतिसत्यापन हेतु कोई उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे। सचल दल इकाइयों द्वारा अभिग्रहण तथा वि0अनु0शा0 द्वारा प्रतिकूल सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आरोपित अर्थदण्ड/कर सम्बन्धी अनुपालन एवं पर्यवेक्षण का अभाव था।

89 आगरा, गजियाबाद-1, झांसी, लखनऊ-1 एवं वाराणसी-1।

90 गजियाबाद-1, लखनऊ-1 एवं वाराणसी-1।

91 अलीगढ़, बरेली, गौतमपुर, गोरखपुर, कानपुर 1 एवं 2, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर।

92 परिपत्र सं: ज्य0क0नि0 (वि0अनु0शा0) नं.-57/स090/वि0अनु0शा0 व्यवस्था परिवर्तन/2013-14/1047 दिनांक 13.09.2013।

- प्रवर्तन अधिकाधिकारों द्वारा अभ्युदय/वसूले गये कर के संबंध में निगरानी/अनुभवण तंत्र स्थापित करना।
 - प्रवर्तन अधिकाधिकारों को उचित उपकरण उपलब्ध करना जिससे कि वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं/आंकड़ों का प्रयोग कर सकें।
 - प्रवर्तन अधिकाधिकारों को उचित उपकरण उपलब्ध करना जिससे कि वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं/आंकड़ों का प्रयोग कर सकें।
 - भारतभार करपवंचन करने वाले व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर्स का डाटाबेस रखने हेतु माइक्रो विकसित करना।
 - टी.डी.एफ. हेतु एन्टी एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।
 - फार्म-38 डाउनलोड करने के पूर्व संयवहार का विवरण आनलाइन भरने का प्रावधान अनिवार्य करना।
- कमियाँ में सुधार हेतु शासन निम्नलिखित संस्तुतियों के क्रियान्वयन पर विचार कर सकता है:

2.8.13 संस्तुतियाँ

कॉन्सल्टिंग फीस को अलग से चार्ज कर दिया गया है।
 विभिन्न प्रकार के कामों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।
 कामों के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

2.10 काम का अनुमान/काम आरेखण

आती है।
 अतिरिक्त लागत न केवल बनी रहती है अपितु नए पदों को भी प्रदान करना पड़ेगा।
 कामों के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।
 कामों के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

2.9 सेवा प्रदान करने की शर्तें

2.10.1 व्यापार कर/मूल्य संवर्धित कर की गलत दर लगाये जाने से कर का अनारोपण/कम आरोपण

उ०प्र० व्यापार कर (उ०प्र०व्या०क०) अधिनियम 1948 की धारा 3 क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर (उ०प्र०मू०सं०क०) अधिनियम 2008 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं शासन द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। केन्द्रीय बिक्री कर (के०बि०क०) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत फार्म 'सी' या फार्म 'डी' में घोषणापत्र से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 31 मार्च 2007 तक 10 प्रतिशत अथवा राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर दोनों में जो भी अधिक हो की दर से कर आरोपणीय है एवं 1 अप्रैल 2007 से उस दर से कर आरोपणीय है जो कि उस राज्य में लागू हो।

हमने नवम्बर 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य 75 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा०क०का०)⁹³ में देखा⁹⁴ कि 95 व्यापारियों द्वारा ₹ 33.79 करोड़ मूल्य के माल की 2002-03 से 2009-10 के मध्य बिक्री पर वैट अनुसूची में दिये गये कर की दर के बजाय जुलाई 2007 से मार्च 2012 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.36 करोड़ व्यापार कर (व्या०क०)/मूल्य संवर्धित कर (मू०सं०क०) का अनारोपण/कम आरोपण

हुआ।

हमारे द्वारा इन मामलों को दिसम्बर 2008 एवं मई 2013 के मध्य विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) 25 मामलों में ₹ 69.49 लाख कर आरोपित कर दिया जिसमें से ₹ 8.91 लाख की वसूली की जा चुकी है। छः अन्य मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

⁹³ डि०क० खण्ड-3 इलाहाबाद, डि०क० खण्ड-5 इलाहाबाद, अ०सि०क० खण्ड-11 इलाहाबाद, डि०क० खण्ड-8 आगरा, डि०क० खण्ड-10 आगरा, अ०सि०क० खण्ड-19 आगरा, डि०क० खण्ड-2 अमरोहा, डि०क० खण्ड-2 बाराबंकी, डि०क० खण्ड-5 बरेली, डि०क० खण्ड-3 बहराइच, डि०क० खण्ड-3 एटा, डि०क० खण्ड-2 इटावा, डि०क० खण्ड-1 फतेहगढ़, ज्वा०क० (कापी०स०) फँजाबाद, ज्वा०क० (कापी०स०) अ गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-9 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-10 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-17 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-2 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-3 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-4 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-10 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-11 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-3 गौतमबुधनगर, अ०सि०क० खण्ड-1 गौतमबुधनगर, डि०क० खण्ड-2 गोरखपुर, डि०क० खण्ड-9 गोरखपुर, अ०सि०क०-4 गोरखपुर, अ०सि०क० खण्ड-10 गोरखपुर, डि०क० खण्ड-1 हरदोई, डि०क० खण्ड-5 कानपुर, डि०क० खण्ड-10 कानपुर, डि०क० खण्ड-17 कानपुर, डि०क० खण्ड-24 कानपुर, डि०क० खण्ड-27 कानपुर, डि०क० खण्ड-28 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-5 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-6 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-11 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-16 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-17 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-19 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-20 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-27 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-29 कानपुर, अ०सि०क० कौशाम्बी, डि०क० खण्ड-1 लखीमपुर खीरी, अ०सि०क० खण्ड-1 लखीमपुर खीरी, डि०क० खण्ड-2 लखनऊ, डि०क० खण्ड-5 लखनऊ, डि०क० खण्ड-13 लखनऊ, डि०क० खण्ड-14 लखनऊ, डि०क० खण्ड-16 लखनऊ, डि०क० खण्ड-17 लखनऊ, डि०क० खण्ड-20 लखनऊ, अ०सि०क० खण्ड-16 लखनऊ, अ०सि०क० खण्ड-20 लखनऊ, डि०क० खण्ड-7 मुरादाबाद, डि०क० खण्ड-6 मेरठ, अ०सि०क० खण्ड-6 मेरठ, अ०सि०क० खण्ड-8 मेरठ, डि०क० खण्ड-4 नोएडा, डि०क० खण्ड-5 नोएडा, डि०क० खण्ड-12 नोएडा, डि०क० खण्ड-14 नोएडा, अ०सि०क० खण्ड-6 नोएडा, अ०सि०क० खण्ड-14 नोएडा, अ०सि०क० खण्ड-3 ओराई, अ०सि०क० खण्ड-2 शाहजहांपुर, अ०सि०क० खण्ड-4 सीतापुर, अ०सि०क० खण्ड-11 सहरनपुर, डि०क० खण्ड-3 वाराणसी एवं डि०क० खण्ड-15 वाराणसी।

⁹⁴ निर्धारित द्वारा दाखिल कर विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावली।

2.10.2 आरजीजीवीवाई (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) योजना में माल की बिक्री पर कर का अनारोपण

उ०प्र० व्यापार कर (उ०प्र० व्या०क०) अधिनियम 1948 की धारा 3 क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ०प्र० व्या०क० अधिनियम की धारा 3 'एच' के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख से अधिक कुल वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर 1 मई 2005 से 1 प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा०वि०क०) आरोपणीय होगा। पुनश्च, उ०प्र० सरकार ने 13 जुलाई 2006 को जारी विज्ञप्ति के अन्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) में ही प्रयोग के लिए राज्य के बाहर से आयातित इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री पर विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से योजना के पूर्ण होने की तिथि तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रदान की गई है।

हमने मार्च 2012 में डि०क० खण्ड-3 सीतापुर के अभिलेखों⁹⁵ की जाँच में देखा कि एक व्यापारी ने⁹⁶ वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 (12 जुलाई 2006 तक) की अवधि में आरजीजीवीवाई योजना के लिए कार्य कर रहे संविदाकारों को 12 जुलाई 2006 तक ₹ 43.33 करोड़ के इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री की। क०नि०प्रा० ने जुलाई 2010 में कर निर्धारण के समय आरजीजीवीवाई योजना में वर्ष 2005-06 एवं 12 जुलाई 2006 तक प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री पर करमुक्ति का गलत लाभ दिया जबकि करमुक्ति⁹⁷ 13 जुलाई

2006 से प्रभावी थी। इस गलत कर मुक्ति के परिणामस्वरूप विकास कर सहित ₹ 4.77 करोड़ के कर का अनारोपण⁹⁸ हुआ।

हमारे द्वारा इस मामले को विभाग एवं शासन को मई 2012 को इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) ₹ 4.64 करोड़ का कर आरोपित कर दिया। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

2.10.3 माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त किराये पर कर का कम आरोपण

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 3 एफ सपठित 14 नवम्बर 2000 की विज्ञप्ति के अनुसार 15 नवम्बर 2000 से किसी माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

हमने डि०क० खण्ड-13 इलाहाबाद के अभिलेखों की जून 2012 में जाँच के दौरान देखा⁹⁹ कि क०नि०प्रा० ने एक व्यापारी का दिसम्बर 2011 में कर निर्धारण करते समय मशीनरी एवं उपकरणों के

प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त किराया ₹ 23.64 करोड़ पर पाँच प्रतिशत के स्थान पर त्रुटिपूर्ण चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.64 लाख का कम कर आरोपित हुआ।

हमारे द्वारा मामले को अगस्त 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित करने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि ₹ 23.64 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

⁹⁵ क०नि०प्रा० एवं व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

⁹⁶ अधि० अभि० विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम वत्सगंज सीतापुर।

⁹⁷ क०नि०-2-1283/XI-9(24)/2006 उ०प्र० अधिनियम/15-48 आदेश-(12)-2006 दिनांक 13 जुलाई 2006।

⁹⁸ व्यापार कर ₹ 4.33 करोड़ रा०वि०क० ₹ 43.33 लाख।

⁹⁹ कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावली।

2.10.4 टाफी एवं कन्फेक्शनरी गुड्स की बिक्री पर कर का कम आरोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा-4(1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं समय-समय पर शासन द्वारा विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। टाफी एवं कन्फेक्शनरी की मदें अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं।

हमने 11 वा0क0का0 में देखा¹⁰⁰ कि क0नि0प्रा0 ने अवधि 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008 तक) एवं 2008-09 के लिए 12 व्यापारियों का मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 8.01 करोड़ मूल्य के ब्रान्डेड¹⁰¹ टाफी एवं कन्फेक्शनरी मदों की बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 68.05 लाख कम कर आरोपित हुआ जो सारणी क्रमांक 2.20 में दर्शाया गया है:-

सारणी क्रमांक 2.20

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि0क0 खण्ड-8 वा0क0 आगरा	1	2008-09 (मार्च 2012)	टाफी (v)	14.00	12.5/4	1.19
2	डि0क0 खण्ड-11 वा0क0 अलीगढ़	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	कन्फेक्शनरी उत्पाद (v)	10.74	12.5/4	0.91
			2008-09 (जनवरी 2012)		33.91	12.5/4	2.88
3	वा0क0अ0 खण्ड-9 वा0क0 अलीगढ़	1	2008-09 (फरवरी 2012)	टाफी कन्फेक्शनरी (v)	10.81	12.5/4	0.92
4	असि0 क0 खण्ड-1 वा0क0 छात्रपति शाहूजी महाराज नगर (गौरी गंज)	1	2008-09 (फरवरी 2012)	कन्फेक्शनरी टाफी एवं च्यूग गम (v)	1.27	12.5/4	0.11
5	असि0क0 खण्ड-8 वा0क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	कन्फेक्शनरी आइटम (v)	53.04	12.5/4	4.51
			2008-09 (जनवरी 2012)	कन्फेक्शनरी (v)	53.13	12.5/4	4.52
6	डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 गोण्डा	1	2008-09 (मार्च 2012)	टाफी एवं टाफी गम (कन्फेक्शनरी उत्पाद) (v)	22.16	12.5/4	1.88
7	डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 गोण्डा	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	कन्फेक्शनरी (v)	13.32	12.5/4	1.13
8	डि0क0 खण्ड-10 वा0क0 गोरखपुर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	टाफी (v)	7.68	12.5/4	0.65
9	डि0क0 खण्ड-3 वा0क0 कानपुर	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	कन्फेक्शनरी (टाफी) (v)	60.06	12.5/4	5.10
10	असि0क0 खण्ड-10 वा0क0 नोएडा	1	2008-09 (मार्च 2012)	कन्फेक्शनरी आइटम (v)	101.82	12.5/4	8.65
11	डि0क0 खण्ड-4 वा0क0 सहारनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	कन्फेक्शनरी (v)	418.85	12.5/4	35.60
योग		12			800.79		68.05

¹⁰⁰ निर्धारित द्वारा दाखिल विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावलियों।

¹⁰¹ एल्बेनलिवे, सेंटर फ्रेश, वलोरमिट, फिली-फाली, फ्रूटला एवं मेंटास इत्यादि।

हमारे द्वारा मामले को अगस्त 2012 एवं मई 2013 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित करने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 3, 5, 6, 7, 9 एवं 11 में वर्णित मामलों में ₹ 53.66 लाख का कर आरोपित कर दिया। शेष मामलों में कर आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

2.10.5 अनियमित स्टॉक ट्रान्सफर पर कर का अनारोपण

के0बि0क0 अधिनियम 1956 की धारा 4 सपठित धारा 3 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल की दशा में जब विक्रय संविदा की जाय एवं अभिनिश्चित या विशिष्ट माल की दशा में विक्रेता या क्रेता द्वारा विक्रय संविदा के प्रति उसके विनियोग के समय चाहे दूसरे पक्ष की अनुमति ऐसे विनियोग के पूर्व या पश्चात की हो तो किसी राज्य के भीतर माल का विक्रय या क्रय हुआ माना जाता है तब ऐसा विक्रय या क्रय अन्य सभी राज्यों के बाहर हुआ समझा जायेगा। पुनश्च, सर्वश्री भारत कार्बन रिबन मैनुफैक्चरिंग कं0 लि0 बनाम हरियाणा राज्य 2005 एन0टी0एन0 के मामले में ग्राहक के साथ हुए संविदा के अन्तर्गत निश्चित विशेषताओं के साथ निर्मित वस्तुओं की अन्ततः उसी ग्राहक को की गयी आपूर्ति एवं बिक्री को प्रान्त के बाहर डिपो शाखा को हस्तान्तरण स्टॉक ट्रान्सफर नहीं माना गया।

हमने अक्टूबर 2011 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट) नोएडा के अभिलेखों¹⁰² में देखा कि एक व्यापारी ने वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान अपने देहरादून एवं मोहाली स्थित शाखाओं को क्रय आदेश में दिये गये विशेषताओं के साथ माल के विवरण के अनुसार ₹ 67.67 करोड़ के माल (सीटीवी/डीवीडी कम्पोनेन्ट/प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड) की आपूर्ति की। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय

इस तथ्य की जांच नहीं की कि पूर्व में किये गये क्रय आदेश के अनुसार निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति विशेष ग्राहकों को करना स्टॉक ट्रान्सफर नहीं था। न्यायिक निर्णय एवं अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद क0नि0प्रा0 ने उसे अनुचित रूप से स्टॉक ट्रान्सफर मानते हुए उस पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

हमने मामले को विभाग/शासन को दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया। उनके उत्तर कई अनुस्मारकों के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2013)।

¹⁰² कर निर्धारण पत्रावलियों एवं निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणियों से।

2.10.6 धान की भूसी की खरीद पर कर का अनारोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अनुसूची-I में वर्गीकृत माल किसी भी बिन्दु पर कर योग्य नहीं है एवं जो वस्तुएं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची-II से IV तक वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत यदि अपंजीकृत व्यापारी से किसी वस्तु की खरीद की जानी है तो उस वस्तु पर उसी दर से जिस दर से उसकी बिक्री पर कर देय है कर के भुगतान का दायी होगा। पशु आहार एवं पशुचारा जिसमें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चोकर, जवी, ज्वार, तेल रहित राइस पालिश, तेल रहित राइस ब्रान, तेल रहित राइस हस्क या धान का बाहरी छिलका शामिल है को अनुसूची-I के क्रमांक 4 के अनुसार कर मुक्ति प्रदान की गयी है। धान का बाहरी छिलका जो धान की भूसी के रूप में जाना जाता है, जो तेल रहित न हो एवं जिसका प्रयोग पशु आहार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया हो इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है एवं इस पर अधिनियम के अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5 की दर से कर देयता है।

हमने चार वाणिज्य कर कार्यालयों में अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य देखा¹⁰³ कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) एवं 2008-09 के दौरान ₹ 34.42 करोड़ मूल्य के धान की भूसी अथवा धान के बाहरी छिलके की खरीद अपंजीकृत विक्रेताओं से खरीद कर इसका प्रयोग अपने निर्माण संयंत्रों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया। धान की भूसी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया गया, जबकि पशुचारा के रूप में ही तेल रहित धान की भूसी वैट से मुक्त है। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय

ईंधन के रूप में प्रयुक्त धान की भूसी या धान के बाहरी छिलके की खरीद पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया, जैसा सारणी क्रमांक 2.21 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.21

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर की धनराशि
1	ज्वा0क0 (काप0स0) वा0क0 इटावा मुख्यालय फिरोजाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	ईंधन के रूप में प्रयुक्त धान की भूसी (अनुसूची-V)	94.30	12.5/0	11.79
2	डि0क0 खण्ड-16 वा0क0 कानपुर	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)		149.28	12.5/0	18.66
3	डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 सम्मल	1	2007-08 (वैट) (नवम्बर 2010)		331.32	12.5/0	41.41
			2008-09 (नवम्बर 2010)		2697.10	12.5/0	337.14
4	डि0क0 वा0क0 सिकन्दराबाद	1	2008-09 (फरवरी 2011)	170.37	12.5/0	21.30	
	योग	4			3442.37		430.30

हमारे द्वारा मामले को विभाग/शासन को अगस्त 2012 एवं मई 2013 के मध्य प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने अगस्त 2013 में बताया कि धान के बाहरी छिलके में तेल नहीं होता है एवं यह अनुसूची-I के प्रविष्टि संख्या-4 से आच्छादित है। हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि पशु चारा के रूप में प्रयुक्त तेल रहित पैडी हस्क पर ही कर मुक्ति है इन प्रकरणों में पैडी हस्क का प्रयोग ईंधन के रूप में किया गया है न कि पशु आहार के रूप में। अतः इस खरीद/बिक्री पर ₹ 4.30 करोड़ का कर आरोपणीय था।

¹⁰³ कर निर्धारण पत्रावलियों एवं निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणियों से।

2.10.7 ट्रांसफार्मर एवं ट्रांसफार्मर के पुर्जों की बिक्री पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। ट्रांसफार्मर अनुसूची-II में दिनांक 29 सितम्बर 2008 तक वर्गीकृत था एवं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य था। इस तिथि के पश्चात् ट्रांसफार्मर को अनुसूची-II से हटा दिया गया और यह 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो गया। ट्रांसफार्मर के पुर्जे एवं ट्रांसफार्मर का तेल अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं है।

हमने पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों¹⁰⁴ की दिसम्बर 2011 एवं नवम्बर 2012 के मध्य जाँच में देखा कि पाँच व्यापारियों का वर्ष 2007-08 (वैट) से 2008-09 की अवधि का मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय क०नि०प्रा० ने जनवरी 2008 से सितम्बर 2008 के मध्य

किये गये ₹ 5.20 करोड़ के ट्रांसफार्मर, इनके पुर्जों एवं ट्रांसफार्मर के तेल की बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया। इस गलत करारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 44.22 लाख का कम कर आरोपित हुआ, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.22 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.22

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि०क० खण्ड-5 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	ट्रांसफार्मर के पुर्जे एवं तेल (v)	112.91	12.5/4	9.60
2	डि०क० खण्ड-6 वा०क० झांसी	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर के पुर्जे (v)	30.66	12.5/4	2.61
3	डि०क० खण्ड-16 वा०क० लखनऊ	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर का तेल (v)	13.42	12.5/4	1.14
4	डि०क० खण्ड-6 वा०क० मेरठ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	ट्रांसफार्मर (v)	186.03	12.5/4	15.81
5	डि०क० खण्ड-12 वा०क० मेरठ	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	ट्रांसफार्मर (v)	177.18	12.5/4	15.06
	योग	5			520.20		44.22

हमने मामले को सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2012 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। उत्तर में (दिसम्बर 2013) उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 3 पर वर्णित एक मामले में विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए ₹ 1.14 लाख का कर आरोपित कर दिया। अनेक अनुस्मारकों के बावजूद भी शेष मामलों के उत्तर एवं वसूली की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

2.10.8 ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन पर 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। ट्रैक्टर एवं अटैचमेन्ट अनुसूची-II में वर्गीकृत है एवं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य है ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर अनुसूची-II से IV में शामिल नहीं है।

हमने तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2012 के मध्य परीक्षण में देखा कि पांच व्यापारियों के मामले में वर्ष 2008-09 के लिए क०नि०प्रा० ने जुलाई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते

समय ₹ 3 करोड़ के ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों की बिक्री पर गलत दर से कर

¹⁰⁴ निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावलि।

आरोपित किया। जैसा कि ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं है अतः उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। हमने पाया कि व्यापारी द्वारा दाखिल विवरणियों/कर बीजकों में ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों की खरीद बिक्री का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, परन्तु क0नि0अ0 ने तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया। कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 25.52 लाख के कर का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण सारणी क्रमांक 2.23 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.23

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि0क0 खण्ड-14 वा0क0 आगरा	1	2008-09 (जुलाई 2011)	ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर (v)	15.11	12.5/4	1.28
2	डि0क0 खण्ड-6 वा0क0 मेरठ	1	2008-09 (फरवरी 2012)		46.71 (प्रा0)	12.5/4	3.97
		1	2008-09 (फरवरी 2012)		99.93 (के0)	12.5/4	8.49
					84.92	12.5/4	7.22
					3.69(प्रा0)	12.5/4	0.31
					36.02 (के0)	12.5/4	3.06
3	असि0क0 खण्ड-8 मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)		13.98	12.5/4	1.19
	योग	5			300.36		25.52

हमने प्रकरण विभाग/शासन को नवम्बर 2012 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया, अनेक अनुस्मारकों के उपरान्त भी उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

2.10.9 पेन्ट पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में सम्मिलित नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पेन्ट अनुसूची-I से IV में सम्मिलित नहीं है। यह न्यायिक रूप से निर्णीत* है कि यदि किसी वस्तु का प्रयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इस पर उस विशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत कर देयता है जहां यह वस्तु वर्गीकृत है।

* सर्वश्री प्यूमा आयुर्वेदिक हर्बल (प्रा0) लिमिटेड बनाम कमिश्नर केन्द्रीय उत्पाद के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

हमने दो वाणिज्य कर कार्यालयों में फरवरी 2013 एवं मार्च 2013 के मध्य देखा कि दो व्यापारियों के मामले में वर्ष 2008-09 की अवधि का कर निर्धारण अक्टूबर 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य करते समय क0नि0प्रा0 ने ₹ 13.78 करोड़ के पेन्ट (पाउडर कोटिंग) एवं पेन्ट ड्रायर को अनुसूची-V में वर्गीकृत करने के बजाय इन्हें

इपोक्सी रेजिन एवं केमिकल मिश्रण मानते हुए गलत दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ। जबकि सभी पाउडर कोटिंग एवं पेन्ट ड्रायर पेन्ट में कार्य में प्रयुक्त होता है एवं पेन्ट अनुसूची-I से IV में वर्गीकृत नहीं है इन वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था न कि चार प्रतिशत की दर से। पाउडर कोटिंग एवं पेन्ट ड्रायर के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी क्रमांक 2.24 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.24

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि०क० खण्ड-5 वा०क० मुरादाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	पेन्ट पाउडर कोटिंग (v)	142.57	12.5/4	12.12
2	ज्वा०क० (कापो० स०)-1 वा०क० वाराणसी	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	पेन्ट ड्रायर (v)	1235.25	12.5/4	104.99
योग		2			1,377.82		117.11

हमने मामले को विभाग/शासन को अप्रैल 2013 एवं जून 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग ने अगस्त 2013 में उत्तर में बताया कि ये वस्तुएँ पालिशिंग मैटीरियल/केमिकल का मिश्रण है जो अनुसूची-II ए के प्रविष्टि 29 में शामिल है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रविष्टि 29 में ये वस्तुएं शामिल नहीं हैं। जैसा कि पेन्ट ड्रायर एवं पेन्ट (पाउडर कोटिंग) विशेष रूप से विशिष्ट प्रयोजन के प्रयोग के लिए पेन्ट कम्पनियों¹⁰⁵ को बेचे गये थे उपर्युक्त वर्णित न्यायिक अभिमत के आलोक में वे अवर्गीकृत हैं एवं उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

2.11 क्रय कर का अनारोपण

उ०प्र०व्या० कर अधिनियम की धारा 3कककक के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यापारी जो किसी पंजीकृत व्यापारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति जिसके लिए वह कर योग्य है या नहीं से वह उस वस्तु के क्रय पर उसी दर से जिस दर से उसकी बिक्री पर कर देय है क्रय कर के भुगतान का दायी होगा।

हमने जून 2009 एवं मई 2011 के मध्य दो वा०क०का० के अभिलेखों¹⁰⁶ में देखा कि दो व्यापारियों ने अवधि 2006-07 से 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) में अपंजीकृत व्यापारियों से ₹ 1.89 करोड़ की खरीद

की। क०नि०प्रा० ने नवम्बर 2008 एवं जनवरी 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय रिटर्नों की जांच नहीं की और अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किये गये ₹ 1.89 करोड़ के माल पर कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.13 लाख का कर अनारोपित रहा जैसा कि सारणी क्रमांक 2.25 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.25

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर
1	डि०क० वा०क० डिबाई बुलन्दशहर	1	2006-07 (नवम्बर 2008)	टिम्बर	52.79	2.5	0	1.32
2	डि०क० खण्ड-8 वा०क० कानपुर	1	2006-07 (अक्टूबर 2010)	टिन कन्टेनर	96.47	5	0	4.82
			2007-08 (1.4.07 से 31.12.07 तक) (जनवरी 2011)		39.79	5	0	1.99
योग		2			189.05			8.13

¹⁰⁵ पेन्ट बनाने वाली कम्पनी को बिक्री जिनके नाम हैं- एशियन पेन्ट्स लि० (विभिन्न इकाइयों), बर्जर पेन्ट्स इंडिया लि० राजदूत डिवीजन जम्मू, कामधेनु पेन्ट (कामधेनु इस्पात लि०) का डिवीजन अलवर राजस्थान, मोनार्क पेन्ट्स, पंजाब पेन्ट्स कलर (प्रा०) लि० कानपुर, नेरोलेक पेन्ट्स लि० कानपुर इत्यादि।

¹⁰⁶ व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियाँ।

हमने विभाग एवं शासन को जुलाई 2009 से जून 2011 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया। विभाग ने आपत्ति को पूर्णरूप से स्वीकार करते हुए (अगस्त 2013) ₹ 8.13 लाख का कर आरोपित किया। वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2013)।

2.12 अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि अनियमित संव्यवहार लेखों से बाहर संव्यवहार उ0प्र0 व्या0क0 और उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम अर्थदण्ड के आरोपण एवं ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.10 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण एवं ब्याज प्रभारित नहीं हुआ जैसा कि अग्रतर प्रस्तारों में उल्लिखित है:

2.12.1 विलम्ब से कर जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(ए) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-54 (1)(1) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है या इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर को जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो तो वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में ऐसे देय कर का न्यूनतम 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 से अधिक हो उ0प्र0व्या0कर अधिनियम के अन्तर्गत तथा देय कर का 20 प्रतिशत उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत अदा करें।

हमने अक्टूबर 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य 22 वा0क0का0¹⁰⁷ में देखा¹⁰⁸ कि 27 व्यापारियों ने अवधि 2006-07 से 2009-10 के लिए ₹ 5.49 करोड़ के अपने स्वीकृत कर को समय से जमा नहीं किया था विलम्ब की अवधि चार से 844 दिनों तक की थी क0नि0प्रा0 ने मार्च 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय देय कर के अतिरिक्त ₹ 99.47 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा विभाग/शासन को नवम्बर 2009 एवं फरवरी 2013 के मध्य प्रकरणों को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार (अगस्त 2013) किया और 12 मामलों में ₹ 79.61 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। शेष मामलों कार्यवाही प्रारम्भ व वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2013)।

2.12.2 टर्नओवर/अपवंचित देय कर के छिपाये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(सी) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझकर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है जो वह ऐसे व्यापारी को कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

2.12.2.1 हमने जुलाई 2009 एवं जून 2012 के मध्य सात वा0क0का0 में देखा¹⁰⁹ कि सात व्यापारियों ने अवधि 2000-01 से 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) के दौरान ₹ 4.21 करोड़ विक्रय टर्नओवर को छिपाया था, जिस पर क0नि0प्रा0 द्वारा

¹⁰⁷ डि0क0 खण्ड-2 इलाहाबाद, ज्वा0क0 (कापी0सा0) बरेली, डि0क0 खण्ड-3 बुलन्दशहर, डि0क0 खण्ड-1 बस्ती, डि0क0 खण्ड-4 बाराबंकी, डि0क0 खण्ड-3 एटा, ज्वा0क0 (कापी0सा0)-अ गाजियाबाद, ज्वा0क0 (कापी0सा0)-ब गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-18 गाजियाबाद, ज्वा0क0 (कापी0सा0) गौतमबुद्ध नगर, डि0क0 खण्ड-6 झांसी, डि0क0 खण्ड-25 कानपुर, ज्वा0क0 (कापी0सा0) जोन-1 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-5 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-14 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-15 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-22 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-2 महाराजगंज, डि0क0 खण्ड-3 नोयडा, डि0क0 खण्ड-11 नोयडा, अरि0क0 खण्ड-9 नोयडा, डि0क0 खण्ड-12 सहारनपुर।

¹⁰⁸ व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली।

¹⁰⁹ व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली।

फरवरी 2007 एवं जनवरी 2012 के मध्य ₹ 37.26 लाख का कर आरोपित किया गया परन्तु क०नि०प्रा० ने ₹ 18.63 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि सारणी क्रमांक 2.26 दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.26

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	छिपाया गया टर्नओवर	छिपाये गये टर्नओवर पर लगाया गया कर	न्यूनतम अर्थदण्ड
1	डि०क० खण्ड-1 वा०क० चन्दौली	1	2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) (जनवरी 2012)	55.46	2.22	1.11
2	असि०क० खण्ड-4 वा०क० गाजियाबाद	1	2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) (अगस्त 2011)	32.89	2.63	1.32
3	असि०क० खण्ड-29 वा०क० कानपुर	1	2005-06 (जुलाई 2010)	207.35	22.81	11.40
4	डि०क० खण्ड-1 वा०क० मऊ	1	2000-01 (फरवरी 2007)	5.23	0.57	0.28
			2001-02 (फरवरी 2007)	22.14	1.56	0.78
			2002-03 (फरवरी 2007)	12.24	1.28	0.64
5	असि०क० खण्ड-8 वा०क० मुरादाबाद	1	2000-01 (अगस्त 2002)	19.16	1.67	0.84
6	असि०क० खण्ड-8 वा०क० नोयडा	1	2005-06 (अप्रैल 2010)	31.00	3.10	1.55
7	डि०क० खण्ड-13 वा०क० वाराणसी	1	2000-01 (दिसम्बर 2010)	35.44	1.42	0.71
योग		7		420.91	37.26	18.63

(₹ लाख में)

हमारे द्वारा विभाग/शासन को सितम्बर 2009 एवं जुलाई 2012 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने अपने उत्तर में हमारी आपत्तियों (दिसम्बर 2013) को स्वीकार करते हुए तीन मामलों¹¹⁰ में ₹ 25.22 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जिसमें से अब तक ₹ 1.55 लाख की वसूली हो चुकी है। विभाग ने दो अन्य मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद शेष दो मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा-54(1)(2) के अन्तर्गत जहाँ पर व्यापारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है तो क०नि०प्रा० व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड का भुगतान करे।

2.12.2.2 हमने अगस्त 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य 44 वा०क०का०¹¹¹ के अभिलेखों¹¹² में देखा कि 55 व्यापारियों ने अवधि 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) से 2010-11 के मध्य

₹ 23.57 करोड़ खरीद और बिक्री के टर्नओवर को छिपाया गया था। क०नि०प्रा० ने दिसम्बर 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 1.09 करोड़ कर आरोपित किया। यद्यपि अपीलीय प्राधिकारियों ने

¹¹⁰ सारणी 2.26 के क्रम संख्या 3, 4 एवं 7

¹¹¹ डि०क० खण्ड-12 आगरा, असि०क० खण्ड-16 आगरा, डि०क० खण्ड-5 अलीगढ़, डि०क० खण्ड-2 बदायूँ, डि०क० खण्ड-4 बाराबंकी, डि०क० खण्ड-3 बरेली, डि०क० खण्ड-4 बुलन्दशहर, डि०क० खण्ड-1 चन्दौली, असि०क० खण्ड-1 चन्दौली, डि०क० खण्ड-1 फैजाबाद, डि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-18 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-4 गोण्डा, डि०क० खण्ड-12 गोरखपुर, डि०क० खण्ड-1 कानपुर, डि०क० खण्ड-12 कानपुर, डि०क० खण्ड-16 कानपुर, डि०क० खण्ड-17 कानपुर, डि०क० खण्ड-18 कानपुर, डि०क० खण्ड-28 कानपुर, डि०क० खण्ड-29 कानपुर, असि०क० खण्ड-1 कानपुर, असि०क० खण्ड-2 कानपुर, असि०क०(इन्वार्ज) कौशांबी, असि०क० खण्ड-16 लखनऊ, डि०क० खण्ड-2 महाराजगंज, असि०क० खण्ड-5 मथुरा, डि०क० खण्ड-2 मिर्जापुर, असि०क० खण्ड-7 मुरादाबाद, असि०क० खण्ड-8 मुरादाबाद, असि०क० खण्ड-4 मुजफ्फरनगर, ज्वा०क० (कापी०स०)-1 नजीबाबाद, डि०क० खण्ड-1 नजीबाबाद, डि०क० खण्ड-6 नोयडा, डि०क० खण्ड-8 नोयडा, डि०क० खण्ड-9 नोएडा, डि०क० खण्ड-10 नोएडा, असि०क० खण्ड-2 नोएडा, असि०क० खण्ड-6 नोएडा, डि०क० खण्ड-1 प्रतापगढ़, डि०क० खण्ड-6 सहारनपुर, डि०क० खण्ड-1 सोनमढ़ एवं डि०क० खण्ड-8 वाराणसी।

¹¹² व्यापारियों का अंतिम क०नि०अ०, स्वीकृत कर जो व्यापारियों द्वारा जमा कर दिया गया है और अपीलीय प्राधिकारियों का आदेश।

(दिसम्बर 2010 और सितम्बर 2012 के मध्य) व्यापारियों द्वारा छिपाये गये टर्नओवर/देय कर का अपवंचन की पुष्टि की या व्यापारियों द्वारा इसे स्वयं स्वीकार¹¹³ करते हुए छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया गया, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने ₹ 3.27 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा विभाग/शासन को सितम्बर 2011 एवं मई 2013 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने उत्तर में हमारी आपत्तियों को स्वीकार (सितम्बर 2013) करते हुए 20 मामलों में ₹ 48.58 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद इन मामलों में वसूली की स्थिति और अन्य शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

2.12.3 मिथ्या घोषणा पत्र जारी करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(एल) के अन्तर्गत कोई व्यापारी जो मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी करता है या प्रस्तुत करता है, जिसके कारण कर आरोपणीय नहीं रह जाता तो वह कर के अतिरिक्त ऐसे कर की धनराशि जो बचा ली गयी होती के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की राशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा।

हमने नवम्बर 2009 एवं जुलाई 2011 के मध्य देखा¹¹⁴ कि दो व्यापारियों ने मिथ्या घोषणा पत्र जारी अथवा प्रस्तुत किया था जिसके कारण वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 के मध्य की गई खरीद अथवा बिक्री ₹

11.43 लाख पर कर आरोपित नहीं हुआ तथापि क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य इन व्यापारियों का कर निर्धारण करते समय न्यूनतम ₹ 5.72 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। नीचे दी गई सारणी क्रमांक 2.27 में विवरण दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.27

क्र0 सं0	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	टर्नओवर	मिथ्या घोषणा पत्र जारी करके बचाया गया कर	आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड (₹ लाख में)
1	डि0क0 खण्ड-5 वा0क0 मथुरा	2002-03 (अप्रैल 2008)	रोड़ी, गिट्टी, बदरपुर एवं बालू	42.13	1.88	0.94
2	ज्वा0क0 (कापी0स0) वा0क0 राबर्टसगंज सोनमद्र	2004-05 (मार्च 2011)	एलुमिनियम इन्गट एवं रिडा राइस	159.25	9.55	4.78
योग				201.38	11.43	5.72

हमारे द्वारा दिसम्बर 2009 एवं सितम्बर 2011 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने हमारे बिन्दु को स्वीकार (अगस्त 2013) किया और बताया कि अर्थदण्ड के आरोपण की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है; अब तक ₹ 46,000 की वसूली हो चुकी है।

¹¹³ डि0क0 खण्ड-3 बरेली, के एक मामले व्यापारी द्वारा क0नि0प्रा0 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की गयी।

¹¹⁴ व्यापारी से सम्बन्धित क0नि0 आदेश एवं पत्रावलियों।

2.12.4 कम काटे गये/विलम्ब से जमा सकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा-8 डी (6) एवं उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को सकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी सकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा और कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क०नि०प्रा० ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

2.12.4.1 हमने सितम्बर 2011 एवं अगस्त 2012 के मध्य 13 वा०क०का० के कर निर्धारण आदेशों में देखा कि 13 व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 एवं 2008-09 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 1.44 करोड़ के सकर्म संविदा कर की कटौती की परन्तु उसे निर्धारित समयावधि के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि तीन दिन से लेकर 1285 दिनों तक की थी। क०नि०प्रा० ने मार्च 2009 एवं अप्रैल 2012 के मध्य

कर निर्धारण करते समय ₹ 2.88 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.28 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.28

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०क० खण्ड-2 वा०क० आजमगढ़	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	4.81	26 से 78	9.61
2	असि०क० खण्ड-2 वा०क० अमरोहा	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	4.17	120 से 181	8.34
3	डि०क० खण्ड-12 वा०क० गाजियाबाद	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (माच 2010)	3.67	117 से 362	7.34
			2007-08 (वैट) (मार्च 2010)	1.88	38 से 98	3.77
4	असि०क० खण्ड-16 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	3.43	7 से 38	6.86
5	असि०क० खण्ड-3 वा०क० गौतमबुद्धनगर	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (दिसम्बर 2010)	30.68	6 से 421	61.36
			2007-08 (वैट) (दिसम्बर 2010)	11.28	16 से 690	22.56
6	असि०क० खण्ड-4 वा०क० गोण्डा	1	2008-09 (मार्च 2012)	28.18	13 से 115	56.35
7	ज्वा०क० (कार्पो०सं०)-2 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	2.32	63 से 275	4.64
8	डि०क० खण्ड-12 वा०क० लखनऊ	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	8.34	13 से 26	16.68
9	डि०क० खण्ड-7 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	30.83	24 से 94	61.66
10	असि०क० खण्ड-8 वा०क० मुरादाबाद	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	3.49	19 से 1182	6.98
11	डि०क० खण्ड-11 वा०क० नोएडा	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (जुलाई 2010)	1.10	12 से 23	2.20
12	असि०क० खण्ड-3 वा०क० नोएडा	1	2005-06 (उ०प्र०व्या०क०) (माच 2009)	1.34	3 से 1285	2.68
13	असि०क० खण्ड-1 वा०क० रामपुर	1	2008-09 (अगस्त 2011)	8.52	17 से 53	17.04
	योग	13		144.04		288.07

हुआ। विवरण सारणी 2.29 में दर्शाया गया है:

पंजीयन प्रमाण पत्र और उपयोग किंसे गये काम 'सी' के विवरण की जांच नहीं की। कोई निवारक कार्रवाई नहीं की गई, अतः ₹ 99.86 लाख का अर्धदण्ड आरोपित नहीं कर निर्धारण करते समय एवं मार्च 2012 के मध्य क०नि०प्र० ने मार्च 2009 से आच्छादित नहीं था। उनके पंजीयन प्रमाण पत्र 2009 पर खरीद जो कि क०नि०प्र० की रियायती कर की रियायती दर पर खरीद गये माल का प्रयोग उस प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से क०नि०प्र० अधिनियम के अन्तर्गत उसका जाही पंजीयन पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल 10 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फर्म 'सी' की धारणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर धारणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से क०नि०प्र० अधिनियम के अन्तर्गत उसका जाही पंजीयन प्रमाण पत्र जाही किया गया है तो व्यापारी अभियोजन प्रयोग होता है। यद्यपि अभियोजन के बदले यदि क०नि०प्र० उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के दंड गूने तक का अर्धदण्ड आरोपित कर सकता है।

इसने अगस्त 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य 'देखा'¹¹⁸ कि वर्ष 2005-06 एवं 2009-10 के दौरान 10 व्यापारियों ने फर्म 'सी' की धारणा के आधार पर ₹ 6.83 करोड़ का माल क०नि०प्र० की रियायती दर पर खरीद जा कि प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से क०नि०प्र० अधिनियम के अन्तर्गत उसका जाही पंजीयन प्रमाण पत्र जाही किया गया है तो व्यापारी अभियोजन प्रयोग होता है। यद्यपि अभियोजन के बदले यदि क०नि०प्र० उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के दंड गूने तक का अर्धदण्ड आरोपित कर सकता है।

2.12.5 क०नि०प्र० के अन्तर्गत अर्धदण्ड का अनारोपण

प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)। का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्धदण्ड एवं कम आरोपित जमा कर की वर्सुली का अर्धदण्ड आरोपित किया। तथापि ₹ 90.52 लाख के कम आरोपित कर की वर्सुली अपने उत्तर में हमारी आपत्ति को स्वीकार (दिसम्बर 2013) करते हुए ₹ 1.81 करोड़ इमने प्रकरण को दिसम्बर 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने आरोपण हुआ।

दिया। इसके परिणामस्वरूप अर्धदण्ड के अलावा ₹ 90.52 लाख के कम कर की वर्सुली पर की गयी कर की कम कटौती पर ध्यान नहीं कटौती करके जमा किया जाना अपेक्षित था। मार्च 2012 में क०नि०प्र० ने कर निर्धारण प्रारणों के अन्तर्गत खोल पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 2.29 करोड़ के कर की जबकि संविदाकार को ₹ 57.29 करोड़ का भुगतान किया गया था। अधिनियम के 2008-09 के दौरान एक व्यापारी¹¹⁷ द्वारा खोल पर ₹ 1.39 करोड़ की कटौती की गयी 2012 में अगस्त 2012 में हि०क० खण्ड-8 के अभिलेखा¹¹⁶ में देखा कि वर्ष

गयी है।

करोड़ का अर्धदण्ड आरोपित कर दिया गया, शेष मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी प्रतिवेदित किंसे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि साल मामलों¹¹⁵ में ₹ 1.08 हमारे द्वारा विभाग/शासन को नवम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य प्रकरण को

सारणी क्रमांक 2.29

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	पंजीयन प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओं के नाम	खरीद का मूल्य	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०क० खण्ड-2 वा०क० बाराबंकी	1	2006-07 (मार्च 2009)	यार्न	13.30	8	12	1.60
2	डि०क० खण्ड-5 वा०क० गोरखपुर	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	डी०जी० सेट ट्रक ¹¹⁹ माउन्टेक, बैचिंग प्लान्ट बैटोनाइट पाउडर और टाट ट्रिपर (उ०प्र० व्या०क०) बैटरी	397.02	10	15	56.85
3	डि०क० खण्ड-1 वा०क० ग्रेटर नोएडा	1	2008-09 (मार्च 2012)	इजन और शटरिंग मैटरियल	7.92	10	15	1.19
				यू जेक	3.71	12	18	0.67
				टाइल्स और शटरिंग मैटरियल	11.55	12.5	18.75	2.16
4	डि०क० खण्ड-18 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	किचये पर डी०जी० सेट (उ०प्र०व्य० क०)	29.20	10	15	4.38
				किचये पर डी०जी० सेट (वैट)	20.86	4	6	1.25
5	असि०क० खण्ड-1 वा०क० लखीमपुर खीरी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	डी०जी० सेट	11.99	4	6	0.72
6	डि०क० खण्ड-19 वा०क० लखनऊ	1	2006-07 (मार्च 2009)	डी०जी० सेट	88.02	10	15	13.20
7	डि०क० खण्ड-4 वा०क० मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)	हाट मिक्स प्लान्ट	23.72	12.50	18.75	4.45
				एयर कम्प्रेसर जनरेटर जे०सी०बी०डी० एक्स वाइब्रेटर और वैट मिक्स प्लान्ट	53.63	12.50	18.75	10.05
8	असि०क० खण्ड-09 वा०क० नोएडा	1	2007-08 (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर के पार्ट्स एवं एसेसरीज	4.66	12.50	18.75	0.87
				डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स और केमीकल	0.62	4	6	0.04
9	डि०क० खण्ड-09 वा०क० सहारनपुर	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (अगस्त 2011)	बी०ओ०पी०पी० टेप (वैट)	0.24	4	6	0.01
				एडहेसिव/ गम एवं सिंक स्लीब्स (वैट)	0.61	12.50	18.75	0.11
				बी०ओ०पी०पी० टेप (उ०प्र० व्या०क०)	0.24	5	7.50	0.02
				एडहेसिव (उ०प्र० व्या०क०)	0.18	12	18	0.03
				सिंक स्लीब्स और प्लारिस्टिक बैग (उ०प्र० व्या०क०)	2.29	10	15	0.34
10	डि०क० खण्ड-17 वा०क० वाराणसी	1	2005-06 (मार्च 2009)	डी०जी०सेट और हाट गियर्ड ट्राली ग्राइन्डर बेस प्लेट	12.81	10	15	1.92
योग		10			682.57			99.86

हमारे द्वारा दिसम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) छः मामलों¹²⁰ में ₹ 22.18 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और बताया कि शेष मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

¹¹⁹ पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित अवधि के पूर्व की अवधि में रियायती दर का दावा किया गया।

¹²⁰ क्रम संख्या 1, 5, 6, 8, 9 और 10।

हमने प्रकरण को मई 2013 में विभागा/एवं शासन को इंतित किया। अनेक अर्जसकारकों के भेजे जाने के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.88 लाख के कर एवं ब्याज की अर्जित करमुक्ति प्रदान की करने के बजाय काम 'एफ' से अनाच्छादित आवत पर अर्जित कर मुक्ति प्रदान किया। गया। कोनि0310 ने ₹ 3.93 लाख कर¹²⁶ एवं साध ही ₹ 2.95 लाख ब्याज आरोपित इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 98 लाख के संव्यवहार हेतु काम 'एफ' प्रस्तुत नहीं किया। काम 'एफ' प्रस्तुत किया।

संव्यवहार से आच्छादित संव्यवहार से आच्छादित करों के लिए ₹ 1.99 करोड़ के लिए मातृ (2008) के लिए (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2007-08 व्यापारी ने वर्ष 2007-08 को। कोनि0 के समय की अर्जित बिक्री एतित करों मूल्य के क्राट वषर रूप पत्र-24 में ₹ 2.97 करोड़ के मासिक विवरणी मातृ (2008) के दौरान एक (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2007-08 देखा कि वर्ष 2007-08 नजीबाबाद के अभिलेखों में 10क0 10क0-1 10क0-1

है।
काम 'एफ' पर वार प्रविष्टि की दर से कर आरोपणीय कर 30000000 कर अधिनियम के अनुसूची-II के अन्तर्गत मासिक विवरणी रूप पत्र-24 में दाखिल करना है। व्यापारी को अर्जित बिक्री के विषय में पृथक सूचना 30000000 कर नियमावली के नियम 45(2) के अन्तर्गत अथवा बिक्री पर लागू कर की दर से कर आरोपणीय है। काम 'एफ' से अच्छादित नहीं है वहां ऐसी वस्तु की खरीद संव्यवहार आच्छादित होगा ऐसे मामलों में जहां संव्यवहार एकदर होगा। एक काम 'एफ' पर एक कैलन्डर मास का संख्या और तिथि का उल्लेख है तो वह करमुक्ति का कर्तव्य पत्नीयन संख्या, वेधता की अवधि, क्रय आदेश की काम 'एफ' से एक घोषणा प्रस्तुत करता है जिसमें उसकी पर कर निर्धारण के समय अन्तर्लि (दस्तावेज़ों) से प्राप्त नियमावली के नियम 12(5) के अन्तर्गत यदि एक व्यापारी को 10क0 अधिनियम की धारा 6 ए सफहित को 10क0 व्यापारी के नियम 12(5) के अन्तर्गत यदि एक व्यापारी पर कर निर्धारण के समय अन्तर्लि (दस्तावेज़ों) से प्राप्त काम 'एफ' से एक घोषणा प्रस्तुत करता है जिसमें उसकी कर्तव्य पत्नीयन संख्या, वेधता की अवधि, क्रय आदेश की तिथि और तिथि का उल्लेख है तो वह करमुक्ति का एकदर होगा। एक काम 'एफ' पर एक कैलन्डर मास का संव्यवहार आच्छादित होगा ऐसे मामलों में जहां संव्यवहार काम 'एफ' से अच्छादित नहीं है वहां ऐसी वस्तु की खरीद व्यापारी को अर्जित बिक्री के विषय में पृथक सूचना 30000000 कर अधिनियम के अनुसूची-II के अन्तर्गत मासिक विवरणी रूप पत्र-24 में दाखिल करना है।

2.14.2 पार्षण बिक्री पर अर्जित कर मुक्ति

हमारे द्वारा इन मामलों को इंतित किया जाने पर विभागा ने हमारी आपतित स्वीकार करते हुए कहा कि कायदाही की जा रही है एवं एक मामले¹²⁵ में को 10क0 आरोपित करके वसूली कर ली गयी है। अन्य मामलों में वसूली प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

हमने इस प्रकार की मई 2013 में विभाग/शासन की प्रतिवेदन किया विभाग ने उत्तर में हमारी आपत्ति को स्वीकार (दिसम्बर 2013) करते हुए ₹ 81.88 लाख का कर आयोजित कर दिया। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

आलोक में इस केन्द्रीय विभागीय पर कर मुक्ति अर्जमन्थ नहीं है। इस प्रकार क०नि०प्रा० नं

हमने मार्च 2013 में
 वृ०-1
 नजीबाबाद के कर निर्धारण में देखा कि
 क०नि०प्रा० नं मार्च 2011
 में एक व्यापारी का वर्ष
 2007-08 (1 अप्रैल 2007
 से 31 दिसम्बर 2007) के
 लिए कर निर्धारण करते
 समय काम 'सी' से
 आच्छादित
 ₹ 3.96
 करोड़ के वीरे की
 अन्तर्प्रान्तीय विभागीय
 ₹ 11.88 लाख एवं छुपाये
 गये टर्नओवर ₹ 3.50
 करोड़ पर ₹ 70 लाख की
 अर्जित कर मुक्ति प्रदान
 कयी। व्यापारी को
 प्रशासनिक खर्च का
 भुगतान किसे जाने के
 आधार पर क०नि०प्रा० द्वारा
 यह अर्जित कर मुक्ति
 प्रदान की गयी। व्यापारी
 वीरे की विभागीय पर कर
 मुक्ति सामान्य न होकर
 वही, मा० उच्च
 न्यायालय के निर्णय के
 अनुसार प्रदान की।

क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत काम (1) के अन्तर्गत काम 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अन्तर्प्रान्तीय विभागीय पर 1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है तथा क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत काम (2) के अन्तर्गत काम 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की विभागीय पर 1 अप्रैल 2007 से उस समस्त वस्तु की खरीद या विभागीय पर आरोपणीय कर की दर से कर आरोपणीय है। पुनरेव विभागीय पर 2007 तक 20 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। यह व्यापारी रूप से निर्णीत है कि यदि प्रशासनिक प्रमाण का भुगतान किया गया है तो उ०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत विभागीय पर 8 (2क) के प्रावधान वही लागू अन्तर्प्रान्तीय विभागीय के मामले में लागू नहीं है। पुनरेव व्यापारी रूप से यह भी निर्णीत है कि क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर से मुक्त की गयी है न कि कुछ विशेष परिस्थितियों में।

* सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत काम (1) के अन्तर्गत काम 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अन्तर्प्रान्तीय विभागीय पर 1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। यह व्यापारी रूप से निर्णीत है कि यदि प्रशासनिक प्रमाण का भुगतान किया गया है तो उ०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत विभागीय पर 8 (2क) के प्रावधान वही लागू अन्तर्प्रान्तीय विभागीय के मामले में लागू नहीं है। पुनरेव व्यापारी रूप से यह भी निर्णीत है कि क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर से मुक्त की गयी है न कि कुछ विशेष परिस्थितियों में।

क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत काम (1) के अन्तर्गत काम 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अन्तर्प्रान्तीय विभागीय पर 1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। यह व्यापारी रूप से निर्णीत है कि यदि प्रशासनिक प्रमाण का भुगतान किया गया है तो उ०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत विभागीय पर 8 (2क) के प्रावधान वही लागू अन्तर्प्रान्तीय विभागीय के मामले में लागू नहीं है। पुनरेव व्यापारी रूप से यह भी निर्णीत है कि क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर से मुक्त की गयी है न कि कुछ विशेष परिस्थितियों में।

उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत काम (1) के अन्तर्गत काम 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अन्तर्प्रान्तीय विभागीय पर 1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। यह व्यापारी रूप से निर्णीत है कि यदि प्रशासनिक प्रमाण का भुगतान किया गया है तो उ०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर के अन्तर्गत विभागीय पर 8 (2क) के प्रावधान वही लागू अन्तर्प्रान्तीय विभागीय के मामले में लागू नहीं है। पुनरेव व्यापारी रूप से यह भी निर्णीत है कि क०नि०प्रा० अर्जित कर मुक्ति प्रदान कर से मुक्त की गयी है न कि कुछ विशेष परिस्थितियों में।

2.14.3 वीरे की अन्तर्प्रान्तीय विभागीय पर अर्जित कर मुक्ति

2.14.4 फार्म "एच" के विरुद्ध अनुचित कर मुक्ति

के0बि0क0 अधिनियम की धारा-5 सपठित के0बि0क0 नियमावली (पंजीकरण एवं आवर्त) के नियम 12(10) के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय या क्रय हुआ तभी समझा जायेगा जब उस विक्रय या क्रय से ऐसा निर्यात होता है या वह विक्रय या क्रय भारत के सीमा शुल्क सीमान्तों से माल के पार हो जाने के पश्चात इस शर्त के साथ माल की हक दस्तावेजों के अन्तरण (ट्रांसफर) किया जाता है कि घोषणा प्रपत्र 'एच' में करेगा एवं कर निर्धारण के समय प्राधिकारी के समय प्रस्तुत करेगा। प्रपत्र 'एच' निर्यातक (क्रेता व्यापारी) द्वारा विक्रेता व्यापारी को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र है कि उससे क्रय की गई वस्तु भारत के बाहर निर्यात कर दी गयी है। पुनश्च प्रपत्र 'सी' के लिए लागू त्रैमासिक प्रपत्र प्रस्तुत करने के नियम एवं शर्त प्रपत्र 'एच' में प्रमाण पत्र के लिए भी लागू होगी।

हमने दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य दो वा0क0का0 के अभिलेखों¹²⁸ देखा कि दो व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 (1 अप्रैल 2007 से 31 दिसम्बर 2007) की अवधि में ₹ 7.02 करोड़ मूल्य के माल का निर्यात किया एवं प्रत्येक ने प्रत्येक त्रैमास हेतु पृथक प्रपत्र 'एच' प्रस्तुत करने के बजाय पूरे वर्ष 2007-08 के संव्यवहार के लिए एक प्रपत्र 'एच' प्रस्तुत किया। सम्पूर्ण संव्यवहार में से ₹ 1.06 करोड़ का संव्यवहार एक त्रैमास से अधिक से सम्बन्धित था। जुलाई 2009 तथा फरवरी

2010 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0नि0अ0 ने ₹ 10.47 लाख की अनुचित कर मुक्ति प्रदान किया जैसा कि सारणी क्रमांक 2.31 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.31

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	प्रपत्र 'एच' से आच्छादित वस्तु का मूल्य	एक त्रैमास से अधिक का संव्यवहार	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	(₹ लाख में) अनारोपित कर
1	डि0क0 वा0क0 कोसीकला	1	2007-08 (फरवरी 2010)	एसिड कैसिन, लैक्टोस, ग्रेड पाउडर	652.19	81.20	8	6.50
2	असि0क0 खण्ड-4 वा0क0 मुरादाबाद	1	2007-08 (जुलाई 2010)	ग्लास वेयर	50.20	24.84	16	3.97
योग		2			702.39	106.04		10.47

हमारे द्वारा मामले को जनवरी 2011 एवं मई 2012 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि दोनों मामलों में ₹ 10.47 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

2.15 राज्य विकास कर का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3 ज सपठित कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 3 मई 2005 प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50 लाख से अधिक समेकित वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त रा0वि0 क0 वसूल किया जायेगा।

हमने अक्टूबर 2008 एवं जुलाई 2012 के मध्य 9 वा0क0 का0 में 10 व्यापारियों के कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच में देखा कि उनका समेकित वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक था। क0नि0प्रा0 ने अवधि 2005-06 से 2007-08

¹²⁸ व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं कर निर्धारण आदेश।

(दिसम्बर 2007 तक) के लिए कर निर्धारण¹²⁹ करते समय ₹ 81.21 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर रा0वि0क0 आरोपित नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 81.21 लाख रा0वि0क0 अनारोपित रहा जैसा कि सारणी क्रमांक 2.32 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.32

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय राज्य विकास कर
1	डि०क० खण्ड-12 वा०क० आगरा	1	2006-07 (अक्टूबर 2011)	635.35	6.35
2	असि०क० खण्ड-5 वा०क० गाजियाबाद	1	2007-08 (मार्च 2010)	111.00	1.11
		1	2007-08 (मार्च 2010)	87.00	0.87
3	डि०क० खण्ड-15 वा०क० गाजियाबाद	1	2005-06 (फरवरी 2010)	62.89	0.63
4	डि०क० खण्ड-9 वा०क० गोरखपुर	1	2005-06 (सितम्बर 2011)	96.76	0.97
5	डि०क० खण्ड-28 वा०क० कानपुर	1	2006-07 (दिसम्बर 2010)	143.97	1.44
6	डि०क० खण्ड-1 वा०क० कानपुर	1	2005-06 (फरवरी 2008)	6,377.87	63.78
7	डि०क० खण्ड-2 नोएडा	1	2006-07 (दिसम्बर 2011)	170.08	1.70
8	असि०क० खण्ड-2 वा०क० रामपुर	1	2006-07 (दिसम्बर 2010)	184.23	1.84
9	असि०क० वा०क० शिकोहाबाद	1	2005-06 (जून 2008)	252.08	2.52
योग		10		8,121.23	81.21

हमारे द्वारा जनवरी 2009 एवं अगस्त 2012 के मध्य इन मामलों को इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया कि छः मामलों (उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 6 और 9) में ₹ 73.74 लाख का रा0वि0क0 आरोपित कर दिया गया है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद शेष मामलों में वसूली की सूचना एवं उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

¹²⁹ फरवरी 2008 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।

130 अर्थोपकरण-11 आग, अर्थोपकरण-12 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-13 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-14 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-15 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-16 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-17 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-18 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-19 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-20 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-21 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-22 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-23 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-24 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-25 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-26 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-27 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-28 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-29 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-30 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-31 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-32 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-33 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-34 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-35 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-36 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-37 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-38 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-39 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-40 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-41 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-42 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-43 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-44 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-45 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-46 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-47 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-48 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-49 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-50 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-51 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-52 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-53 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-54 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-55 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-56 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-57 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-58 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-59 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-60 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-61 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-62 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-63 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-64 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-65 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-66 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-67 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-68 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-69 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-70 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-71 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-72 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-73 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-74 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-75 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-76 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-77 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-78 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-79 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-80 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-81 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-82 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-83 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-84 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-85 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-86 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-87 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-88 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-89 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-90 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-91 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-92 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-93 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-94 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-95 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-96 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-97 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-98 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-99 अर्थोपकरण, अर्थोपकरण-100 अर्थोपकरण

हमने मामले का जून 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य विभाग/शासन की प्रतिवेदन किया, विभाग ने सितम्बर 2013 में हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि आठ मामलों¹³² में ₹ 1.29 लाख का अर्धवृद्ध एवं ब्याज आरक्षित कर दिया गया है, एवं अब तक ₹ 31,096 की वसूली की जा चुकी है। 12 मामलों¹³³ में कार्यावृत्ति प्रारम्भ कर दी गयी है एवं शेष मामलों में सुधारानत्मक कार्यावृत्ति करी गई है।

अनारोपण की समाप्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।
 विन संचनाओं की अनदेखी की। इस प्रकार अनारोपित इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं देखा कि कर निर्धारण वादों को लीनड घोषित करते समय कंजिंटोरियो ने विवरणों में एवं नियमित संचनाओं के पत्रवाले किया जाना अपेक्षित था। इन सभी मामलों में हमने लेखा पुस्तकों के परीक्षण का निस्तारण व्यापारियों के जारी है। अतः इन वादों धनराशि भी संचिदध है टैक्स क्रेडिट की अनुमत्य की धनराशि और इनपुट टैक्स का आवर्त विवरणनीय नहीं विकस या कथ या दोनों पूर्ण संचना के अभाव में अर्पण/माल संचना¹³¹ दी।

हमने 88 घोषित कर¹³⁰ कायलियों में स्वकर निर्धारण वादों में से वर्ष 2012-13 में 1693 मामलों की जांच की एवं पाया कि इनमें से 12 प्रतिशत मामलों में व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए कर विवरणों के निरधारित प्रपत्र में संचिदध/माल संचना के अभाव में पूर्ण संचना के अभाव में विकस या कथ या दोनों का आवर्त विवरणनीय नहीं रह जाला है एवं देय कर उक्त निरधारित और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमत्य की धनराशि भी संचिदध है जारी है। अतः इन वादों का निस्तारण व्यापारियों के लेखा पुस्तकों के परीक्षण एवं नियमित संचनाओं के पत्रवाले किया जाना अपेक्षित था। इन सभी मामलों में हमने देखा कि कर निर्धारण वादों को लीनड घोषित करते समय कंजिंटोरियो ने विवरणों में एवं देखा कि अनारोपण की समाप्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।

2.16 अर्पण संचना होने पर भी वाद को लीनड घोषित किया जाना

2.17 ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किये जाने के कारण विलम्ब की तिथि तक ₹ 59.65 लाख का ब्याज आकर्षित होता है। क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण करते समय यह प्रभारित नहीं किया गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.33 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.33

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	स्वीकृत कर	विलम्ब की अवधि (दिन में)	ब्याज की दर प्रति वर्ष	आरोपणीय ब्याज
1	डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 बदायूं	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.18	1267	15	0.61
				1.88	1185	15	0.91
2	डि0क0 खण्ड-3 वा0क0 एटा	1	2008-09 (मार्च 2012)	3.50	761	15	1.09
				0.73	844	15	0.25
				1.53	844	15	0.53
3	डि0क0 खण्ड-4 वा0क0 फेजाबाद	1	2007-08 (वैट) (सितम्बर 2011)	1.43	1229	15	0.72
4	डि0क0 खण्ड-4 वा0क0 फिरोजाबाद	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	5.28	1338	15	2.47
5	ज्वा0क0 (कार्पो0स0) जोन बी वा0क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.81	606	15	0.45
				4.85	1241	15	2.47
6	असि0क0 खण्ड-4 वा0क0 गाजियाबाद	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जून 2012)	0.94	92	14	0.03
					1763	15	0.68
7	ज्वा0क0 (कार्पो0स0) वा0क0 गोरखपुर	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	3.50	435	15	0.63
8	डि0क0 खण्ड-6 वा0क0 झांसी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	38.75	966	15	15.39
				75.58	601	15	18.67
9	डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	3.30	92	14	0.12
					1180	15	1.39
10	डि0क0 खण्ड-5 वा0क0 कानपुर	1	2007-08 (वैट) (सितम्बर 2011)	11.12	1368	15	6.25
11	डि0क0 खण्ड-16 वा0क0 कानपुर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	2.71	1340	15	1.49
12	डि0क0 खण्ड-12 वा0क0 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.43	1360	15	0.24
				0.51	1403	15	0.29
				0.25	1336	15	0.14
				1.12	1426	15	0.64
				3.68	1428	15	2.16
13	डि0क0 खण्ड-6 वा0क0 नोएडा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	2.74	1407	15	1.53
14	डि0क0 खण्ड-4 वा0क0 सहारनपुर	1	2008-09 (फरवरी 2011)	1.36	897	15	0.50
योग		19		168.18			59.65

हमने जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) पांच

¹³⁴ व्यापारियों द्वारा दाखिल क0नि0 पत्रावली एवं विवरणी।

जमा प्रवेश कर पर आरोपणीय ब्याज नहीं प्रभारित किया गया। बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद भुनाने के पश्चात् मात्र देय प्रवेश कर एक बार जमा किया गया, जबकि बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद प्रश्नगत वर्षों के देय प्रवेश कर के लिए थी। यद्यपि स्वीकृत प्रवेश कर ₹ 52.02 करोड़ 20 माह 28 दिन से 55 माह सात दिन तक के विलम्ब के पश्चात् शासकीय कोषागार में जमा किया गया फिर भी क0नि0प्रा0 शासकीय खाते में विलम्ब से जमा पर ₹ 26.71 करोड़ ब्याज प्रभारित करने में विफल रहे जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा मामलों को अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2013) कि 10 मामलों¹⁴⁰ में ₹ 5.90 करोड़ की मांग निकाली जा चुकी है तथा पांच मामलों में ₹ 34.09 लाख ब्याज की वसूली की जा चुकी है।

2.17.2.2 बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का नकदीकरण न कराया जाना

हमने दिसम्बर 2012 एवं मई 2013 के मध्य तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों¹⁴¹ में देखा कि तीन व्यापारियों के मामलों में वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान जमा बैंक गारण्टी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 9 (4) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय व्यापारी के द्वारा जमा बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का क0नि0प्रा0 के द्वारा नकदीकरण कराया जाना था। हमने देखा कि मार्च 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य प्रकरणों को अंतिम रूप देते समय क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों को जमा कर का लाभ दिया परन्तु ₹ 1.27 करोड़ के बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के साथ ₹ 68.46 लाख के ब्याज का नकदीकरण नहीं कराया (लेखापरीक्षा की तिथि तक) विवरण सारणी क्रमांक 2.34 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.34

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	अभिलेख का प्रकार	माल का मूल्य	आरोपित प्रवेश कर	चालान से जमा प्रवेश कर	बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा प्रवेश कर	आरोपणीय ब्याज
1	ज्वा0क0 (कापो0स0)-1 कानपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	मोटर वाहन	सावधि जमा रसीद	1,623.21	16.23	6.62	9.56	6.45
			2009-10 (मार्च 2012)	मोटर वाहन	सावधि जमा रसीद	3,405.85	34.06	0.00	34.09	17.89
2	ज्वा0क0 (कापो0स0) लखनऊ	1	2009-10 (जून 2012)	सीमेन्ट एवं हाई स्पीड डीजल	बैंक गारण्टी	3,451.22	77.46	0.00	75.69	39.08
3	डि0क0 खण्ड-19 वाराणसी	1	2008-09 (मार्च 2011)	साफ्ट कोक	बैंक गारण्टी	526.31	10.52	3.06	7.47	5.04
योग		3				9,006.59	138.27	9.68	126.81	68.46

हमारे द्वारा मामले को मार्च 2013 एवं जुलाई 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार (दिसम्बर 2013) करते हुए ₹ 41.82 लाख के ब्याज की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

¹⁴⁰ क्रम संख्या 3, 5, 6, 7, 9, 11 एवं 13।

¹⁴¹ मांग पंजिका एवं कर निर्धारण पत्रावलियां।

2.18 कर की दर की गलत अनुमन्यता

हमने जून 2012 और मार्च 2013 के दौरान तीन वा0क0का0 के व्यापारियों के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए पारित क0नि0आ0 एवं उनकी पत्रावलियां में देखा कि

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 4(1)(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 4(ख) के अनुसार डीजल पर 1 अप्रैल 2008 से 7 जून 2008 तक 21 प्रतिशत की दर से, 8 जून 2008 से 28 जनवरी 2009 तक 16.16 प्रतिशत की दर और 29 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2009 तक 17.23 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उसी अनुसूची से 7 (ख) के अनुसार फर्नेस आयल या अवशिष्ट फर्नेस आयल पर 29 सितम्बर 2008 तक 20 प्रतिशत की दर से और इसके बाद 21 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। क्रमशः प्रविष्टि संख्या 4 (क) एवं 7(क) के अनुसार केवल करयोग्य वस्तुओं के निर्माता को ही कमिश्नर द्वारा निर्धारित फार्म-‘डी’ के विरुद्ध डीजल और फर्नेस आयल जिसके अन्तर्गत अवशिष्ट फर्नेस आयल सम्मिलित है, कि 29 सितम्बर 2008 तक की खरीद पर चार प्रतिशत की दर से और उसके बाद पांच प्रतिशत की रियायती दर से खरीद का हकदार है। न्यायिक[#] रूप से निर्णीत है कि बड़े पत्थर से छोटी गिट्टियां अथवा चूर्ण बनाना विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं है। पुनश्च, कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2007 के अनुसार तिल (सीसम) का प्रसंस्करण भी विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं है। आगे अधिनियम की धारा 54 (1)(11) (1) के अनुसार यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो जिसके कारण विक्रय या क्रय पर कर उदग्रहणीय नहीं रह जाता है तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

[#]एस0टी0आई0 2000 एस0सी0 53 उत्तर प्रदेश बनाम लालकुआ स्टोन क्रशर प्रा0लि0।

क0नि0प्रा0 ने वर्ष फरवरी 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य तीन व्यापारियों का कर निर्धारण करते समय फार्म ‘डी’ के विरुद्ध फर्नेस आयल एवं डीजल की रियायती दर पर की गई खरीद को अनुचित रूप से अनुमन्य किया। इसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड के अलावा ₹ 41.45 लाख की रियायती कर की दर अनुचित रूप से अनुमन्य की गयी। चूंकि केवल करयोग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले निर्माताओं को ही रियायती दर का लाभ अनुमन्य है, करमुक्त माल का निर्माण करने वाले क्रम सं0 1 के व्यापारी को रियायती दर का लाभ दिया जाना गलत था। शेष दो मामलों में व्यापारी द्वारा निर्मित उत्पाद¹⁴² विनिर्माण की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। विवरण सारणी क्रमांक 2.35 में दर्शाया

गया है:

¹⁴² क्रमशः तिल एवं छोटी गिट्टियां।

सारणी क्रमांक 2.35

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	खरीद की अवधि	वस्तु का नाम	डीजल/फ० आ० का मूल्य	संदत/संदेय कर की दर	प्राप्य अनियमित रियाती कर	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०क० खण्ड-12 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	01.04.2008 से 07.06.2008 तक	फरनेश आयल	17.41	20/4	2.78	8.71
				01.04.08 से 07.06.2008 तक	डीजल	51.88	21/4	8.82	25.94
				08.06.2008 से 29.09.2008 तक		66.94	16.16/4	8.14	33.49
				30.09.2008 से 28.01.2009 तक		23.31	16.16/5	2.60	11.66
				29.01.2009 से 31.03.2009 तक		12.74	17.23/5	1.59	6.37
2	डि०क० खण्ड-2 वा०क० मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	01.04.2008 से 07.06.2008 तक	डीजल	15.32	21/4	2.60	7.66
				08.06.2008 से 29.09.2008 तक		3.62	16.16/4	0.44	1.81
				30.09.2008 से 28.01.2009 तक		24.41	16.16/5	2.71	12.21
				29.01.2009 से 31.03.2009 तक		12.69	17.23/5	1.55	6.35
3	डि०क० खण्ड-1 वा०क० नजीबाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	2008-09	डीजल	44.09	16.16/4	5.36	22.05
			2009-10 (फरवरी 2011)	2009-10		39.72	17.23/5	4.86	19.86
योग		3				312.13		41.45	156.11

हमने मार्च 2013 एवं मई 2013 के मध्य इस प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2013) उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 2 पर वर्णित मामले में ₹ 7.32 लाख का कर एवं ₹ 28.02 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। अनेक अनुस्मारक के बावजूद वसूली की सूचना एवं अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

2.19 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं समय समय पर शासन द्वारा विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी सूची में वर्गीकृत नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क०नि०प्रा० को व्यापारी के व्यापार और अन्य सुसंगत अभिलेखों से सम्बन्धित उसके द्वारा रखे जाने वाले खाते लेखे और अभिलेखों की जांच करके क०नि०आ० पारित किया जाना चाहिए।

हमने दिसम्बर 2011 और मार्च 2013 के मध्य आठ वा०क०का० के अभिलेखों की जांच में देखा कि नौ व्यापारियों के मामले में वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि में क०नि०प्रा० को प्रस्तुत अभिलेखों में इन व्यापारियों ने ₹ 8.20 करोड़ की बिक्री को टर्नओवर के रूप में दर्शाया। इन

व्यापारियों की संवधित कर निर्धारण पत्रावलियों में छूटे हुए टर्नओवर का विवरण¹⁴³ उपलब्ध है, क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण करते समय इन विवरणों की जांच की जानी चाहिए थी। क०नि०प्रा० द्वारा मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 79.90 लाख का कर अनारोपित रहा। जैसा कि सारणी क्रमांक 2.36 में दर्शाया गया है:

¹⁴³ व्यापार और लाभ हानि खाता, वार्षिक बैलेंस शीट, वर्तमान और पिछले वर्षों का कर निर्धारण आदेश आदि।

सारणी क्रमांक 2.36

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर
1	ज्वा०क० (कार्पा०स०) वा०क० आगरा	1	2008-09 (मार्च 2012)	यूज्ड कार (II)	12.54	4/0	0.50
2	डि०क० खण्ड-7 वा०क० आगरा	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08 तक) (जून 2010)	आटोमेटिक फिल्टर और लूब्रीकेंट आयल (V)	84.65	12.5/0	10.58
3	डि०क० खण्ड-10 वा०क० बरेली	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08 तक) (मार्च 2011)	कार ट्रक और आटो व्हीकल के टायर ट्यूब (V)	23.25	12.5/0	2.91
4	डि०क० खण्ड-4 वा०क० फिरोजाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	पेंट (V)	7.89	12.5/0	0.99
5	डि०क० खण्ड-7 वा०क० झांसी	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	वैटरी और मोटर पार्टस (V)	3.39	12.5/0	0.42
				मशीनरी पार्टस (II)	5.52	4/0	0.22
			2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	बैटरी और मशीनरी पार्टस (V)	10.53	12.5/0	1.32
				ट्रैक्टर पार्टस (II)	8.31	4/0	0.33
6	ज्वा०क० (कार्पा०स०) वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	स्पेयर पार्टस और लूब्रीकेन्ट्स (V)	327.67	12.5/0	40.96
7	डि०क० खण्ड-1 वा०क० मऊ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	लाइलोन फिलामेंट यार्न (II)	198.67	4/0	7.95
8	डि०क० वा०क० मोदी नगर	1	2006-07 और 2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (अप्रैल 2011)	डि०श ऐन्टीना और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स	137.16	10/0	13.72
योग		9			819.58		79.90

हमारे द्वारा जनवरी 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि उपरोक्त सारणी के दो मामलों (क्रम संख्या 4 और 7) में ₹ 8.53 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद भी शेष मामलों में वसूली की सूचना और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

2.20 कर की वापसी के द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 29 एवं उ०प्र०मू०सं० कर अधिनियम 2008 की धारा 40 के अन्तर्गत किसी व्यापारी को उसके द्वारा कर शुल्क अथवा अन्य देयों के मद में अधिक जमा धनराशि की वापसी के प्रावधान हैं। पुनश्च, न्यायिक निर्णय* में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर के भार को अन्य व्यक्ति पर अन्तरित कर देता है तो उस कर की वापसी उस व्यक्ति को अनुचित लाभ मानी जायेगी। साबित करने की जिम्मेदारी व्यापारी पर है।

* मे० मफतलाल इण्डस्ट्रीज लि० बनाम यूनिन आफ इण्डिया इत्यादि (1996) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

हमने अगस्त 2011 और दिसम्बर 2012 के मध्य 20 वा०क०का०¹⁴⁴ के 35 संविदाकारों से सम्बन्धित क०नि०आ० की जांच में देखा कि 20 व्यापारियों के मामले में वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि में क०नि०प्रा० द्वारा फरवरी 2010 और मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते

¹⁴⁴ असि०क० खण्ड-14 इलाहाबाद, असि०क० खण्ड-5 बरेली, डि०क० खण्ड-1 बस्ती, डि०क० खण्ड-1 धामपुर, असि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-5 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-11 कानपुर, डि०क० खण्ड-13 कानपुर, डि०क० खण्ड-14 कानपुर, डि०क० खण्ड-22 कानपुर, डि०क० खण्ड-2 लखनऊ, डि०क० खण्ड-8 लखनऊ, डि०क० खण्ड-14 लखनऊ, डि०क० खण्ड-17 लखनऊ, डि०क० खण्ड-19 लखनऊ, डि०क० खण्ड-22 लखनऊ, असि०क० खण्ड-1 लखनऊ, डि०क० खण्ड-4 मेरठ, डि०क० खण्ड-2 मुजफ्फरनगर एवं असि०क० खण्ड-2 सहारनपुर।

समय स्रोत¹⁴⁵ पर की गयी कटौती का आरोपित कर में समायोजन किया गया, शेष अधिक जमा ₹ 71.62 लाख वापसी के आदेश पारित किये गये। न्यायिक निर्णय के आलोक में क0नि0प्रा0 से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यापारी को अधिक जमा धनराशि की वापसी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि जिस व्यक्ति को अधिक जमा धनराशि की वापसी की जा रही है उसने अधिक जमा कर की राशि का भार किसी अन्य पक्ष पर अन्तरित तो नहीं कर दिया था और ऐसी वापसी के द्वारा कही अनुचित वित्तीय लाभ तो नहीं हुआ। केवल आठ मामलों¹⁴⁶ में क0नि0प्रा0 ने सही जांच करते हुए इन मामलों में धनराशि की वापसी नहीं की। अन्य 21 मामलों में अनियमित वापसी का विवरण सारणी क्रमांक 2.37 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.37

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर की वापसी
1	असि0क0 खण्ड-14 इलाहाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	1.13
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	3.98
		1	2008-09 (मार्च 2012)	1.47
2	असि0क0 खण्ड-5 बरेली	1	2006-07 (फरवरी 2010)	1.05
3	डि0क0 खण्ड-1 बस्ती	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	1.64
		1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	2.49
		1	2008-09 (अगस्त 2011)	1.24
		1	2009-10 (अगस्त 2011)	1.21
4	डि0क0 खण्ड-1 घामपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	2.91
5	असि0क0 खण्ड-8 गाजियाबाद	1	2009-10 (दिसम्बर 2011)	1.46
6	डि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	2.36
7	डि0क0 खण्ड-13 कानपुर	1	2008-09 (जुलाई 2010)	22.63
8	डि0क0 खण्ड-14 कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	9.25
9	डि0क0 खण्ड-17 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.86
10	डि0क0 खण्ड-19 लखनऊ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	3.45
11	डि0क0 खण्ड-4 मेरठ	1	2007-08 (दिसम्बर 2010)	0.51
12	डि0क0 खण्ड-2 मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	5.27
		1	2009-10 (फरवरी 2012)	4.10
13	असि0क0 खण्ड-2 सहारनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.91
		1	2008-09 (मई 2011)	0.61
		1	2008-09 (अप्रैल 2011)	0.47
		1	2008-09 (अप्रैल 2011)	0.62
योग		21		71.62

हमने ठेके देने वाले सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों¹⁴⁷ के अभिलेखों¹⁴⁸ के प्रतिस्त्यापन में देखा और पाया कि संविदाकारों द्वारा अपने सम्बन्धित सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से जो कर की प्राप्ति की गयी थी, उसमें संविदा में दी गई सामग्री की दरों में कर भी शामिल था। इस प्रकार सम्बन्धित सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्रोत पर की गई कटौती को संविदाकारों द्वारा पहले

¹⁴⁵ डि0क0 खण्ड-14 कानपुर के एक मामले में व्यापारी ने कर को नकद जमा किया लेकिन इसे खर्च के रूप में अपने लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया।

¹⁴⁶ डि0क0 खण्ड-2 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-8 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-14 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-22 लखनऊ असि0क0 खण्ड-1 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-11 कानपुर, डि0क0 खण्ड-14 कानपुर एवं डि0क0 खण्ड-22 कानपुर।

¹⁴⁷ लो0नि0वि0 के विभिन्न खण्ड, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पो0लि0, यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पो0लि0, उ0प्र0 जल निगम आदि।

¹⁴⁸ संविदा/सहमति बन्धपत्र के उद्घरण, मात्रात्मक बिल, आशय पत्र, रनिंग बिल आदि।

155 व्यापारियों से संबंधित कठिनताओं एवं परेशानियों।
 156
 157

दुम्कारे द्वारा अगस्त 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2013) कि छ: मामलों¹⁵⁷ में ₹ 5.88 लाख की आइटी0टी0टी उक्तमित कर दी गयी थी और ₹ 16.11 लाख का अर्थात् 2011 आयोजित कर दिया गया जिसमें से ₹ 7.20 लाख की अब तक वर्षों की जा चुकी है

आइटी0टी0टी, अर्थात् और ब्याज आकर्षित होता है।
 जैसे कि परिशिष्ट-III में उक्तमित करों की आइटी0टी0टी पर ₹ 8.24 लाख का प्रत्येक वर्ष का अर्जा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार अर्जा नही है पर दावा आइटी0टी0टी का नाम बरतने पर विन सब पर बरतने पर, कर कर मुक्त इन्वॉयस पर पूर्णतया गैर खरीद, अनियमित अतिरिक्त फर्मों से की आया पर जैसे कि उल्लेखन किया/कपटपूर्ण एवं नियमों के प्राधानों के आइटी0टी0टी अतिनियम की अर्जा की। यह एवं कपटपूर्ण आइटी0टी0टी की प्रत्या 1.23 करोड़ की प्रत्या सत्यापन नहीं किया और आइटी0टी0टी का प्रति दावाकृत द्वारा करते समय व्यापारियों 2012 के मध्य कर निर्धारण करवही 2011 और माई किया था। कठिनता का दावा की आइटी0टी0टी का दावा व्यापारियों ने 1.23 करोड़ आइटी0टी0टी का 41¹⁵⁶ के 35¹⁵⁵ दायन देखा कि 2010-11 की अवधि के 2007-08 से

आइटी0टी0टी की धारणाओं को धराया जायेगा।
 पहले से दावा की गयी आइटी0टी0टी में से ऐसी उक्तमित ऐसी आइटी0टी0टी उक्तमित की जायेगी और व्यापारी द्वारा अर्जन्य नही वर्य के सम्बन्ध में गलत ढंग से दावा की गयी दावाकृत आइटी0टी0टी जिस सीमा तक आइटी0टी0टी का नाम अर्जन्य नही है या इस अतिनियम के प्राधानों के विपरीत का नोट मिला है उस धारणाओं पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट का धारणाओं के लिए निकला व्यापारी से कला व्यापारी को क्रेडिट 21(4) के अनुसार जिस 3000 इन्पुट टैक्स क्रेडिट का नाम करने का दावा होगा। उक्तमित प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहित उक्तमित धारणाओं का गैर होने की सम्मान होने वाली अवधि के लिए टैक्स क्रेडिट का नाम देने वाली घटना जिस दिनांक को अर्जन्य नही है, उक्तमित किया जाएगा। उक्तमित इन्पुट टैक्स का नाम उस सीमा तक जाते तक आइटी0टी0टी का नाम के सम्बन्ध में गलत तरीके से आइटी0टी0टी का दावा अतिरिक्त अतिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत याद किस्वी प्रत्येक के बराबर धारणाओं का भूतान करेगा। इसके बाद आइटी0टी0टी की धारणाओं के प्रत्या व्यापारी या ब्याज, उसके द्वारा देयकर के अतिरिक्त, यदि धारणाओं का दावा करता है, वह निर्दिष्ट कर सकला है कि धारणाओं का दावा करेगा के रूप में प्रत्या या कपटपूर्ण तरीके से सत्य है कि नहीं, यथास्थिति, कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य अतिनियम की धारा 54(1)(19) के अन्तर्गत याद कठिनता आइटी0टी0टी का उक्तमित किए जाने का प्राधान है। वृत् एवं 25 में अतिनियम के प्राधानों के उल्लेखन में दावाकृत 14 सफल 3000 इन्पुट टैक्स अर्जन्य है। उक्त अतिनियम की धारा आइटी0टी0टी का नाम अर्जन्य कर की सीमा तक गैर खरीद या बिक्री पर संदेय कर की सीमा तक की गयी खरीद पर नकद नाम धारणाओं पर उनके द्वारा की की गैर खरीद पर देये कर या अधीकृत व्यापारियों से व्यापारी द्वारा टैक्स इन्वॉयस के विक्रम पूर्णकृत व्यापारियों से 3000 इन्पुट टैक्स अतिनियम 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत 2008 की धारा 13 सफल

2.21.1 कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान में न लिये जाने वाले मामले

अनेक अनुस्मारक के बावजूद शेष अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

2.21.2 ब्याज/अर्थदण्ड का अनारोपण

हमने 27 वा0क0का0¹⁵⁸ में 32 व्यापारियों के मामलों में देखा¹⁵⁹ कि अक्टूबर 2010 एवं जून 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0नि0प्रा0 द्वारा व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 के प्रति सत्यापन में पाया गया कि व्यापारियों ने कपटपूर्ण तरीके से ₹ 71.70 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया था। हमने पाया कि क0नि0प्रा0 द्वारा यद्यपि आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गई थी लेकिन उन्होंने न तो ₹ 47.79 लाख ब्याज और न ही ₹ 3.59 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया जैसा कि परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है:

हमने प्रकरण को अगस्त 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। अनेक अनुस्मारक के बावजूद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

2.21.3 खरीदे गये माल पर गलत कर की दर दर्शाते हुए आई0टी0सी0 का अनुचित दावा किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 13 सपठित उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 24 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयुक्त माल के लिए कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रान्त के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से की गई खरीद पर संदत या संदेय कर की सीमा तक आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की अनुसूचि-I से V तक में प्रत्येक वस्तु के लिए लागू कर की दर को विहित किया गया है।

आठ वा0क0का0 में 10 व्यापारियों ने ₹ 4.76 करोड़ की खरीद पर 12.5 प्रतिशत की दर से मिथ्या रूप से आई0टी0सी0 का दावा किया। ये वस्तुएं

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची-II में वर्णित हैं और उन पर लागू कर

की दर चार प्रतिशत है। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 और मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया और बिना विस्तृत जांच किये और प्रतिसत्यापन किये व्यापारियों के चार प्रतिशत की करदेयता वाली वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 के दावे पर, अधिक गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को अनुमन्य किया। इस मिथ्या दावा किये जाने के कारण ₹ 2.69 करोड़ का उत्क्रमित आई0टी0सी0, अर्थदण्ड और ब्याज आकर्षित होता है, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.38 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.38

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	लागू कर की दर/ गलत ढंग से लागू	अनुक्रमित आई0टी0सी0 की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रभासित ब्याज
1	ज्वा0 क0 (कार्पो0 सं0) इटावा	1	2008-09 (मार्च 2012)	एल्यूमिनियम वायर और कापर वायर (II)	45.37	4/12.5	3.86	19.28	2.03
2	डि0क0 खण्ड-4 वा0क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	पम्प (II)	7.84	4/12.5	0.67	3.33	0.45
3	डि0क0 खण्ड-7 वा0क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	डुप्लेक्स पेपर (II)	31.32	4/12.5	2.66	13.30	1.80
		1	2008-09 (मार्च 2012)	कापर केबल स्क्रैप (II)	4.72	4/12.5	0.40	2.00	0.27

¹⁵⁸ ज्वा0क0 (कार्पो0सं0) आगरा, डि0क0 खण्ड-12 आगरा, डि0क0 खण्ड-2 इटावा, डि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-10 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-19 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-4 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-11 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-1 कानपुर, डि0क0 खण्ड-14 कानपुर, डि0क0 खण्ड-18 कानपुर, डि0क0 खण्ड-20 कानपुर, डि0क0 खण्ड-29 कानपुर, डि0क0 खण्ड-2 काशीरामनगर (कासगंज), डि0क0 खण्ड-1 कासगंज, डि0क0 खण्ड-3 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-11 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-20 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-13 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-2 महाराजगंज, डि0क0 खण्ड-1 मथुरा, डि0क0 खण्ड-12 मेरठ, डि0क0 खण्ड-7 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड-8 नोएडा, डि0क0 खण्ड-3 पीलीभीत एवं ज्वा0क0 (कार्पो0सं0)-2 वाराणसी।

¹⁵⁹ व्यापारी से सम्बन्धित क0नि0प्रा0 एवं पत्रावलियां।

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	लागू कर की दर/ गलत ढंग से लागू	अनुत्कमित आईटीसी की घनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रसारित ब्याज
4	खण्ड-1 वा0क0 गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	पैकिंग बाक्सज कैमिकल (II)	6.05	4/12.5	0.51	2.57	0.34
		1	2008-09 (मार्च 2012)	कैमिकल एण्ड होज पाईप (II)	6.18	4/12.5	0.52	2.62	0.35
5	खण्ड-2 वा0क0 गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	कापर पैकिंग मैटिरियल (II)	337.09	4/12.5	28.66	143.30	19.34
6	खण्ड-3 वा0क0 गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	पी0यू फोम (II)	32.55	4/12.5	2.77	13.83	1.87
7	खण्ड-4 वा0क0 मुरादाबाद	1	2008-09 (मार्च 2011)	आइरन वेयर (II)	2.64	4/12.5	0.22	1.12	0.16
8	खण्ड-2 वा0क0 हसनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	आइसक्रीम (II)	2.14	4/12.5	0.18	0.91	0.12
	योग	10			475.90		40.45	202.26	26.73

हमने मई 2012 और जुलाई 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि दो मामलों में (क्रम सं० 2 एवं 3) ₹ 18.64 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है और ₹ 3.73 लाख की आईटीसी उत्कमित की गई है। अनेक अनुस्मारक के बावजूद शेष अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

2.22 जमा की पुष्टि न होना

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 3(1) एवं उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी अपने कर योग्य माल के विक्रय या क्रय अथवा दोनो जैसा भी प्रकरण हो, के कर योग्य टर्नओवर पर प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित दर से कर के भुगतान का दायी होगा। परन्तु दोनों अधिनियमों में किसी योजना के अन्तर्गत बिना मूल्य दिये प्राप्त माल, जिस पर अधिकतम खुदरा मूल्य दर्ज हो, के विक्रय पर वसूले गये कर को सरकारी कोष में जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

हमने मार्च 2011 एवं फरवरी 2013 के मध्य पांच वा०क०का० के 17 व्यापारियों की कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच में देखा कि उनके द्वारा उ०प्र० के बाहर से ₹ 110.56 करोड़ मूल्य की दवा विक्रेता निर्माताओं द्वारा दवाओं की बिक्री बिना मूल्य चुकाये योजना¹⁶⁰ के अन्तर्गत प्राप्त किया। इन व्यापारियों

ने वस्तु के रूप में छूट की योजना¹⁶¹ के अन्तर्गत आने के कारण इन निःशुल्क दवाइयों पर कोई कर नहीं दिया था। इन व्यापारियों ने ₹ 110.61 करोड़ मूल्य की फ्री मेडिसिन को अपने खुदरा थोक व्यापारियों को कर योग्य दवाओं के साथ हस्तान्तरित किया।

हमने इन खुदरा/थोक क्रेता व्यापारियों के कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच एवं प्रतिसत्यापन में पाया कि सम्बन्धित कर विवरणियों¹⁶² में इन व्यापारियों ने बिना मूल्य की प्राप्त दवाइयों की प्राप्ति को नहीं दर्शाया था। इसके अलावा हमने देखा कि ऐसे संव्यवहार पर कर की वसूली एवं जमा सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नर वाणिज्य कर के 25 सितम्बर 2012¹⁶³ के आदेश का वा०क०का० द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। केवल डिप्टी कमिश्नर खण्ड-5 नोएडा के मामलों में ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वा०क०का० को पत्र जारी किये गये थे। इन संव्यवहारों के प्रति सत्यापन के अभाव में ₹ 4.42 करोड़ के प्रेषण पर न तो कर को सुनिश्चित किया जा सका है और

¹⁶⁰ दवा निर्माताओं की ऐसी योजना जिसमें दवाओं की कुछ मात्रा को बिना मूल्य लिये वितरकों/खुदरा व्यापारियों को दवाओं की खरीद पर दी जाती है।

¹⁶¹ जैसा कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2003 में निर्णीत।

¹⁶² अनुलग्नक 'क' जो कि अपने वा०क०का० को प्रस्तुत किये जाने वाले मासिक/वार्षिक विवरणी का भाग है।

¹⁶³ आडिट महालेखाकार 2012-13/15551/वाणिज्य कर।

न ही उ0प्र0मू0सं0क0 की धारा 33(2)¹⁶⁴ और 54(1)(2)¹⁶⁵ के अन्तर्गत छिपाये टर्नओवर पर आरोपणीय ब्याज और अर्थदण्ड सुनिश्चित किया जा सका है, विवरण सारणी क्रमांक 2.39 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.39

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	प्री बोनस के रूप में वितरित दवाओं का मूल्य	प्री बोनस पर कर का प्रभाव (चार प्रतिशत की दर से)
1	ज्वा0 क0 (कापो0 सं0)-1 लखनऊ	मे0 एलकैम लैबोरेटरीज लि0 सी-31 ट्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	12,379.77	788.11	31.50
		मे0 ल्यूपिन लि0 ई-207 ट्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	16,080.13	937.00	37.48
		मे0 सिपला लि0 सी-27 ट्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (सितम्बर 2011)	दवाएं	20,986.84	3797.12	151.88
		मे0 रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लि0 गगन पैलेस बाग नं०-2 लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	12,384.27	4019.82	160.79
		मे0 अलेम्बिक लि0 35 हैवलक रोड लखनऊ	2008-09 (मार्च 2012)	दवाएं	6,838.64	634.20	25.37
2	डि०क० खण्ड-9 लखनऊ	मे0 सिंघ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स 67 विजय नगर कृष्णा नगर लखनऊ	2008-09 (मई 2011)	दवाएं	690.02	41.99	1.68
		मे0 पंजाब फार्मूलेशन लि0 ई-104 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (अगस्त 2011)	दवाएं	618.13	29.08	1.16
		मे0 सेन्दूर फार्मास्यूटिकल्स लि0 ई-323 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	604.56	77.08	3.08
		मे0 पैनासिया बायोटेक लि0 बाग नं०-2 लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	1,275.63	25.64	1.03
		मे0 इण्डिको रेमीडीज लि0 ई-132 ट्रांसपोर्ट लगर लखनऊ	2008-09 (अक्टूबर 2011)	दवाएं	1,332.10	159.49	6.38
		मे0 अल्टेट हेल्थ केयर प्रा०लि० सी-516 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2009-10 (दिसम्बर 2011)	दवाएं	159.68	60.07	2.40
		मे0 एस०एस० बायोटेक 565-566 विश्वामित्र कम्प्लेक्स लखनऊ	2008-09 (जनवरी 2012)	दवाएं	174.61	32.99	1.32
		मे0 माप्रा लैबोरेटरीज प्रा०लि० ई०३/१० ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (मई 2011)	दवाएं	443.63	56.33	2.25
		मे० फाइजर प्रोडक्ट्स प्रा०लि० सी०-43 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (जनवरी 2012)	दवाएं	1,080.94	12.59	0.50
3	डि०क० खण्ड-2 लखनऊ	मे० कन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० 35 हैवलक रोड लखनऊ	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	दवाएं	163.56	18.70	0.75
4	डि०क० खण्ड-5 नोएडा	मे० मार्टिन एण्ड हैरिस प्रा०लि० श्रीजी कम्प्लेक्स शर्मा मार्केट सी-5 नोएडा	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	2,290.97	217.31	8.69
5	डि०क० खण्ड-5 मेरठ	मे० ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज लि० 38-ए पप्पल स्ट्रीट मेरठ	2008-09 (सितम्बर 2010)	दवाएं	1,558.07	153.97	6.16
योग		17			79,061.55	11,061.49	442.42

चूंकि इन निःशुल्क दवाइयों पर कर सहित अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित था निःशुल्क दवाइयों का थोक/खुदरा व्यापारियों का वितरण कर की परिधि से बाहर छिपाई गई

¹⁶⁴ उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

¹⁶⁵ उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा-54(1)(2) के अन्तर्गत जहां पर व्यापारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है तो क०नि०प्रा० व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड का भुगतान करे।

बिक्री है, क्योंकि थोक/खुदरा व्यापारियों द्वारा दाखिल मासिक और वार्षिक कर विवरणी के अनुलग्नक 'क' में इसे नहीं दिखाया गया है।

उदाहरण के लिए हम उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 4 पर अंकित व्यापारी¹⁶⁶ का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसका कर निर्धारण ज्वा0क0 (कार्पो0स0)-1 लखनऊ द्वारा किया गया था। उसने ₹ 13.52 करोड़ की निःशुल्क दवाइयां डि0क0 खण्ड-9 लखनऊ में पंजीकृत अपने अनुवर्ती व्यापारी¹⁶⁷ को देना दिखाया है। इस अनुवर्ती व्यापारी ने अपने विवरणी में कुल ₹ 12.50 करोड़ का टर्नओवर दिखाया था जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ₹ 13.52 करोड़ की निःशुल्क दवाइयों को उसके खाते में नहीं लिया गया था।

31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद विभाग ने ऐसे संव्यवहार पर वसूले गये और जमा कर को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक तंत्र की स्थापना नहीं की। हमने देखा कि ज्वा0क0 (कार्पो0स0)-1 लखनऊ के केवल एक मामले में क0नि0प्रा0 द्वारा फ्री बोनस के रूप में दी गई दवाओं को अनुमन्य न करते हुए कर आरोपित किया गया था।

हमने दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य इस प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने अगस्त 2013 में बताया कि विक्रेता व्यापारियों द्वारा क्रेता व्यापारियों को फ्री बोनस के रूप में दी गयी दवाएं उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार बिक्री टर्नओवर विक्रय मूल्य की परिधि में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक न्यायिक निर्णयों के अनुसार मात्रात्मक छूट और निःशुल्क दवाओं की आपूर्ति, बिक्री के अन्तर्गत नहीं आते। दवाइयों की आपूर्ति में मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त न होने के कारण ऐसे संव्यवहार पर कोई कर आरोपणीय नहीं था। ऐसे संव्यवहार पर वसूले गये और जमा कर को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक तंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में हमारी उदायी गई आपत्ति के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया।

इन 17 व्यापारियों में से परवर्ती क्रेता व्यापारियों की कर निर्धारण प्रत्रावलियों¹⁶⁸ का प्रतिसत्यापन और जांच में हमने पाया कि 86 मामलों में परवर्ती क्रेता व्यापारियों ने अपने वैट विवरणी में अपने द्वारा प्राप्त निःशुल्क दवाओं की प्राप्ति को नहीं दिखाया। इस प्रकार उनके द्वारा प्राप्त की गई निःशुल्क दवाइयों की आगे की जांच संभव नहीं है।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार कमिश्नर वाणिज्य कर कर्नाटक¹⁶⁹ की तर्ज पर एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है, जिससे ऐसे संव्यवहारों पर कर की वसूली एवं उनका जमा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

¹⁶⁶ मे0 रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लि0 गगन पैलेस बाग नं-2 कानपुर रोड, लखनऊ।

¹⁶⁷ मे0 सोर फार्मसिया प्रा0लि0 कानपुर रोड, लखनऊ।

¹⁶⁸ 22 वा0क0 में।

¹⁶⁹ कर्नाटक में कमिश्नर वाणिज्य कर ने एक परित्र संख्या सी0एल0आर0सी0आर0/149/05-06 दिनांक 28 जून 2006 को निर्मित करते हुए स्पष्ट किया है किसी व्यापारी के मामले में जिसने अन्य दवाओं के साथ मुक्त नमूनों की दवाओं की आपूर्ति क्रेता व्यापारियों को की है ऐसे निर्माता/आयातक/थोक विक्रेता व्यापारी फुटकर व्यापारी को मुक्त दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है, जिसका प्रतिफल के बदले बिक्री करने की अनुमति मिली हो। यद्यपि उन्होंने खुदरा व्यापारी से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया हो ऐसी आपूर्ति मुक्त नमूनों की आपूर्ति पर यदि कर प्रमासित किया गया हो, तो फुटकर व्यापारी इनपुट टैस क्रेडिट के लिए पात्र होगा।

2.2.3 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 7 (3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायती दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी आवेदनकर्ता का पंजीयन करेगा, एवं विहित प्रारूप में उसे पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। जिसमें उस वर्ग या वर्गों के माल को निविदिष्ट करेगा जो उसके द्वारा पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूरसंचार नेटवर्क या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है। पुनश्च कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को परिपत्र सं0-17 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देशित किया था कि निर्माताओं/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेंट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

हमने सोनभद्र स्थित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पो0स0) वा0क0 जोन-II वाराणसी के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2012) के दौरान देखा कि एक व्यापारी¹⁷⁰ को मार्च 1985 (संशोधित मार्च 1998)में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण के लिए प्रयुक्त माल की खरीद हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के0प0प्र0प0) प्रदान किया गया था। के0प0प्र0प0 में सीमेन्ट और बैटरी की खरीद भी शामिल थी जिसका व्यापारी ने वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान ₹ 61.93 लाख के सीमेंट एवं बैटरी की खरीद की एवं उसने इस खरीद पर के0बि0क0 की रियायती दर (2008-09 में 31 मई 2008 तक एवं 2007-08 के लिए तीन प्रतिशत) का दावा किया।

चूंकि व्यापारी का व्यापार विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण का था और उक्त के उत्पादन के लिए सीमेंट एवं बैटरी कच्चा माल/प्रसंस्करण सामग्री नहीं है। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा सिर्फ उन माल को क्रय करने के लिए है जिनका उपयोग उस माल के विनिर्माण व प्रसंस्करण में किया जाय जो बेचने के उद्देश्य से हो। क0नि0प्रा0 द्वारा के0प0प्र0प0 में सीमेंट की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने के साथ ही साथ कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेशों के विरुद्ध भी था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2012 में वर्ष 2008-09 के लिए क0नि0आ0 पारित करते समय इस त्रुटि को सज्ञान में नहीं लिया। क0नि0प्रा0 की इस त्रुटि के परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 5.78 लाख का अनुचित लाभ मिला।

हमने प्रकरण को नवम्बर 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्ति को सीमेंट के मामले में स्वीकार किया (अगस्त 2013) लेकिन बैटरी की खरीद के सम्बन्ध में बताया कि इसका प्रयोग जनरेटर में किया जाता है जो कि प्लाण्ट एवं मशीनरी का अभिन्न अंग है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि इस थर्मल पावर प्लाण्ट के व्यापारी के के0प0प्र0प0 के साथ संलग्न सूची में बैटरी को प्लाण्ट एवं मशीनरी के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

¹⁷⁰ मे0 केन्द्रीय वित्तीय लेखा और बजट संगठन, एन0टी0पी0सी0 अनपरा सोनभद्र।

2.24 आदेश के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-13 में व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने एवं देय कर के विरुद्ध इसका समायोजन करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करती है। कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 में भी राजस्व के व्यापक हित में अक्टूबर 2008 एवं सितम्बर 2009 के द्वारा आई0टी0सी0 के सत्यापन तथा इसका डाटाबेस रखने के सम्बन्ध में क0नि0प्रा0 को निर्देश जारी किये थे। सभी डिप्टी कमिश्नर के लिए आवश्यक है कि सर्वाधिक आई0टी0सी0 का दावा करने वाले 20 बड़े व्यापारियों की अनुलग्नक-‘क’ (क्रय सूची) का अनुलग्नक-‘ख’ (विक्रय सूची) से शतप्रतिशत सत्यापन कर लिया गया है एवं उपरोक्त विवरणों की वाह्य एजेन्सी अथवा विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रविष्टि कराकर एक डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त यादृच्छिक सांख्यिकीय विधि से आच्छादित मामलों का शतप्रतिशत जांच एवं सत्यापन किया जाना था।

वाणिज्य कर विभाग ने विभाग की दक्षता में वृद्धि करने के लिए वेब आधारित सिटीजन सेन्ट्रिक सर्विसेज की उपलब्धता कराने हेतु कम्प्यूटरीकृत परियोजना पर ₹ 45 करोड़ का व्यय किया। विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू कामटैक्स यू0पी0 एन0आई0सी0) पर जनसाधारण के लिए एवं व्यास (वाणिज्य कर आटोमेशन सिस्टम) पर विभागीय उपयोग के लिए उपलब्ध है। अवधि 2007-08¹⁷¹ से 2010-11

के लिए नमूना जांच (2012-13) के दौरान हमने देखा कि:

- क0नि0प्रा0 ने बिना आई0टी0सी0 के दावों के सत्यापन का प्रयास किये ही 38¹⁷² वा0क0का0 के 122 व्यापारियों के लिए ₹ 13.07 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन उनके देयकर के विरुद्ध करते हुए क0नि0आ0 पारित कर दिया।
- क0नि0प्रा0 ने 39¹⁷³ वा0क0क0 के से सम्बन्धित 122 व्यापारियों के लिए ₹ 23.33 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन उनके देयकर के विरुद्ध करते हुए क0नि0आ0 पारित कर दिया, परन्तु सत्यापन के लिए दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

क0नि0प्रा0 ने ₹ 36.40 करोड़ के आई0टी0सी0 के समायोजन सम्बन्धी आदेश बिना इनका सत्यापन किये ही पारित कर दिया।

हमारे द्वारा प्रकरण को मई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया कि (अगस्त 2013) में बताया कि विवरणियों

¹⁷¹ 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008 तक।

¹⁷² डि0क0 खण्ड-7 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड-12 आगरा, डि0क0 खण्ड-2 अम्बेडकर नगर, डि0क0 खण्ड-2 अमरोहा, डि0क0 खण्ड-1 औरैया, डि0क0 खण्ड-1 बस्ती, डि0क0 खण्ड-1 चन्दौली, डि0क0 खण्ड-2 चन्दौली, डि0क0 खण्ड-1 देवरिया, डि0क0 खण्ड-1 धामपुर, डि0क0 खण्ड-1 फतेहगढ़, डि0क0 खण्ड-4 फिरोजाबाद, डि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-8 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-2 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-4 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-8 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-10 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-13 लखनऊ, डि0क0 महोबा, डि0क0 खण्ड-2 मुरादाबाद, डि0क0 खण्ड-3 औराई, डि0क0 खण्ड-8 वाराणसी एवं डि0क0 खण्ड-10 वाराणसी, असि0क0 खण्ड-12 इलाहाबाद, असि0क0 खण्ड-1 अलीगढ़, असि0क0-5 बरेली, असि0क0 खण्ड-1 चन्दौली, असि0क0 खण्ड-1 छत्रपति साहूजीमहाराज नगर, असि0क0 खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, असि0क0 खण्ड-3 गौतमबुद्धनगर, असि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-10 कानपुर, असि0क0 खण्ड-4 लखनऊ एवं असि0क0 खण्ड-20 लखनऊ।

¹⁷³ ज्वा0क0 (कार्पो0स0)-2 वाराणसी, डि0क0 खण्ड-22 आगरा, डि0क0 खण्ड-1 चन्दौली, डि0क0 खण्ड-2 चन्दौली, डि0क0 खण्ड-1 धामपुर, डि0क0 खण्ड-2 इटावा, डि0क0 खण्ड-4 फैजाबाद, डि0क0 खण्ड-1 फतेहगढ़, डि0क0 खण्ड-4 फिरोजाबाद, डि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-12 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड-4 गोण्डा, डि0क0 खण्ड-15 कानपुर, डि0क0 खण्ड-21 कानपुर, डि0क0 खण्ड-24 कानपुर, डि0क0 खण्ड-25 कानपुर, डि0क0 खण्ड-2 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-8 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-10 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-11 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-12 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-22 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-9 मेरठ, डि0क0 खण्ड-3 औराई, डि0क0 खण्ड-5 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड-1 उन्नाव, डि0क0 खण्ड-15 वाराणसी, असि0क0 खण्ड-18 आगरा, असि0क0 खण्ड-19 आगरा, असि0क0 खण्ड-1 अलीगढ़, असि0क0 खण्ड-5 बरेली, असि0क0 खण्ड-2 बदरौं, असि0क0 खण्ड-12 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड-22 कानपुर, असि0क0 खण्ड-1 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-2 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-4 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-22 लखनऊ एवं असि0क0 खण्ड-10 मेरठ।

की अत्यधिक मात्रा होने, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं एवं निधि की कमी एवं अन्य कठिनाइयों के कारण आईटीसी के दावों के प्रतिसत्यापन की कार्यवाही वांछित तरीके से नहीं की जा सकी। यद्यपि विभाग यादृच्छिक संख्याओं के आधार पर आईटीसी के दावों का प्रतिसत्यापन कर रहा है और कई मामलों में गलत/मिथ्या आईटीसी के दावे प्रकाश में आये हैं।

2.25 कपड़े की बिक्री पर कर के प्रावधान का न होना

1957 के केन्द्रीय अधिनियम 58 कुछ वस्तुएँ जैसे चीनी, तम्बाकू, कारखाना निर्मित कपड़ा आदि पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए लागू किया गया। राज्य अपना अंश ऐसे संग्रहीत शुल्क से प्राप्त करते हैं और इस लिए वे इस पर बिक्री कर नहीं आरोपित करते हैं।

विज्ञप्ति संख्या 11/2006 केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 1 मार्च 2006 के द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएँ) अधिनियम, 1957 वापस ले लिया गया विज्ञप्ति संख्या के0ए0 एन0आई0-993/XI-9 (94)/07-उ0प्र0 अधिनियम-15-48-आदेश-(04)-2007 लखनऊ दिनांक 30 मई 2007 के अनुसार सभी प्रकार के अनिर्मित तम्बाकू तम्बाकू के अवशिष्ट आदि पर उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अंतर्गत 32.5 प्रतिशत की दर से एवं बाद में उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत चार प्रतिशत की दर से कर योग्य बनाया गया कर योग्य बनाया गया।

कपड़े की खरीद/बिक्री पर उ0प्र0व्या0क0/मू0सं0क0 आरोपित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया जबकि सरकार को कर आरोपित करने के लिए अधिकृत किया गया है परन्तु आज तक ऐसी कोई विज्ञप्ति निर्गत नहीं की गयी।

विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वापस लेने के पश्चात कारखाना निर्मित कपड़ों की बिक्री/खरीद पर उ0प्र0व्या0क0/मू0सं0क0 के अनारोपण के प्रभाव का हमने परीक्षण किया। हमने 13 वाणिज्य कर कार्यालयों¹⁷⁴ के कपड़ों के 27 व्यापारियों के वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक से सम्बन्धित क0नि0आ0 की जांच (अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य) किया एवं पाया कि ₹ 369.73 करोड़ के कपड़ों की बिक्री के कारोबार पर शासन द्वारा कोई मू0सं0क0 (वैट) आरोपित नहीं किया गया। मात्र इन 27 व्यापारियों के मामलों में 4 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने पर ₹ 14.79 करोड़ की वसूली होती, जो उक्त पर

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त करने के कारण विभाग राजस्व में हुई कमी को पूरा कर सकती थी। यदि राज्य के इस प्रकार के सभी व्यापारियों के लिए आगणित किया जाता तो यह बहुत अधिक होता। यह स्पष्ट है कि 1 मार्च 2006 से कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त किये जाने के बाद से राज्य के विभाज्य राजस्व में कमी आयी है और सरकार को कारखाना निर्मित कपड़े की बिक्री पर कर लगाने पर विचार करना चाहिए।

हमारे द्वारा फरवरी 2013 में मामले को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया; विभाग ने अगस्त 2013 में उत्तर दिया कि किसी वस्तु पर कर की दर एवं कर देयता तय करने का राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। अनेक अनुस्मारकों के भेजे जाने के बाद भी शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

हम संस्तुति करते हैं कि अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं तमिलनाडु के समान सरकार भी कपड़े की बिक्री पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त करने के आलोक में उस पर कर आरोपित कर सकती है।

¹⁷⁴ डि0क0 खण्ड-11 आगरा, डि0क0 खण्ड-12 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-2 कानपुर, असि0क0 खण्ड-6 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-10 लखनऊ, वा0क0अ0 खण्ड-8 सरखना मंडल, असि0क0 खण्ड-8 सरखना मंडल, असि0क0 सरखना मंडल, असि0क0 खण्ड-10 मेरठ, असि0क0 खण्ड-13 मेरठ, डि0क0 खण्ड-1 नोएडा, डि0क0 खण्ड-4 नोएडा, एवं असि0क0 खण्ड-2 नोएडा।

कार्यपालिका सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया

इस अध्याय में हमने "नई आबकारी नीति और उसका राजस्व पर प्रभाव" पर एक प्रस्तार और उससे सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में धीरे से अन्वेषण का काम उन्पादन, शारित का अनारोपण, विदेशी मदरा की टुकानों के लाइसेंस फीस का काम आरोपण, ब्याज का कम आरोपण, अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित ₹ 192 करोड़ के निदेशों मामले दर्शाये हैं।

कर संग्रह अधिकता/कमी

राज्य आबकारी विभाग की कुल प्राप्तिया वर्ष 2012-13 में ₹ 9782.49 करोड़ थी, जिसमें गतवर्ष की तुलना में 20.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु यह बजट अनुमान से ₹ 285.79 करोड़ कम थी, जो (-)2.84 प्रतिशत है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा/आन्तरिक नियन्त्रण

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा 140 इकाइयों की लेखापरीक्षा विहित की गयी जबकि केवल 119 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तिया के 148 इकाइयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जांच में कर के अनियमितताएं एवं अन्य अनियमितताओं के 238.03 करोड़ के 317 मामले प्रकाश में आये, जो धीरे से अन्वेषण का काम उन्पादन, शारित का अनारोपण, विदेशी मदरा के टुकानों के लाइसेंस फीस का कम आरोपण, ब्याज का कम आरोपण और अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं।

विभाग ने अनियमितताएं एवं अन्य कर्मियों के 34 मामलों में ₹ 6.55 लाख स्वीकार एवं वसूल किये, जिसमें से ₹ 2.00 लाख के पांच मामले वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष विगत वर्ष में इतिगत किये गये थे।

हमारा निष्कर्ष

विभाग की आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने सहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे तन्त्र की कर्मियां पता लगें और हमारे द्वारा पकड़ी गई प्रवृत्तियों को भविष्य में टाला जा सके।

हमारे द्वारा इतिगत किये गये वसूली न होने, कर के कम आरोपण, अर्थात् आदि के विशेषतः उन मामलों में जहाँ विभाग ने हमारे प्रेषण को स्वीकारा है, की वसूली के लिये भी पुनः कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

अध्याय-III राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर, अन्य मादक द्रव्यों जैसे चरस, भाँग एवं गांजा इत्यादि पर फीस आरोपित या आदेशित समपहरण उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उ०प्र०आ०अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत की जाती है। ये नियम मदिरा तथा अन्य मादक द्रव्यों की अवैध खरीद-बिक्री, अल्कोहल के आयात-निर्यात तथा उसके विधिविरुद्ध उत्पादन पर नियंत्रण करते हुए विभाग में राजस्व के रिसाव पर प्रबल नियंत्रण रखने हेतु बनाये गये हैं।

आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः चीनी निर्माण के दौरान सहउत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे से होता है। अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे०म०) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा०नि०वि०म०) जैसे व्हिस्की, ब्राण्डी, रम एवं जिन निर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आसवनी से मानव उपभोग हेतु मदिरा का निर्गम या तो बन्ध-पत्र के अधीन बिना आबकारी अभिकर के या निर्धारित दर पर उसके अग्रिम भुगतान पर होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। जिला अधिकारी (जि०अ०), जिला आबकारी अधिकारी (जि०आ०अ०) की सहायता से, जिले में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी है।

3.2 प्राप्तियों का रुझान

राज्य आबकारी से वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों को सारणी क्रमांक 3.1 में दर्शाया गया है :

सारणी क्रमांक 3.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों से प्रतिशत
2008-09	5,040.00	4,720.01	(-) 319.99	(-) 6.35	28,658.97	16.47
2009-10	5,176.45	5,666.06	(+) 489.61	9.46	33,877.60	16.73
2010-11	6,763.23	6,723.49	(-) 39.74	(-) 0.59	41,355.00	16.26
2011-12	8,124.08	8,139.20	(+) 15.12	0.19	52,613.43	15.47
2012-13	10068.28	9782.49	(-) 285.79	(-) 2.84	58098.36	16.84

स्रोत: उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखे।

राज्य आबकारी विभाग की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 में ₹ 9,782.49 करोड़ थी जिसमें गतवर्ष की तुलना में 20.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु यह बजट अनुमान से ₹ 285.79 करोड़ कम थी, जो (-) 2.84 प्रतिशत है।

3.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व बकाया ₹ 54.06 करोड़ था जिसमें से ₹ 48.51 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक पुराने थे। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में राजस्व बकाये की स्थिति सारणी क्रमांक 3.2 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2008-09	61.39	0.59	0.03	61.95
2009-10	61.95	1.35	0.07	63.23
2010-11	63.23	0.45	6.96	56.72
2011-12	56.72	0.03	1.93	54.82
2012-13	54.82	0.02	0.78	54.06

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाने के लिए विचार करें।

3.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के लिये सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण सारणी क्रमांक 3.3 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 3.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2010-11	6,723.49	95.72	1.42	3.64
2011-12	8,139.20	101.26	1.24	3.05
2012-13	9,782.49	116.88	1.19	2.98

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हमने पाया कि राज्य आबकारी विभाग की संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम है।

3.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को विश्वस्त बनाता है कि निर्धारित प्रणालियां तक्रसंगत तरीके से कार्य कर रही हैं।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में एक वित्त नियन्त्रक, एक वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी, एक वित्त लेखाधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी, छः वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं छः लेखा परीक्षको के स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी, एक वित्त लेखाधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी, दो वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं तीन लेखा परीक्षक ही कार्यरत हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु कुल 140 इकाईयों योजित थीं, किन्तु आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा केवल 119 इकाईयों की ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। उठाये गये निरीक्षण टीप की संख्या, उसमें निहित धनराशि, उसके अनुपालन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिसम्बर 2013 तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

3.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

3.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान, हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 1360.37 करोड़ की कर के अवनियमितताओं के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के मामलों दर्शाये

गये। विभाग द्वारा ₹ 8.53 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की गयी, जिसमें से मार्च 2013 तक ₹ 4.83 करोड़ की वसूली की गयी, विवरण सारणी क्रमांक 3.4 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 3.4

क्रम सं०	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तरो में शामिल धनराशि	स्वीकार किये गये प्रस्तरो की धनराशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि
1	2007-08	1.26	0.76	0.26
2	2008-09	1,344.56	4.24	3.93
3	2009-10	1.44	0	0
4	2010-11	1.03	3.04	0.52
5	2011-12	12.08	0.49	0.12
	योग	1,360.37	8.53	4.83

उपरोक्त सारणी क्रमांक का विश्लेषण यह दर्शाता है कि स्वीकार किये गये प्रस्तरो और उनकी धनराशि की प्रतिशतता बहुत कम है। वसूली की धनराशि स्वीकार किये गये प्रस्तरो की धनराशि के सापेक्ष 57 प्रतिशत है।

3.6.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1240 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 1786.46 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 108 मामलों में शामिल ₹ 2.65 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की एवं इसकी वसूली की गई। विवरण सारणी क्रमांक 3.5 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 3.5

वर्ष	लेखा परीक्षा इकाईयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गई धनराशि		वसूल की गई धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2007-08	82	93	18.80	12	0.06	12	0.06
2008-09	118	189	1,372.36	9	0.20	9	0.20
2009-10	119	140	66.93	20	0.95	20	0.95
2010-11	190	435	231.03	46	1.33	46	1.33
2011-12	200	383	97.34	21	0.11	21	0.11
योग	709	1240	1,786.46	108	2.65	108	2.65

उपर्युक्त सारणी क्रमांक का विश्लेषण करने पर देखा गया कि स्वीकार किये गये प्रस्तरो के धनराशि की प्रतिशतता काफी कम है। जबकि, स्वीकार किये गये प्रस्तरो के सम्बन्ध में वसूली की राशि शत प्रतिशत है।

3.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तियों के 148 इकाईयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 238.03 करोड़ के 317 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत सारणी क्रमांक 3.6 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 3.6

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव	1	188.80
2.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	10	24.60
3.	देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान न किया जाना	04	3.00
4.	लाइसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण	101	11.75
5.	ब्याज का अनारोपण	07	0.25
6.	अन्य अनियमितताएं	194	9.63
योग		317	238.03

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 34 मामलों में ₹ 6.55 लाख स्वीकार एवं वसूल किये, जिसमें से ₹ 2.00 लाख के पाँच मामले वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे।

प्रस्तर "नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव" और कुछ अन्य निदर्शी मामले जिनमें ₹ 192 करोड़ की धनराशि सन्निहित हैं, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है।

3.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में अल्कोहल का कम उत्पादन, अर्धदण्ड/ब्याज का अनारोपण आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियों प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

3.8 नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव

3.8.1 प्रस्तावना

राज्य आबकारी विभाग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त करने वाला विभाग है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 और नियमावलियों के अन्तर्गत और नई आबकारी नीति 2001 यथा संशोधित¹, द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को फीस के आरोपण और अल्कोहल के उत्पादन, स्वामित्व, परिवहन, विक्रय व क्रय पर आबकारी अभिकर के आरोपण की शक्ति प्रदान करते हैं।

आबकारी नीति के रूप में दिनांक 01 अप्रैल 2001 को प्रख्यापित “नई आबकारी नीति” ने नये शराब उद्यमियों के प्रवेश द्वारा शराब सिंडीकेट का एकाधिकार सीमित/समाप्त करने का उद्देश्य है। नीति की मुख्य विशेषता दुकानों का आर्बटन नीलामी अथवा टेण्डर के स्थान पर सार्वजनिक लाटरी द्वारा किया जाना था। नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि समुचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता की मदिरा उपभोक्ताओं को सुलभ हो। उपभोग आधारित आबकारी शुल्क के आरोपण से नई आबकारी नीति बनाई गयी जिसमें:

- मदिरा के अधिकतम थोक मूल्य (एम0डब्लू0पी0) व अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0 आर0पी0) का निर्धारण और मदिरा के थोक व फुटकर अनुज्ञापियों का लाभांश सीमित किया गया।
- मदिरा दुकानों के लिए लाइसेंसों के जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया, और लाइसेंस फीस का निर्धारण किया गया।
- विभिन्न प्रकार की मदिरा पर आबकारी अभिकर की देयता निर्धारित करी गयी।
- उपभोक्ताओं को मानक मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और आबकारी राजस्व की चोरी रोकने हेतु होलोग्राम का लगाया जाना अनिवार्य किया गया।
- माडल शाप्स स्थापित करी गयीं।

3.8.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, राज्य आबकारी, प्रशासनिक प्रमुख है। राज्य आबकारी विभाग का सम्पूर्ण नियन्त्रण व उत्तरदायित्व राज्य आबकारी आयुक्त (आ0आ0), उत्तर प्रदेश, मुख्यालय इलाहाबाद का है, जिनका सहयोग मुख्यालय स्तर पर दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, तीन संयुक्त आबकारी आयुक्त, 10 उप आबकारी आयुक्त और छः सहायक आबकारी आयुक्त करते हैं। वित्तीय मामलों में, आबकारी आयुक्त का सहयोग वित्त अधिकारी एवं मुख्य लेखा अधिकारी करते हैं। आबकारी आयुक्त पर आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के माध्यम से विभिन्न इकाईयों पर निगरानी रखने का भी उत्तरदायित्व है। प्रभावी प्रशासन के उद्देश्य से प्रदेश को पाँच जोन एवं 18 प्रमार्शों में

¹ दिनांक 10 जनवरी 2007, 04 मार्च 2008, 11 फरवरी 2009, 26 फरवरी 2010 और 12 मार्च 2011।

विभक्त किया गया है, जिसमें से प्रत्येक संयुक्त आबकारी आयुक्त और उप आबकारी आयुक्त के प्रभार में हैं, जिनका सहयोग प्रत्येक जनपद में एक सहायक आबकारी आयुक्त करते हैं। आबकारी प्राप्तियों के मामले में जनपद में जिला अधिकारी आबकारी प्रशासन का प्रमुख है।

3.8.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी कि:

- विभाग में आबकारी अभिकर् और लाइसेंस फीस इत्यादि के आरोपण एवं वसूली की समुचित एवं पर्याप्त प्रक्रिया विद्यमान है, और ये शासकीय खाते में जमा किये जा रहे हैं,
- नई आबकारी नीति के प्रावधानों को समुचित और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है,
- विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण अस्तित्व में है, और यह समुचित और प्रभावी है।

3.8.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निम्नलिखित अधिनियमों, नियमावलियों और आदेशों के परिप्रेक्ष्य में नई आबकारी नीति एवं उसका राजस्व पर प्रभाव सम्बन्धी लेखापरीक्षा सम्पन्न की गई:

- (i) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910,
- (ii) उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964,
- (iii) उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, 1974,
- (iv) नई आबकारी नीति, समय-समय पर यथा संशोधित,
- (v) शासकीय/विभागीय आदेशों/परिपत्रों और अधिनियमों² इत्यादि,

विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख सम्बन्धित प्रस्तरों में किया गया है।

3.8.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

इस लेखापरीक्षा हेतु हमने इकाईयों को अत्यधिक, मध्यम एवं लघु जोखिम क्षेत्र³ के रूप में विभाजन जिला आबकारी कार्यालयों द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि में राजस्व अर्जन के आधार पर किया। हमने अभिलेखों की जांच 14 जिला⁴ कार्यालयों का चुनाव अत्यधिक जोखिम, 27 जिलों में से सात जिला⁵ कार्यालयों का चुनाव मध्यम जोखिम और शेष 30 जिलों में से तीन जिला⁶ कार्यालयों का चुनाव लघु जोखिम क्षेत्र के रूप में किया। इकाईयों का मध्यम एवं लघु जोखिम वर्ग में चयन यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया। आबकारी आयुक्त⁷ के अभिलेखों की जांच की गयी, किन्तु शासन के अभिलेख⁷ अनेक प्रयासों के पश्चात् भी हमें उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखापरीक्षा अवधि सितम्बर 2012 से अप्रैल 2013 के दौरान सम्पन्न की गई।

2 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908, और उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997।

3 अत्यधिक जोखिम : जहाँ वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 100 करोड़ है।
मध्यम जोखिम : जहाँ वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 100 करोड़ से कम है।
लघु जोखिम : जहाँ वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 10 करोड़ से कम है।

4 अलीगढ़, बरेली, जौ0बी0 नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर और उन्नाव।

5 इलाहाबाद, बिजनौर, फिरोजाबाद, जौनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद और वाराणसी।

6 बदरौ, बागपत और कौशाम्बी।

7 वर्ष 2007-08 से 2012-13 के लिए नीति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

* इस सभिति के सदस्य अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन), वित्त नियन्त्रक, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी हैं।

* इसमें शीरा की लागत सहित कर्नाट राज्य उत्पाद शुल्क का भुगतान, प्रशासनिक प्रभार और इसके परिवहन की लागत शामिल है।

देशी मदिरा के अधिकतम शोक मूल्य और अधिकतम फुटकर मूल्य प्राप्त करने हेतु।

देशी मदिरा के अधिकतम शोक मूल्य और अधिकतम फुटकर मूल्य प्राप्त करने हेतु।

- फुटकर विक्रय के लिये एवं
- फुटकर विक्रय की वैशेषिक लाइसेंस फीस का अधिभार,
- दलालीयाम लगाने की लागत,
- शोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का अधिभार एवं गोदाम खर्च,
- आसवनी से शोक गोदाम तक परिवहन लागत,
- बाल, लैबल, कॅप्सूल और पैकेजिंग लागत,
- कॅरेमल इन्डोशन एवं एसेन्स लागत,
- जाँटना : अल्कोहल के अपभ्रंश पर परीक्षण एवं श्रम लागत,
- शीरे को अल्कोहल एवं ई एन ए में बदलने की लागत,
- शीरे का मूल्य तय करना,

आबकारी आयुक्त देशी मदिरा के अधिकतम शोक एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य निर्धारण हेतु समिति गठित करते हैं। मूल्य निर्धारण समिति निम्नलिखित कार्यों को शामिल करते हुए अधिकतम शोक मूल्य तय करते हैं:

सर्वप्रथम आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 41 व उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की शोक विक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 का नियम 13 प्रावधानित करता है कि आबकारी आयुक्त राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से देशी मदिरा का तीबलावार (25 प्रतिशत और 42.8 प्रतिशत वी/वी) मूल्य या मात्रा जिससे अधिक या कम पर किसी मादक पदार्थ की विक्री या आपूर्ति न हो, निर्धारित करे।

3.8.7 देशी मदिरा का मूल्य निर्धारण

लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

देशी आबकारी आयुक्त (आ0आ10) द्वारा सूचना तथा लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रदान करने के लिए विद्ये गये सहयोग हेतु आभार व्यक्त करते हैं।

3.8.6 अभिस्वीकृति

दिनांक 20 नवम्बर 2012 को आबकारी आयुक्त के साथ प्रारम्भिक विचारगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य पर चर्चा की गई थी और समापन विचार गोष्ठी 31 जुलाई 2013 को आयोजित की गई थी जिसमें प्रमुख सचिव/आबकारी आयुक्त और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे। इससे प्रेषणों के प्रति विभाग/सरकार की प्रतिक्रिया को समुचित स्थानों पर समितित किया गया है।

3.8.7.1 देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारण करते समय पूर्णांकन (राउंडिंग आफ) में एकरूपता न होना

विदेशी मदिरा की दर सूची के अनुसार विदेशी मदिरा के अधिकतम मूल्य को पूर्णांकित करते हुए ₹ 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित कर अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में आबकारी राजस्व में समाहित किया जायगा। देशी मदिरा के मामलों में यह पूर्णांकित धनराशि सरकारी खाते में अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में नहीं जमा की जाती है। देशी मदिरा के मूल्य निर्धारण समिति ने अपने संस्तुति में वर्ष 2007-08 के लिए ₹ 15 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी), वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए ₹ 20 और वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लिए ₹ 21.50 की दर से फुटकर विक्रेता के व्यय व लाभांश निश्चित किये थे, और इसे देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य की गणना में शामिल किया था।

आसवनियों¹⁰ के अभिलेखों¹¹ की अप्रैल 2007 से मार्च 2013 की अवधि की जांच में पाया गया कि देशी मदिरा की अधिकतम फुटकर मूल्य के निर्धारण में समान प्रक्रिया अपनायी गयी। लेकिन पूर्णांकित धनराशि को सरकारी खातों में अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में नहीं जमा किया गया, तथा इस पूर्णांकित धनराशि को आदर्श फुटकर लाभ (आपटिमम शेटलर मार्जिन) में जोड़कर फुटकर विक्रेता का लाभ बढ़ाया गया। देशी मदिरा के मूल्य निर्धारण में इस पूर्णांकित धनराशि के भेदकारी व्यवहार से अतिरिक्त प्रतिफल फीस ₹ 481.20 करोड़ का राजस्व सरकार को अप्राप्त था, और यह धनराशि देशी मदिरा के फुटकर विक्रेता को दिया गया। विवरण परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है। हमने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013)। शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि मूल्य निर्धारण समिति के विचार से पूर्णांकित धनराशि को परम्परागत रूप से फुटकर विक्रेताओं को दिया जाता है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि फुटकर विक्रेताओं को समिति के निर्धारित लाभांश से अधिक¹² लाभ दिये जाने के कारण, नीति का लाभांश को सीमित करने का उद्देश्य विफल रहा। पूर्णांकित धनराशि को समिति द्वारा निर्धारित किये गये लाभांश में जोड़ने से लाभांश बढ़ जाता है जिससे राजकोष को क्षति हुई।

हम संस्तुति करते हैं कि देशी मदिरा के पूर्णांकित धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में सरकारी राजस्व में जमा किया जाय जैसा कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मामलों में किया जाता है।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य की गणना में पूर्व आसवनी मूल्य में आबकारी राजस्व को जोड़ते हैं तत्पश्चात् योग के लिए फुटकर विक्रेता का लाभांश जोड़ते हैं। इसी योग को ₹ 5 के गुणांक में पूर्णांकित (राउंड आफ) करते हैं और इसको आबकारी राजस्व में अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में शामिल करा जाता है।

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश और 18

¹⁰ वेब आसवनी (अलीगढ़), केसर इण्टर प्राइजेज, सुफीरियर आसवनी (बरेली), सिन्मावली आसवनी, मोदी आसवनी (गाजियाबाद), लाईस आसवनी (गाजीपुर), सरैया आसवनी, आई जी एल आसवनी (गोरखपुर), पलिया आसवनी (लखीमपुर खीरी), दौराला आसवनी (बरेली), एन आई सी एल आसवनी (मुरादाबाद), शामली आसवनी, सर शादीलाल आसवनी (मुजफ्फर नगर), रामपुर आसवनी (रामपुर), पिलखनी आसवनी, शाकुम्भरी आसवनी, को आपस्टिव आसवनी टपरी (सहारनपुर) और उन्नाव आसवनी (उन्नाव)।

¹¹ मूल्य निर्धारण सूची, विक्रय विवरणियां और आबकारी नीति इत्यादि।

¹² उदाहरण : वर्ष 2010-11 के लिए कुल विक्रीत बोतलों (750 एम एल की 36 प्रतिशत वी/वी) की संख्या = 3978180
आदर्श फुटकर मूल्य = अधिकतम थोक मूल्य, फुटकर विक्रेता के थैला0फी0 का अधिभार, फुटकर विक्रेता का व्यय व लाभ = (123.61 + 15.75 + 15) = ₹ 154.36

जबकि अधिकतम फुटकर मूल्य ₹ 158 निर्धारित था।
अधिकतम फुटकर मूल्य - आदर्श फुटकर मूल्य = ₹ 158 एल = ₹ 154.36 = ₹ 3.64 इस प्रकार राउण्डेड आफ धनराशि फुटकर विक्रेता के लाभांश में जुड़ गया, जो बल्कर ₹ 15 (₹ 20 प्रति बल्क लीटर की दर से 750 एम एल के लिए जो मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित था) के स्थान पर ₹ 18.64 प्रति बोतल हो गया।

3.8.7.2 देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापी को अदेय लाभ

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 के नियम-11 के अन्तर्गत देशी मदिरा से भरी बोतल के संचय के लिए गोदामों के लाइसेंस स्वीकृत किये जाते हैं। अभिवहन या बंधित गोदाम में संग्रहण के दौरान शराब के अग्नि, दुर्घटना, चोरी अथवा किसी भी अन्य कारण से होने वाले क्षय, हानि या क्षति के लिए कोई छूट नहीं दी जायेगी। उक्त नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत अनुज्ञापी देशी मदिरा की आपूर्ति आसवनी से निर्धारित क्षमता और तीव्रता की बोतलों में जिनपर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम लगे हों, प्राप्त करेगा।

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि के अभिलेखों¹³ की जांच में पाया गया कि देशी मदिरा की मूल्य निर्धारण कमेटी ने देशी मदिरा के अधिकतम थोक मूल्य व अधिकतम फुटकर मूल्य के निर्धारण के समय थोक विक्रेता को पूर्व आसवनी मूल्य पर (आबकारी शुल्क को शामिल करते हुए) 0.5

प्रतिशत गलत छीजन (वेस्टेज) अनुमन्य किया गया। उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 के नियम 4 और 11 देशी मदिरा से भरी बोतल पर छीजन अनुमन्य नहीं करता। अग्रेत्तर, उक्त छीजन पर तीन से एक प्रतिशत¹⁴ का अस्वीकार्य लाभ¹⁵ भी प्रदान किया गया। इन छूटों के कारण थोक विक्रेता को ₹ 111.57 करोड़ का अदेय लाभ प्रदान किया। देशी मदिरा के थोक विक्रेताओं को दिया गया अदेय लाभ परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।

शासन ने उत्तर में कहा कि (जुलाई 2013) 0.5 प्रतिशत अभिवहन छीजन मदिरा के बल्क परिवहन¹⁶ पर अनुमन्य है। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं, ये सभी मदिरा के टैंकर में बल्क परिवहन के प्रकरण नहीं है, वास्तव में ये देशी मदिरा से भरी बोतलें हैं जिनपर सुरक्षा होलोग्राम लगे हैं जिनका परिवहन किया गया। इसके अतिरिक्त आबकारी नियम देशी मदिरा से भरी बोतल पर किसी प्रकार का छीजन अनुमन्य नहीं करता।

3.8.7.3 देशी मदिरा के थोक विक्रेता द्वारा थोक लाइसेंस फीस की अधिक संग्रहीत धनराशि को राजकोष में जमा करने के प्रावधान का अभाव

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के अनुसार लाइसेंस फीस का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन थोक देशी मदिरा के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफलन से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर जैसे कि आबकारी नीति द्वारा अधिसूचित किया जाये, देय होगी। मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार देशी मदिरा के अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण में उक्त लाइसेंस फीस को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक मूल्य में समायोजित किया जाता है।

थोक लाइसेंस फीस की गणना किसी आबकारी वर्ष में देशी मदिरा की अनुमानित बिक्री के आधार पर की जाती है, एवं लाइसेंसधारी से उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व अग्रिम रूप से संग्रहीत की जाती है। अधिकतम थोक मूल्य के निर्धारण के समय थोक अनुज्ञापी द्वारा भुगतान करी जाने वाली थोक लाइसेंस फीस को

¹³ मूल्य सूची, विक्रय विवरणी एवं आबकारी नीति इत्यादि।

¹⁴ वर्ष 2007-08 व 2008-09 में तीन प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में एक प्रतिशत।

¹⁵ उदाहरण : बोतलों की संख्या (36% वी/वी का 750एम एल) वर्ष 2010-11 में = 3978180

छीजन @ 0.5% + 1% छीजन पर लाभ (0.59 + 0.0059) = ₹ 0.5959। कुल लाभ जो छीजन पर दिया गया= 3978180 x 0.5959 = ₹ 2370597

¹⁶ टैंकर में शराब का बल्क परिवहन।

समायोजित किया जाता है। हमने देखा कि देशी मदिरा की वास्तविक बिक्री अनुमानित बिक्री से अधिक थी, अतः देशी मदिरा के थोक बिक्रेता द्वारा फुटकर बिक्रेताओं से, देशी मदिरा की वास्तविक बिक्री पर अधिक थोक लाइसेंस शुल्क की वसूली की गयी। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि दो वर्षों¹⁷ में थोक बिक्रेता द्वारा देशी मदिरा के फुटकर बिक्रेता से वसूल करी गयी तथा अधिकतम थोक मूल्य में समायोजित थोक लाइसेंस फीस, अपेक्षाकृत थोक अनुज्ञापी द्वारा सरकार को भुगतान किये गये थोक लाइसेंस फीस, से अधिक था। देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापी द्वारा अधिक लाइसेंस फीस वसूल कर अपने पास रखने का विवरण सारणी क्रमांक 3.7 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 3.7

(₹ में)

वर्ष	देशी शराब का उपभोग बल्क लीटर में (36% वी/वी)	थोक बिक्रेता के थोक लाइसेंस फीस का अधिभार प्रति बल्क लीटर (36% वी/वी)	थोक बिक्रेता द्वारा थोक लाइसेंस फीस का भुगतान	थोक बिक्रेता द्वारा फुटकर बिक्रेता से वसूल किया गया थोक लाइसेंस फीस	थोक लाइसेंस फीस का सरकार को किये गये भुगतान से अधिक थोक लाइसेंस फीस का संग्रह
2009-10	229260962	1.46	327100000	334721005	7621005
2010-11	234546651	1.56	359810000	365892776	6082776
				योग	13703781 या ₹ 1.37 करोड़

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

थोक विक्रेताओं द्वारा देशी मदिरा के फुटकर विक्रेता से वसूल करी गयी अधिक समायोजित थोक लाइसेंस फीस स्वयं अपने पास रख ली गयी। चूँकि ऐसा कोई प्रावधान/नियम नीति में नहीं है कि उक्त धनराशि लाइसेंस फीस के रूप में जमा किया जाय।

शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2013) कि अन्तर इस कारण उत्पन्न हुआ कि लाइसेंस फीस का निर्धारण अनुमानित आँकड़ों के आधार पर किया गया था। परन्तु शासन ने अधिक लाइसेंस फीस के समायोजन के बिन्दु पर कुछ नहीं कहा।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन ऐसा नियम बनाने का विचार करें कि यह अन्तरीय थोक लाइसेंस फीस थोक, अनुज्ञापी से वर्ष के अन्त में वसूली जाये अथवा वर्ष के अन्त में थोक अनुज्ञापी के प्रतिभूति धनराशि से समायोजित कर के वसूल करी जाय। यह प्रस्तावित प्रक्रिया आबकारी नीति की उस प्रक्रिया के अनुरूप होगी जिसमें विदेशी मदिरा के बोटल भराई के लाइसेंस एफ एल-3 व एफ एल-3ए¹⁸ के नवीनीकरण फीस को अनुमानित बोटल भराई के आधार पर जमा कराया जाता है, तथा वास्तविक बोटल भराई अधिक होने पर अन्तरीय नवीनीकरण फीस आगामी वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल से पूर्व जमा कराया जाता है।

3.8.8 उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के फुटकर विक्रय लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 का अनुपालन न किया जाना

आबकारी नीति वर्ष 2007-08 से 2012-13 के प्रावधानों के अनुपालन का भी निरीक्षण किया गया और हमने ऐसे प्रकरणों जैसे बेसिक लाइसेंस फीस (बे0ला0फी0) एवं प्रतिभूति जमा का जब्त न किया जाना, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0प्र0मा0) का कम उठान, न्यू0प्र0मा0 में कम आधार पर वृद्धि, शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन, लाइसेंस फीस का कम आरोपण और ब्याज का अनारोपण आदि में अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में देखा। हमारे निष्कर्ष निम्न रूप में वर्णित हैं।

¹⁷ 2009-10 एवं 2010-11।

¹⁸ एफ एल-3: आसवक द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोटल भराई लाइसेंस, एवं एफ एल-3ए : बाहरी आसवक, यवासवक या विन्टनर द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा व वाइन जिसपर अपना ब्राण्ड लेबल हो, बोटल भराई लाइसेंस।

3.8.8.1 बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति जमा का सम्पहरण न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के फुटकर बिक्री के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम 12 में प्रावधानित है, कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि, 10 कार्य दिवस के अन्दर आधी प्रतिभूति धनराशि एवं शेष धनराशि 20 कार्य दिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता के प्रकरण में, दुकान का चयन निरस्त कर दिया जायेगा, और बे0ला0फी0 एवं प्रतिभूति जमा की धनराशि, यदि कोई हों, शासन के पक्ष में समपहृत हो जायेगी, और दुकान का पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

विफलता में नियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत कोई शिथिलता अनुमन्य नहीं है, विभाग के द्वारा कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप शासन ₹ 53.68 करोड़ की बे0ला0फी0 एवं प्रतिभूति जमा की धनराशि जमा कराने से वंचित रहा।

हमने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013)। शासन ने हमारे प्रेषण को स्वीकार किया (जुलाई 2013), शासन ने यह भी बताया कि शायद परिचालन की कठिनाईयों के कारण, जिला कर्मचारियों द्वारा नियम-12 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी।

शासन के उत्तर से स्थापित हुआ कि धारा-12 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी थी।

3.8.8.2 देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी शुल्क की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के फुटकर बिक्री के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रत्येक अनुज्ञापी, प्रत्येक लाइसेंस के लिए निर्धारित समस्त मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0प्र0मा0) को उठाने के लिए उत्तरदायी है। असाफल होने की दशा में लाइसेंस प्राधिकारी, अनुज्ञापी की जमा प्रतिभूति से लाइसेंस शुल्क की बकाया अवशेष धनराशि का समायोजन करेगा तथा अगले माह की तीसरी तारीख तक अनुज्ञापी को नोटिस भी देगा कि प्रतिभूति राशि में आयी कमी को, या तो देशी मदिरा की उतनी मात्रा, जिसमें समायोजित धनराशि के बराबर निहित शुल्क हो, उठाकर अथवा नकद जमा कर या फिर दोनों ही विकल्पों द्वारा पूरा करें। यदि अनुज्ञापी आगामी माह की 10 तारीख तक प्रतिभूति की राशि की कमी को पूरा करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस निरस्त समझा जायेगा।

हमने छ: जिला आबकारी कार्यालयों¹⁹ के अभिलेखों²⁰ के निरीक्षण में देखा कि वर्ष 2011-12 में 639 देशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन या नवीनीकरण किया गया था। इन अनुज्ञापियों द्वारा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक बे0ला0फी0 एवं प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी थी। विलम्बित अवधि 01 से 105 दिनों के मध्य थी। इस

हमने मई 2012 में जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी के अभिलेखों में देखा कि चार अनुज्ञापियों ने वर्ष 2011-12 की अवधि में न्यू0प्र0मा0 42560 ब0 ली0 के सापेक्ष 29381.70 ब0ली0 देशी मदिरा का उठान किया। चूंकि वर्ष के दौरान देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 की सम्पूर्ण मात्रा का उठान नहीं किया गया था, अतः 13178.30 ब0 ली0 मदिरा के कम उठान

¹⁹ जि0आ0अ0-अलीगढ़, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, कानपुर एवं कौशांबी।

²⁰ 12ग-एक प्रतिवेदन, जिसमें व्यवस्थापित दुकानों का विस्तृत विवरण हो।

के लिए ₹ 20.69 लाख²¹ अन्तरीय लाइसेंस फीस, अनुज्ञापियों से वसूल किया जाना था।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2012), शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा कहा कि वसूली की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

3.8.8.3 मार्च माह में देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी शुल्क की कम वसूली

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के फूटकर बिक्री के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत, आबकारी आयुक्त के परिपत्र दिनांक 9 मार्च 2009 के अनुसार, अनुज्ञापी को माह मार्च में न्यूनप्रमा0 का कम से कम 80 प्रतिशत उठान किया जाना है। यदि अनुज्ञापी इसे करने में असफल रहता है, तो लाइसेंस फीस अनुज्ञापियों की जमा प्रतिभूति से समायोजित किया जायेगा।

हमने अगस्त 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य 15 जिला आबकारी कार्यालयों²² के अभिलेखों में देखा कि वर्ष 2007-08 2008-09 व 2009-10 के दौरान 902 अनुज्ञापियों ने माह मार्च 2008, 2009 व 2010 के लिए निर्धारित मासिक कोटे 1724353.05

ब0ली0 के सापेक्ष 1140947.58 ब0ली0 देशी मदिरा का उठान किया। इस कम उठान के कारण लाइसेंस फीस की अन्तरीय धनराशि ₹ 5.51 करोड़ विभाग द्वारा अनुज्ञापियों की जमा प्रतिभूति से समायोजित नहीं की गयी।

हमने प्रकरण शासन को (जून 2013) प्रतिवेदित किया, शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (जुलाई 2013) और कहा कि ₹ 54.27 लाख की धनराशि की वसूली की जा चुकी है एवं शेष धनराशि की वसूली प्रक्रिया में है।

3.8.9 देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में कम आधार के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की वृद्धि किया जाना

संबन्धित वर्ष की आबकारी नीति के अन्तर्गत, वर्ष 2008-09 का न्यूनप्रमा0 का निर्धारण, विगत वर्ष के न्यूनप्रमा0 में वृद्धि करके किया जाना था। वर्ष 2008-09 में वृद्धि दर 7 प्रतिशत, वर्ष 2009-10 में 7 प्रतिशत (8 प्रतिशत विशिष्ट मेरठ जोन में), वर्ष 2010-11 में 3 प्रतिशत, एवं वर्ष 2011-12 में एक प्रतिशत थी। वर्ष में दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त वृद्धि के अनुसार किया जाना था।

हमने 13 जिला आबकारी कार्यालयों²³ के उपभोग पंजिका, 12-ग²⁴ एवं अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया और देखा कि न्यूनप्रमा0 में वृद्धि विगत वर्ष के निर्धारित न्यूनप्रमा0 में किया गया था, जबकि विगत वर्षों में वास्तविक खपत न्यूनप्रमा0 से 0.001

से 6.69 प्रतिशत से अधिक थी। वास्तविक उठान के बजाय विगत वर्ष के न्यूनप्रमा0 के आधार के कारण वर्षों में 24.99 लाख ब0ली0 न्यूनप्रमा0 का कम निर्धारण हुआ, और शासन को बे0ला0फी0 के रूप में ₹ 4.13 करोड़ के राजस्व प्राप्ति से वंचित होना पड़ा। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013), शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि शासन द्वारा देशी मदिरा का न्यूनप्रमा0 का निर्धारण आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। न्यूनप्रमा0 का निर्धारण वास्तविक उठान के आधार पर सम्भव नहीं है।

²¹ कम उठाई गई मात्रा 13178.30 पर ₹ 157 प्रति ब0ली0 की दर से।

²² जि0आ0अ0-अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बदायूं, बिजनौर, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सहरनपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

²³ जि0आ0का0-इलाहाबाद, बदायूं, बागपत, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, कौशाम्बी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर एवं रामपुर।

²⁴ 12ग-एक प्रतिवेदन, जिसमें व्यवस्थापित दुकानों का विवरण हो।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन वर्ष की समाप्ति पर बे०ला०फी० के अन्तर की धनराशि वसूल किये जाने का अथवा वर्ष की समाप्ति पर फुटकर अनुज्ञापियों की प्रतिभूति से अन्तर की धनराशि का समायोजन करने हेतु प्रावधान बनाये। यह प्रक्रिया आबकारी नीति (वर्ष 2012-13 हेतु) के क्रम में होगा, जहाँ विदेशी मदिरा के बाटलिंग फीस की अग्रिम वसूली अनुमानित बोटलों के आधार पर है, किन्तु वास्तविक बोटलों की बिक्री के आधार पर नवीनीकरण फीस का अन्तर, अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की समाप्ति के पूर्व जमा करने का प्रावधान है।

3.8.10 शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन के फलस्वरूप राजस्व क्षति

शासनादेश संख्या 192/तेरह-18-91, दिनांक 5 अप्रैल 1991 के अनुसार प्रत्येक कुन्तल शीरे से 22.5 अल्कोहलिक लीटर (अ०ली०) (94% वी/वी) अल्कोहल के उत्पादन का मानदण्ड निर्धारित है जो कि राष्ट्रीय मानक है। देशी मदिरा की लागत की गणना उपर्युक्त मानक के आधार पर देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के निर्धारण के समय आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 के धारा 8(1) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त जो शीरा नियन्त्रक भी हैं, और आरक्षित शीरा देशी मदिरा निर्माता आसवकों को प्रदिष्ट (एलौट) करता है। उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, 1974 के नियम-21 के अनुसार नियन्त्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेशन ग्रहीता को प्रदिष्ट शीरा का प्रयोग उस प्रयोजन के, जिसके लिए वह प्रदिष्ट किया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। एक कुन्तल शीरे से 22.5 अ०ली० (94% वी/वी) अल्कोहल के उत्पादन के मानक के आधार पर देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण साथ ही साथ इसी आधार पर आबकारी शुल्क का आरोपण किया जाता है।

एक कुन्तल शीरे से 22.5 अ०ली० (94% वी/वी) अल्कोहल के उत्पादन के मानक के आधार पर देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण किया जाता है, साथ ही साथ इसी आधार पर आबकारी शुल्क का आरोपण किया जाता है। अतः हमने आसवनियों द्वारा मानकों के अनुपालन न करने के प्रकरणों में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का परीक्षण किया।

हमने 19 आसवनियों²⁵ के सी०ओ०टी०²⁶ पंजिका जैसे अभिलेखों की जांच की और पाया कि अगस्त

2012 व मई 2013 के मध्य इन आसवनियों²⁷ द्वारा मानक के अनुरूप शीरे से न्यूनतम अल्कोहल का उत्पादन²⁸ नहीं किया गया। अप्रैल 2007 से मार्च 2013 की अवधि में इन आसवनियों द्वारा 239.79 लाख कुन्तल शीरे से 5071.49 लाख अ०ली० अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए था, इसके विरुद्ध अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 4781.07 लाख अ०ली० हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप, 290.42 लाख अ०ली० अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ। इसे इन आसवनियों में उत्पादित कुल पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल के समानुपात में बॉटने के उपरान्त, हमने पाया कि इससे 174.85 लाख अ०ली० पेय अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ था, जिसमें ₹ 736.49 करोड़ का राजस्व सन्निहित था, कम उत्पादित अल्कोहल जिसे कि परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है।

²⁵ वेब आसवनी (अलीगढ़), केसर इण्टरप्राइजेज व सुपीरियर आसवनी (बरेली), सिम्भावली आसवनी, मोहन मीकिन आसवनी व मोदी आसवनी (गाजियाबाद), लाईस आसवनी (गाजीपुर), सरेया आसवनी व आई जी एल आसवनी (गोरखपुर), पलिया आसवनी (लखीमपुर खीरी), दीराला आसवनी (मेरठ), एन आई सी एल आसवनी (मुरादाबाद), शामली आसवनी व सर शादीलाल आसवनी (मुजफ्फर नगर), रामपुर आसवनी (रामपुर), शाकुम्भरी आसवनी व को आपरेटिव आसवनी, टपरी (सहारनपुर), सेजा आसवनी (शाहजहाँपुर) और उन्नाव आसवनी (उन्नाव)।

²⁶ आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त शीरे का मिश्रित नमूना तीन क्रमिक आउट टर्न में लेकर और इस तीन समान भागों में बाँटकर प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने मुहर से इसे मुहरबन्द किया जाता है।

²⁷ आबकारी आयुक्त द्वारा, पेय और अपेय अल्कोहल के निर्माण हेतु, रचीकृत पी डी-2 लाइसेंसधारी आसवनियों।

²⁸ शोधित आसव (आर एस) या इक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई एन ए)।

* 94 प्रतिशत वी/वी की अल्कोहल के विनिर्माण की लागत की गणना के लिए अपनाया गया सूत्र -
= आरक्षित शीरे की लागत (कु० में) = एक लीटर 94 प्रतिशत वी/वी के अल्कोहल की लागत
22.5

इस लागत में कनवर्जन लागत, श्रम लागत, छीजन इत्यादि शामिल कर आवश्यक तीव्रता (25, 36 अथवा 42.5 प्रतिशत) के अल्कोहल की लागत प्राप्त होती है। इसमें बाटलिंग, लेबुलिंग, कैप्सुलिंग, पैकेजिंग लागत, होलीग्राम की लागत जोड़ा गया है। तलपश्चात् आबकारी अधिकारी जोड़ा जाता है, पुनः देशी मदिरा के अन्तिम अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारण की गणना में माझा, गोदाम व्यय, छीजन (0.5 प्रतिशत), थोक बिक्रेता के लाइसेंस फीस का अधिभार, थोक बिक्रेता का लाभ, फुटकर बिक्रेता के लाइसेंस फीस का अधिभार, फुटकर बिक्रेता का व्यय एवं लाभ शामिल किया जाता है।

आरोपित किये जाने का प्रावधान है। शास्ति आरोपित किये जाने के पश्चात् इन मामलों में लाइसेंस के निलम्बन एवं रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। शासन का उत्तर अधिनियम के अनुरूप नहीं है। लाइसेंसधारी द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा 34 में आबकारी आयुक्त को लाइसेंस के निलम्बन/रद्द करने का अधिकार है। लाइसेंस की सामान्य और विशेष शर्तों में स्पष्ट है कि शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में शास्ति/प्रशमन के भुगतान के अलावा अनुज्ञापी प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने का दायी होगा। उल्लंघन के दोहराये गये मामलों सहित इन सभी मामलों में विभाग ने केवल शास्ति आरोपित व वसूल की किन्तु अवरोध (डिटरेन्स) के रूप में लाइसेंस को रद्द करने/प्रतिभूति जमा के समपहरण की कोई कार्यवाही नहीं की।

3.8.13 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलनीय होता है।

आबकारी विभाग के तीन कार्यालयों में देखा गया कि वर्ष 2003-04 से 2008-09 की अवधि का आबकारी राजस्व⁵⁴ ₹ 63.15 लाख माह अप्रैल 2007 और दिसम्बर 2011 के मध्य, 126 से 2823 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया। विभाग द्वारा

विलम्बित भुगतान पर ब्याज की धनराशि ₹ 19.47 लाख का आरोपण नहीं किया गया, विवरण सारणी क्रमांक 3.8 के अनुसार :

सारणी क्रमांक 3.8

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	अवधि	धनराशि	(₹ लाख में)	
				विलम्ब की अवधि दिनों में	ब्याज की धनराशि
1	जिला आबकारी अधिकारी, इलाहाबाद	2008-09	30.76	126 - 513	1.84
2	सहायक आयुक्त, दौराला आसवनी, दौराला, मेरठ	2003-04 से 2006-07	24.00	398 - 1493	11.19
3	जिला आबकारी अधिकारी, मऊ	2003-04 से 2008-09	8.39	828-2823	6.44
योग			63.15	126 - 2823	19.47

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013)। शासन ने इस आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2013), और क्रम संख्या 2 और 3 के मामले में वसूली के लिए नोटिस जारी किया। क्रम संख्या 1 के सम्बन्ध में उत्तर दिया कि प्रतिभूति जमा कोषागार में जमा थी, और इस पर ब्याज आरोपणीय नहीं था। हम उत्तर के इस भाग से सहमत नहीं हैं, हमारी आपत्ति आबकारी ड्यूटी के विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज के अनारोपण का था, जबकि विभाग ने उत्तर दिया कि प्रतिभूति जमा कोषागार में जमा थी। ये दोनों⁵⁵ भिन्न मदे हैं और विभाग का उत्तर हमारे अभिव्यक्ति से अलग बिन्दु पर है।

⁵⁴ आबकारी अभिकर ₹ 30.76 लाख, लाइसेंस फीस ₹ 32.39 लाख।

⁵⁵ प्रतिभूति जमा और आबकारी अभिकर।

3.8.14 गोदामों पर किराये का कम आरोपण व स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 के नियम 5(2) व (3) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किराये का भुगतान करने पर जिले के मुख्यालय पर स्थित आबकारी विभाग के गोदाम भवन में लाइसेंसधारी को बंधित गोदाम चलाने की अनुमति दी जायेगी। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम-4 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा व्यावसायिक सम्पत्तियों के किराये की दरें द्विवार्षिक निर्धारित की जाती हैं, जिसे साक्रिल रेट कहा जाता है। जब जिला मुख्यालय पर कोई सरकारी गोदाम न हो अथवा सरकारी गोदाम में पर्याप्त स्थान न होने की स्थिति में बंधित गोदाम जिला मुख्यालय पर निजी परिसर में खोला जा सकता है, जिसे उस जिले के जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के धारा-18 के उपबन्धों के अन्तर्गत अवल सम्पत्ति की पट्टा जो कि एक वर्ष से अधिक अवधि की नहीं है पंजीयन कराना ऐच्छिक है। फिर भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची एक खा के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत एक वर्ष से अनधिक अवधि की पट्टा पर हस्तांतरण विलेख के समान देय सम्पूर्ण राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के धारा 33(1) के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी (पुलिस अधिकारी के सिवाय), प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाय, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हैं और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं हैं, उसे जब्त करेगा और जिला कलेक्टर को मूल्यांकन के लिए भेज देगा।

वसूली की गयी।

- वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान हमने तीन जनपदों⁵⁸ के आठ प्रकरणों में देखा कि ₹ 10 व ₹ 100 के स्टाम्प पत्र पर पट्टा निष्पादित⁵⁹ किये गये परन्तु पंजीकृत नहीं कराया गया। इस प्रकार इन प्रकरणों में ₹ 1.62 लाख स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान छः जनपदों⁶⁰ के 29 प्रकरणों में यद्यपि जिला आबकारी अधिकारियों ने थोक अनुज्ञापियों को किराये पर आबकारी गोदाम आबंटित किया, परन्तु न तो किरायानामा निष्पादित किया गया और न ही स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 3.45 लाख स्टाम्प शुल्क का आरोपण किरायेनामे पर नहीं किया गया।

जनपद के जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा किरायेनामे पर सही किराया आरोपित करने व स्टाम्प शुल्क के भुगतान को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया गया।

हमने अगस्त 2012 एवं अप्रैल 2013 के मध्य सात जिला आबकारी कार्यालयों⁵⁶ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा कि देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों को विभागीय गोदाम पट्टे पर दिया गया। दो जनपदों⁵⁷ में निजी परिसर में स्थित गोदाम में थोक अनुज्ञापियों को गोदाम खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गयी। हमने निम्न-लिखित अनियमिततायें इन प्रकरणों में पायी :

- वर्ष 2007-08 से 2012-13 के मध्य देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों से गोदामों को दिये गये पट्टे पर अनुमोदित साक्रिल रेट के अनुसार सही किराया प्रभार्य नहीं किया गया, जिससे ₹ 66.79 लाख किराये की कम

⁵⁶ अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, जौनपुर, रामपुर, उन्नाव और वाराणसी।

⁵⁷ बरेली और लखनऊ।

⁵⁸ बरेली, लखीमपुर खीरी और लखनऊ।

⁵⁹ बरेली व लखनऊ (निजी परिसर), लखीमपुर खीरी (सरकारी गोदाम)।

⁶⁰ जिलाओड्डा-अलीगढ़, बरेली, जौनपुर, रामपुर, उन्नाव और वाराणसी।

परिणामस्वरूप, शासन ₹ 71.86 लाख (₹ 66.79 कम किराया व ₹ 5.07 लाख स्टाम्प शुल्क) के राजस्व से वंचित रहा।

हमने मामला शासन को (जून 2013) प्रतिवेदित किया। शासन ने हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए कहा कि वसूली के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं। वसूली का विवरण प्रतीक्षित है।

3.8.15 देशी मदिरा के थोक बिक्रेता को अभिलेखों के रखरखाव में कमी के फलस्वरूप गोदाम व्यय अनुमन्य किया जाना

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारण के समय थोक बिक्रेता को गोदाम परिव्यय अनुमन्य किया गया, जिसे देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य वर्ष 2007-08 में ₹ 1.30 प्रति बल्क लीटर वर्ष 2008-09 से 2010-11 में ₹ 1.39 प्रति बल्क लीटर एवं वर्ष 2011-12 में ₹ 1.53 प्रति बल्क लीटर की दर से सम्मिलित किया गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 के नियम-7 के उपनियम-3 के अनुसार लाइसेंसधारी प्रभारी अधिकारी को एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें अभिकर्ता तथा ऐसे समस्त कर्मचारियों के नाम होंगे जिनकी सेवायें गोदाम में आवश्यक हैं। गोदाम परिव्यय में, किराया, कर्मचारियों का वेतन, जल व विद्युत प्रभार सम्मिलित हैं।

नौ⁶¹ जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों⁶² की जांच में हमने देखा कि देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों को सात⁶³ जिला आबकारी अधिकारियों ने विभागीय गोदाम आबंटित किया एवं दो⁶⁴ जिला आबकारी अधिकारियों के पास निजी परिसर में गोदाम होने का विवरण था। संबंधित थोक अनुज्ञापियों⁶⁵ द्वारा उपलब्ध करायी गयी कर्मचारियों की सूची सभी नौ जिला आबकारी

कार्यालयों में उपलब्ध थी। हमने पाया कि गोदाम में कर्मचारियों की संख्या दो से चार⁶⁶ व वास्तविक किराया का खर्च देशी मदिरा के थोक बिक्रेता को आबंटित गोदाम परिव्यय, जो थोक बिक्रेता की मार्जिन का भाग है, का केवल 0.28 से 6.99 प्रतिशत की सीमा में था। इन नौ जनपदों में वर्ष 2007-08 व वर्ष 2011-12 के मध्य थोक बिक्रेताओं को अकेले ₹ 29.74 करोड़ गोदाम परिव्यय के रूप में अनुमन्य किया गया था। जब वास्तविक परिव्यय की तुलना उपलब्ध आकड़ों⁶⁷ से करते हैं तो वह बहुत उच्च प्रतीत होता है, जिसे परिशिष्ट-XIV में दर्शाया गया है।

जब हमने इसे इंगित किया तो, शासन ने अपनी सहमति प्रकट की कि गोदाम परिव्यय के संगणना के लिए कोई गणना-प्रपत्र नहीं था, और कहा कि किराया जल व विद्युत प्रभार, कम्प्यूटर, लेखन सामग्री और कर्मचारियों/श्रमिकों का वेतन को गोदाम परिव्यय के निर्धारण में संज्ञान में लिया जाता है। शासन के उत्तर से स्पष्ट है कि मूल्य निर्धारण समिति द्वारा वास्तविक व्यय की गणना नहीं की गयी है।

हम संस्तुति करते हैं कि गोदाम परिव्यय उचित अभिलेखों जैसे वास्तविक किराया, वेतन/मजदूरी इत्यादि जो कि पूर्व के वर्षों में भुगतान किया गया था, के आधार पर प्राक्कलित किया जाय।

⁶¹ जि0आ0अ0-अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रामपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

⁶² गोदामों की लीज डीड।

⁶³ जि0आ0अ0-अलीगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, रामपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

⁶⁴ जि0आ0अ0-बरेली एवं लखनऊ।

⁶⁵ सी एल-1सी (थोक अनुज्ञापन) विवरण में।

⁶⁶ वर्ष 2007-08 में बरेली में अपवादस्वरूप नौ को छोड़कर।

⁶⁷ लेखे में सम्मिलित नियमित जल व विद्युत प्रभार औसत 223.09 वर्ग मीटर गोदाम के लिए।

को शीरा निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर चीनी मिल में वापस प्राप्त हो जाने चाहिए। शीरा नियंत्रण अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोग/अर्थदण्ड से संबंधित कार्यवाही की जायेगी।

3.10 अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण परिहार्य व्यय

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम एवं वैट अधिनियम के अन्तर्गत टेण्डर फार्मों की बिक्री इन अधिनियमों में विहित दर पर कर की देयता को आकर्षित करता है। टेण्डर फार्म विक्रेता ऐसे फार्मों की बिक्री पर खरीदने वाले व्यक्ति से कर का आरोपण एवं संग्रहण करने और इसको कोषागार में जमा करने का दायी है।

हमने 29 जिला आबकारी कार्यालयों⁷⁰ के अभिलेखों⁷¹ की प्रति परीक्षा जांच में देखा (अप्रैल 2011 से जनवरी 2012) कि 1,25,664 टेण्डर फार्मों का विक्रय किया गया, और वर्ष 2007-08 से

2010-11 के दौरान प्रोसेसिंग फीस ₹ 3,864.66 लाख संग्रहीत की गयी। इस बिक्री पर आरोपणीय व्यापार कर/वैट की धनराशि ₹ 1.69 करोड़ जिला आबकारी कार्यालयों द्वारा फार्म के क्रेताओं से संग्रहीत नहीं की गयी थी।

हमारे द्वारा इसको इंगित किये जाने के पश्चात् (जून 2011 व फरवरी 2012 के मध्य) शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2013), कि आबकारी आयुक्त द्वारा वाणिज्य कर विभाग को इन फार्मों की बिक्री पर देय वैट के भुगतान हेतु प्रेषित मॉग के सापेक्ष जुलाई 2012 में शासन द्वारा ₹ 5.92 करोड़ की अनुदान आबटित कर दी गयी है। शासन का उत्तर हमारी आपत्ति की पुष्टि करता है, कि विभाग ने क्रेताओं से कर का संग्रहण नहीं किया, और शासन पर इसका भार डाल दिया, जिसको अनुदान के रूप में स्वीकृत करना पड़ा। हमने यह भी देखा कि ₹ 5.92 करोड़ की मॉग प्रेषित किये जाने के कारणों में यह बताया गया कि आवेदकों से धनराशि की वसूली में असमर्थ हैं क्योंकि आवेदकों के पते उपलब्ध नहीं हैं। आवेदन के अभिलेखों का हमने निरीक्षण किया, व हमने देखा कि फार्मों में आवेदकों के नाम व पते स्पष्ट रूप से अंकित थे। इसलिए हमारे लेखापरीक्षा द्वारा यह स्थापित है, कि अनुदान हेतु उठायी गयी मॉग का आधार वास्तविक रूप में सही नहीं था।

अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने और आवेदकों से कर की वसूली हेतु समय से कार्यवाही न किये जाने के कारण शासकीय राजकोष पर परिहार्य भार पड़ा।

⁷⁰ लिओआफको-अलीगढ़, अवेडकर नगर, औरिया, बागपत, बहराइच, बलिया, बांदा, बिजनौर, हुलन्दशहर, कन्दौली, एटा, गावियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मऊ, मेरठ, रमाबाई नगर, (फागपुर देहात), सहायपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और सोनमद।

⁷¹ टेण्डर फार्म बिक्री पत्रिका, रसीद बुक और रोकड़ बही।

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया

इस अध्याय में हमने ₹ 9.66 करोड़ के निदर्शी मामले प्रस्तुत किये हैं जो परिवहन विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये थे। हमने माल एवं यात्री वाहनों से कर एवं शास्ति के न/कम वसूली होना, सीटिंग क्षमता के त्रुटिपूर्ण निर्धारण से वाहनों से देय कर की कम वसूली, अधिक भार ढोने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण, परमिट के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण शास्ति का अनारोपण, परमिट के आवेदन एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न होना, जब्त वाहनों से न/कम वसूली होना और कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर जो वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, पर कर तथा अर्थदण्ड का अनारोपण, के कई मामले पाये।

कर संग्रह में अधिकता/कमी

वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में 25.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन बजट अनुमान से यह 1.54 प्रतिशत कम रहा।

आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0)

प्रमुख सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति का विभाग में गठन किया गया था, जो आ0ले0प0शा0 के कार्यकलापों पर चर्चा के लिये आवधिक रूप से मिलती है। वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने चार मामलों में आ0ले0प0शा0 के दृष्टान्त पर ₹ 12.13 लाख की वसूली की।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

हमने 2012-13 की अवधि में परिवहन विभाग की 72 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और कर अवनियमितताओं और दूसरी अनियमितताओं, जिनमें ₹ 151.56 करोड़ सम्निहित था, के 668 मामले पाये। विभाग ने कर अवनियमितताओं और दूसरी कमियों के ₹ 10.30 लाख के मामलों को स्वीकार किया और ₹ 10.10 लाख की वसूली की।

हमारा निष्कर्ष

विभाग को आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे तन्त्र की कमियाँ पता लगे और हमारे द्वारा पकड़ी गई प्रवृत्तियों को भविष्य में टाला जा सके।

हमारे द्वारा इंगित किये गये वसूली न होने, कर के कम आरोपण, अर्थदण्ड आदि के विशेषतः उन मामलों में जहाँ विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकारा है, की वसूली के लिये भी त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

बकायों के अन्तिम अवशेष में वृद्धि हुई है। पाँच वर्ष से अधिक के पुराने बकाये और विभिन्न अवस्थायें जहाँ अवरोध बकाया राजस्व की वसूली नहीं हो पाई है, उसके बारे में बारम्बार अनुरोध के बाद भी विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गयी (दिसम्बर 2013)।

4.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान माल एवं यात्री वाहनों पर कर का सकल संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे अंकित है।

सारणी क्रमांक 4.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह के लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए संग्रह लागत की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008-09	1,391.15	50.43	3.62	2.58
2009-10	1,674.55	69.16	4.13	2.93
2010-11	2,058.58	78.13	3.80	3.07
2011-12	2,380.67	79.86	3.35	3.71
2012-13	2,993.96	95.45	3.19	2.96

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि संग्रह लागत पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक क्रमशः कम होती गई किन्तु संग्रह की लागत वर्ष 2012-13 में अखिल भारतीय औसत से अभी भी अधिक है।

4.5 आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा

किसी संगठन की आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भलीभाँति कार्य कर रहे हैं।

विभाग में प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो समय-समय पर आ0ले0प0शा0 के कार्यकलापों पर चर्चा करती है। वर्ष 2012-13 में विभाग ने आ0ले0प0शा0 के दृष्टान्त पर चार प्रकरणों में ₹ 12.13 लाख की वसूली की।

आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और तीन लेखा परीक्षक नियुक्त हैं। विभाग द्वारा शाखा की स्वीकृत पदों की संख्या, लेखा परीक्षा योजना का विवरण जैसे लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षा हुई इकाइयों की संख्या, वर्ष के दौरान उठाई गई एवं समाधानित आपत्तियों की संख्या एवं उनमें निहित धनराशि की सूचना नहीं दी गई।

हम संस्तुति करते हैं कि आ0ले0प0शा0 को मजबूत किया जाय और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाय।

4.6 लेखा परीक्षा का राजस्व प्रभाव

4.6.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

हमने वर्ष 2007-08 से 2011-12 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में यात्रीकर/अतिरिक्त कर का न/कम आरोपण किया जाना, मार्ग कर/माल कर का अवनिर्धारण और दूसरी अनियमितताओं के मामले जिनमें ₹ 121.51 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, प्रतिवेदित किये थे। इनमें से विभाग ने ₹ 83.50 करोड़ की आपत्तियाँ

स्वीकार की थी और 31 मार्च 2013 तक ₹ 12.76 करोड़ वसूल कर लिया था। विवरण सारणी क्रमांक 4.4 में अंकित है:

सारणी क्रमांक 4.4

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गई धनराशि 31.03.2013 तक
2007-08	82.02	73.22	8.80
2008-09	5.80	0	0
2009-10	15.80	8.16	2.61
2010-11	2.46	1.28	0.62
2011-12	15.43	0.84	0.73
योग	121.51	83.50	12.76

विगत पाँच वर्षों के दौरान वसूल की गयी धनराशि स्वीकृत मामलों की तुलना में शून्य या बहुत कम रही।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार कम से कम उन आपत्तियों के विषय में जो स्वीकार की गयी हैं, वसूली की स्थिति सुधारने हेतु उपयुक्त कदम उठाये।

4.6.2 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कर के कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, गलत छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,819 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 399.45 करोड़ का राजस्व निहित था। इनमें से विभाग/शासन ने 459 मामलों में निहित ₹ 10.13 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की तथा 31 मार्च 2013 तक इन मामलों में निहित धनराशि वसूल कर ली थी। विवरण सारणी क्रमांक 4.5 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गई धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2007-08	62	213	94.45	4	0.25	4	0.25
2008-09	71	344	118.34	148	2.49	148	2.49
2009-10	71	245	26.46	40	0.85	40	0.85
2010-11	71	369	29.54	263	6.44	263	6.44
2011-12	96	648	130.66	4	0.10	04	0.10
योग	371	1819	399.45	459	10.13	459	10.13

अधिक मात्रा में लेखापरीक्षा प्रेक्षकों के लंबित रहने की दृष्टि से शासन नियमित अन्तराल में प्रस्तरो के त्वरित निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन करना सुनिश्चित करे।

4.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान परिवहन विभाग से सम्बन्धित 72 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 151.56 करोड़ के

- 4 वाहनों के विवरण जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, कर आदि के बिधे निर्दिष्ट।
- 5 194 वाहन।
- 6 १०५०५०० अलीगढ़, इलाहाबाद, बादा, बरेली, कानपुर और गोरख का उत्तर प्रतीक्षित है।
- 7 परमिट रजिस्टर एवं सम्बन्धित काडल।
- 8 3359 वाहनों में से।
- 9 34789 वाहनों में से।

कार्यवाही करनी चाहिए थी।

विभाग की राजकाश के हित में वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत करने में सक्रियता से वाहन ३०५०५०० नियमावली के नियम २२ के अनुसार प्रयोग में समझे जाने थे और गयी थी और परमिट/दस्तावेज अस्पष्ट नही किये गये थे। इस प्रकार यह माटर कभी भी आवेदन नही किया। इस महत्व नही है क्योंकि परमिट की वैधता समाप्त हो इसके नही बरखा गया क्योंकि परमिट धारक ने नवीनीकरण या निरस्तीकरण के लिए परमिट धारक आवेदन करवा है। इन प्रकारों में कोई भी परमिट और आवेदन बतयाया (सितम्बर २०१३) कि परमिट का नवीनीकरण तभी किया जाता है जब इसके हमारे द्वारा इसे विभाग और शासन को जून २०१२ में इंगित किये जाने पर विभाग ने विभाग द्वारा विहित नही किया गया।

जमा कर और वाहनों के अन्य विवरण वाहन साफ्टवेयर में उपलब्ध थे, इन प्रकारों को इस तथ्य के बावजूद कि सभी सूचनायें जैसे कि परमिट वैधता की समाप्ति की तिथि, नियमावली, १९९८ के नियम २२ के अनुसार प्रयोग में समझे जायें।

३०५०५०००

4.7.2 हमने परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखा^१ से देखा कि (मई २०१२) कि ५५ वर्षों^२ एवं १११ माटर टैक्सियां^३ के परमिट की वैधता जनवरी २००८ से मार्च २०१२ के मध्य समाप्त हो गई थी। क्योंकि वाहन स्वामियों ने दस्तावेज अस्पष्ट नही किये, माटर वाहन

जाया कि माटर वाहन प्रयोग में है।
दस्तावेज अस्पष्ट नही किया जाता तो यह समझा दस्तावेज अस्पष्ट करना होगा। यदि परमिट और अन्य अनुसार वाहन को प्रयोग से हटाने पर परमिट और अन्य है। ३०५०५००० नियमावली, १९९८ के नियम २२ के १५ दिन से पूर्व आवेदन कर नवीनीकरण कराया जा सकता है। ३०५०५००० (२) के अधीन परमिट, वैधता अवधि समाप्ति के परमिट से निम्न परमिट पूर्व वर्ष तक प्रभावी रहेगा। धारा ८८ की उप धारा-(८) के अधीन निर्गत विशेष करवा है कि धारा ८७ के अधीन निर्गत अस्थाई परमिट या १०५०००० अधिनियम, १९८८ की धारा ८१(१) प्रावधानित

- १००८ वाहनों के संबंध में १०५००० अधिनियम की धारा-८६ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।
- ७७९ वाहनों के राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र ₹ १.१० करोड़ सम्मिलित फीस तथा नवीनीकरण फीस लेकर, नवीनीकरण किये गये।
- ८४२ वाहनों के परमिट निरस्त किये गये।

२०१४) कि :

हमारे द्वारा इस बिन्दु को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बतयाया^४ (जनवरी अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गई।
आदेश के अनुसार कार्यवाही की गई और १०५००० अधिनियम, १९८८ की धारा-८६ के हमने देखा कि केवल सहारनपुर^५ में १०५०३१० द्वारा ५०३१० के फरवरी २००० में दिये है।

प्रारम्भ नही की गयी जैसा कि परिवहन आयुक्त के फरवरी २००० के आदेश में वर्णित विभाग द्वारा परमिट धारक को नोटिस निर्गत कर परमिट निरस्त करने की कार्यवाही साफ्टवेयर^६ में उपलब्ध थे, इन प्रकारों को विभाग द्वारा विहित नही किया गया।

राज्य सरकार मो0या0 अधिनियम/उ0प्र0मो0वा0 नियमावली अथवा फरवरी 2000 के विभागीय आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र विकसित करे जिससे कि राजस्व का क्षरण न हो।

4.8 निजी/कृषि कार्य हेतु पंजीकृत वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग

उ0प्र0 मो0 यान अधिनियम, 1997 की धारा 4(2) के अन्तर्गत दिनांक 28 अक्टूबर 2009 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार सन्निर्माण उपस्कर यान इक्विपमेन्ट कंस्ट्रक्शन वेहिकल या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान, जो वाणिज्यिक उद्देश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाये, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए देय कर, ₹ 500 प्रति त्रैमास अथवा ₹ 1800 प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय है।

हमने (जून 2012 और दिसम्बर 2012 के मध्य) चार स0प0का0¹⁰ और तीन स0स0प0का0¹¹ के अभिलेखों¹² की जांच की और पाया कि :

4.8.1 फरवरी 2010 से जुलाई 2012 की अवधि के दौरान 10 वाहन¹³ निजी वाहन के रूप में पंजीकृत

थे और केवल एकबारीय कर जमा किया था। चूंकि इन सभी वाहनों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया था, इन वाहनों का निजी वाहन के रूप में पंजीकृत होना और एकबारीय कर का आरोपण किया जाना गलत था। विवरण सारणी क्रमांक 4.7 में दर्शित है :

सारणी क्रमांक 4.7

(₹ लाख में)

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	निजी रूप में पंजीकृत वाहनों की संख्या	₹ 1800 प्रति टन प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय कर	एक बारीय जमा कर	पंजीकरण की अवधि
1	स0प0का0 आजमगढ़	04	8.64	5.23	02/2010 से 07/2012
2	स0प0का0 गाजियाबाद	04	8.50	5.11	07/2011 से 01/2012
3	स0स0प0का0 हरदोई	02	4.59	0.88	08/2011 से 12/2011
	योग	10	21.73	11.22	

पुनश्च, 14 वाहनों¹⁴ में स्वामियों द्वारा एक से आठ त्रैमास का त्रैमासिक कर भी नहीं जमा किया गया था और अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही थी। इसके फलस्वरूप ₹ 3.06 लाख के कर का अनारोपण हुआ जैसा कि सारणी क्रमांक 4.8 में दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक 4.8

(₹ लाख में)

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	निजी रूप में पंजीकृत वाहनों की संख्या	₹1800 प्रति टन प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय कर	जमा कर	देय कर	पंजीकरण की अवधि
1	स0प0का0 लखनऊ	14	3.06	—	3.06	7/2010 से 3/2012
	योग	14	3.06	—	3.06	

¹⁰ आजमगढ़, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ।

¹¹ हरदोई, महाराजगंज और मऊ।

¹² टैक्स पोस्टिंग रजिस्टर, पंजीयन रजिस्टर, कर रजिस्टर, अभियोजन पुस्तिका, अपराध एवं जल्दी रजिस्टर।

¹³ जे.सी.बी. मशीन(1), क्रेन(1), अर्थ मूविंग मशीन(4), उत्खनक वाहन (4)।

¹⁴ क्रेन(13), कैश वैन(1)।

हमारे द्वारा मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये जाने पर (जुलाई 2012 से फरवरी 2013) विभाग ने आजमगढ़, लखनऊ और हरदोई के मामले में हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और नोटिस निर्गत करने तथा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। गाजियाबाद¹⁵ के मामले और हरदोई के एक वाहन (क्रेन) के विषय में विभाग ने बताया कि फर्म द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार, वाहनों का उपयोग गैर परिवहन/निजी वाहन के रूप में किया जा रहा है। उपरोक्त के विषय में हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ये सभी वाहन व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि फर्मों के लिए पंजीकृत की गई थी और ये उत्खनक वाहन (एक्सकवेटर) तथा क्रेन थे।

कृषि कार्य से भिन्न वाणिज्यिक उद्देश्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर पर प्रत्येक मीट्रिक टन लदान रहित भार या उसके भाग पर ₹ 500 प्रति त्रैमास या ₹ 1800 वार्षिक की दर से कर देय है। अग्रेतर, मो0या0 अधिनियम की धारा 192-अ के अनुसार जो कोई धारा-66 की उपधारा (1) के प्रावधानों के विपरीत अथवा उस उद्देश्य जिसके लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकता है, उस पर प्रथम अभियोग के लिए ₹ 2500 जिसे दिनांक 25 अगस्त 2010 से उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना संख्या 1452/ 30-4-10-172/89 के द्वारा बढ़ाकर ₹ 4000 कर दिया गया है, से दण्डनीय है।

4.8.2 अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2012 के मध्य 86 मामलों में कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर उपखनिज (बालू और साधारण मिट्टी) परिवहन के वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे। इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों द्वारा इन ट्रैक्टरों को निर्गत एम0एम0-11 प्रपत्रों से हुई थी। अभियोजन पंजिका से यह ज्ञात हुआ कि विभाग

ने वाणिज्यिक रूप में प्रयुक्त इन वाहनों से अन्तरीय कर के आरोपण एवं वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और न ही इन पर अधिनियम के उल्लंघन के लिए कोई आवश्यक दण्ड लगाया गया। इस प्रकार कार्यवाही न करने से कर और अर्थदण्ड के ₹ 4.31 लाख की वसूली नहीं हो पाई जैसा कि विवरण सारणी क्रमांक 4.9 में दिया गया है-

सारणी क्रमांक 4.9

(₹ लाख में)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहन का लदान रहित भार (टन में)	वाहन संचालन की अवधि	वाहनों की संख्या	देय कर की धनराशि ₹ 500 प्रति त्रैमास प्रति टन लदान रहित भार का	देय शास्ति ₹ 4000 प्रति वाहन की दर से	कर और शास्ति की कुल धनराशि
1.	स0प0का0 कानपुर नगर	02	04/2011 से	07	0.07	0.28	0.35
		03	07/2012	02	0.03	0.08	0.11
2.	स0स0प0अ0 महाराजगंज	02	03/2011 से 06/2011	37	0.37	1.48	1.85
3.	स0स0प0अ0 मऊ	02	08/2009 से 09/2010	40	0.40	1.60	2.00
योग				86	0.87	3.44	4.31

हमारे द्वारा मामले को विभाग एवं शासन को (जुलाई 2012 से फरवरी 2013) प्रतिवेदित करने पर विभाग हमारे प्रेक्षण से सहमत नहीं हुआ और कहा (नवम्बर 2013) कि प्रवर्तन

¹⁵ गाजियाबाद में चार उत्खनक वाहन।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ये वाहन संबंधित अवधि जिसमें वाहन बिना स्वस्थता प्रमाणपत्र के संचालित थे, कर जमा कर रहे थे। इस प्रकार हमारे द्वारा इंगित तथ्य अनुत्तरित रहा कि कर अदायगी के समय स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना विभाग ने सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा विभाग ने ₹ 19.05 लाख स्वस्थता शुल्क एवं ₹ 14.16 लाख शास्ति²³ वसूल किया और शेष प्रकरणों के हमारे द्वारा इंगित करने के बाद स्वस्थता शुल्क की वसूली हेतु वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किया। विभाग का उत्तर उसके द्वारा संलग्न की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है जहाँ विभाग ने स्वस्थता फीस के रूप में ₹ 19.05 लाख और शास्ति के रूप में ₹ 14.16 लाख वसूल किया और शेष प्रकरणों में स्वस्थता फीस की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया।

4.11 स्कूल वाहनों पर परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में वर्ष 2000 में यथासंशोधित उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु बिना समुचित परमिट के वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (31 दिसम्बर 2010 को यथा संशोधित) का नियम-125 नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु ₹ 3,750 प्रावधानित करता है।

हमने एक स0प0का0²⁴ और चार स0स0प0का0²⁵ के अभिलेखों²⁶ की जाँच की (मई 2012 और जून 2012 के मध्य) और पाया कि मई 2011 से मई 2012 की अवधि में 255 स्कूल वाहन परिक्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित हो रहे थे। इसके फलस्वरूप ₹ 9.56 लाख

की परमिट फीस की वसूली नहीं हुई जैसा कि सारणी क्रमांक 4.11 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.11

(₹ लाख में)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	प्रतिवाहन आरोपणीय परमिट फीस (₹)	सन्निहित राजस्व की धनराशि
1	स0स0प0का0 अम्बेडकरनगर	31	3750	1.16
2	स0प0का0 बरेली	29	3750	1.09
3	स0स0प0का0 जे0पी0नगर	30	3750	1.12
4	स0स0प0का0 महोबा	09	3750	0.34
5	स0स0प0का0 लखीमपुर खीरी	156	3750	5.85
	योग	255		9.56

हमारे द्वारा मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित करने पर (जून 2012 और जुलाई 2012), विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2013) और 119 वाहनों से ₹ 4.46 लाख वसूल किये और कहा कि शेष वाहनों के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

²³ स0स0प0का0 उन्नाव ₹ 1.44 लाख और स0प0का0 वाराणसी ₹ 12.72 लाख।

²⁴ स0प0का0 बरेली।

²⁵ स0स0प0का0 अम्बेडकरनगर, जे0पी0नगर, लखीमपुर खीरी और महोबा।

²⁶ वाहनों की पत्रावलियाँ, परमिट रजिस्टर और वाहनों का डाटाबेस।

4.12 दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होने का प्रभाव

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (2009 में यथा संशोधित) की धारा-8(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) कही जायेगी। धारा-4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा-6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों²⁷ से हमने देखा (मई 2012) कि अप्रैल 2011 और मार्च 2012 की अवधि के मध्य विभाग द्वारा माल और यात्री वाहनों से कर और अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 786.74 करोड़ वसूल किया गया। इस धनराशि का दो प्रतिशत ₹ 15.73

करोड़ उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 में जमा किया जाना था लेकिन विभाग द्वारा इसे निधि में जमा नहीं कराया गया क्योंकि निधि की स्थापना अभी होनी है। अग्रेतर, हमने देखा कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों की दुर्घटना में 1039 मामलों में यात्रियों या इन यात्रियों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 61.90 लाख का भुगतान बजट के मुख्य शीर्ष "2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" से किया गया। निधि की स्थापना न होने से अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य निष्प्रभावी रहा और क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य के राजस्व बजट से करना पड़ा।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2012)। उत्तर में विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति में है। वसूला गया कर और अतिरिक्त कर शासन के कोषागार में जमा किया जा चुका है अतः शासन राजस्व से वंचित नहीं था। मुख्य शीर्ष "2235" से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया अतः कोई भी लाभार्थी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं रहा। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विभाग कर एवं अतिरिक्त कर को, बजाय इसके दो प्रतिशत को उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 में जमा करने के, पूर्णतया मुख्य शीर्ष "0041" में जमा करके बढ़ी हुई राजस्व आय दिखा रहा है। साथ-साथ निधि की स्थापना न किये जाने से अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो गया।

²⁷ राजस्व प्राप्तियों का मासिक ब्यौरा।

43 १०५०क० बरती ।
 44 १०१५०क० औरेया, बिजौर, फरखाराद, कर्नाल, कुशीनार, महीबा, मयुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर और सीमर ।
 45 समर्पण रजिस्टर बहिन परावर्तिया, यात्री कर रजिस्टर और माल कर रजिस्टर ।
 46 करधान अधिकारी: ३०५०मी०या०क० अतिरिक्त, १९९८ के अन्तर्गत क्रमशः अपनी क्षेत्र या उपक्षेत्र की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत १०५०क० या १०१५०क० को करधान अधिकारी परेगर्भित किया गया है ।

प्रारम्भ नहीं की। जिसके फलस्वरूप ₹ 87.55 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी।

एक १०५०क० और ४३ १०५०क० १०१५०क० ४४ १०१५०क० के ४५ आभिलेखा की जाँच की (अर्बल २०१२ और नवम्बर २०१२ के मध्य) और देखा कि १७९ बहिन मई २०११ से अक्टूबर २०१२ की अवधि के दौरान तीन कैलेंडर माह से अधिक अवधि से सम्पत्ति थी। इस तथ्य के बावजूद भी कि तीन माह से अधिक सम्पत्ति के विषय में सम्बन्धित १०५०क० द्वारा विस्तार स्वीकार नहीं किया गया था, करधान अधिकारियों^{४६} ने देय कर/अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

उपरोक्तियों में व्यवस्था है कि जब परिवहन बहिन स्वाधी को अपने मोटर बहिन को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करना हो, तो करधान अधिकारी को मोटर बहिन के परीक्षण प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वरूपा प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अर्पित करेंगे। करधान अधिकारी एक कैलेंडर वर्ष में, तीन कैलेंडर माह से अधिक, किसी बहिन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेंगे। तथापि, यदि स्वाधी निर्धारित शून्य के साथ करधान अधिकारी को आवेदन करला है तो सम्बन्धित सम्पत्ति पर परिवहन अधिकारी तीन कैलेंडर माह से अधिक की अवधि हेतु अर्पण स्वीकार कर सकेंगे। यदि फिर भी ऐसा कोई बहिन १०५०३१० द्वारा सम्पत्ति की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेंडर माह से अधिक अवधि के लिए अर्पित बना रहता है, तो अर्पण रद्द माना जायेगा और बहिन स्वाधी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का दायी होगा। पुनश्च, उपनियम (४) में प्राधानों के अधीन सम्पत्ति बहिन का स्वाधी, जिसके बहिन का सम्पत्ति पूर्व में स्वीकार किया गया है, किसी भी कैलेंडर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। यह करधान अधिकारी से सम्पत्ति प्रमाण पत्र वापस किये गये हो अथवा नहीं।

4.17 तीन माह से अधिक सम्पत्ति बहिनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया है

इस अध्याय में हम विकासकर्ता अनुबन्ध के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के कम आरोपण पर एक अलग प्रस्तर और 2012-13 के दौरान स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाये गये चुने हुए परीक्षणों से ₹ 6.14 करोड़ के कुछ अन्य विस्तृत प्रकरणों को प्रस्तुत करते हैं।

प्राप्तियों का रूझान

वर्ष 2012-13 के दौरान स्टाम्प और पंजीयन से कुल संग्रह ₹ 8,742.17 करोड़ था। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण

आन्तरिक लेखा परीक्षा मार्च 2009 में रोक दी थी और जुलाई 2008 की शासकीय अधिसूचना द्वारा विभाग में तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ के नाम से एक नया सेट अप स्थापित किया गया जो आन्तरिक लेखा परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर पदस्थ सहायक महानिरीक्षक अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति 2012-13

हमने वर्ष 2012-13 के दौरान निबन्धन विभाग से सम्बन्धित 352 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच किया और दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण/सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन एवं अन्य अनियमितताओं के 1302 प्रकरणों में ₹ 211.37 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस की कमी पायी गयी। विभाग ने 15 प्रकरणों में ₹ 5.90 लाख के कम निर्धारण को स्वीकार किया।

हमारे निष्कर्ष

विभाग में तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने सहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार की जरूरत है ताकि प्रणाली की कमजोरियों को व्यवस्थित किया जाये और हमारे द्वारा चिन्हित की गयी चूकों से भविष्य में बचाव हो।

हमारे द्वारा इंगित प्रेक्षणों में निहित धनराशि, विशेषतः उन मामलों में जिनमें हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया गया है, की वसूली के लिये त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय-V स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 कर प्रशासन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा0स्टा0 अधिनियम) 1899, भारतीय निबन्धन अधिनियम (भा0नि0 अधिनियम) 1908, उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (स्टा0स0मू0) नियमावली, 1997 तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं परिपत्रों के अन्तर्गत राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियाँ विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टाम्प शुल्क का अपवंचन, सामान्यतः सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन, विलेखों को निबन्धन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत न किए जाने तथा निष्पादनकर्ताओं द्वारा निबन्धन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के कम/न भुगतान किए जाने के कारण होता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण और अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0) विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं तथा विभाग के कार्यान्वयन पर समग्र अधीक्षण तथा नियंत्रण का संचालन करते हैं। उनकी सहायता एक अपर महानिरीक्षक (अ0म0नि0), मण्डल स्तर पर 24 उप महानिरीक्षक (उ0म0नि0), जिला स्तर पर 96 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) तथा जिला एवं तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धक (उ0नि0) करते हैं।

5.2 प्राप्तियों का रुझान

5.2.1 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के प्रावधान के अनुसार बजट बनाने में बजट का उद्देश्य वास्तविक प्राप्तियों एवं अनुमानित प्राप्तियों में यथासम्भव निकटता होनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि बजट अनुमान में न केवल राजस्व एवं प्राप्तियों की सभी मदें होनी चाहिए बल्कि पिछले वर्षों के संग्रह हेतु यदि कोई बकाया हो तो उसको भी सम्मिलित करना चाहिए।

मुख्य लेखा शीर्ष 0030-स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस-गैर न्यायिक स्टाम्प से प्राप्ति के अन्तर्गत निर्धारित राजस्व संग्रह का लक्ष्य एवं वास्तविक प्राप्ति का विवरण सारणी क्रमांक 5.1 में दिया गया है:-

सारणी क्रमांक 5.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर (+/-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की प्राप्तियों का कुल कर	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	4,600	4,138.27	(-) 461.73	(-) 10.04	28,658.97	14.44
2009-10	4,800	4,562.23	(-) 237.77	(-) 4.95	33,877.60	13.47
2010-11	5,000	5,974.66	(+) 974.66	(+) 19.49	41,355.00	14.45
2011-12	6,612	7,694.40	(+) 1,082.40	(+) 16.37	52,613.43	14.62
2012-13	9,308	8,742.17	(-) 565.83	(-) 6.08	58,098.36	15.05

स्रोत: विभिन्न वर्षों के वित्तीय लेखें एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा गया कि बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच का अन्तर क्रमशः (-) 10.04 और 19.49 प्रतिशत रहा।

विभाग ने बताया कि ऐसी गिरावट एवं वृद्धि की निगरानी के लिए कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं है।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुमान तैयार करे एवं अन्तर के कारणों की जाँच करे।

5.2.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को ₹ 586.67 करोड़ राजस्व का बकाया था। पाँच वर्ष से अधिक पुराने बकाये का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि का राजस्व बकाया की स्थिति का विवरण सारणी क्रमांक 5.2 में दिया गया है:-

सारणी क्रमांक 5.2

वर्ष	बकाया राशि का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान बकाये की अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहित धनराशि	बकाया राशि का अन्तिम अवशेष
2008-09	213.24	448.88	109.07	553.05
2009-10	553.05	171.65	129.87	594.83
2010-11	594.83	(-) 3.03	132.16	459.64
2011-12	459.64	(-) 2.33	125.87	331.44
2012-13	331.44	417.80	162.57	586.67

(₹ करोड़ में)

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हमने पाया कि बकाया ₹ 586.67 करोड़ में से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ₹ 382.75 करोड़ स्थगित किया गया था तथा ₹ 63.21 करोड़ कम किया गया था एवं शेष धनराशि ₹ 140.71 करोड़ विभाग द्वारा वसूल किया जाना अपेक्षित था। हालांकि इन बकायों के प्रकरणों की कुल संख्याओं का विवरण विभाग उपलब्ध कराने में विफल रहा।

हम अनुशंसा करते हैं कि वसूली के स्पष्ट मामलों, जो स्थगन आदेश के दायरे में न हों में विभाग बकाया राशि के शीघ्र वसूली के लिए उचित कदम उठाने का विचार करें।

5.2.3 संग्रह की लागत

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण सारणी क्रमांक 5.3 में दिया गया है।

सारणी क्रमांक 5.3

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2010-11	5,974.66	145.46	2.43	2.47
	2011-12	7,694.40	149.10	1.94	1.60
	2012-13	8742.17	232.33	2.66	1.89

(₹ करोड़ में)

स्रोत: विभिन्न वर्षों के वित्तीय लेखें एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से देख सकते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन शुल्क की संग्रह की लागत वर्ष 2010-11 में अखिल भारतीय औसत से कम है जबकि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में यह अधिक थी।

शासन को संग्रह की लागत नीचे लाने के लिये उचित कदम उठाने की जरूरत है।

5.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा/आन्तरिक नियन्त्रण

आन्तरिक लेखा परीक्षा (आ0ले0प0) नियंत्रण तन्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है एवं सामान्य रूप से सभी नियंत्रण पर निगरानी रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे यह अभिनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्रणाली अच्छी तरह से कार्य कर रही है।

हमने देखा कि आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य मार्च 2009 से समाप्त कर दिया गया था एवं जुलाई 2008 की सरकारी अधिसूचना द्वारा एक नयी संरचना तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित की गयी जो आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर कार्यरत सहायक महानिरीक्षक निबन्धन अपने अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं। प्रकोष्ठ में स्वीकृत पद, लेखा परीक्षा योजना का विवरण जैसे योजित लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या एवं उठायी गयी और निस्तारित की गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि की सूचना विभाग द्वारा इस वर्ष नहीं दी गयी थी।

5.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.4.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा स्टाम्प शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं के जिसमें ₹ 517.61 करोड़ का राजस्व निहित था, प्रतिवेदित किये। विभाग ने इनमें से ₹ 57.71 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें से ₹ 2.31 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। स्वीकृत किये गये एवं वसूली किये गये प्रकरणों का विवरण सारणी क्रमांक 5.4 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 5.4

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	स्वीकृत मामलों में वसूली का प्रतिशत
2007-08	87.09	50.53	-	-
2008-09	4.05	-	-	-
2009-10	0.69	0.44	0.02	4.55
2010-11	10.36	6.70	2.25	33.58
2011-12	415.42	0.04	0.04	100.00
योग	517.61	57.71	2.31	4.00

सिवाय वर्ष 2011-12 के विगत पांच वर्षों में वसूली का प्रतिशत या तो शून्य रहा अथवा अत्यन्त कम रहा।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकार्य मामलों में शासन को वसूली की स्थिति सुधारने हेतु उचित कदम उठाने चाहिये।

5.4.2 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा स्टाम्प शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमितता के जिसमें ₹ 5.91 करोड़ का राजस्व निहित था, को प्रतिवेदित किया। विभाग/शासन ने दिसम्बर 2012 तक इनमें

से ₹ 53.72 लाख की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें से ₹ 46.12 लाख की वसूली की जा चुकी है। विवरण सारणी क्रमांक 5.5 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 5.5

(₹ लाख में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	आपत्तिगत धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2007-08	93.30	निरंक	निरंक
2008-09	10.74	7.73	0.13
2009-10	14.96	3.56	3.56
2010-11	11.73	37.79	37.79
2011-12	460.01	4.64	4.64
योग	590.74	53.72	46.12

यह देखा जा सकता है कि शासन/विभाग ने वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के निरीक्षण प्रतिवेदनों के स्वीकार्य मामलों के सापेक्ष पूरी वसूली की जबकि वर्ष 2008-09 के निरीक्षण प्रतिवेदन में स्वीकृत धनराशि ₹ 7.73 लाख के सापेक्ष केवल ₹ 13000 की वसूली की जा सकी।

5.4.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के 352 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण, /अवनिर्धारण से स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं में निहित ₹ 211.37 करोड़ के 1,302 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा सारणी क्रमांक 5.6 में दिया है:

सारणी क्रमांक 5.6

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विकासकर्ता अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क का आरोपण	1	2.32
2.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	303	8.95
3.	सम्पत्तियों के अवमूल्याकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	275	6.05
4.	अन्य अनियमितताएं	723	194.05
	योग	1302	211.37

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 15 मामलों¹ में ₹ 5.90 लाख स्वीकार्य किये, जो विगत वर्षों में लेखा परीक्षा द्वारा लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण/अवनिर्धारण से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं से संबन्धित थे।

¹ वर्ष 1997-98, 2004-05, 2007-08 और 2008-09 से सम्बन्धित एक प्रकरण, 2009-10 और 2010-11 के दो प्रकरण एवं 2011-12 के सात प्रकरण।

हमने अक्टूबर 2012 और मई 2013 के मध्य प्रकरण विभाग एवं शासन की प्रतिवेदित किया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि सम्बन्धित नगर पंचायतों से अधिसूचना के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद दो प्रतिशत आतिरिक्त स्टाफ शूल्क आरोपित करना शुरू कर दिया था। हम सहमत नहीं हुए क्योंकि आतिरिक्त स्टाफ शूल्क अधिसूचना की लिखित से आरोपणीय था। अगले उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2013)।

सम्पत्तियों के अन्तर्गत विवेक्षा पर दो प्रतिशत की दर से आतिरिक्त स्टाफ शूल्क का आरोपण नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 11.87 लाख के आतिरिक्त स्टाफ शूल्क का

हमने तीन उप निबन्धकों के अभिलेखा (अगस्त 2011 से मार्च 2013 के मध्य) की जांच की और पाया कि दिसम्बर 2008 और जनवरी 2013 के मध्य नगर पंचायत क्षेत्रों जैसे नगर पंचायत रसूलगाबाद (उन्नाव), नगर पंचायत सहजनवा (मिर्जापुर), पशुपति गाँव (मिर्जापुर) में स्थित ₹ 5.94 करोड़ मूल्य की अवल

समय समय पर संशोधित 30 प्रो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128-अ के प्राधान्यों के अन्तर्गत किसी नगर पालिका/नगर पंचायत जिसे शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है, की सीमा के अन्दर अवल सम्पत्ति के अन्तर्गत पर दो प्रतिशत आतिरिक्त स्टाफ शूल्क आरोपणीय होगा। शासन ने सितम्बर 2008, दिसम्बर 2010 और अप्रैल 2011 में क्रमशः नगर पंचायत रसूलगाबाद (उन्नाव), नगर पंचायत सहजनवा (मिर्जापुर), पशुपति गाँव (मिर्जापुर) को नगरीय क्षेत्र घोषित किया था।

5.5 विकसित क्षेत्रों में आतिरिक्त स्टाफ शूल्क का अनारोपण

176 उप निबन्धकों के कार्यालयों एवं महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय (बर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा में प्राप्त मामलों सहित जो पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में विहित नहीं किये गये) की लेखापरीक्षा में निहित ₹ 6.14 करोड़ के महत्वपूर्ण प्रकरणों का वर्णन अनुवर्ती प्रस्तारों में वर्णित है।

5.6 स्टाप्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाप्प अधिनियम 1899 की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 23 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तांतरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाप्प शुल्क प्रभावी है। उत्तर प्रदेश स्टाप्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन ने जून 2003 में जारी दिशा निर्देशों द्वारा स्पष्ट किया कि स्टाप्प शुल्क के आरोपण के लिये एक ही प्लॉट (गाटा) की एक सम्पत्ति को विभिन्न उद्देश्यों के लिये एक से अधिक टुकड़ों में नहीं करना चाहिये अर्थात् एक कृषि और दूसरा गैर कृषिक के लिये। उसी दिशा निर्देश में इसका भी उल्लेख था कि यदि सम्पत्ति के चारों तरफ आवासीय सम्पत्ति हो तो उसका मूल्यांकन आवासीय सम्पत्ति की तरह किया जाना चाहिये।

5.6.1 मई 2011 और फरवरी 2013 के मध्य 39 उप निबन्धकों³ के अभिलेखों⁴ की जांच में हमने पाया कि मार्च 2010 और नवम्बर 2012 के मध्य गैर कृषिक भूमि के 64 हस्तान्तरण विलेख कृषि दर से ₹ 9.95 करोड़ के मूल्यांकन से पंजीकृत कराये गये और ₹ 65.20 लाख स्टाप्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का आरोपण किया गया। हमने पाया कि निम्नलिखित कारणों से मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिये था:

- उसी प्लॉट का हिस्सा पूर्व में आवासीय दर से बेचा गया था (54 विलेख)।
- उसी प्लॉट का हिस्सा उसी दिन आवासीय दर से बेचा गया था (3 विलेख)।
- प्लॉट के चारों तरफ आवासीय प्लॉटों के मालिक थे। (7 विलेख)

प्लॉट कृषि दर से मूल्यांकित पाये गये जैसा ऊपर विवरण दिया गया है, उनका सही मूल्यांकन आवासीय दर से ₹ 50.82 करोड़ आंकलित किया गया। इस पर स्टाप्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 3.08 करोड़ आरोपणीय था जबकि केवल ₹ 65.20 लाख स्टाप्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का आरोपण किया गया था। सम्पत्ति का सही मूल्यांकन न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.43 करोड़ कम स्टाप्प शुल्क आरोपित किया गया।

हमने मई 2011 और अप्रैल 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने उत्तर में हमारी आपत्तियों को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया और प्रकरणों को सम्पत्ति के सही मूल्यांकन हेतु कलेक्टर स्टाप्प को सन्दर्भित कर दिया।

³ उ.नि. अतरौली अलीगढ़, उ.नि. खैर अलीगढ़, उ.नि. तृतीय अलीगढ़, उ.नि. करछना इलाहाबाद, उ.नि. सोरांव इलाहाबाद, उ.नि. आजमगढ़, उ.नि. बलरामपुर, उ.नि. तुलसीपुर बलरामपुर, उ.नि. उत्तरीला बलरामपुर, उ.नि. सदर बाराबंकी, उ.नि. आवला बरेली, उ.नि. इटावा, उ.नि. सोहावल फैजाबाद, उ.नि. दादरी जी बी नगर, उ.नि. ग्रेटर नोएडा जी बी नगर, उ.नि. जेवर जी बी नगर, उ.नि. कर्नैलगंज गोण्डा, उ.नि. सवायजपुर हरदोई, उ.नि. मौढवा हमीरपुर, उ.नि. सदर हमीरपुर, उ.नि. छिबरामऊ कन्नौज, उ.नि. तिवर्वा कन्नौज, उ.नि. प्रथम कानपुर नगर, उ.नि. तृतीय कानपुर नगर, उ.नि. चायल कौशाम्बी, उ.नि. सिराथू कौशाम्बी, उ.नि. प्रथम लखनऊ, उ.नि. चतुर्थ लखनऊ, उ.नि. मांट मथुरा, उ.नि. प्रथम मेरठ, उ.नि. तृतीय मेरठ, उ.नि. कांठ मुरादाबाद, उ.नि. तृतीय नोएडा, उ.नि. सदर पीलीभीत, उ.नि. सदर रामपुर, उ.नि. सदर सीतापुर, उ.नि. सिधौली सीतापुर, उ.नि. प्रथम वाराणसी और उ.नि. गंगापुर वाराणसी।

⁴ बही 1, खण्ड और पंजीकृत दस्तावेज।

कलेक्टर स्टाम्प ने पांच मामलों में ₹ 5.63 लाख स्टाम्प शुल्क की कमी को निश्चित किया। शेष मामलों में कार्यवाही बाकी है (दिसम्बर 2013)।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अनुसार एक जिले का कलेक्टर विहित प्रक्रिया के अनुश्रवण के बाद स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य के लिये विभिन्न श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति (कृषि, आवासीय, व्यावसायिक इत्यादि) का न्यूनतम बाजार मूल्य (क्षेत्रवार दरे) क्षेत्रवार एवं श्रेणीवार निर्धारित करता है।

5.6.2 मार्च 2012 से मार्च 2013 के मध्य चार उप निबन्धकों के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि कृषि/आवासीय दर से मूल्यांकित ₹ 1.31 करोड़ के गैर कृषिक भूमि के अन्तरण सम्बन्धी आठ विलेख फरवरी 2011 और जनवरी 2013 के

मध्य पंजीकृत थे और अनुमोदित क्षेत्रवार दरों के अनुसार ₹ 6.52 करोड़ के बाजार मूल्य की इन सम्पत्तियों पर आरोपणीय ₹ 40.50 लाख के स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस के सापेक्ष, ₹ 8.13 लाख स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस आरोपित था।

- पंजीकरण के समय छः प्लॉट लागू सक्रिल दरों पर आवासीय घोषित थे (क्रमांक 1, 2 और 3 पर छः विलेख)।
- दो प्लॉट सड़क पर स्थित थे और पंजीकरण के समय लागू क्षेत्रवार दरों के सामान्य निर्देशों के अनुसार दिये गये विशेष दर (वाणिज्यिक दर) पर मूल्यांकित किये जाने थे (क्रमांक 4 पर दो विलेख)।

सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 32.37 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ जैसा सारणी क्रमांक 5.7 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.7

(₹ लाख में)									
क्रम संख्या	इकाई का नाम	लेखपत्र संख्या/पंजीयन तिथि	खसरा संख्या/क्षेत्रवार दर लागू होने की तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)/मूल्यांकन (लेखपत्र के अनुसार)	लागू बाजार मूल्य (सूची के अनुसार)	आवासीय/व्यावसायिक दर पर आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	कम आरोपण	
1.	उ. नि. सहस्रवान बदायूं	745/16.03.2012	102/31.07.2010	1680/6.96	75.60	5.59	0.58	5.01	
		4716/17.12.2011	13/31.07.2010	1540/1.85	46.20	2.31	0.10	2.21	
		4717/17.12.2011	13/31.07.2010	1050/1.26	31.50	1.58	0.06	1.52	
		3067/12.08.2011	70/31.07.2010	1612.5/2.98	65.50	3.33	0.21	3.12	
2.	उ. नि. हाथरस महामायानगर	2370/30.04.2012	236/24.10.2011	6160/64.68	147.84	7.49	3.23	4.26	
3.	उ. नि. प्रथम मथुरा	2340/13.2.2012	125/01.09.2011	3790/37.93	170.55	12.04	2.76	9.28	
4.	उ. नि. सदर मऊ	564/04.02.2012	321/01.06.2011	700/10.50	70.00	5.00	0.83	4.17	
		2948/05.07.12	354/01.06.2011	753.3/4.52	45.20	3.16	0.36	2.80	
योग				17285.8/130.68	652.39	40.50	8.13	32.37	

हमने अक्टूबर 2012 और मई 2013 के मध्य प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने सूचित (सितम्बर 2013) किया कि उप निबन्धक मऊ के प्रकरण में ₹ 49000 की वसूली की जा चुकी है और अन्य शेष प्रकरण सम्पत्ति के सही मूल्यांकन के लिये कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किये जा चुके हैं। उसके आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

⁵ उ.नि. अतरौली अलीगढ़, उ.नि. चतुर्थ लखनऊ, उ.नि. करनैलगंज गोण्डा, उ.नि. बलरामपुर, उ.नि. सदर आजमगढ़।

⁶ उ.नि. सहस्रवान बदायूं, उ.नि. हाथरस महामायानगर, उ.नि. प्रथम मथुरा और उ.नि. सदर मऊ

⁷ बही 1, खण्ड और पंजीकृत दस्तावेज

5.7 तथ्यों को छिपाने से सम्पत्ति का अवमूल्यांकन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दस्तावेज में तथ्य एवं परिस्थितियाँ, जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता या उस प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, को पूर्णतया एवं सत्यता पूर्वक व्यक्त किये जायें। अधिनियम की धारा 47-अ (3) के अन्तर्गत लेखपत्र यदि यथास्टाम्पित नहीं पाया गया तो कलेक्टर स्टाम्प को परीक्षण एवं सही मूल्यांकन हेतु सन्दर्भित किया जा सकता है।

फरवरी 2013 में एक उप निबन्धक के कार्यालय के अभिलेखों⁸ की जाँच में हमने पाया कि 23 दिसम्बर 2012 को एक विक्रय विलेख को निष्पादनकर्ता द्वारा दर्शायी गयी चौहद्दी के आधार पर घोषित कृषि भूमि⁹ क्षेत्रफल 4090 वर्ग मीटर क्रय/विक्रय के लिये निष्पादित किया गया।

इसके पश्चात् 27 दिसम्बर 2012 को सम्पत्ति¹⁰ का एक पट्टा विलेख, जिसमें वह सम्पत्ति (गाटा क्रमांक 345) शामिल थी जिसका विक्रय विलेख 23 दिसम्बर 2012 को निष्पादित किया गया था, में इसका उल्लेख था कि विचाराधीन सम्पत्ति में भूतल एवं प्रथम तल में छः कमरे निर्मित थे। इन तथ्यों के आधार पर सम्पत्ति जिसका पंजीयन 23 दिसम्बर 2012 को किया गया था, को आवासीय एवं गैर कृषिक में वर्गीकृत किया जाना था।

तथ्यों को छिपाने के कारण निर्धारित आवासीय दर¹¹ की जगह विक्रय विलेख पर कृषि दर¹² से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया। इसके अनुसार ₹ 7.77 लाख स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाना था जबकि केवल ₹ 45000 स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था। तथ्यों को छिपाने के कारण भूमि के अवमूल्यांकन एवं कलेक्टर को संदर्भित न होने के परिणामस्वरूप ₹ 7.32 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

हमने जून 2012 और मई 2013 के मध्य प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित (सितम्बर 2013) कर दिया। उसके आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

⁸ बही 1, खण्ड, विक्रय विलेख दिनांक 23.12.2012 और पट्टा विलेख दिनांक 27.12.2012

⁹ गाटा संख्या 345

¹⁰ गाटा संख्या 345, 346 और 347

¹¹ ₹ 3800 प्रति वर्ग मीटर

¹² ₹ 2200 प्रति एअर (100 वर्ग मीटर=1 एअर)

5.8 भूमि प्रयोग के अनियमित परिवर्तन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 प्रावधानित करता है कि जहाँ हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर* अपनी खेती या उसके भाग का असम्बद्ध प्रयोजन कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा करता है तो परगने का प्रभारी स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो नियत की जाय, उस आशय की घोषणा कर सकता है।

उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 144 प्रावधानित करता है कि यदि किसी भूमि का मालिक उक्त भूमि को गैर-कृषिक के रूप में नहीं उपयोग करना चाहता है, प्रार्थना पत्र पर या स्वप्रेरणा से सम्बन्धित एसडीएम भूमि की प्रकृति को गैर-कृषिक से कृषिक में परिवर्तित कर सकता है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-अ (3) प्रावधानित करता है कि कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी न्यायालय या स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के अभिदेश पर लेखपत्र, सम्पत्ति के बाजार मूल्य की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष के भीतर मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और यदि ऐसे परीक्षण के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि लेखपत्र में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य और उस पर देय शुल्क अवधारित कर सकता है।

*व्यक्ति जिसके पास हस्तान्तरणीय अधिकारों के साथ मुक्त भूमि हो।

सितम्बर 2012 में उप निबन्धक सदर पीलीभीत के अभिलेखों¹³ की जांच में हमने पाया कि गैर-कृषिक भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण के दो विलेख कृषि दर से ₹ 32.80 लाख के लिये अप्रैल 2012 में पंजीकृत किये गये थे और ₹ 2.30 लाख स्टाम्प शुल्क आरोपित था। हमने पाया कि उक्त प्लॉट एसडीएम¹⁴ द्वारा पूर्व में (सितम्बर 2011) गैर-कृषिक घोषित¹⁵ किया गया था और तत्पश्चात छः महीने बाद (मार्च 2012) पुनः गैर-कृषिक से कृषिक घोषित¹⁶ किया गया, दोनों बार भूमि मालिक की प्रार्थना¹⁷ पर। हमने पाया कि उक्त भूमि गैर-कृषिक घोषित करते समय (15 सितम्बर 2011) तहसीलदार की सूचना में स्पष्ट उल्लेख था कि भूमि परती थी एवं आबादी के लिये प्रयोग की जा रही थी और छः महीने के अन्दर कृषिक घोषित करते समय (31 मार्च 2012)

तहसीलदार की सूचना में कहा गया कि परती और आवासीय भूमि अब कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जा रही है। इस तरह एक ही भूमि की प्रकृति को छः महीने में दो बार परिवर्तित किया गया था। छः माह के अन्दर परती का आबादी के लिये भूमि उपयोग¹⁸ से प्रत्यावर्तन और उसके बाद तहसीलदार की क्रमिक सूचनाओं¹⁹ में कृषि उद्देश्य के लिये प्रयोग दिखाये जाने का परीक्षण पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया जिन्होंने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित नहीं किया। इसके सापेक्ष ₹ 11.36 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया जैसा सारणी क्रमांक 5.8 में दिखाया गया है:

¹³ बही 1, खण्ड, पंजीकृत विलेख, उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 और 144 के अन्तर्गत आदेश

¹⁴ दिनांक 15 सितम्बर 2011 और 31 मार्च 2013 को एक ही अधिकारी एसडीएम के पद पर था।

¹⁵ दिनांक 15 सितम्बर 2011 को उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आदेश संख्या 133/10-11 द्वारा

¹⁶ दिनांक 31 मार्च 2012 को उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश संख्या 03/11-12 द्वारा

¹⁷ मालिक ने पहले सितम्बर 2011 में भूमि उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के लिये अनुरोध किया चूँकि प्लॉट का आवासीय उपयोग किया जा रहा था और मार्च 2012 में पुनः प्लॉट को कृषि में परिवर्तित करने का अनुरोध किया।

¹⁸ उसी एसडीएम द्वारा

¹⁹ तहसीलदार की सूचनाएं क्रमशः दिनांक 15 सितम्बर 2011 और 31 मार्च 2012

सारणी क्रमांक 5.8

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	गाटा संख्या / रकबा (वर्ग मीटर)	लेखपत्र संख्या / पंजीयन तिथि	धारा 143/144 के अन्तर्गत आदेश की तिथि	मूल्यांकन (लेखपत्र के अनुसार)	लागू बाजार मूल्य (सूची के अनुसार)	आवासीय / व्यावसायिक दर पर आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	कम आरोपण
1.	उ. नि. पीलीभीत	560/6110	3273/23.04.2012	15.9.2011/ 31.3.2011	20.54 ²⁰	122.20 ²¹	8.56	1.44	7.12
		558/3645	3274/23.04.2012	15.9.2011/ 31.3.2011	12.26	72.90	5.10	0.86	4.24
योग					32.80	195.10	13.66	2.30	11.36

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2012 में प्रतिवेदित किया। विभाग हमारे परीक्षण से सहमत नहीं हुआ (सितम्बर 2013) और बताया कि हाल ही में किये गये जांच में कोई कमी नहीं पायी गयी थी। हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विभाग ने उन कारकों, जिन्होंने भूमि जो परती एवं आबादी हेतु प्रयोग में लायी जा रही थी, को छः माह में कृषि हेतु प्रयोग में परिवर्तित करने के लिये एसडीएम को प्रवृत्त किया, के परीक्षण हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 (3) के अन्तर्गत प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित नहीं किया। चूंकि एसडीएम दोनो अवसरों पर एक ही अधिकारी था, भूमि की प्रकृति में कृषि से परती एवं आबादी में परिवर्तन के कारणों का कलेक्टर स्टाम्प²² (जिलाधिकारी), जो एसडीएम का नियन्त्रक अधिकारी है, द्वारा अच्छी तरह से परीक्षण किया जा सकता था।

5.9 भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत किये गये मूल्यांकन में अनियमिततायें

भा0 स्टा0 अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी अन्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा उसमें प्रदर्शित मूल्य, जो भी अधिक है आरोपणीय है। शासन ने आदेश द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन प्रकरण में जिलाधिकारी की अधिकारिता को स्पष्ट किया, सम्बन्धित उप निबन्धकों की सूचना को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिये और ऐसी सूचना के प्रकाश में निर्णय लिया जाना चाहिये।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा।

मार्च 2013 में उप-निबन्धक तृतीय एवं उप निबन्धक चतुर्थ आगरा कार्यालयों के अभिलेखों²³ की जांच में हमने पाया कि 12 मार्च 2012 और 27 अप्रैल 2012 के मध्य तीन अन्तरण विलेखों में निहित 44351.46 वर्ग मीटर भूमि का पंजीयन किया गया था। सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल की धनराशि ₹ 3.81 करोड़ पर किया गया था। पंजीयन से पूर्व धारा 31 के अन्तर्गत दस्तावेज न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत हुआ था और अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.) द्वारा जो

²⁰ ₹ 28,00,000 प्रति हेक्टेअर + विक्रीत क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत

²¹ ₹ 2,000 प्रति वर्ग मीटर विक्रीत क्षेत्रफल से गुणा करने पर

²² भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(6) के अन्तर्गत परिभाषित कलेक्टर (जिलाधिकारी)

²³ वही 1. खण्ड, विक्रय विलेख और भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत आदेश

कलेक्टर स्टाम्प नामित था, तहसीलदार सदर आगरा के निरीक्षण आख्या को ध्यान में रखते हुए सम्पत्ति का मूल्य ₹ 3.81 करोड़ निर्धारित किया गया था।

हमने पाया कि:

- इस तथ्य के बावजूद कि सम्पत्ति उप निबन्धक तृतीय एवं चतुर्थ आगरा के दायरे में आती है दिसम्बर 1999 के शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में उप निबन्धक तृतीय एवं चतुर्थ आगरा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं करी गयीं।
- क्षेत्रवार दर के अनुसार भूमि का वास्तविक मूल्य ₹ 8.66 करोड़ था जिसका निर्णय करते हुए अपर जिलाधिकारी (एडीएम) द्वारा ₹ 3.81 करोड़ निर्धारित किया गया।
- सभी तीन प्रकरणों में एक ही अधिकारी एडीएम (वि एवं रा) के पद पर था ने तहसीलदार आगरा की निरीक्षण आख्या के आधार पर सम्पत्ति का मूल्य कम कर दिया था। हमने पाया कि दिसम्बर 1999 के शासनादेश के उल्लंघन को विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी गयी एवं सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सीसीआरए/माननीय उच्च न्यायालय²⁴ के समक्ष अपील करने की पहल नहीं की। सीसीआरए/माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की पहल न करने के कारण ₹ 33.91 लाख के स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी जैसा सारणी क्रमांक 5.9 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.9

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	खण्ड/लेखपत्र संख्या	पंजीयन तिथि	बिक्रीत रकबा (वर्ग मीटर)	आरोपित दर (वर्ग मीटर)	आरोपित बाजार मूल्य ²⁵	आरोपित स्टाम्प	आरोपणीय दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	आरोपणीय बाजार मूल्य ²⁶	देय स्टाम्प	अन्तर
1	उ. नि. तृतीय आगरा	4410/2365	12-3-2012	32570	525	170.99	11.97	1050	341.99	23.94	11.97
		4415/2433	14-3-2012	6474.25	1600	103.69	7.25	4000	258.97	18.13	10.88
2	उ. नि. चतुर्थ आगरा	2305/2496	27-4-2012	5307.21	2000	106.15	7.51	5000	265.37	18.57	11.06
योग				44351.46		380.83	26.73		866.33	60.64	33.91

प्रकरण मई 2013 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जायेगी। इसके आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

²⁴ धारा 31 के प्रकरण सामान्यतया सीधे माननीय उच्च न्यायालय को सन्दर्भित किये जाते हैं

²⁵ बिक्रीत क्षेत्रफल को आरोपित दर से गुणा किया

²⁶ बिक्रीत क्षेत्रफल को आरोपित दर से गुणा किया

5.10 भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 में प्रावधान है कि जहाँ हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपनी खेती या उसके भाग का असम्बद्ध प्रयोजन कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा करता है तो परगने का प्रभारी स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो नियत की जाय, उस आशय की घोषणा कर सकता है। पुनश्च, मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 11 जून 2010 द्वारा, जो सभी आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित था, इस बात पर जोर दिया कि अगर भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सम्बन्धित एस0डी0एम0 को स्वतः प्रेरणा से उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अधीन सम्पूर्ण भूमि को आबादी के रूप में घोषणा की जानी चाहिए। यदि उपरोक्त अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत भूमि गैर-कृषिक घोषित की गयी थी तो स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिये।

अगस्त 2012 और मार्च 2013 के मध्य दो उप निबन्धकों²⁷ के अभिलेखों²⁸ की जांच में हमने पाया कि कृषि दर से मूल्यांकित करते हुए ₹ 61.75 लाख के प्रतिफल पर तीन विलेख अप्रैल 2012 और जनवरी 2013 के बीच पंजीकृत थे जिस पर ₹ 4.65 लाख के स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था। हमने पाया कि तीनों विलेखों के पंजीयन तिथि से पूर्व ही सम्बन्धित आराजी संख्याओं को उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर-कृषिक घोषित किया गया था। अतएव सम्पत्तियों का मूल्यांकन

आवासीय दर से ₹ 3.29 करोड़ किया जाना अपेक्षित था और स्टाम्प शुल्क ₹ 23.34 लाख आरोपणीय था। सम्बन्धित उप निबन्धकों ने दस्तावेजों के पंजीयन में इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.69 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ जैसा कि सारणी क्रमांक 5.10 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.10

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	लेखपत्र संख्या/पंजीयन तिथि	आराजी संख्या/ धारा 143 के अन्तर्गत आदेश की तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)/ मूल्यांकन (लेखपत्र के अनुसार)	लागू बाजार मूल्य (सूची के अनुसार) ²⁹	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	कम आरोपण
1.	उ. नि. द्वितीय फिरोजाबाद	563/24.01.2013	335म/26.11.2012	5760/21.34	230.40	16.23	1.60	14.63
		3532/04.07.2012	1350/10.05.2012	4610/9.11	46.10	3.32	0.74	2.58
2.	उ. नि. प्रथम मेरठ	4022/12.04.2012	134म और 137/20.03.2012	5180/31.30	52.76	3.79	2.31	1.48
		योग		15550/61.75	329.26	23.34	4.65	18.69

प्रकरण विभाग एवं शासन को मई 2013 में प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि सम्पत्ति के सही मूल्यांकन के लिये प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किये जा चुके हैं। उसके आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

²⁷ उ. नि. द्वितीय फिरोजाबाद और उ. नि. प्रथम मेरठ

²⁸ वही 1, खण्ड, विक्रय विलेख और क्षेत्रवार दर

²⁹ विक्रीत क्षेत्रफल को लागू आवासीय दर से गुणा किया

5.11 30 वर्षों से अधिक अवधि के निष्पादित पट्टे

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विलेख पर जहाँ कि लीज 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वत अवधि के लिये तात्पर्यित न हो स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल पर हस्तान्तरण की भाँति प्रभाय है।

तीन उ0नि0 कार्यालयों के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) में पाया गया कि 30 वर्ष से अधिक अवधि के पांच पट्टा विलेख मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 के

बीच पंजीकृत थे जिन पर औसत वार्षिक किराये के छः गुना प्रतिफल पर ₹ 6720 स्टाम्प शुल्क आरोपित था। चूँकि पट्टा विलेख 30 वर्ष से अधिक अवधि के थे, सम्पत्ति के बाजार मूल्य³⁰ के बराबर प्रतिफल के आधार पर ₹ 4.43 करोड़ मूल्यांकित करते हुए स्टाम्प शुल्क ₹ 22.66 लाख आरोपणीय था। 30 वर्ष से कम पट्टा अवधि की सही गणना न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 22.66 लाख स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 48000 निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया जैसा कि सारणी क्रमांक 5.11 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.11

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	खण्ड/लेखन संख्या एवं रकबा (वर्ग मीटर में)	पंजीयन का माह/ लीज अवधि	सम्पत्ति का मूल्य लागू होने योग्य/ लागू किया गया	आरोपणीय/आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस (₹ में)	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
1.	उ. नि. सहस्रवान बदायूँ	3459/2372 (743.49)	जुलाई 2012 से 01.07.2042 (30 वर्ष 1 दिन)	37.18/0.14	2,70,260/900	³¹ 2.69
		3398/1073 (353.16)	अप्रैल 2012 से 01.07.2012 से 01.07.2042 (30 वर्ष 1 दिन)	15.90/0.14	79,500/700	³¹ 0.79
		3398/1072 (297.4)	अप्रैल 2012 से 01.07.2012 से 01.07.2042 (30 वर्ष 1 दिन)	13.39/0.14	66,950/700	³¹ 0.66
2.	उ. नि. पूरनपुर पीलीभीत	2925/7490 (213.2)	अक्टूबर 2011 से 20.10.2011 से 19.10.2042 (31 वर्ष)	17.70/0.72	98,500/2,260	³¹ 0.97
3.	उ. नि. सिधौली सीतापुर	2225/2981 (7950)	अगस्त 2012 से अगस्त 2042 (30 वर्ष 1 माह)	359.08/0.72	18,05,400/2,160	18.03
योग				443.25/1.86	23,20,610/6,720	23.14

प्रकरण विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2012 और मार्च 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 2 और 3 सही मूल्यांकन के लिये कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किया जा चुका है। एक प्रकरण में उत्तर (सारणी की क्रम संख्या 1) एवं क्रम संख्या 2 और 3 के प्रकरणों में आगे की प्रगति नहीं प्राप्त हुई है (दिसम्बर 2013)।

³⁰ जैसे क्षेत्रवार दर में परिभाषित

³¹ विलेखों में निर्मित क्षेत्रफल दिया है इसके बावजूद इन प्रकरणों में गणना के लिये निर्मित क्षेत्रफल के लिये उच्च दर ₹11500, ₹10500 और ₹10500 के स्थान पर खुले क्षेत्रफल का दर क्रमशः ₹ 5000, ₹ 4500 और ₹ 4500 प्रति वर्ग मीटर लगाया गया है।

सारणी क्रमांक 5.12

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम / द्वारा अनुमोदित लेआउट योजना	सम्पत्ति का विवरण	मालिक का नाम	विकासकर्ता का नाम / विकासकर्ता नियुक्ति का तिथि	लगाया गया स्टाम्प	मूल्यांकन दर प्रति वर्ग मीटर	मूल्यांकन	देय स्टाम्प शुल्क / निबन्धन फीस	अन्तर स्टाम्प शुल्क / निबन्धन फीस	बुल अन्तर
1	उ० नि० प्रथम सहारनपुर / सहारनपुर विकास प्राधिकरण	ग्राम-मानकमऊ परगना व जिला सहारनपुर क्षेत्रफल-25000 वर्ग मीटर	श्रीमती मेधा-9730 वर्ग मीटर, श्रीमती नितिका-11500 वर्ग मीटर एवं श्रीमती पूजा आनन्द-3680 वर्ग मीटर	श्रीमती परवीन रानी / 01.04.2009	750	2500	625.00	43.65/0.10	43.64/0.10	43.74
2	उ० नि० प्रथम बरेली / बरेली विकास प्राधिकरण	शेरपुर, संजय नगर बाई पास रोड बरेली, खसरा संख्या 279, 280, 281, 282, 291, 293, 294, 295 क्षेत्रफल-22000 वर्ग मीटर	डा. वीरेन्द्र अग्रवाल एवं डा. जितेन्द्र अग्रवाल	क्वॉलिटी एंसीसिएट / 01.10.2011	0	3000	660.00	46.20/0.10	46.20/0.10	46.30
3	उ० नि० प्रथम बरेली / बरेली विकास प्राधिकरण	कारु नगला बरेली, खसरा संख्या 10 / अ. 12 क्षेत्रफल-1891.72 वर्ग मीटर	श्री राजेश गुप्ता, बमैन्द गुप्ता, शिवम एसोसिएट्स	मे. संजय मेड डायनोस्टिक प्रा. लि. / 06.02.2013	100	4000	75.67	5.29/0.10	5.29/0.10	5.39
4	उ० नि० द्वितीय बरेली / बरेली विकास प्राधिकरण	रीवपुर हाकिमस तहसील सदर बरेली खसरा संख्या 241, 242, 311, 312, 315 क्षेत्रफल-6960.61 वर्ग मीटर	श्री पूरतन, श्री यासीन मिया एवं शिव कुमार शर्मा	मे. हिमालयन हाउसिंग प्रा. लि. / 03.10.2011	0	4000	278.42	19.49/0.10	19.49/0.10	19.59
5	उ० नि० चन्दौली / नगर पालिका समूह	ग्राम-देवरखोड़ा तहसील चन्दौली, समूह खसरा संख्या 796 से 800, 806 क्षेत्रफल-2187 वर्ग मीटर	बाला जी एसोसिएट्स	मे. विनयक फार्मर्स / 03.05.2012	0	3500	76.55	5.36/ 0.10	5.36/ 0.10	5.46
6	उ० नि० चतुर्थ वाराणसी / वाराणसी विकास प्राधिकरण	ग्राम-जोद्ला वार्ड नगाबाकूआ परगना देहात अमानत तहसील सदर वाराणसी खसरा संख्या 36 / 1, 36 / 2 क्षेत्रफल-1510 वर्ग मीटर	श्रीमती कमला त्रिपाठी पत्नी श्री हरे राम त्रिपाठी एवं मृदुंजय त्रिपाठी पुत्र श्री हरे राम त्रिपाठी	विद्या देवी पत्नी विन्ध्यवासिनी मिश्रा / 04.06.2009	0	4800	72.48	5.07/0.10	5.07/0.10	5.17
7	उ० नि० तृतीय वाराणसी / वाराणसी विकास प्राधिकरण	प्लाट संख्या बुजनेवर नगर कालोनी क्षेत्रफल-25000 वर्ग मीटर	दुष्यन्त सिंह	दिग्विजय सिंह उत्तमनगर वाराणसी / 18.03.2013	0	14280	42.40	2.97/0.10	2.97/0.10	3.07
8	उ० नि० प्रथम गोरखपुर / गोरखपुर विकास प्राधिकरण	ग्राम-मानकमऊ परगना व जिला सहारनपुर क्षेत्रफल-25000 वर्ग मीटर	श्री मधुव प्रसाद जालान एवं प्रेम प्रकाश जालान	मे. कामदगिरि डेवलपर्स, गोरखपुर / 25.10.2012	800	6500	175.79	12.30/0.10	12.30/0.10	12.40
योग					1650		2006.31	140.34/0.80	140.32 /0.80	141.12

*जिलाधिकारी द्वारा नियमित क्षेत्रवार दर के अनुसार

प्रकरण मई 2013 में विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि निबन्धन अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत दण्डात्मक प्रावधान का अभाव है और इस प्रकार के विलेखों के निष्पादन के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। अग्रतर शासन स्तर पर नियमित मासिक बैठकों में सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं। लेकिन भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं को दिशा निर्देश जारी करने की भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 73 (अ) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही के विषय में विभाग मौन रहा।

5.12.3 स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 23 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तांतरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभावी है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है।

हमने उपनिबन्धक प्रथम मुजफ्फरनगर कार्यालय के अभिलेखों³⁹ की जांच की और उनका विकास प्राधिकरण के अभिलेखों⁴⁰ से मिलान में पाया कि निर्माणकर्ता और भूमि मालिक के मध्य बिना कब्जा का एक अनुबन्ध का निष्पादन जुलाई 2010 में किया गया। प्रतिफल की धनराशि⁴¹ ₹ 2 करोड़ पर ₹ 4 लाख

स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 10000 निबन्धन फीस आरोपित था। उस भूखण्ड की ले आउट योजना विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिये 16 मई 2011 को अनुमोदित की गयी थी। उस सम्पत्ति के विक्रय विलेख का निष्पादन दिसम्बर 2011 और जून 2012 के मध्य पहले से बिना कब्जे के अनुबन्ध विलेख में भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क को समायोजित करने के बाद कृषि दर पर विकासकर्ता के पक्ष में किया गया। हमने पाया कि विक्रय विलेख के पूर्व⁴² ही आवासीय ले आउट योजना अनुमोदित की जा चुकी थी, भूमि का मूल्यांकन कृषि दर के बजाय आवासीय दर⁴³ से किया जाना अपेक्षित था। भूमि के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप प्रतिफल की धनराशि ₹ 17.97 करोड़ कम निश्चित की गयी और उस क्रम में ₹ 1.26 करोड़ स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ जैसा सारणी क्रमांक 5.13 में दिया है:

सारणी क्रमांक 5.13

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या / निष्पादन तिथि	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	भूमि का विवरण	भूमि का मूल्यांकन	निबन्धन फीस / स्टाम्प शुल्क	मूल्यांकन आरोपित @ ₹5000 प्रति वर्ग मीटर	स्टाम्प शुल्क आरोपित	अन्तर स्टाम्प शुल्क	
1	7600/01.06.2012	श्री मुरताक अहमद	ए. एस. जे. प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	खसरा संख्या 2263 & 2269 ग्राम-सुजड़, क्षेत्रफल-1.1405 हेक्टेअर	57.14	0.10/4.00	570.25	39.92	35.92	
2	9199/29.06.2012	श्री मुरताक अहमद	ए. एस. जे. प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	खसरा संख्या 2263 & 2269 ग्राम-सुजड़, क्षेत्रफल-1.1408 हेक्टेअर	57.14	0.10/4.00	570.40	39.93	35.93	
3	15040/31.12.2011	श्री मुरताक अहमद	ए. एस. जे. प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	खसरा संख्या 2263 & 2269 ग्राम-सुजड़, क्षेत्रफल-0.5702 हेक्टेअर	28.57	0.10/2.00	285.10	19.96	17.95	
4	6114/07.06.2012	श्री मुरताक अहमद	ए. एस. जे. प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	खसरा संख्या 2263 & 2269 ग्राम-सुजड़, क्षेत्रफल-1.1405 हेक्टेअर	57.14	0.10/4.00	570.25	39.92	35.91	
योग						199.99	0.40/14.00	1996	139.73	125.71

* जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रवार दर के अनुसार.

हमने मई 2013 में प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने सूचित (सितम्बर 2013) किया कि प्रकरणों को सम्पत्ति का बाजार मूल्य निश्चित करने और उन पर उचित शुल्क के भुगतान के लिये कलेक्टर को सन्दर्भित किया जा चुका है। उसके आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

³⁹ वही 1 जिसमें पंजीकृत विलेखों का विवरण होता है

⁴⁰ लेआउट योजना की पत्रावली

⁴¹ भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची एक-1 के अनुच्छेद 5 (ख-1) के अनुसार प्रतिफल की धनराशि के पचास प्रतिशत पर स्टाम्प शुल्क प्रभावी है।

⁴² 16 मई 2011

⁴³ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रवार दर ₹ 5000 प्रति वर्ग मीटर के अनुसार

द्वारा नहीं किया गया है। इससे आगे प्रकरणों को विभाग की जानकारी में लाने के बाद भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 73-अ (1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी जो कि जिला स्टाम्प अधिकारी भी है, के माध्यम से विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। विभाग ने नियन्त्रण कार्यविधि और विकासकर्ता अनुबन्धों के पंजीकरण की जांच की निगरानी के लिये कोई प्रणाली नहीं बनायी। विकास प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं और निबन्धन प्राधिकारियों के मध्य तालमेल का अभाव था।

5.12.7 अनुशंसा

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिकाओं से तालमेल के लिये एक कार्यप्रणाली विकसित करे ताकि सही मूल्य के स्टाम्प पर विकासकर्ता अनुबन्धों का पंजीकरण/निष्पादन हो।

5.13 अलाभकारी व्यय

हमने महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबन्धन इलाहाबाद के अभिलेखों की जांच किया (सितम्बर 2012) और पाया कि उप निबन्धक सलेमपुर, देवरिया को एक कार्यालय भवन उपलब्ध कराने हेतु शासन⁵⁴ द्वारा ₹ 42.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी और शासन द्वारा कार्य कार्यदायी संस्था⁵⁵ को आबंटित किया गया। इस स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 22.12 लाख 20 फरवरी 2009 में और शेष ₹ 20.65 लाख 16 मई 2011 को कार्यदायी संस्था को निर्गत किया गया।

धनराशि प्राप्त होने के आठ महीने विलम्ब से नवम्बर 2009 में कार्यदायी संस्था द्वारा उप निबन्धक सलेमपुर, देवरिया के कार्यालय भवन का कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में कार्य 31 मार्च 2009 तक पूर्ण करना था, पर विभाग के सचिव द्वारा कार्यदायी संस्था को मई 2012 तक का समय विस्तार दिया गया।

हमने पाया कि कार्य की प्रगति की निगरानी के लिये समिति/नियमित प्रगति प्रतिवेदन भेजने की प्रणाली नहीं थी। पहला संयुक्त निरीक्षण उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों के साथ केवल अगस्त 2012 में किया गया अर्थात् कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के तीन महीने बाद। निरीक्षण में यह प्रतिवेदित किया गया कि भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता बहुत खराब थी और मानक के अनुरूप नहीं थी क्योंकि बहुत सी कमियाँ⁵⁶ थीं। इन कमियों के कारण ₹ 42.77 लाख की धनराशि व्यय होने के बावजूद भवन बिना उपयोग के पड़ा था। निष्क्रियता/निगरानी के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 42.77 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ।

हमने नवम्बर 2012 में प्रकरण विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने स्वीकार किया (सितम्बर 2013) कि भवन हस्तगत नहीं किया गया है और कमियों की जांच के लिये जो समिति गठित है उसका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

⁵⁴ कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या क.नि.-5-4902/11-2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 द्वारा

⁵⁵ पैक्सफेड अर्थात् उ.प्र. सहकारी विधायन एवम शीतगृह संघ लि. लखनऊ

⁵⁶ छत और दीवारों पर बहुत सी दरारें थी, प्लास्टर उखड़े हुए थे एवं शीघ्र और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। फिटिंग्स एवं निर्माण कार्य, फर्श एवं शीशालय, सीढ़ी की रेलिंग का कार्य अचूरा छोड़ दिया गया था और मुख्य सड़क से कार्यालय भवन का सम्पर्क मार्ग नहीं बनाया गया था।

कायदात्मिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यताओं को किया

मनोरंजन विभाग एवं मूलतः तथा खनन विभाग के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच के दौरान पाये गये आपत्तियाँ में से ₹ 70.19 करोड़ के व्याख्यात्मक प्रकरणाँ को हम इस अध्याय में प्रस्तुत करते हैं। हमने, विभाग द्वारा कर, रायल्टी और ब्याज की न/कम वर्सुली के कड़े उदाहरण पाये।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अर्जपत्रन की स्थिति (2012-13)

अर्थात् 2012-13 के दौरान हमने मनोरंजन कर विभाग एवं मूलतः एवं खनन विभाग के क्रमशः 24 एवं 73 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच सम्पन्न की और कर, रायल्टी, ब्याज और अन्य अनियमितताओं के न/कम वर्सुली के 490 प्रकरणाँ में सन्निहित धनराशि रु0 665.93 करोड़ के प्रकरण को पाया।

विभाग ने अव-निर्धारण तथा अन्य कमियों को माना तथा ₹ 18.20 लाख वर्सुल किया।

हमारा निष्कर्ष

विभागों को आन्तरिक लेखापरीक्षा की मजबूती को सम्मिलित करते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे प्रणाली में कमियों का पता चले और हमारे द्वारा इंगित कमियों की प्रकृति से भविष्य में बचा जाय।

हमारे द्वारा इंगित न वर्सुले गये कर, कम कर के आयोग अर्थात् वर्सुले आदि की कायदात्मिक शक करने भी की भी आवश्यकता है और विशेषकर उन प्रकरणाँ में जिन्हें विभागों ने हमारे प्रेषण में स्वीकार किया है।

मनोरंजन कर विभाग

6.3 अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना

उ०प्र० सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उ०प्र० अधिनियम संख्या 3) की धारा-4, उ०प्र० सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 1988 के नियम-12, 16 व 18 और उ०प्र० सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी निम्न कालम-I में बताये गये जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र में कालम II या III के में निर्दिष्ट दर पर एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये, शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि से अनधिक के लिये वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन सिग्नल रिसीवर की एजेन्सी हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

कालम-I (स्थानीय क्षेत्र)	कालम-II (वीडियो लाइब्रेरी हेतु अनुज्ञा शुल्क)	कालम-III (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर हेतु अनुज्ञा शुल्क)
(अ) नगर निगम नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा	पाँच हजार रुपये	दस हजार रुपये
(ब) नगर परिषद	तीन हजार रुपये	छः हजार रुपये
(स) टाउन एरिया/ अन्य स्थानों	एक हजार रुपये	तीन हजार रुपये

जून 2012 और फरवरी 2013 के मध्य चार सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/मनोरंजन कर कार्यालयों¹ की पत्रावलियों² में हमने पाया कि अप्रैल 2010 और फरवरी 2013 की अवधि में 50 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी तथा 72 वीडियो लाइब्रेरी, जो कि जिले में संचालित थे, से कोई अनुज्ञा शुल्क³ नियमानुसार वसूल नहीं किया गया था। इस प्रकार, शासन देय अनुज्ञा शुल्क ₹ 5.47 लाख तथा ब्याज ₹ 74,000/- के राजस्व

से वंचित रहा। विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है-

सारणी क्रमांक 6.2

(₹ लाख में)

क्रम सं०	जिले का नाम	टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी	वीडियो लाइब्रेरी	देय अनुज्ञा शुल्क	देय ब्याज (लेखापरीक्षा तिथि तक आगणित)
1	बरेली	—	72	1.90	0.09
2.	बिजनौर	14	—	0.91	0.13
3.	मुरादाबाद	13	—	1.27	0.26
4.	मुजफ्फरनगर	23	—	1.39	0.26
	योग	50	72	5.47	0.74

जून 2012 और फरवरी 2013 के मध्य प्रकरण विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकारा तथा कहा (अगस्त 2013) कि बरेली में अनुज्ञा शुल्क अब जमा कराया जा चुका है और 19 वीडियो लाइब्रेरी, जो संचालित पाये गये, उनसे विलम्ब शुल्क वसूला गया। विभाग ने अन्य तीन जिलों के बचे हुए प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है।

¹ म०क०आ०: बरेली और बिजनौर स०आ०म०: मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर।

² वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन की अनुज्ञा शुल्क पंजिका।

³ 78 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी तथा 113 वीडियो लाइब्रेरी में से।

6.6.2 ईट बनाने की मिट्टी के हटान पर आवेदन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 का नियम 52 खनन अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रार्थना के तरीके का प्रावधान करता है। प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 400 निर्धारित थी, जिसे शासन की विज्ञप्ति संख्या 7338/86-2011-18 दिनांक 01 दिसम्बर 2011 द्वारा बढ़ाकर ₹ 2,000 कर दिया गया।

जुलाई 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य हमने आठ जिला खान अधिकारियों¹⁹ के अभिलेखों²⁰ की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान, 299 ईट भट्टा स्वामियों ने

खनन अनुज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 2000 के स्थान पर संशोधन के पूर्व की दर ₹ 400 की दर से भुगतान किया और 150 ईट भट्टा स्वामियों ने किसी प्रार्थना पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों ने प्रार्थना पत्र शुल्क के कम/न भुगतान का पता नहीं लगाया और न उसे वसूलने की शुरुआत की। परिणामतः प्रार्थनापत्र शुल्क ₹ 7.76 लाख का न/कम आरोपण हुआ, जैसा कि सारणी क्रमांक 6.3 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 6.3

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	मामलों की संख्या	देय आवेदन शुल्क	जमा आवेदन शुल्क	अन्तर
1.	जिला खान अधिकारी, इलाहाबाद	2011-12	72	1.44	0.29	1.15
2.	जिला खान अधिकारी, आजमगढ़	2011-12	25	0.50	0	0.50
			49	0.98	0.23	0.75
3.	जिला खान अधिकारी, चन्दौली	2011-12	125	2.50	0	2.50
			45	0.90	0.18	0.72
4.	जिला खान अधिकारी, जौनपुर	2011-12	42	0.84	0.17	0.67
5.	जिला खान अधिकारी, लखनऊ	2011-12	26	0.52	0.10	0.42
6.	जिला खान अधिकारी, मऊ	2011-12	13	0.26	0.05	0.21
7.	जिला खान अधिकारी, शाहजहाँपुर	2011-12	31	0.62	0.12	0.50
8.	जिला खान अधिकारी, श्रावस्ती	2011-12	21	0.42	0.08	0.34
	योग		449	8.98	1.22	7.76

हमने इसे (सितम्बर 2012 और मई 2013 के मध्य) शासन और विभाग को इंगित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को माना और कहा कि वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है (अगस्त 2013)।

¹⁹ इलाहाबाद, आजमगढ़, चन्दौली, जौनपुर, लखनऊ, मऊ, शाहजहाँपुर और श्रावस्ती।

²⁰ ईट भट्टा पंजिका और सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

6.7 अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 व 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तों के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा।

खान एवम् खनिज (विनिमय एवम् विकास) अधिनियम, 1957 (खान अधिनियम) की धारा-21 (1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57* आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम पच्चीस हजार रूपये तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

* विज्ञप्ति संख्या 7338/86-2011-183/211 लखनऊ दिनांक 01 दिसम्बर 2011 द्वारा यथासंशोधित

जुलाई 2012 एवम् जनवरी 2013 के मध्य पाँच जिला खान कार्यालयों²¹ की अवैध खनन पत्रावलियों एवं पंजिकाओ में हमने पाया कि अप्रैल 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य 35 प्रकरणों में 4,80,358 घनमीटर के उप खनिज को बिना विधि सम्मत प्राधिकार के निकाला गया।

बिना खनन अनुज्ञा/पट्टा के खनिजों की खुदाई न केवल अवैध थी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित किया। बावजूद इसके कि अवैध खनन के ये

प्रकरण विभाग के संज्ञान में थे, विभाग ने अवैध खनन की गयी खनिज की निर्दिष्ट रायल्टी की दर के पाँच गुना के खनिज मूल्य के आरोपण एवं उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार अर्थदण्ड के आरोपण की कोई कार्यवाही नहीं की। यह कार्यहीनता ₹ 2.78 करोड़ के खनिज मूल्य के न/कम आरोपण तथा अर्थदण्ड के न/कम आरोपण की ओर अग्रसर हुई जैसा कि सारणी क्रमांक 6.4 में वर्णित है।

सारणी क्रमांक 6.4

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला खान कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	प्रकरणों की संख्या	खनिज मात्रा घनमीटर में	रायल्टी की दर (₹ में)	खनिज की रायल्टी	खनिज का मूल्य ²²	देय धनराशि	अदा/आरोपित धनराशि	भुगतान की जाने वाली शेष धनराशि	आरोपित अर्थदण्ड/कम आरोपित/अनारोपित
1.	अलीगढ़	सा. मिट्टी	1	32410	9	2.92	14.58	17.50	0	17.50	अनारोपित
		सा. मिट्टी	1	209700	9	18.87	94.37	113.24	37.75	75.49	आरोपित
2.	बिजनौर	बालू/ बजरी	1	84520	22	18.59	92.97	111.57	20.71	90.86	अनारोपित
		सा. मिट्टी	1	85050	9	7.65	38.27	45.93	7.65	38.27	अनारोपित
		बालू	1	17560	22	3.86	19.32	23.18	3.10	20.08	अनारोपित
3.	मेरठ	सा. मिट्टी	2	16222	9	1.46	7.30	8.76	0	8.76	अनारोपित
4.	श्रावस्ती	सा. मिट्टी	23	22997	9	2.07	10.35	12.42	0	12.42	अन्तरीय दर से आरोपित
		बालू	4	8099	22	1.78	8.91	10.69	0	10.69	अन्तरीय दर से आरोपित
5.	वाराणसी	बालू	1	3800	22	0.84	4.18	5.02	0.84	4.18	आरोपित
योग			35	480358		58.04	290.25	348.31	70.05	278.25	

मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2012 से मार्च 2013)। विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2013) की अधिनियम एवम् नियमावली में खनिज मूल्य प्रभारित करने का कोई प्रावधान नहीं है और प्रावधान केवल अर्थदण्ड के आरोपण तक ही सीमित है। विभाग ने आगे बताया कि अर्थदण्ड आरोपित करना या खनिज मूल्य या रायल्टी वसूलना यह

²¹ अलीगढ़, बिजनौर, मेरठ, श्रावस्ती और वाराणसी।

²² खनिज मूल्य का 20 प्रतिशत रायल्टी है जैसा कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 21 (2) में निर्दिष्ट है।

प्राधिकारी का विवेकाधिकार है, इसलिए इन मामलों में सक्षम प्राधिकारियों ने अपने विवेकाधिकार से खनिज मूल्य वसूलने के बजाय अर्थदण्ड आरोपित किया। विभाग का उत्तर अनुचित है क्योंकि खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 (1) और (5) में अवैध खनन हेतु निर्दिष्ट दण्ड में किराया, रायल्टी या कर से पृथक खनिज मूल्य की वसूली समाहित है। उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली इन मामलों में अर्थदण्ड के आरोपण और/या अपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान है। खनिज मूल्य की वसूली न करके तथा अर्थदण्ड का अनारोपण करके विभाग ने अधिनियम एवम् नियमावली का उल्लंघन किया।

6.8 रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (2) के अनुसार 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने पर किसी किराया, रायल्टी या सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपित की जायेगी। केवल ईट भट्टों से रायल्टी वसूली के प्रकरण में 18 मई 2009 के शासनादेश के तहत ब्याज की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी थी। आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2011 द्वारा पुनः ब्याज दर बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया।

मई 2012 एवम् दिसम्बर 2012 के मध्य हमने नौ जि0खा0अ0²³ की पट्टा पत्रावलियों में पाया कि 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान 493 प्रकरणों में ₹ 2.07 करोड़ की देय रायल्टी जमा की जानी थी जो 37 से 851 दिनों के विलम्ब से जमा की गयी। विलम्ब से भुगतान का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध के

बावजूद विभाग ने विलम्ब से किये गये इन भुगतानों पर ब्याज के आरोपण और वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणाम स्वरूप ब्याज के ₹ 19.10 लाख की वसूली नहीं हुई जिसका ब्यौरा सारणी क्रमांक 6.5 में है:

सारणी क्रमांक 6.5

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	देय अवधि	मामलों की संख्या	देय धनराशि	जमा धनराशि	आरोपणीय ब्याज ²⁴	ब्याज सहित देय कुल धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	शुद्ध वसूलनीय ब्याज
1.	बागपत	2009-10	68	36.43	36.43	3.04	39.47	43 से 732	3.04
2.	बिजनौर	2009-10	88	45.43	45.43	4.19	49.62	91 से 851	4.19
		2010-11	5	2.62	2.62	0.33	2.95	142 से 290	0.33
		2011-12	2	1.023	1.02	0.03	1.05	37 से 85	0.03
3.	चन्दौली	2011-12	45	16.28	16.28	2.23	18.51	84 से 422	2.23
4.	गाजियाबाद	2009-10	62	34.06	34.06	1.89	35.95	60 से 324	1.89
5.	कौशाम्बी	2011-12	05	2.09	2.09	0.05	2.14	64 से 221	0.05
6.	मिर्जापुर	2011-12	24	7.37	7.37	1.01	8.38	126 से 398	1.01
7.	मुरादाबाद	2010-11	13	6.62	6.62	0.98	7.60	69 से 454	0.98
8.	संतरविदास नगर	2009-10	23	8.18	8.18	0.97	9.15	119 से 399	0.97
9.	वाराणसी	2009-10	139	39.44	39.44	3.70	43.14	65 से 562	3.70
	योग		493	207.33	207.33	19.10	226.43		19.10

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) विभाग ने हमारी आपत्तियों को अपने उत्तर (अगस्त 2013) में माना और कहा कि विलम्ब से जमा के लिये नोटिसें समय से जारी नहीं की गयी थी। विभाग ने आगे बताया कि नियमावली में विहित समय सीमा के अन्तर्गत नोटिसें प्रेषित नहीं की गयी थी, इसलिये अब ब्याज की वसूली नहीं की जा सकती है। विभागीय उत्तर शासकीय देयताओं की वसूली के प्रति इसकी उदासीनता को दर्शाता है। विभाग को शीघ्रतापूर्वक नोटिसें जारी करने हेतु कदम उठाना चाहिए और विलम्ब से जमा रायल्टी पर देय ब्याज को

²³ बागपत, बिजनौर, चन्दौली, गाजियाबाद, कौशाम्बी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, संत रविदास नगर और वाराणसी।

²⁴ ब्याज दर 2009-10 में 18 प्रतिशत, 2010-11 में 24 प्रतिशत तथा 2011-12 में 24 प्रतिशत प्रति वर्ष।

6.9.1 हमने जिला अधिकाषी खनन के खनन पट्टी की पञ्चालियाँ की नमना जाँच की नमना (सितम्बर 2012) में पाया कि पट्टीधारकों ने जुलाई 2003 से मार्च 2012 के दौरान 260049.66 घनमीटर स्टोन बैलास्ट का खनन अनुमोदित खनन योजनाओं में उचितखिल मात्रा से अधिक का किया। इस प्रकार पट्टीधारकों द्वारा उपखनित का खनन अनुमोदित या और पट्टीधारकों से खनित मूल्य ₹ 7.08 करोड़ बर्तनीय था। जिओखा 310 द्वारा तथ्य को नहीं देखा गया तथा अनुमोदित मात्रा से अधिक खनित के खनन के बावजूद भी पट्टीधारकों का एम0एम-11 फर्म निर्मित करना जारी रखा। जिओखा10 ने खनन योजना से अधिक खनन के लिए पट्टीधारकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की तथा निकाले गये खनित के मूल्य ₹ 7.08 करोड़ और अर्द्धपट्टी को बर्तनीय की कोई कार्रवाई नहीं की जैसा कि सारणी क्रमांक 6.6 में वर्णित है।

खनित परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22ए में प्रावधान है कि खनन से संक्रियार्थ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टी संभालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है। खान एवं खनित विनियम एवं विकास अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनित को किसी भी से हटाना, रख्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उदाय गये खनित या जहाँ ऐसा खनित पूर्व में ही हटया गया है, रायवटी के साथ खनित मूल्य बर्तनीय कर सकती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत रायवटी खनिमूल्य का अधिकतम 20% की दर से निर्धारित है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) के अन्तर्गत संग्रामर, घुने का पत्थर, इमारती पत्थर जैसे बालू पत्थर और ग्रेनाइट, स्टोन ब्ल्यास्ट (फिट्टी), बजरी आदि, के प्रकारों में पट्टीधारक द्वारा प्रथम एम0एम-1 (ए) में प्रावना पत्र के साथ खनन योजना संभलन करना अपेक्षित है। नदी तल में पाये जाने वाले बालू और मारम के लिए खनन योजना की आवश्यकता नहीं है।

6.9 अनुमोदित खनन

बर्तनीय बाहिए तथा उन कर्मियों जिन्होंने समय से नोटिस निर्गत नहीं किया, का उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना चाहिए।

सारणी क्रमांक 6.6

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	फर्म का नाम सर्वश्री	मामलों की संख्या	खनन योजना के अनुसार अनुमन्य मात्रा घनमीटर में	कुल उत्खनित मात्रा घनमीटर में	अधिक उत्खनन घनमीटर में	वसूली योग्य खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	सोनभद्र	ए.के.मौर्या	1	6000	77071.66	71071.66	131.43	0.25
		के०के०स्टोन प्रोडक्ट	1	6000	79800	73800	184.68	0.25
		सौरभ क्रशर	1	30000	48178	18178	61.80	0.25
		बशीर बेग	1	20000	117000	97000	329.80	0.25
		योग	4	62,000	3,22,049.66	2,60,049.66	707.71	1.00

6.9.2 खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उपखनिज का उत्खनन

जिला खान अधिकारी मिर्जापुर और सोनभद्र की पत्रावलियों से हमने पाया (सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2012 के मध्य) कि पट्टाधारको ने उपखनिजों का उत्खनन और परिवहन अपनी खनन योजनाओं के नवीनीकरण/अनुमोदन के बिना किया। पट्टाधारको की खनन योजना केवल 3 वर्ष के लिये अनुमोदित की गयी थी, फिर भी पट्टाधारकों ने खनन योजना की अवधि समाप्ति के पश्चात भी उपखनिजों का निकालना जारी रखा। अप्रैल 2003 एवम् मई 2012 के मध्य 1 दिन से लेकर 1,060 दिनों की अवधि में पट्टाधारको द्वारा 6,26,783 घनमीटर उपखनिजों का अवैध उत्खनन किया गया। जिला खान अधिकारियों द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तथा उन्होंने खनन योजना की समाप्ति के बाद भी पट्टाधारको को एम०एम०-11 निर्गत करना जारी रखा।

जिला खान अधिकारियों ने अनधिकृत उत्खनन को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की एवम् खनन किये गये खनिज जिसका मूल्य ₹ 18.82 करोड़ था तथा उस पर शास्ति दोनों की वसूली भी पट्टाधारकों से नहीं की।

इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2012 एवम् दिसम्बर 2012), विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि खनन योजना/खनन योजना के नवीनीकरण के बिना किया गया उत्खनन का यह उल्लंघन अवैध न होकर उ०प्र०ख०प० नियमावली के नियम 34 का उल्लंघन है।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि खनन संक्रियायें अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना अपेक्षित था और विभाग को उत्खनित खनिज का मूल्य व इस उल्लंघन के लिये उस पर देय अर्थदण्ड की वसूली की कार्यवाही करनी थी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

परिशिष्टियाँ

क्रम सं०	इकाई का नाम	वर्ष	वर्ष में कुल दिनों की सं०	जाँच किये गये दिनों की सं०	प्राप्त राजस्व	जाँच न किये गये दिनों की सं०
18	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-2, कानपुर	2011-12	366	136	117.70	230
		2008-09	365	311	241.91	54
		2009-10	365	305	141.95	60
		2010-11	365	229	19.22	126
		2011-12	366	188	49.25	177
19	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-3, कानपुर	2010-11	365	260	108.09	105
		2011-12	366	239	144.35	127
20	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-8, कानपुर	2011-12	366	78	21.56	288
21	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-12, कानपुर	2010-11	365	229	43.37	45
		2011-12	366	107	13.20	259
22	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-1, लखनऊ	2010-11	365	275	167.98	90
		2011-12	366	214	154.09	152
23	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-5, लखनऊ	2011-12	366	331	130.06	35
24	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-4, मथुरा	2011-12	366	209	288.73	157
25	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-4, मेरठ	2010-11	365	266	182.35	99
		2011-12	366	296	236.98	70
26	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-2, मेरठ	2011-12	366	265	211.68	101
27	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-5, मेरठ	2011-12	366	305	167.14	61
28	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-3, मुरादाबाद	2009-10	365	148	99.69	217
		2010-11	365	205	75.16	160
		2011-12	366	202	118.39	164
29	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-6, मुरादाबाद	2011-12	366	236	114.03	130
30	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-1, नोएडा	2010-11	365	316	298.18	49
		2011-12	366	279	312.65	87
31	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-5, नोएडा	2011-12	366	343	152.37	23
32	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-6, नोएडा	2010-11 (15/09/2010 से)	198	172	281.20	26
		2011-12	366	301	338.02	65
33	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-1, सहारनपुर	2009-10	365	256	131.62	109
		2010-11	365	209	120.37	156
34	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-4, सहारनपुर	2011-12	366	109	100.67	257
35	असि०कमि० (प्रभारी) सचल दल-4, वाराणसी	2009-10	365	286	133.19	79
		2010-11	365	268	117.68	97
		2011-12	366	242	118.51	124
योग			25,051	16,695	10,633.09	8,254

परिशिष्ट-II
बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के नकदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना
 (सन्दर्भित प्रस्तर सं०. 2.17.2.1)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर	नकदी करण का दिनांक	विलम्ब की अवधि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत में)	आरोपित ब्याज	आरोपणीय ब्याज	ब्याज का अनारोपण
1.	ज्वा०क० (कार्पो०स०) वा०क० अलीगढ़	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	2.55	17.04.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 17 दिन	15	0	1.26	1.26
2.	डि०क० खण्ड-10 वा०क० अलीगढ़	1	2008-09 (मार्च 2010)	7.80	02.02.12 (बैंक गारण्टी)	37 माह 2 दिन	15	0	3.61	3.61
3.	ज्वा०क० (कार्पो०स०) 2 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	12.83	06.01.12 (बैंक गारण्टी)	36 माह 6 दिन	15	0	5.80	5.80
			2008-09 (फरवरी 2012)	235.54	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 5 दिन	15	0	115.31	115.31
				228.46	06.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 6 दिन	15	0	111.93	111.93
			2007-08 (मार्च 2010)	282.01	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	51 माह 5 दिन	14/15	0	179.47	179.47
			2008-09 (नवम्बर 2011)	39.54	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 5 दिन	15	0	19.36	19.36
			2008-09 (जून 2012)	8.36	03.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 3 दिन	15	0	4.09	4.09
			2008-09 (मार्च 2012)	10.53	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 5 दिन	15	0	5.15	5.15
			2009-10 (मार्च 2013)	28.15	31.12.11 (बैंक गारण्टी)	27 माह	15	9.70	9.70	0
4.	ज्वा०क० (कार्पो०स०)-1 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	24.78	4.1.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह	15	12.08	12.08	0
			2009-10 (अप्रैल 2013)	36.28	4.1.12 (बैंक गारण्टी)	27 माह 4 दिन	15	15.36	15.36	0
5.	डि०क० खण्ड-6 वा०क० गाजियाबाद	1	2007-08 (जनवरी 2012)	96.05	30.12.11 (बैंक गारण्टी)	45 से 48 माह	14/15	0	60.99	60.99
			2008-09 (मई 2012)	305.90	30.12.11 (बैंक गारण्टी)	39 माह	15	0	149.13	149.13
			2007-08 (मार्च 2010)	7.81	30.12.11 एवम 05.01.12 (बैंक गारण्टी)	48 माह 5 दिन	14/15	0	4.97	4.97
			2008-09 (मार्च-2012)	8.13	05.01.12 (बैंक गारण्टी)	39 माह 5 दिन	15	0	3.98	3.98

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर	नकदी करण का दिनांक	विलम्ब की अवधि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत में)	आरोपित ब्याज	आरोपणीय ब्याज	ब्याज का अनारोपण
16	डि०क० खण्ड-6 वा०क० मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (फरवरी 2011)	0.40	23.02.12 (बैंक गारण्टी)	37 माह 23 दिन	15	0	0.19	0.19
17	डि०क० खण्ड-8 वा०क० वाराणसी	1	2008-09 (जनवरी 2012)	1.32	23.1.12 बैंक गारण्टी)	39 माह 23 दिन	15	0	0.65	0.65
			2009-10 (दिसम्बर 2011)	2.34	23.1.12 बैंक गारण्टी)	27 माह 23 दिन	15	0	0.81	0.81
	योग	30		5202.49				46.40	2717.20	2670.80

परिशिष्ट-III
कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान में न लिये जाने वाले मामले
(सन्दर्भित प्रस्तर सं०. 2.21.1)

(₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	गलत/मिथ्या आईटीसी दावा की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रभारित ब्याज
1.	डि०क० खण्ड-12 वा०क० आगरा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.40	1.99	0.27
2.	ज्वा०क० (कार्पो०स०) वा०क० आगरा	1	2008-09 (जनवरी 2012)	10.85	54.25	7.32
		1	2010-11 (अप्रैल 2012)	2.51	12.56	0.94
3.	डि०क० खण्ड-2 वा०क० आजमगढ़	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.71	3.55	0.48
4.	ज्वा०क० (कार्पो०स०) ए वा०क० बरेली	1	2008-09 (जनवरी 2012)	6.69	33.42	4.52
5.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० बस्ती	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.17	5.86	0.79
6.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० छात्रपतिशाहू जी महाराज नगर गौरीगंज	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.82	4.08	0.55
7.	डि०क० खण्ड-2 वा०क० गौतमबुद्धनगर	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	3.06	15.30	2.07
		1	2008-09 (मार्च 2012)	0.91	4.55	0.61
8.	डि०क० खण्ड-9 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	23.24	116.21	15.69
9.	डि०क० खण्ड-7 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2011)	1.13	5.65	0.76
		1	2008-09 (मार्च 2012)	3.71	18.55	2.50
10.	डि०क० खण्ड-6 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.24	1.22	0.16
11.	डि०क० खण्ड-4 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	2.86	14.30	1.93
12.	असि०क० खण्ड-6 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.47	2.37	0.32
13.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० गोण्डा	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	1.00	5.00	0.73
14.	डि०क० खण्ड-5 वा०क० गोरखपुर	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (फरवरी 2011)	1.27	6.34	0.95
15.	डि०क० खण्ड-4 वा०क० हापुड़	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.48	2.40	0.32
16.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० हरदोई	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.14	0.70	0.09
17.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० हसनपुर	1	2007-08 (मार्च 2011)	0.26	1.30	0.19
18.	डि०क० खण्ड-2 वा०क० हाथरस	1	2008-09 (मार्च 2012)	10.60	52.99	7.16
19.	डि०क० खण्ड-2 वा०क० कनौज	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	0.23	1.13	0.20
20.	डि०क० खण्ड-18 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	10.17	50.85	6.86
21.	डि०क० खण्ड-12	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.16	0.80	0.11

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	गलत/मिथ्या आईटीसी दावा की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रभारित ब्याज
	वा०क० कानपुर					
22.	असि०क० खण्ड-9 वा०क० कानपुर	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (फरवरी 2011)	0.63	3.15	0.46
23.	डि०क० खण्ड-20 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.56	2.80	0.38
		1	2009-10 (अगस्त 2011)	3.98	19.90	2.09
24.	डि०क० खण्ड-18 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (अगस्त 2011)	11.08	55.40	7.48
25.	डि०क० खण्ड-17 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	0.64	3.20	0.43
		1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.27	6.35	0.86
26.	असि०क० खण्ड-21 वा०क० लखनऊ	1	2010-11 (जनवरी 2012)	0.84	4.22	0.32
27.	असि०क० खण्ड-18 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.47	7.34	0.99
28.	असि०क० खण्ड-15 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (जनवरी 2012)	1.21	6.05	0.82
29.	असि०क० खण्ड-8 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (जनवरी 2012)	14.41	72.05	9.73
30.	डि०क० खण्ड-8 वा०क० मेरठ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.36	6.80	0.92
31.	डि०क० खण्ड-4 वा०क० मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.57	2.85	0.38
32.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० पडरौना (कुशीनगर)	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	0.61	3.07	0.48
33.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० रायबरेली	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.22	6.10	0.82
		1	2008-09 (जनवरी 2012)	0.35	1.77	0.24
34.	डि०क० खण्ड-4 वा०क० वाराणसी	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	0.22	1.10	0.15
35.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० वाराणसी	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.17	0.87	0.11
	योग	41		123.67	618.39	82.18

परिशिष्ट- IV
ब्याज/अर्थदण्ड का अनारोपण।
 (सन्दर्भित प्रस्तर सं०. 2.21.2)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	गलत/मिथ्या आईटीसी का दावा	आरोपणीय अर्थदण्ड	ब्याज की धनराशि
1.	ज्वा०क० (कार्पो०सं०) वा०क० आगरा	1	2008-09 (मई 2012)	2.10	10.50	1.42
2.	डि०क० खण्ड-12 वा०क० आगरा	1	2008-09 (मार्च 2012)	6.04	30.20	4.08
		1	2007-08(वैट) (मार्च 2012)	1.67	8.35	1.23
3.	डि०क० खण्ड-2 वा०क० इटावा	1	2008-09 (मार्च 2012)	4.58	22.90	3.09
4.	डि०क० खण्ड-19 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.14	0.72	0.09
5.	डि०क० खण्ड-10 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.46	2.29	0.31
		1	2008-09 (मार्च 2012)	2.18	10.91	1.47
6.	डि०क० खण्ड-7 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.29	1.47	0.20
7.	डि०क० खण्ड-5 वा०क० गाजियाबाद	1	2010-11 (नवम्बर 2011)	1.08	5.38	0.41
8.	असि०क० खण्ड-11 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	0.31	1.57	0.21
			2009-10 (दिसम्बर 2011)	0.19	0.96	0.10
9.	असि०क० खण्ड-4 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	0.19	0.96	0.13
10.	डि०क० खण्ड-29 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (फरवरी 2012)	3.18	15.90	2.15
		1	2009-10 (दिसम्बर 2011)	3.89	19.45	2.04
11.	डि०क० खण्ड-20 वा०क० कानपुर	1	2009-10 (जून 2012)	0.12	0.58	0.06
12.	डि०क० खण्ड-14 वा०क० कानपुर	1	2009-10 (जनवरी 2012)	0.38	1.90	0.20
13.	डि०क० खण्ड-18 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.50	2.50	0.34
		1	2008-09 (मार्च 2012)	0.22	1.10	0.15
14.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	10.09	50.45	6.81
15.	डि०क० खण्ड-2 वा०क० काशी राम नगर (कासगंज)	1	2008-09 (मार्च 2012)	12.38	61.88	8.36

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	गलत/मिथ्या आईटीसी का दावा	आरोपणीय अर्थदण्ड	ब्याज की धनराशि
		1	2008-09 (मार्च 2011)	0.60	3.00	0.41
16.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० कासगंज	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.55	2.73	0.37
17.	डि०क० खण्ड-20 वा०क० लखनऊ	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	3.11	15.55	2.30
18.	डि०क० खण्ड-11 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	2.29	11.45	1.55
19.	डि०क० खण्ड-3 वा०क० लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2011)	0.80	4.02	0.42
20.	असि०क० खण्ड-13 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (जुलाई 2011)	4.47	22.35	3.02
21.	डि०क० खण्ड-2 वा०क० महाराजगंज	1	2008-09 (अक्टूबर 2010)	0.82	4.08	0.55
22.	डि०क० खण्ड-1 वा०क० मथुरा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	3.16	15.80	2.13
23.	डि०क० खण्ड-12 वा०क० मेरठ	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	1.45	7.25	1.07
24.	डि०क० खण्ड-7 वा०क० मुजफ्फर नगर	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2012)	1.68	8.40	1.24
25.	डि०क० खण्ड-8 वा०क० नोएडा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.29	1.46	0.20
26.	डि०क० खण्ड-3 वा०क० पीलीभीत	1	2008-09 (मार्च 2012)	2.33	11.65	1.57
27.	ज्वा०क०मि० (कार्पो०स०)-2 वा०क० वाराणसी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.16	0.81	0.11
	योग	32		71.70	358.52	47.79

परिशिष्ट-V

देशी मदिरा व भारत निर्मित विदेशी मदिरा का अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारित करते समय पूर्णांकन में एकरूपता न होना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.7.1)

(₹ में)

विवरण	25%				36%							42.80%				
	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	750 मिली	375 मिली	240 मिली	200 मिली	180 मिली	140 मिली	100 मिली	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	
2007-08																
बोतलों की संख्या	1446876	9623944	8883500	195758796	6555702	30055174	9645203	19620840	731476478	अधिकृत	अधिकृत	28248	357024	बिक्री नहीं	46245229	
आठ फुटमू एवं आठ फुटमू का अन्तर	3.94	1.88	0.72	0.15	8.96	2.39	2.65	1.45	1.22	—	—	9.83	2.83	—	1.63	
घनराशि ₹ में	5700691	18093015	6396120	29363819	58739090	71831866	25559788	28450218	892401303	—	—	277678	1010378	—	75379723	1213203689
2008-09																
बोतलों की संख्या	1258008	8236808	15856165	186723658	6464940	24405816	8379042	64872795	728592755	40000	अधिकृत	अधिकृत	110232	2602008	46273796	
आठ फुटमू एवं आठ फुटमू का अन्तर	1.8	1.68	0.82	0.02	5.44	1.01	1.82	1.39	0.53	0.3	—	—	1.12	1.59	1.31	
घनराशि ₹ में	2264414	13837837	13002055	3734473	35169274	24649874	15249856	90173185	386154160	12000	—	—	123460	4137193	60618673	649126455
2009-10																
बोतलों की संख्या	634596	894144	3786934	235262118	4707276	12602832	14939988	18650816	860137027	अधिकृत	9267350	अधिकृत	42984	60750	95565409	
आठ फुटमू एवं आठ फुटमू का अन्तर	0.95	0.7	0.18	0.54	3.1	0.78	1.08	1.09	0.45	—	0.36	—	1.09	0.86	0.84	
घनराशि ₹ में	602866	625901	681648	127041544	14592556	9830209	16135187	20329389	387061662	—	3336246	—	46853	52245	80274944	660611249
2010-11																
बोतलों की संख्या	62868	35880	3793350	254266950	3978180	13413768	14219982	111554160	775238338	अधिकृत	5519190	अधिकृत	60000	अधिकृत	121050140	
आठ फुटमू एवं आठ फुटमू का अन्तर	2.7	0.57	0.38	0.11	3.64	0.55	1.55	0.63	0.54	—	0.64	—	1.95	—	1.01	
घनराशि ₹ में	169744	20452	1441473	27969365	14480575	7377572	22040972	70279121	418628703	—	3532282	—	117000	—	122260641	688317899

तीव्रता	28%				36%				42.80%							
	धारिता	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	750 मिली	375 मिली	240 मिली	200 मिली	180 मिली	140 मिली	100 मिली		750 मिली	375 मिली	200 मिली
2011-12																
बोतलों की संख्या	52320	69192	154689120	1030860	29427828	5087160	अधिकृत	903717960	अधिकृत	अधिकृत	4014630	54780	55200	13199400	95267480	
आपफु0मू0 एवं अ0फु0मू0 का अन्तर	5.76	1.93	0.5	0.39	3.1	1.61	—	0.72	—	—	0.5	3.01	2.06	2.43	1.06	
घनराशि ₹ में	301363	133541	77344560	402035	91226267	8190328	—	650676931	—	—	2007315	164888	113712	32074542	100983529	963619010
2012-13																
बोतलों की संख्या	अधिकृत	अधिकृत	193793364	अधिकृत	72300	360000	अधिकृत	633632490	अधिकृत	अधिकृत	252000	579984	1103064	330252210	23181470	
आपफु0मू0 एवं अ0फु0मू0 का अन्तर	—	—	0.01	—	0.76	0.44	—	0.1	—	—	0.19	0.25	0.68	1.7	0.4	
घनराशि ₹ में	—	—	1937934	—	54948	158400	—	63363249	—	—	47880	144996	750084	561428757	9272588	637158835
														महायोग		4812037138 या 481.20 करोड़

आपफु0मू0 : आदर्श फुटकर मूल्य,
अ0फु0मू0 : अधिकतम फुटकर मूल्य.

नोट :- आसवनी द्वारा प्रत्येक धारिता एवं तीव्रता की विक्रीत बोतलों की संख्या पर आधारित।

परिशिष्ट-VI
देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापी को अदेय लाभ

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.7.2)

(₹ में)

तीव्रता	25%				36%						42.80%					
	घारिता	750 मिली	375 मिली	200 मिली	180 मिली	750 मिली	375 मिली	240 मिली	200 मिली	180 मिली	140 मिली	100 मिली	750 मिली	375 मिली		200 मिली
2007-08																
बिक्रीत बोतलों की संख्या	1446876	9623944	8883500	195758796	6555702	30055174	9645203	19620840	731476478	अबिक्रीत	अबिक्रीत	28248	357024	बिक्री नहीं	46245229	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.30	0.16	0.09	0.08	0.41	0.22	0.14	0.12	0.11	—	—	0.48	0.25	—	0.13	
छीजन + 3% छीजन पर लाभ	0.309	0.1648	0.0927	0.0824	0.4223	0.2266	0.1442	0.1236	0.1133	—	—	0.4944	0.2575	—	0.1339	
घनराशि	447085	1586026	823500	16130525	2768473	6810502	1390838	2425136	82876285	—	—	13966	91934	—	6192236	121556506
2008-09																
बिक्रीत बोतलों की संख्या	1258008	8236808	15856165	186723658	6464940	24405816	8379042	64872795	728592755	40000	अबिक्रीत	अबिक्रीत	110232	2602008	46273796	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.33	0.18	0.10	0.09	0.46	0.24	0.16	0.13	0.12	0.10	—	—	0.28	0.16	0.14	
छीजन + 3% छीजन पर लाभ	0.3399	0.1854	0.103	0.0927	0.4738	0.2472	0.1648	0.1339	0.1236	0.103	—	—	0.2884	0.1648	0.1442	
घनराशि	427597	1527104	1633185	17309283	3063089	6033118	1380866	8686467	90054065	4120	—	—	31791	428811	6672681	137252177
2009-10																
बिक्रीत बोतलों की संख्या	634596	894144	3786934	235262118	4707276	12602832	14939988	18650816	860137027	अबिक्रीत	9267350	अबिक्रीत	42984	60750	95565409	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.36	0.19	0.11	0.10	0.50	0.26	0.17	0.14	0.13	—	0.08	—	0.30	0.17	0.15	
छीजन + 1% छीजन पर लाभ	0.3636	0.1919	0.1111	0.101	0.505	0.2626	0.1717	0.1414	0.1313	—	0.0808	—	0.303	0.1717	0.1515	
घनराशि	230739	171586	420728	23761474	2377174	3309504	2565196	2637225	112935992	—	748802	—	13024	10431	14478159	163660035
2010-11																
बिक्रीत बोतलों की संख्या	62868	35880	3793350	254266950	3978180	13413768	14219982	111554160	775238338	अबिक्रीत	5519190	अबिक्रीत	60000	अबिक्रीत	121050140	

सीधता	25%				36%							42.80%				
	घरिता	750 मिला	375 मिला	200 मिला	180 मिला	750 मिला	375 मिला	240 मिला	200 मिला	180 मिला	140 मिला	100 मिला	750 मिला	375 मिला	200 मिला	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.42	0.22	0.12	0.11	0.59	0.31	0.2	0.17	0.15	—	0.09	—	0.36	—	0.18	
छीजन + 1% छीजन पर लाम	0.4242	0.2222	0.1212	0.1111	0.5959	0.3131	0.202	0.1717	0.1515	—	0.0909	—	0.3636	—	0.1818	
धनराशि	26669	7973	459754	28249058	2370597	4199851	2872436	19153849	117448608	—	501694	—	21816	—	22006915	197319221
2011-12																
बिक्रीत बोललो को संख्या	52320	69192	154689120	1030860	29427828	5087160	अबिक्रीत	903717960	अबिक्रीत	अबिक्रीत	4014630	54780	55200	13199400	95267480	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	0.55	0.28	0.16	0.09	0.69	0.36	—	0.2	—	—	0.11	0.81	0.42	0.23	0.21	
छीजन + 1% छीजन पर लाम	0.5555	0.2828	0.1616	0.0909	0.6969	0.3636	—	0.202	—	—	0.1111	0.8181	0.4242	0.2323	0.2121	
धनराशि	29064	19567	24997762	93705	20508253	1849691	—	182551028	—	—	446025	44816	23416	3066221	20206233	253835781
2012-13																
बिक्रीत बोललो को संख्या	अबिक्रीत	अबिक्रीत	193793364	अबिक्रीत	72300	360000	अबिक्रीत	633632490	अबिक्रीत	अबिक्रीत	252000	579984	1103064	330252210	23181470	
छीजन @ 0.5% (₹ में)	—	—	0.16	—	0.7	0.36	—	0.2	—	—	0.11	0.82	0.42	0.23	0.21	
छीजन + 1% छीजन पर लाम	—	—	0.1616	—	0.707	0.3636	—	0.202	—	—	0.1111	0.8282	0.4242	0.2323	0.2121	
धनराशि	—	—	31317008	—	51116	130896	—	127993763	—	—	27997	480343	467920	76717588	4916790	242103421
महा योग															1115727140	या ₹ 111.57 करोड़

परिशिष्ट-VII
देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में कम आधार पर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की वृद्धि किया जाना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.9)

(₹ में)

क्रम संख्या	इकाईयाँ का नाम	वर्ष	गतवर्ष की व्यवस्थित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	गतवर्ष की वास्तविक उठान की मात्रा	अन्तर (कॉलम 5 - कॉलम 4)	गतवर्ष के वास्तविक उठान के अन्तर का गतवर्ष के व्यवस्थित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर प्रतिशतता (कॉलम 6 × 100 / कॉलम 4)	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के वृद्धि की दर प्रतिशत में	गतवर्ष के वास्तविक उठान पर वृद्धि के पश्चात् न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	वर्ष में वास्तविक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	अन्तर (कॉलम 9 - कॉलम 10)	बेसिक लाइसेंस फीस की दर	कम व्यवस्थित मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस की राशि (कॉलम 9 × कॉलम 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	इलाहाबाद	2008-09	5208691	5223474.96	14783.96	0.284	7	5589118.21	5168965	14783.96	15	6302298
		2009-10	5168965	5214285.34	45320.34	0.877	7	5579285.31	5275723	45320.34	20	6071246
2	बगपत	2008-09	1277450	1335783	58333.00	4.566	7	1429287.81	1367250	58333.00	15	930567
		2009-10	1367250	1376466	9216.00	0.674	8	1486583.28	1476640	9216.00	20	198866
		2010-11	1476640	1478546	1906.00	0.129	3	1522902.38	1521260	1906.00	21	34490
3	कोली	2008-09	5750695	5791574	40879.00	0.711	7	6196984.18	6032254	40879.00	15	2470953
		2010-11	6540220	6544324	4104.00	0.063	3	6740653.72	6737880	4104.00	21	58248
		2011-12	6737880	6737915	35.00	0.001	1	6805294.15	6805280	14.15	21	297
4	बिजनौर	2008-09	4231510	4294013.86	62503.86	1.477	7	4594594.83	4528520	66074.83	15	991122
		2009-10	4528520	4558828.28	30308.28	0.669	8	4923534.54	4891380	32154.54	20	643091
		2010-11	4891380	4898898	7518.00	0.154	3	5045864.94	5038820	7044.94	21	147944
		2011-12	5038820	5038886.53	66.53	0.001	1	5089275.40	5089270	5.40	21	113
5	बदायूँ	2008-09	3530640	3531116	476.00	0.013	7	3778294.12	3683250.00	95044.12	15	1425662
		2010-11	3977910	3979493	1583.00	0.040	3	4098877.79	4098490.00	387.79	21	8144
6	गाजियाबाद	2008-09	9425750	9754330.54	328580.54	3.486	7	10437133.68	10086430	350703.68	15	5260555
		2009-10	10086430	10093097.6	6667.64	0.066	8	10900545.45	10894020	6525.45	20	130509
		2010-11	10894020	10896255.3	2235.30	0.021	3	11223142.96	11221440	1702.96	21	35762
7	गजौपुर	2008-09	3111595	3135419	23824.00	0.766	7	3354898.33	3296611	58287.33	15	874310

क्रम संख्या	इकाईयाँ का नाम	अवधि	बैचों की संख्या	प्रयुक्त शीरा की मात्रा (कुन्तल में)	वास्तविक उत्पादन (अ० ली० में)	मानक के अनुसार उत्पादन (कॉलम 5 x 22.5 x 94%) (अ० ली० में)	कम उत्पादन (अ० ली० में)	कम उत्पादन के प्रतिशतता की श्रेणी	आसबनी द्वारा कुल अल्कोहल उत्पादन के सापेक्ष पेय अल्कोहल उत्पादन की प्रतिशतता (अ० ली० में)		प्रेय अल्कोहल पर निर्धारित दर से निहित आबकारी अतिकर
									प्रतिशत	मात्रा	
		2011-12	5	106340	2210037.6	2249091	39053.4	0.24 - 3.76	28.09	10970.10	5126215
7	लाईस आसबनी, नन्दनगंज, गाजीपुर	2007-08	28	260477	5237890.27	5509088.55	271198.28	0.29 - 10.71	85.92	233013.56	45633604
		2008-09	29	279305	5563525.39	5907300.75	343775.36	0.09 - 10.08	90.77	312044.89	123943065
		2009-10	34	221615	4171469.67	4687157.25	515687.58	1.77 - 14.86	99.74	514346.79	216314072
		2010-11	43	231725	4408931.54	4900983.75	492052.21	1.96 - 14.47	99.93	491707.77	206792989
		2011-12	30	117214	2184059.38	2479076.1	295016.72	5.59 - 17.49	100	295016.72	137858280
		2012-13	34	172997	3300540.09	3658886.55	358346.46	0.79 - 13.44	99.56	356769.74	191722054
8	आई जी एल आसबनी, गोरखपुर	2007-08	5	336939	7082538.1	7126259.85	43721.75	0.01 - 1.29	1.03	450.33	142218
		2008-09	7	341947	6923440.4	7232179.05	308738.65	0.07 - 7.84	6.98	21549.96	8559563
		2009-10	8	354873	6957713.2	7505563.95	547850.75	0.44 - 10.59	4.64	25420.27	10690770
		2010-11	24	1166125	23910853.2	24663543.75	752690.55	0.42 - 6.78	17.14	129011.16	54257030
		2011-12	34	1493097	30495199.2	31579001.55	1083802.35	0.05 - 14.26	16.4	177743.59	83057750
		2012-13	30	1314404	26395859.1	27799644.6	1403785.5	0.003 - 14.62	21.94	307990.54	165508934
9	सरैया आसबनी, सरदार नगर, गोरखपुर	2007-08	19	600625	12331675.2	12703218.75	371543.55	0.54 - 5.64	34.84	129445.77	22762155
		2008-09	12	276728	5630913.1	5852797.2	221884.1	0.74 - 10.78	51.11	113404.96	45044028
		2009-10	33	490256	9717955.6	10368914.4	650958.8	0.25 - 16.37	65.09	423709.08	178195409
		2010-11	46	633144	12300802.4	13390995.6	1090193.2	0.60 - 15.30	20.25	220764.12	92844725
		2011-12	44	640512	12653945.3	13546828.8	892883.5	0.13 - 15.23	54.86	489835.89	228895275
		2012-13	52	1013496	19828332.7	21435440.4	1607107.7	0.96 - 17.04	44.73	718859.27	386302881
10	पलिया आसबनी, लखीमपुर खीरी	2009-10	7	133940	2682372.8	2832831	150458.2	0.24 - 8.25	92.03	138466.68	58233651
		2010-11	26	480540	9570995.1	10163421	592425.9	0.10 - 14.69	80.07	474355.42	199495269
		2011-12	12	175700	3481450.9	3716055	234604.1	0.12 - 18.17	87.24	204668.62	95639541
		2012-13	2	41000	850244	867150	16906	1.80 - 2.14	76.35	12907.73	6936398
11	दौराला आसबनी, मेरठ	2007-08	15	281940	5613111.6	5963031	349919.4	1.07 - 8.86	72.67	254286.43	26644490
		2008-09	8	171241	3529664.9	3621747.15	92082.25	0.03 - 6.21	51.38	47311.86	18792094
		2009-10	8	68598	1399885.2	1450847.7	50962.5	0.14 - 7.93	52.73	26872.53	11301530

क्रम संख्या	इकाईयाँ का नाम	अवधि	बैचों की संख्या	प्रयुक्त शीरा की मात्रा (कुन्तल में)	वास्तविक उत्पादन (अ० ली० में)	मानक के अनुसार उत्पादन (कॉलम 5 x 22.5 x 94%) (अ० ली० में)	कम उत्पादन (अ० ली० में)	कम उत्पादन के प्रतिशतता की श्रेणी	आसवनी द्वारा कुल अल्कोहल उत्पादन के सापेक्ष पेय अल्कोहल उत्पादन की प्रतिशतता (अ० ली० में)		प्रेय अल्कोहल पर निर्धारित दर से निहित आबकारी अधिकर
									प्रतिशत	मात्रा	
		2010-11	10	194916	3902044.7	4122473.4	220428.7	0.51 - 10.28	67.94	149759.26	62982866
		2011-12	10	132423	2691518.6	2800746.45	109227.85	0.69 - 5.11	69.57	75989.82	35509259
12	एन आई सी एल आसवनी, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	2007-08	20	313614	6110683.9	6632936.1	522252.2	2.42 - 12.93	58.32	304577.48	9420088
		2008-09	11	159369	3216637.9	3370654.35	154016.45	0.40 - 9.68	98.58	151829.42	60306077
		2009-10	4	31332	629009.8	662671.8	33662	2.52 - 7.03	96.96	32638.68	13726546
		2010-11	2	21084	433131.2	445926.6	12795.4	1.33 - 5.58	92.03	11775.61	4952358
		2011-12	13	157416	3172460.7	3329348.4	156887.7	0.20 - 8.04	54.34	85252.78	39837746
13	शामली आसवनी, शामली, मुजफ्फर नगर	2007-08	4	23246	481073.2	491652.9	10579.7	1.75 - 2.74	17.7	1872.61	222249
		2008-09	19	121362	2543416	2566806.3	23390.3	0.15 - 2.78	30.68	7176.14	2850338
		2009-10	6	37633	792783.8	795937.95	3154.15	0.09 - 2.08	16.19	510.66	214762
14	सर शादीलाल आसवनी, मंसूरपुर, मुजफ्फर नगर	2007-08	12	178628	3643616	3777982.2	134366.2	0.06 - 13.21	71	95400.00	5053491
		2008-09	22	353973	7203079	7486528.95	283449.95	0.84 - 7.93	73.22	207542.05	82434928
		2009-10	13	166447	3330532	3520354.05	189822.05	2.72 - 9.32	87.31	165733.63	69701060
		2010-11	26	406708	8313605	8601874.2	288269.2	0.10 - 6.95	66.51	191727.84	80633206
		2011-12	16	265244	5363270	5609910.6	246640.6	2.69 - 7.57	51.83	127833.82	59735431
		2012-13	5	87163	1762231	1843497.45	81266.45	2.47 - 8.43	53.56	43526.31	23390307
15	रामपुर आसवनी, रामपुर	2009-10	13	620990	12694610	13133938.5	439328.5	0.21 - 6.49	55.11	242113.94	101823618
		2010-11	20	1153385	23267575.4	24394092.75	1126517.35	0.97 - 8.37	42	473137.29	198982971
		2011-12	30	1615926	31590075.7	34176834.9	2586759.2	0.71 - 27.86	36.19	936148.15	437452409
16	को आपरेटिव आसवनी, टपरी, सहारनपुर	2009-10 & 2011-12	27	76182	1508783.8	1611249.3	102465.5	18.18	100	102465.50	44553603
17	शाकुम्भरी आसवनी, सहारनपुर	2007-08	12	139532	2662779.3	2951101.8	288322.5	0.52 - 21.28	1.04	2998.55	143931
		2008-09	6	111380	2268022	2355687	87665	2.79 - 5.42	7.07	6197.92	2461789
18	रोजा आसवनी, शाहजहाँपुर	2009-10 & 2010-11	41	391250	8141877.4	8274937.5	133060.1	0.02 - 6.07	100	133060.10	55959855
19	उन्नाव आसवनी, उन्नाव	2009-10 to 2011-12	78	743440	13597695.1	15723756	2126060.9	4.27 - 23.69	100	2126060.90	922584598
		21012-13	18	140275	2613979.2	2966816.25	352837.05	0.80-19.13	100	352837.05	189608695
	योग		1321	23978677	478107083.8	507149018.6	29041935			17485378.03	7364934982 या ₹ 736.49 करोड़

परिशिष्ट-XI
विदेशी मदिरा के दुकानों का फुटकर अनुज्ञापन
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.11.3)

(₹ में)

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	माह मार्च 2011 से फरवरी 2012 तक 12 माह की वास्तविक बिक्री (बोतलों में)	प्रति बोतल लाइसेंस फीस की दर	12 माह की वास्तविक बिक्री पर आरोपणीय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	कम आरोपित लाइसेंस फीस
1	जि0आ0अ0,अलीगढ़	2012-13	82	2672109	32	85507488	82311000	3196488
2	जि0आ0अ0,इलाहाबाद	2012-13	93	2007704	32	64246528	62372356	1874172
3	जि0आ0अ0,बागपत	2012-13	19	805642	32	25780544	25281000	499544
4	जि0आ0अ0,बरेली	2012-13	12	382126	32	12228032	12086600	141432
5	जि0आ0अ0,बिजनौर	2012-13	52	1676961	32	53662752	49686900	3975852
6	जि0आ0अ0,बदायूँ	2012-13	15	164488	32	5263616	5018900	244716
7	जि0आ0अ0,फिरोजाबाद	2012-13	63	1480577	32	47378464	45519882	1858582
8	जि0आ0अ0,जौबी0नगर	2012-13	15	432049	32	13825568	13351600	473968
9	जि0आ0अ0,गाजियाबाद	2012-13	58	3371556	32	107889792	102470200	5419592
10	जि0आ0अ0,गाजीपुर	2012-13	38	538792	32	17241344	16743100	498244
11	जि0आ0अ0,गोरखपुर	2012-13	43	1004380	32	32140160	30591300	1548860
12	जि0आ0अ0,जौनपुर	2012-13	65	839710	32	26870720	23721000	3149720
13	जि0आ0अ0,कानपुर	2012-13	84	3502647	32	112084704	109453050	2631654
14	जि0आ0अ0,कौशाम्बी	2012-13	34	218151	32	6980832	6447000	533832
15	जि0आ0अ0,लखीमपुर खीरी	2012-13	59	925320	32	29610240	27276900	2333340
16	जि0आ0अ0,लखनऊ	2012-13	74	2109683	32	67509856	64592530	2917326
17	जि0आ0अ0,मेरठ	2012-13	46	1953615	32	62515680	61534800	980880
18	जि0आ0अ0,मुरादाबाद	2012-13	63	2437551	32	78001632	63802300	14199332
19	जि0आ0अ0,मुजफ्फर नगर	2012-13	2	83583	32	2674656	2657700	16956
20	जि0आ0अ0,रामपुर	2012-13	2	4777	32	152864	144500	8364

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	माह मार्च 2011 से फरवरी 2012 तक 12 माह की वास्तविक बिक्री (बोतलों में)	प्रति बोतल लाइसेंस फीस की दर	12 माह की वास्तविक बिक्री पर आरोपणीय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	क्रम आरोपित लाइसेंस फीस
21	जि0आ0अ0,सहारनपुर	2012-13	41	1280053	32	40961696	38171100	2790596
22	जि0आ0अ0,शाहजहाँपुर	2012-13	9	152646	32	4884672	4812700	71972
23	जि0आ0अ0,उन्नाव	2012-13	39	433309	32	13865888	12692800	1173088
24	जि0आ0अ0,वाराणसी	2012-13	73	1873714	32	59958848	58074100	1884748
	योग		1081	30351143		971236576	918813318	52423258 या ₹ 5.24 करोड़

परिशिष्ट-XII

बिना बीयर बार लाइसेंस फीस जमा किये बीयर की बिक्री किया जाना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.11.4)

(₹ में)

इकाई का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल योग
	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०प०पी०य लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०प०पी०य लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०प०पी०य लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०प०पी०य लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०प०पी०य लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०प०पी०य लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	
जि०आ०अ०, अलीगढ़	5	110000	550000	4	110000	440000	4	110000	440000	4	110000	440000	5	150000	750000	7	150000	1050000	3670000
जि०आ०अ०, इलाहाबाद	13	110000	1430000	13	110000	1430000	13	110000	1430000	14	110000	1540000	14	150000	2100000	15	150000	2250000	10180000
जि०आ०अ०, बदायूं	1	85000	85000	1	85000	85000	1	85000	85000	1	85000	85000	1	100000	100000	1	100000	100000	540000
जि०आ०अ०, बरेली	17	110000	1870000	18	110000	1980000	18	110000	1980000	18	110000	1980000	19	150000	2850000	19	150000	2850000	13510000
जि०आ०अ०, बिजनौर	5	85000	425000	5	85000	425000	5	85000	425000	5	85000	425000	5	100000	500000	5	100000	500000	2700000
जि०आ०अ०, फिरोजाबाद	4	85000	340000	4	85000	340000	4	85000	340000	4	85000	340000	6	100000	600000	6	100000	600000	2560000
जि०आ०अ०, जौ०बी०नगर	35	110000	3850000	42	110000	4620000	53	110000	5830000	58	110000	6380000	65	150000	9750000	61	150000	9150000	39580000
जि०आ०अ०, गाजियाबाद	10	110000	1100000	11	110000	1210000	12	110000	1320000	17	110000	1870000	23	150000	3450000	23	150000	3450000	12400000
जि०आ०अ०, गोरखपुर	5	110000	550000	5	110000	550000	5	110000	550000	5	110000	550000	5	150000	750000	5	150000	750000	3700000
जि०आ०अ०, कानपुर	16	110000	1760000	16	110000	1760000	19	110000	2090000	19	110000	2090000	19	150000	2850000	शून्य	शून्य	शून्य	10550000
जि०आ०अ०, खीरी	2	85000	170000	2	85000	170000	2	85000	170000	3	85000	255000	3	100000	300000	4	100000	400000	1465000
जि०आ०अ०,	19	110000	2090000	21	110000	2310000	23	110000	2530000	23	110000	2530000	29	150000	4350000	29	150000	4350000	18160000

इकाईयो का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल योग
	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०पणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०पणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०पणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०पणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०पणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	वि०म०-६ / ६सी / ७ लाइसेंसों की संख्या	प्रति वि०म०-७बी आर०पणीय लाइसेंस फीस	कुल अप्राप्त लाइसेंस फीस	
लखनऊ																			
जि०आ०अ०, मेरठ	12	110000	1320000	11	110000	1210000	11	110000	1210000	11	110000	1210000	12	150000	1800000	13	150000	1950000	8700000
जि०आ०अ०, मुरादाबाद	17	110000	1870000	17	110000	1870000	17	110000	1870000	17	110000	1870000	17	150000	2550000	17	150000	2550000	12580000
जि०आ०अ०, मुजफ्फरनगर	2	110000	220000	2	110000	220000	2	110000	220000	2	110000	220000	2	150000	300000	2	150000	300000	1480000
जि०आ०अ०, रामपुर	1	85000	85000	1	85000	85000	1	85000	85000	1	85000	85000	2	100000	200000	2	100000	200000	740000
जि०आ०अ०, सहारनपुर	10	110000	1100000	9	110000	990000	9	110000	990000	11	110000	1210000	11	150000	1650000	11	150000	1650000	7590000
जि०आ०अ०, उन्नाव	शून्य	85000	शून्य	शून्य	85000	शून्य	शून्य	85000	शून्य	शून्य	85000	शून्य	1	100000	100000	1	100000	100000	200000
जि०आ०अ०, वाराणसी	21	110000	2310000	22	110000	2420000	24	110000	2640000	24	110000	2640000	25	150000	3750000	26	150000	3900000	17660000
महायोग	195		21125000	204		22115000	223		24205000	237		25720000	264		38700000	247		36100000	167965000
																			0
																			या ₹ 16.80 करोड़

परिशिष्ट-XIII

ओवर रेटिंग होने पर भी प्रतिभूति जमा का समपहरण न किया जाना

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.12)

(₹ में)

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	अवधि	मामलों की संख्या	दुबारा पकड़े गये मामलों की संख्या	आरोपित शास्ति	शास्ति की श्रेणी	समपहरण योग्य प्रतिभूति जमा की राशि
1.	जि०आ०अ०, अलीगढ़	2011-12	32	0	37150	300-2000	10744820
2.	जि०आ०अ०, बागपत	2009-10 से 2011-12	168	25	546650	50-5000	39748531
3.	जि०आ०अ०, बरेली	2009-10 से 2011-12	83	11	160200	200-5000	36596930
4.	जि०आ०अ०, बिजनौर	2009-10 से 2010-11	218	55	118000	500-5000	53377140
5.	जि०आ०अ०, बदायूँ	2009-10 से 2011-12	104	19	241000	1000-5000	27263267
6.	जि०आ०अ०, फिरोजाबाद	2007-08 एवं 2011-12	3	0	2000	500-1000	866550
7.	जि०आ०अ०, जी०बी०नगर	2009-10 से 2011-12	128	26	387500	200-5000	35798640
8.	जि०आ०अ०, गाजियाबाद	2009-10 से 2011-12	19	1	95000	5000	12430173
9.	जि०आ०अ०, जौनपुर	2010-11 से 2011-12	34	0	96500	2000-5000	8622815
10.	जि०आ०अ०, कानपुर	2010-11 से 2011-12	249	65	436200	100-2000	82779925
11.	जि०आ०अ०, खीरी	2009-10 से 2011-12	69	8	118500	1500-2000	7594056
12.	जि०आ०अ०, मेरठ	2010-11 से 2011-12	73	7	365000	5000	36974713
13.	जि०आ०अ०, मुरादाबाद	2010-11 से 2011-12	71	18	355000	5000	49255352
14.	जि०आ०अ०, मुजफ्फर नगर	2009-10 से 2011-12	78	7	372500	1500-5000	14284826
15.	जि०आ०अ०, रामपुर	2009-10 से 2011-12	105	8	139600	250-5000	7412301
16.	जि०आ०अ०, सहारनपुर	2009-10 से 2011-12	66	8	202000	1000-5000	25916950
17.	जि०आ०अ०, शाहजहाँपुर	2009-10 से 2011-12	49	13	141400	200-5000	9647193
18.	जि०आ०अ०, उन्नाव	2009-10 से 2011-12	31	4	59800	500-3500	6740047
19.	जि०आ०अ०, वाराणसी	2007-08, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12	30	2	84800	700-10000*	11326044
	योग		1610	277	3958800	50-10000	477380273 या ₹ 47.74 करोड़

नोट : केवल एक मामले में ₹ 10,000 शास्ति आरोपित की गयी थी।

परिशिष्ट-XIV
गोदाम परिव्यय
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.8.15)

(₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	गोदाम का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्राप्तियाँ			भुगतान			प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता	अन्तर
				देशी मदिरा का उपभोग बल्क लीटर में (38% वी/वी)	प्रति बल्क लीटर गोदाम व्यय की स्वीकृत दर	थोक बिक्रेता द्वारा गोदाम व्यय की प्राप्त धनराशि	विभाग को गोदाम किराये के रूप में भुगतान की गई धनराशि	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, वेतन	योग		
1.	अलौगढ़	2007-08	227.57	5212598.00	1.30	6776377	61359	2 से 4	61359	0.91	6715018
		2008-09	227.57	5134295.00	1.39	7196670	61359	2 से 4	61359	0.85	7135311
		2009-10	227.57	5576447.00	1.39	7751261	61359	2 से 4	61359	0.79	7689902
		2010-11	227.57	5722628.00	1.39	7954452	61359	2 से 4	61359	0.77	7893093
		2011-12	227.57	5800255.00	1.53	8874390	61359	4	61359	0.69	8813031
2.	इलाहाबाद	2007-08	735.63	5223475.00	1.30	6790517	474924	2 से 4	474924	6.99	6315593
		2008-09	293.68	5214285.00	1.39	7247856	227590	2 से 4	227590	3.14	7020266
		2009-10	409.66	5348746.00	1.39	7434756	290040	2 से 4	290040	3.90	7144716
		2010-11	281.61	5516682.00	1.39	7668187	222060	2 से 4	222060	2.90	7446127
		2011-12	286.61	5586257.00	1.53	8546973	243936	2 से 4	243936	2.85	8303037
3.	बरेली	2007-08	43	5791574.00	1.30	7529046	162300	9	162300	2.16	7366746
		2008-09	43	6052284.00	1.39	8412674	82560	2	82560	0.98	8330114
		2009-10	43	6544324.00	1.39	9096610	82560	2	82560	0.91	9014050
		2010-11	43	6737915.00	1.39	9365701	82560	2	82560	0.88	9283141
		2011-12	उपलब्ध नहीं	6805320.00	1.53	10412139	165000	2	165000	1.58	10247139
4.	जौनपुर	2007-08	163.33	3744326.56	1.30	4867625	52728	2 से 4	52728	1.08	4814897
		2008-09	82.29	3936165.55	1.39	5471270	37645	2 से 4	37645	0.69	5433625
		2009-10	163.33	4231079.31	1.39	5881200	52800	4	52800	0.90	5828400
		2010-11	163.33	4286404.36	1.39	5958102	52800	2	52800	0.89	5905302
		2011-12	163.33	4330988.18	1.53	6626412	52800	2	52800	0.80	6573612
5.	खीरी	2009-10	78.8	1706206.80	1.39	2371627	113472	3	113472	4.78	2258155
		2010-11	78.8	1763644.37	1.39	2451466	113472	2	113472	4.63	2337994
		2011-12	78.8	1780916.89	1.53	2724803	113472	2	113472	4.16	2611331
6.	लखनऊ	2009-10	उपलब्ध नहीं	12347556.59	1.39	17163104	825000	4	825000	4.81	16338104
		2010-11	उपलब्ध नहीं	12690198.03	1.39	17639375	825000	4	825000	4.68	16814375
		2011-12	उपलब्ध नहीं	13124903.48	1.53	20081102	990000	4	990000	4.93	19091102
7.	रामपुर	2007-08	427	1698025.00	1.30	2207432	99240	2 से 4	99240	4.50	2108192
		2008-09	427	1807044.00	1.39	2511791	99240	4	99240	3.95	2412551
		2009-10	427	1939275.00	1.39	2695592	99240	4	99240	3.68	2596352
		2010-11	427	1979339.00	1.39	2751281	99240	4	99240	3.61	2652041
		2011-12	427	2014346.00	1.53	3081949	99240	4	99240	3.22	2982709
8.	उन्नाव	2007-08	75.79	2937913.16	1.30	3819287	15636	2 से 4	15636	0.41	3803651
		2008-09	75.79	3121805.23	1.39	4339309	15636	2 से 4	15636	0.36	4323673
		2009-10	75.79	3381885.90	1.39	4700821	13250	2 से 4	13250	0.28	4687571
		2010-11	75.79	3434529.08	1.39	4773995	15900	2 से 4	15900	0.33	4758095
		2011-12	75.79	3469871.00	1.53	5308903	15900	4	15900	0.30	5293003

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	गोदाम का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्राप्तियाँ				भुगतान		प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता	अन्तर
				देशी मदिरा का उपभोग बल्क लीटर में (36% वी/वी)	प्रति बल्क लीटर गोदाम व्यय की स्वीकृत दर	शोक बिक्रेता द्वारा गोदाम व्यय की प्राप्त धनराशि	विभाग के गोदाम किराये के रूप में भुगतान की गई धनराशि	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, वेतन	योग		
9.	वाराणसी	2007-08	598.29	6749957.21	1.30	8774944	402484	2 से 4	402484	4.59	8372460
		2008-09	158.92	6634313.83	1.39	9221696	123120	2 से 4	123120	1.34	9098576
		2009-10	286.71	6939283.99	1.39	9645605	197592	4	197592	2.05	9448013
		2010-11	286.71	7248434.11	1.39	10075323	222120	2	222120	2.20	9853203
		2011-12	286.71	7321129.56	1.53	11201328	222120	2	222120	1.98	10979208
			8420.34	210886627.19		297402953	7309472		7309472		290093481

औसत क्षेत्रफल :- $8254.26 / 41 = 223.0881$ वर्ग मीटर

परिशिष्ट—XV
अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.13)

(₹ में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वाहन जिससे अधिक भार ढोया गया	परिवहित उपखनिज	अवधि जिनमें ओवरलोडेड वाहन संचालित थे	वाहन द्वारा ढोया गया भार (टन में, घनमीटर से बदलने के बाद)	वाहनों के प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमन्य ढोये जाने वाला भार (टन में)	अनुमन्य सीमा से अधिक परिवहित भार (टन में)	प्रत्येक वाहन पर आरोपणीय शास्ति	वाहनों की संख्या	आरोपणीय शास्ति की घनराशि जो आरोपित और वसूल नहीं की गयी
1.	स०स०प०क०, अम्बेडकरनगर	ट्रैक्टर (चार पहिया)	बालू	12/2011, और 03/2012	6	5.25 ³	0.75	3000	40	120000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	03/2011 और 04/2011	30	19	11	13000	70	910000
2.	स०स०प०क०, औरैया	ट्रैक्टर (चार पहिया)	बालू	03/2010, 05/2010 and 06/2010	6	5.25	0.75	3000	74	222000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	03/2010 और 06/2010	24	13	11	13000	100	1300000
3.	स०स०प०क०, बदायूं	ट्रैक्टर (चार पहिया)	बालू	06/2011	6	5.25	0.75	3000	22	66000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	10/2010, 12/2010, और 06/2011	24	19	5	7000	200	1400000
4.	स०स०प०क०, बागपत	ट्रैक्टर	बालू	12/2011, 01/2012, 03/2012, 04/2012	10	5.25	4.75	7000	149	1043000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	01/2012 और 04/2012	20	13	7	9000	109	981000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	01/2012, 03/2012 और 04/2012	40	19	21	23000	118	2714000
5.	स०स०प०क०, बहराइच	ट्रैक्टर	बालू	11/2010, 12/2010, 02/2011,	6	5.25	0.75	3000	12	36000
6.	स०स०प०क०, बलरामपुर	ट्रैक्टर	बालू	12/2011, 01/2012, 08/2012, और 10/2012	6	5.25	0.75	3000	81	243000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	06/2012 और 10/2012	20	13	7	9000	109	981000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	09/2012 और 10/2012	30	19	11	13000	120	1560000
7.	स०स०प०क०, बांदा	ट्रैक्टर	बालू	12/2011, 01/2012 और 02/2012	8	5.25	2.75	5000	110	550000

³ पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकतम अनुमन्य लदान भार = सकल यान भार (स०या०भा०) - लदान रहित भार (ल०र०भा०)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वाहन जिससे अधिक भार डोया गया	परिवहित उपखनिज	अधि जिनमें ओवरलोडेड वाहन संचालित थे	वाहन द्वारा डोया गया भार (टन में, घनमीटर से बदलने के बाद)	वाहनों के प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमन्य डोये जाने वाला भार (टन में)	अनुमन्य सीमा से अधिक परिवहित भार (टन में)	प्रत्येक वाहन पर आरोपणीय शास्ति	वाहनों की संख्या	आरोपणीय शास्ति की धनराशि जो आरोपित और वसूल नहीं की गयी
18.	स०स०प०क०, मऊ	ट्रैक्टर	मिट्टी/ बालू	08/2009, 11/2009, 03/2010, 04/2010 07/2010, और 09/2010	6	5.25 ⁵	0.75	3000	66	198000
		ट्रक (छ: पहिया)	बालू	04/2010	24	13	11	13000	76	988000
19.	स०स०प०क०, प्रतापगढ़	ट्रक (छ: पहिया)	बालू	04/2012	18	13	5	7000	48	336000
20.	स०स०प०क०, सहारनपुर	ट्रक (छ: पहिया)	बालू	09/2012	20	13	7	9000	100	900000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	09/2012	40	19	21	23000	75	1725000
21.	स०स०प०क०, सन्तरविदास नगर	ट्रक (छ: पहिया)	बालू	02/2009 से 07/2009, और 09/2009 से 12/2009	18	13	5	7000	162	1134000
22.	स०स०प०क०, सीतापुर	ट्रैक्टर	बालू	10/2011	8	5.25	2.75	5000	18	90000
		ट्रक (छ: पहिया)	बालू	09/2009, 10/2009 और 09/2011	24	13	11	13000	12	156000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	09/2011	24	19	5	7000	8	56000
23.	स०स०प०क०, उन्नाव	ट्रक (छ: पहिया)	साधारण मिट्टी	05/2012 और 06/2012	15.3	13	2.3	5000	50	250000
		ट्रक (दस पहिया)	साधारण मिट्टी	07/2011 और 12/2011	20.4	19	1.4	4000	4	16000
		ट्रक (दस पहिया)	साधारण मिट्टी	07/2011 और 12/2011	22.12	19	3.12	6000	34	204000
		ट्रक (दस पहिया)	साधारण मिट्टी	07/2011 और 12/2011	23.8	19	4.8	7000	32	224000
योग									3706	29748000

⁵ पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकतम अनुमन्य लदान भार = सकल यान भार (स०या०भा०) - लदान रहित भार (ल०र०भा०)

परिशिष्ट संख्या XVI

ईट भट्टा मालिकों से रायल्टी व ब्याज का न वसूल किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 6.5)

क्र.सं.	जिला	कुल ईट भट्टों की संख्या	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल रायल्टी	कुल ब्याज	कुल योग
			ईट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ब्याज 18% प्रतिवर्ष की दर से 30.06.2009 से 31.03.2013 (45 माह)	ईट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ब्याज 24% प्रतिवर्ष की दर से 15.1.2011 से 31.03.2013 (26.5 माह)	ईट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ब्याज 24% प्रतिवर्ष की दर से 15.12.2011 से 31.03.13 (15.5 माह)	ईट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ब्याज 24% प्रतिवर्ष की दर से 15.12.2012 से 31.03.13 (3.5 माह)			
1.	अलीगढ़	354				177	94.44	50.05	177	94.40	29.27				188.88	79.32	268.20
2.	इलाहाबाद	41							41	15.52	4.81				15.52	4.81	20.33
3.	औरिया	89				89	48.00	25.44							48.00	25.44	73.44
4.	आजमगढ़	13							13	3.43	1.06				3.43	1.06	4.49
5.	बदायूँ	14							14	6.82	2.11				6.82	2.11	8.93
6.	बागपत	48	4	2.07	1.4				44	24.93	7.73				27.00	9.13	36.13
7.	बलिया	17							17	4.18	1.3				4.18	1.30	5.48
8.	बलरामपुर	7							7	1.92	0.59				1.92	0.59	2.51
9.	बाराबंकी	11							11	4.60	1.43				4.60	1.43	6.03
10.	बुलन्दशहर	57	10	5.13	3.46	21	10.66	5.65	26	13.25	4.11				29.04	13.22	42.26
11.	चन्दौली	125							125	46.48	14.41				46.48	14.41	60.89
12.	फतेहपुर	83							83	31.05	9.63				31.05	9.63	40.68
13.	गौतमबुद्धनगर	205	37	20.34	13.73	84	47.94	24.94	84	47.06	14.59				114.45	53.26	167.71
14.	हाथरस	30							30	16.07	4.98				16.07	4.98	21.05
15.	जालौन	4							4	1.48	0.46				1.48	0.46	1.94
16.	कन्नौज	8							8	3.31	1.03				3.31	1.03	4.34
17.	कानपुर	2							2	1.03	0.32				1.03	0.32	1.35
18.	महराजगंज	150							150	33.66	10.43				33.66	10.43	44.09
19.	मऊ	150							150	36.68	11.37				36.68	11.37	48.05
20.	मुरादाबाद	145							145	75.52	23.35				75.52	23.35	98.87
21.	पीलीभीत	19							19	9.64	2.99				9.64	2.99	12.63
22.	सहारनपुर	65										65	49.56	3.47	49.56	3.47	53.03
	योग	1637	51	27.54	18.59	371	200.15	106.08	1150	470.87	105.97	65	49.56	3.47	748.12	274.11	1022.23

